

© भारत के  
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agaudelhi.cag.gov.in](http://www.agaudelhi.cag.gov.in)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2015 की प्रतिवेदन संख्या 2



भारत के  
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र  
(गैर—सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)  
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

Hj r ds  
fu; æd&egkys[ ki jh{k dk i frou

l kft d| l kU; , oavkEd {k=  
1/2S&l kZ fud {k= mi Øe<sup>1/2</sup>  
31 ekZ2014 dks l ekR o"Zdsfy,

jK'Vr, jkt /kuh {k= fnYyh l jdkj  
वर्ष 2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

## fo"k l ph

fooj.k	l nHZe	
	i\$kkQ	i"B l a
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xii
<b>v/; k I: iZrkouk</b>		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचत	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार का प्रत्युत्तर	1.6	3
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पुनरीक्षणों एवं पैराग्राफों का वर्ष-वार विवरण	1.10	5
<b>v/; k II: fu"i knu ys\$kkjh\$kk</b>		
<b>f' k\$kk foH\$kk</b>		
मध्याह्न भोजन योजना	2.1	7
<b>xg foH\$kk</b>		
जेल प्रबंधन	2.2	22
<b>l ekt dY; k k foH\$kk</b>		
अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाएँ	2.3	41
<b>'lgjh fodkl foH\$kk</b>		
विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2.4	56
सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता सेवाओं की कार्यप्रणाली	2.5	77

<b>v/; k III: vuqkyuk ys[ ki jk</b>		
<b>fodkl foHkx</b>		
प्रयोगशाला उपकरण का गैर-उन्नयन	3.1	95
<b>f' kkk foHkx</b>		
दिल्ली में सरकारी स्कूलों में एकीकृत आधारभूत संरचना सुधार पर लेखापरीक्षा (रूपांतर)	3.2	96
<b>LoLF; rFk ifjokj dY; k k foHkx</b>		
₹ 1.26 करोड़ का निष्फल व्यय	3.3	99
यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के बिजनेस मॉडल से विचलन	3.4	100
<b>xg foHkx</b>		
बिजली बिलों पर ₹ 70.06 लाख का परिहार्य व्यय	3.5	103
<b>Je foHkx</b>		
<b>fnYyh Hou rFk vU; fueZk Jfed dY; k k cM</b>		
₹ 37.10 लाख के ब्याज की हानि	3.6	103
<b>ykL fueZk foHkx</b>		
निविदा आमंत्रित किए बिना अनियमित रूप से ₹ 1.77 करोड़ का कार्य सौंपा जाना	3.7	104
कार्य प्रदान करने की अनियमित स्वीकृति	3.8	105
सड़कों के सुदृढीकरण पर परिहार्य व्यय— ₹ 73.31 लाख	3.9	106
<b>jkt Lo foHkx</b>		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा	3.10	109
<b>i f' k k rFk rduhdh f' kkk foHkx fun'sky;</b>		
₹ 75.20 लाख का निष्फल व्यय (ने.सु.त.सं.)	3.11	112
<b>ifjogu foHkx</b>		
परामर्शदाता को अनुचित लाभ तथा औचित्यता अध्ययनों पर ₹ 9.85 करोड़ का निष्फल व्यय	3.12	113
₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन	3.13	114

'lgjh fodkl foHkx		
नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा बहुस्तरीय कार पार्किंग सहवाणिज्यिक परिसरों का प्रचालन	3.14	115
₹ 73.85 लाख का निष्फल व्यय	3.15	123

## vuyXud

vuyXud l a	fooj.k	dsl nHZe	
		i\$kkQ	i"B l a
2.1	दूध के उपभोग तथा वास्तविक प्राप्ति में अन्तर	2.2.4.2 (ii)	127
2.2	एम पी लैड्स तथा एम एल ए लैड्स के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण	2.4.2	128
2.3	दि.न.नि. में विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी	2.5.6.1	132
2.4	आ.क.सं. की प्रतिक्रियाओं का सारांश	2.5.8	133
3.1	36 चयनित विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के निष्कर्षों का सारांश	3.2.5 (ii)	134
3.2	संकाय सदस्यों के वेतन का तुलनात्मक विवरण	3.4(i)	135

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछले प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2013-14 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ आवश्यक हो, सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।

fogakoykdu



## fogxloykdu

इस प्रतिवेदन में पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जैसे; मध्याह्न भोजनयोजना, जेल का प्रबंधन, अशक्त व्यक्तियों के कल्याण की योजनाएँ, विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं सुरक्षा तथा सफाई सेवाओं का यंत्रीकरण तथा ₹ 189.66 करोड़ सहित 15 पैराग्राफ जो अधिक/निरर्थक/निष्फल/व्यर्थ/परिहार्य व्यय निष्क्रिय निवेश, हानि, निधियों का अवरोधन इत्यादि से संबंधित थे। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

2009-14 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 24319.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 32726.31 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय ₹ 13900.88 करोड़ से बढ़कर ₹ 22366.52 करोड़ से 60.90 प्रतिशत तक बढ़ गया, गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 9158.12 करोड़ से बढ़कर 14904.24 करोड़ तक 62.74 प्रतिशत बढ़ गया तथा पूंजीगत व्यय ₹ 4717.27 करोड़ से घटकर 4707.42 करोड़ हो गया।

## fu"i knu ys[ kki jhkk

e/; lgu Hkt u ; kt uk

- स.शि.अ. के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. एवं वै.न.शि. केंद्रों में अध्ययनरत 18000 बच्चों में से केवल 1154 बच्चों को 2013-14 के दौरान सम्मिलित किया गया था।

*¼§kxhQ 2-1-2-1½*

- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं धारणीयता को नहीं बढ़ाया जा सका था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति 2009-10 के 74 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 66 प्रतिशत हो गई।

*¼§kxhQ 2-1-4-1 , oa2-1-4-3½*

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में विनिर्धारित दिनों की संख्या तक म.भो. नहीं दिया गया था। 2010-14 के दौरान पकाए गए भोजन के 2102 नमूनों में से, कुल 1876 नमूने (89 प्रतिशत) पोषण मूल्य के लिए परीक्षण में विफल रहे।

*¼§kxhQ 2-1-5-2 ¼ii½, oa ¼iii½*

- सेवा प्रदाताओं ने खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया एवं सिविक एजेंसियों व अग्नि विभाग से बिना "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" लिये ही अपनी रसोई चला रहे थे।

*¼§kxhQ 2-1-5-2 ¼iv½*

t syla dki zaku

- जेलों में 6250 की क्षमता के मुकाबले 14209 कैदी होने के कारण जेल अत्यंत भीड़ युक्त थी। नरेला, बपरोला एवं घिटोरनी में भूमि अधिग्रहण में देरी या अधिग्रहण न होने के कारण नई जेलों का प्रस्तावित निर्माण कार्यान्वित नहीं हो सका। मण्डोली जेल का

निर्माण अवधारणा, बनावट एवं अवश्यकताओं में बार-बार बदलाव के कारण पूरा नहीं हो सका।

*§ 2-2-1 (i) , oa(ii) ½*

- सुरक्षा उपकरणों जैसे सीसीटीवी पर अत्याधिक खर्च करने के बावजूद, प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

*§ 2-2-3-5 , oa2-2-6-1½*

- 1:6 के अभीष्ट अनुपात के मुकाबले, संस्वीकृत संख्या के अनुसार गार्ड कर्मचारियों एवं कैदियों का अनुपात 1:11 से 1:14 एवं वास्तविक पदासीन संख्या के अनुसार 1:16 से 1:21 था।

*§ 2-2-3-6½*

- चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी के कारण 93224 कैदी 2009-14 के दौरान बाहरी अस्पतालों में भेजे गये, जिनमें से 77232 केवल बाह्य चिकित्सा सेवा के लिए भेजे गये।

*§ 2-2-4-4½*

- फ़ैक्ट्री संचालन के लेखे नहीं बनाये गये। संविदा प्रदान करने एवं लागत निर्धारण में अनियमितताओं के कारण परिहार्य घाटे के मामले पाये गये।

*§ 2-2-5-1½*

v'kä 0 fä; kds dY; k k dsfy, ; k uk ½-0 -½

- विभाग ने घर-घर कोई स्वतंत्र सर्वे नहीं कराया बल्कि दिल्ली में रहने वाले अशक्त व्यक्तियों का विस्तृत डाटाबेस बनाने हेतु जनगणना सांख्यिकी पर निर्भर था। उन्होंने अ.व्य. के बारे में पता लगाने की राज्य अशक्तता नीति का विकास नहीं किया।

*§ 2-3-2-1 , oa2-3-2-2½*

- विभाग ने योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं किया और अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिला।

*§ 2-3-4-1½*

- मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्मित आशा किरण काम्प्लेक्स 350 व्यक्तियों की क्षमता की तुलना में 970 निवासियों की भीड़-भाड़ से युक्त था जबकि इसके पास 502 देखभाल करने वाले स्टॉफ की तुलना में मात्र 215 स्टाफ हैं।

*§ 2-3-5 (i) , oa(iii) ½*

- स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी निर्धारित बैठकें करने में नियमित नहीं थे। एससीसी नवंबर 2004 में अपने प्रारंभ से अब तक निर्धारित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल चार तथा एस.ई.सी. ने अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 40 बैठकों के प्रति केवल एक बार बैठक की।

*1/2 § kxhQ 2-3-7-1½*

- विभाग दिल्ली के 52330 अशक्त बच्चों के लिए 1250 बच्चों की क्षमता रखने वाले केवल छः विद्यालय चला रहा था। फिर भी यह विद्यालय अकादमी स्टाफ की 50 प्रतिशत से अधिक तक की कमी का सामना कर रहे थे।

*1/2 § kxhQ 2-3-7-3½*

- अ. व्य. के लिए सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाओं का अभाव था।

*1/2 § kxhQ 2-3-7-6½*

fo/ku l Hk l nL; LFkuh {k= fodkl ; kt uk ¼e , y , , y , Mh , l ½

- एम एल ए एल ए डी एस के दिशानिर्देशों में कई कमियाँ थीं जिससे योजना के क्रियान्वयन में स्पष्टता तथा पारदर्शिता का अभाव था। कई प्रावधानों से एम एल ए एल ए डी एस के दिशानिर्देशों के प्रभाव में धीरे-धीरे कमी आ गई।

*1/2 § kxhQ 2-4-2 , oa2-4-2-1½*

- श.वि.वि. ने अपेक्षित पूर्व आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना ₹ 39.90 करोड़ के 248 निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया

*1/2 § kxhQ 2-4-4-2 , oa2-4-5-4½*

- योजना के अंतर्गत कार्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आरंभ किया गया था। तथापि, ₹ 277.36 करोड़ के व्यय वाले 3160 निर्माण कार्यों में 60 प्रतिशत निधियाँ वर्तमान परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुधार पर खर्च की गई तथा ₹ 61.94 करोड़ के व्यय वाले 585 निर्माण कार्य दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं थे।

*1/2 § kxhQ 2-4-5-1½*

- कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों में बहुत-सी अनियमितताएँ जैसे कि व्यय का आधिक्य, संस्वीकृत कार्यों का अप्राधिकृत रद्दीकरण/समापन, कार्यों के सौंपने एवं समापन में देरी, निविदाओं को बिना आमंत्रित किए कार्य को सौंपना इत्यादि थीं।

*1/2 § kxhQ 2-4-7½*

- श.वि.वि. ने योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा था। इसने योजना निधियों की लेखापरीक्षा एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण हेतु किसी तंत्र को स्थापित नहीं किया

गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था।

*1/2 §kxkQ 2-4-8-1/ 2-4-8-2 , oa2-4-8-3½*

**l j{k k rFlk LoPNrk l okvldk ; ahdj.k**

- दि.न.नि. में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त किए जाने वाले स्वच्छता सेवाओं के नियत लक्ष्यों के साथ कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाएँ भी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

*1/2 §kxkQ 2-5-2½*

- 2013-14 के दौरान कचरे के प्रभावी एकत्रीकरण व पृथक्करण हेतु दि.न.नि. की उपलब्धि मात्र 17.44 तथा 25.30 प्रतिशत थी।

*1/2 §kxkQ 2-5-3-2 , oa2-5-3-3½*

- 2013-14 के दौरान मात्र 41 प्रतिशत कचरे का तथा 47 प्रतिशत निर्माण व विध्वंस अवशिष्ट का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि बाकी कचरा भराव क्षेत्रों में डाल दिया गया।

*1/2 §kxkQ 2-5-3-6 (i) , oa(ii) ½*

- दि.वि.प्रा. द्वारा, क.भ.क्षे. के लिए 600 एकड़ की भूमि की आवश्यकता के प्रति केवल 324.60 एकड़ भूमि ही आबंटित की गई थी जसमें से 150 एकड़ भूमि ही क.भ.क्षे. के लिए उपयुक्त थी।

*1/2 §kxkQ 2-5-3-6 (iv) ½*

- लगभग ₹ 22.96 करोड़ के 567 निर्जल मूत्रालयों के निर्माण के बावजूद दि.न.नि. साधारण जनता को गुणवत्तापूर्ण शौच सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहे।

*1/2 §kxkQ 2-5-3-10½*

- दि.न.नि. में इनके दिन प्रतिदिन स्वच्छता क्रियाकलापों जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालों की गाद साफ किया जाना, शौचालयों की सफाई, इत्यादि की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

*1/2 §kxkQ 2-5-7 (i) ½*

## वृत्तियुक्त यत्न

### 1 जे.ए.ए.ओ. वि.नि. के लिए, ए.ए.ओ. वि.नि. के लिए, ए.ए.ओ. वि.नि. के लिए

परियोजना को शिक्षा विभाग (शि.वि.) द्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को बिना किसी औपचारिक अनुबंध के सौंप दिया गया तथा कार्य के विस्तृत विवरण के अभाव में शिक्षा विभाग सुनिश्चित नहीं कर सका कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने परियोजना के अंतर्गत दिए गए सभी कार्य पूर्ण कर दिये। प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था नहीं थी। 183 विद्यालयों में से जहाँ दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा कार्य पूर्ण करने का दावा किया गया, शि.वि. ने केवल 78 को पूर्ण पाया, 50 प्रगति पर, तथा 55 को विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना था। शि.वि. ने दि.रा.औ.अ.वि.नि. को ₹ 343.13 करोड़ निर्गत किया, यद्यपि कैबिनेट ने परियोजना के लिए केवल ₹ 272.94 करोड़ स्वीकृत किया था।

₹ 3-2½

### लोक निर्माण विभाग के लिए

गुरु तेग बहादुर अस्पताल में निर्मित चार नये आवासीय बंगले पाँच से अधिक वर्षों तक काम में नहीं लाए गए जिसके कारण इन बंगलों के निर्माण में ₹ 1.26 करोड़ का का व्यय निष्फल था।

₹ 3-3½

### ; -र, ओ.ए.ए.ओ. वि.नि. के लिए

बिजनेस मॉडल से विचलित हो गया क्योंकि यह अपने संकाय सदस्यों को एक एकमुश्त राशि पैकेज के बजाय नियमित वेतनमान व भत्ते का भुगतान कर रहा था। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्टाफ को देय दरों से अधिक पर मकान किराया भत्ता व वार्षिक अभिवृद्धि तथा संकाय सदस्यों को गैर-व्यवहार्य भत्ता दिया गया।

₹ 3-4½

### जे.ए.ए.ओ. वि.नि.

अस्वीकृत/वापस किए गए चेकों की उपकर राशि को वसूल करने हेतु शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने में बोर्ड एवं उपायुक्त-श्रम की निष्क्रियता के कारण ₹ 37.10 लाख के ब्याज की हानि हुई। बोर्ड ने लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 4.80 करोड़ से ₹ 3.95 करोड़ की वसूली की।

₹ 3-6½

### यत्नपूर्वक निर्माण

लोक निर्माण विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 1.77 करोड़ का कार्य सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन एवं खुली निविदा आमंत्रण के बिना निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सौंपा। कार्य में 551 दिनों की देरी से पूरा हुआ।

₹ 3-7½

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (एमजेड-3) तथा अधीक्षण अभियंता (एम-35) ने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए एक कार्य के तीन विभाजित भागों के लिए अनियमित रूप से ₹ 13.54 करोड़ की बोलियाँ स्वीकृत की।

*₹ 13.54 करोड़ 3-8½*

### **भूमि अधिग्रहण कलेक्टर निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण प्रक्रियाओं को पूरा करने में**

तथा भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजे का भुगतान करने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा। तात्कालिकता खंड को एक नियमित ढंग से लागू किया गया था। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के नियमित नियंत्रण करने के लिए निर्धारित समितियों का गठन नहीं किया गया।

*₹ 12.68 करोड़ 3-10½*

### **₹ 9.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि परिवहन विभाग (प.वि.) ने पी आर टी पद्धति के लिए दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टि-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डिम्टस) के द्वारा बनाये गए व्यवहार्यता प्रतिवेदनों पर, आगे किसी कार्यवाही को आरम्भ नहीं किया।**

परिवहन विभाग (प.वि.) की प्रवर्तन शाखा में ई-चालान की परियोजना की अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप उपकरणों, जो कि तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रहे, के क्रय पर ₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

*₹ 1.47 करोड़ 3-12½*

परिवहन विभाग (प.वि.) की प्रवर्तन शाखा में ई-चालान की परियोजना की अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप उपकरणों, जो कि तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रहे, के क्रय पर ₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

*₹ 1.47 करोड़ 3-13½*

### **न.दि.न.प. ने परामर्शदाता की नियुक्ति में संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया। पुनः प्राप्ति कार्यप्रणाली में परिवर्तन की अनुमति से रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया। रियायतग्राही ने ₹ 96.36 लाख रियायत शुल्क कम जमा किया सांविधिक विनियमों के गैर-अनुपालन से कस्तूरबा गाँधी मार्ग बहुस्तरीय कार पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर को स्थगित कर दिया गया, जिससे ₹ 9.13 करोड़ का अवरोध हुआ और धरातल पार्किंग को बंद करने के कारण ₹ 11.71 करोड़ का घाटा हुआ। न.दि.न.प. ने स्थगित परियोजना के लिए आई.ई. के शुल्क के रूप में ₹ 1.22 करोड़ का अपव्यय किया।**

न.दि.न.प. ने परामर्शदाता की नियुक्ति में संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया। पुनः प्राप्ति कार्यप्रणाली में परिवर्तन की अनुमति से रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया। रियायतग्राही ने ₹ 96.36 लाख रियायत शुल्क कम जमा किया सांविधिक विनियमों के गैर-अनुपालन से कस्तूरबा गाँधी मार्ग बहुस्तरीय कार पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर को स्थगित कर दिया गया, जिससे ₹ 9.13 करोड़ का अवरोध हुआ और धरातल पार्किंग को बंद करने के कारण ₹ 11.71 करोड़ का घाटा हुआ। न.दि.न.प. ने स्थगित परियोजना के लिए आई.ई. के शुल्क के रूप में ₹ 1.22 करोड़ का अपव्यय किया।

*₹ 11.71 करोड़ 3-14½*

v/; k; -I  
i Ľrkouk

v/; k -I

iLrkouk

1-1 ctV : ijskk

रा.रा.क्षे. दिल्ली में 66 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2009-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों एवं उनके विरुद्ध वास्तविकों की स्थिति rkfydk 1-1 में दी गई है:

rkfydk1-1

2009-14 ds njsku jkT; ljdkj dk ct V , oaQ ;

₹ djM-ez

fooj.k	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	ct V vuqku	okLrfod	ct V vuqku	okLrfod	ct V vuqku	okLrfod	ct V vuqku	okLrfod	ct V vuqku	okLrfod
<b>jkT Lo Q :</b>										
सामान्य सेवाएं	1304.63	3629.67	1273.48	3728.95	1589.55	4347.23	3128.74	5738.57	5792.69	5597.48
सामाजिक सेवाएं	8370.95	8103.58	9345.57	8718.80	11567.05	10717.11	12616.68	11737.43	13134.81	12314.54
आर्थिक सेवाएं	1703.20	1650.28	1542.56	1392.46	2253.06	2172.22	2611.64	2350.82	3783.08	3650.00
सहायता अनुदान एवं योगदान	521.44	517.35	555.84	541.53	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50
<b>dy ¼½</b>	<b>11900.22</b>	<b>13900.88</b>	<b>12717.45</b>	<b>14381.74</b>	<b>16145.89</b>	<b>17964.85</b>	<b>19190.83</b>	<b>20659.35</b>	<b>23515.08</b>	<b>22366.52</b>
<b>ipkr ifjQ :</b>										
<b>ipkr Q ;</b>	4883.55	4717.27	4433.08	3984.80	4209.53	4004.27	4835.80	4176.63	4889.22	4707.42
forfjr _ .k , oavfxæ	5702.05	5701.30	6378.47	6364.73	3404.58	3345.42	4082.37	3734.83	5694.00	5652.37
ykcl _ .k dk i qHqrku	699.50	606.47	800.00	793.06	1090.00	1087.88	1288.00	1287.99	1325.29	1325.29
vkdlfledrk fuf/k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ykcl yqkalsforj.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vUr jkM-'kk	0	3387.70	0	7713.20	0	4636.28	0	1985.75	0	880.65
<b>dy ½½</b>	<b>11285.10</b>	<b>14412.74</b>	<b>11611.55</b>	<b>18855.79</b>	<b>8704.11</b>	<b>13073.85</b>	<b>10206.17</b>	<b>11185.20</b>	<b>11908.51</b>	<b>12565.73</b>
<b>l dy tM-¼½</b>	<b>23185.32</b>	<b>28313.62</b>	<b>24329.00</b>	<b>33237.53</b>	<b>24850.00</b>	<b>31038.70</b>	<b>29397.00</b>	<b>31844.55</b>	<b>35423.59</b>	<b>34932.25</b>

स्रोत : वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ तथा राज्य सरकार के वित्त लेखे

1-2 jkT; ljdkj ds l a kkuak dk vuqz kx

2009-14 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय<sup>1</sup> ₹ 24319.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 32726.31 करोड़ हो गया था तथा राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 13900.88 करोड़ से 2013-14 में ₹ 22366.52 करोड़ तक 60.90 प्रतिशत से बढ़ा था। 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9158.12 करोड़ से ₹ 14904.24 करोड़ तक 62.74 प्रतिशत से बढ़ा था एवं पूँजीगत व्यय 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 4717.27 करोड़ से ₹ 4707.42 करोड़ तक घट गया।

वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 57.15 से 68.34 प्रतिशत था एवं पूँजीगत व्यय 19.40 से 14.38 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय आठ प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2009-14 के दौरान 8.87 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

<sup>1</sup>लोककरण के पुनर्भूगतान तथा नगद शेषों को छोड़कर



### 1-3 fuarj cpr

छः मामलों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक में ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण rkydk1-2 में दिया गया है।

#### rkydk 1-2 o"K2009-14 dsnkku fuarj cpr ds l kfk vuqku dh l ph

₹ djM-ea/2

Ø- l a	vuqku l q; k rFk ule	cpr dh jf' k				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
jkt Lo ½er½						
1.	vuqku l a 3 %U k dk izkku	8.49	6.50	8.69	5.00	6.04
2.	vuqku l a 5 %xg	2.56	2.85	6.49	4.89	3.41
3.	vuqku l a 7 %fpfdR k, oaykd LokE;	12.22	2.04	7.45	1.93	3.50
4.	vuqku l a 11 % 'lgjh fodkl rFk ykd fuelZk foHkx	198.93	64.45	300.93	189.87	325.16
i wkr ½er½						
5.	vuqku l a 8 %l kkt d dY; k k	30.00	10.00	240.75	8.39	97.21
6.	vuqku l a 11 % 'lgjh fodkl rFk ykd fuelZk foHkx	14.59	8.16	23.32	19.54	20.18

स्रोत: विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम भण्डार मदों के क्रय, योजना के अंतर्गत दिन.नि. को निधि कम/नहीं प्राप्त होना, नगरपालिकाओं का गैर निष्पादन, अनुदान का द्विभाजन, योजना का गैर क्रियान्वयन समय पर संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थी।

### 1-4 Hkjr ljdkj l sl gk rk vuqku

2009-10 से 2013-14 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान rkydk1-3 में दी गई है:

#### rkydk1-3 Hkjr ljdkj l sl gk rk vuqku dso"Kokj C; ks

₹ djM-ea/2

fooj. k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
xS&; kt ukxr vuqku	1913.12	2338.71	978.85	333.57	326.91
jkt'; ; kt ukxr ; kt ukvlagrqvuqku	1430.94	1743.49	728.54	861.81	581.03
dhel; ; kt ukxr ; kt ukvlagrq vuqku	60.92	144.81	86.22	57.92	136.78
dhel; ik; ktr ; kt ukvlagrqvuqku	131.10	130.39	167.03	249.22	358.14
dy	<b>3536.08</b>	<b>4357.40</b>	<b>1960.64</b>	<b>1502.52</b>	<b>1402.86</b>
fi Nys o"Kdh rquk eaof) %S@deh %½dh i fr' krk	(+) 89.02	(+) 23.23	(-) 55.00	(-) 23.37	(-) 6.63
jkt Lo i fr; k	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69
jkt Lo i fr; k; dk i fr' kr	17.29	17.41	8.76	5.88	5.01

2009-11 की अवधि के दौरान भा.स. से कुल सहायता अनुदान ₹ 3536.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 4357.40 करोड़ हो गया तदन्तर 2011-14 के दौरान ₹ 4357.40 करोड़ से ₹ 1402.86 करोड़ तक की महत्वपूर्ण कमी हुई। इसका राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 5.01 से 17.41 प्रतिशत के मध्य थी।

### 1-5 **यस कि जहक ध ; क्तुक रफक i zalu**

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि, गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार हफ्ते में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2013-14 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय से राज्य के 142 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 10 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गईं।

### 1-6 **यस कि जहक ifronu ij ljdkj dkiR षंkj**

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा तथा कार्यकारी अधिकारी को उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर फोकस था।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों को संबंधित प्रधान सचिवों/विभाग के सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताहों के भीतर अपने प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए, प्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से जवाबों की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से उल्लेखित किया जाता है। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ तथा 21 पैराग्राफों को प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया

था। इनमें से दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 21 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2015)।

### 1-7 यक्षिणक्षेत्रीय विभागों की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान वसूली शामिल करते हुए लेखापरीक्षा प्राप्ति पाई गई जिन्हें विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं. अ.) की पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2013-14 के दौरान ₹ 170.61 करोड़ के 199 मामलों में वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं सं. अ. ने 2013-14 के दौरान 28 मामलों में ₹ 1.60 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली शामिल करते हुए) की वसूली की।

### 1-8 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेखापरीक्षा

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव साक्ष्यांकित करती है। इन जाँचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जाँच के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इत्यादि पाई जाती हैं एवं तत्काल नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें नि.प्र. के द्वारा निरीक्षित कार्यालयाध्यक्ष को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष तथा उनके उच्च प्राधिकारियों को नि.प्र. की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर उसकी अनुपालना की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को करनी चाहिए।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2014 को 1548 नि.प्र. में बकाया 6679 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ रकम-1 में दी गई हैं:

**रकम-1**  
**रकम-1 में दी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण**

₹ करोड़ में

क्षेत्र	रकम-1 में दी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	रकम-1 में दी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का मूल्य	रकम-1 में दी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का मूल्य (₹ करोड़ में)
सामाजिक क्षेत्र	774	3129	219.56
सामान्य क्षेत्र	616	3000	256.34
आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	158	550	4682.75
	<b>1548</b>	<b>6679</b>	<b>5158.65</b>

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में पैराग्राफों का लंबन लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की कमी को दर्शाता है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत तथा उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए।



v/; k, -II

fu"i knu ys[ kki jh{k

v/; k -II

fu"i knu ys[ kki jhkk

f' kkk foHkx

2-1 e/; k'u Hkt u ; kt uk

fnYyh ea e/; k'u Hkt u ; kt uk N% dk; kb; u , t sh ; ka ds } kjk Lora : i l s dk; kb; dh t krh gS f' kkk funs'ky; ; kt uk ds dk; kb; u ds fy, ukMy , t h gS t k ekuo l d k/ku fodkl ea;ky; %ekl afo-ea% Hkr l jdkj , oal eLr vU , t sh ; ka ds l kFk l elb; dk dk; Zdjr k gS egRoi wZys[ kki jhkk fu"d"Zulps fn, x, g%

fof' kVrk ;

- स.शि.अ. के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. एवं वै.न.शि. केंद्रों में अध्ययनरत 18000 बच्चों में से केवल 1154 बच्चों को 2013–14 के दौरान सम्मिलित किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2.1)

- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं धारणीयता को नहीं बढ़ाया जा सका था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति 2009–10 के 74 प्रतिशत से कम होकर 2013–14 में 66 प्रतिशत हो गई।

(पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.3)

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में विनिर्धारित दिनों की संख्या तक म.भो. नहीं दिया गया था। 2010–14 के दौरान पकाए गए भोजन के 2102 नमूनों में से, कुल 1876 नमूने (89 प्रतिशत) पोषण मूल्य के लिए परीक्षण में विफल रहे।

(पैराग्राफ 2.1.5.2 (ii) व (iii))

- सेवा प्रदाताओं ने खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया एवं सिविक एजेंसियों व अग्नि विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये ही अपनी रसोई चला रहे थे।

(पैराग्राफ 2.1.5.2 (iv))

2-1-1 iLrkouk

अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) प्राथमिक विद्यार्थियों के नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति को बढ़ाकर साथ ही उनके पोषण के प्रभाव को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। दिल्ली में योजना शिक्षा निदेशालय

(निदेशालय) एवं पाँच स्थानीय निकायों<sup>1</sup> द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित की जाती है। निदेशालय, नोडल एजेंसी है जो बजट के आबंटन व जारी करने के मामलों में अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), भारत सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। दिल्ली में विद्यालयों में पकाए गए मध्याह्न भोजन (म.भो.) की आपूर्ति हेतु विभिन्न गै.स.सं. को आउटसोर्स किया गया है जिसके लिए उन्हें भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

### 2-1-1-1 लक्षित क्षेत्र

मा.सं.वि.मं. देश में योजना के व्यापक कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है एवं मा.सं.वि.मं. का कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (का.अ.बो.) सभी राज्यों में योजना की स्थिति व प्रगति की समीक्षा करता है। प्रधान सचिव (शिक्षा) रा.रा.क्षे.दि.स., दिल्ली में योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है एवं निदेशालय के निदेशक, अपर निदेशक, उ.नि.शि. (म.भो.), सहा.नि.शि.(म.भो.), उ.नि.शि.(जिला), निदेशालय के शिक्षा अधिकारी (क्षेत्र) उसकी सहायता करते हैं। विद्यालय में विद्यालय के प्रमुख (वि.प्र.) एवं म.भो. प्रभारी विद्यालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की देखभाल करते हैं।

### 2-1-1-2 यशस्वी प्रकल्पों, योजनाओं, कार्यक्रमों

2009-14 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा पीपीएसडब्ल्यूओआर<sup>2</sup> पद्धति (जिले में विद्यालयों की संख्या के रूप में आकार माप के साथ) द्वारा चयनित 13 जिलों में से दो जिलों (पूर्वी व दक्षिणी) एवं एसआरएसडब्ल्यूओआर<sup>3</sup> पद्धति द्वारा चयनित 60 विद्यालयों (पू.दि.न.नि. एवं द.दि.न.नि. के 40 प्राथमिक विद्यालय एवं निदेशालय के 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के अभिलेखों की जाँच करते हुए अगस्त 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच संचालित की गयी थी। लेखापरीक्षा ने निदेशालय में म.भो. शाखा, पू.दि.न.नि. एवं द.दि.न.नि. के शिक्षा विभाग के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। दिल्ली में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वयन के निष्पादन लेखापरीक्षा को मार्च 2006 (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) को समाप्त वर्ष के लिए नि. एवं महा ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के खण्ड II में शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए, शिक्षा निदेशक के साथ प्रवेश सम्मेलन (अक्टूबर 2014) का आयोजन किया गया था। समापन सम्मेलन का आयोजन (मार्च 2015) किया गया था एवं बाद में प्राप्त सरकार के उत्तर को उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

### 2-1-1-3 यशस्वी प्रकल्पों ;

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या :

<sup>1</sup>उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उ.दि.न.नि.), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पू.दि.न.नि.), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् व दिल्ली छावनी बोर्ड (दि.छा.बो.)

<sup>2</sup>बिना बदलाव किए संभावित आनुपातिक आकार

<sup>3</sup>बिना बदलाव किए सामान्य यादृच्छिक नमूना

- यह योजना सभी पात्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयी बच्चों को सम्मिलित करने हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी,
- आबंटित निधियों का मितव्ययी तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा था,
- योजना ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति बढ़ाने, और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पोषण की स्थिति सुधारने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और
- योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशाली ढंग से निगरानी की जा रही थी।

## 2-1-2 ; kt uk

### 2-1-2-1 f' kxk; ks@oSu-f' k dHlarFlk enj l ka dks l ffefyr fd; k t kuk

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शि.गा.यो.<sup>4</sup>/वै.न.शि.<sup>5</sup> केन्द्रों एवं मदरसों के सम्मिलित किये जाने में कमियाँ थीं जबकि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (का.अ.बो.) ने अपनी बैठक (मई 2009) में, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2013-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. तथा वै.न.शि. केन्द्रों में, सभी 18000 पढ़ने वाले बच्चों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, योजना के अंतर्गत केवल तीन वै.न.शि. केन्द्रों तथा पाँच मूक व बधिर विद्यालयों के 1154 बच्चों को, सम्मिलित किया गया था। इसका उल्लेख पूर्ववर्ती रिपोर्ट में भी किया गया था, हालाँकि, कोई पर्याप्त सुधार नहीं देखा गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल 2047 बच्चे गै.स.सं./मदरसों द्वारा चलाए जा रहे 19 केन्द्रों में अध्ययन कर रहे हैं एवं उन्हें अप्रैल 2015 से योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इनका उत्तर, शि.गा.यो. तथा वै.न.शि. केन्द्रों के सभी बच्चों का पता लगाने एवं सम्मिलित करने में निदेशालय की दोषपूर्ण योजना को इंगित करता है। इनका उत्तर स.शि.अ. के अन्तर्गत बच्चों के आच्छादन के संबंध में मौन है।

### 2-1-2-2 e-Hks ; kt ukdsi fr t kx: drkmRi Uk djusrq; kt ukdkxj&i fri knu

मा.सं.वि.मं. के परिपत्र (22 जुलाई 2013) में पणधारियों, विशेषतः बच्चों व सामुदायिक सदस्यों के बीच में, टी.वी., रेडियो, प्रिंट मीडिया इत्यादि के माध्यम से योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशालय ने पणधारियों के बीच स्कीम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

### 2-1-2-3 mPp i kFed fo | ky; kae; kt uk ds dk kb; u eanjh

सितम्बर 2007 में मा.सं.वि.मं. ने रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2008-09 से इस योजना के उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तार करने का निर्देश दिया था। परंतु, निदेशालय ने इस योजना

<sup>4</sup>शिक्षा गारंटी योजना

<sup>5</sup>वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा



को 29 सितम्बर 2009 अर्थात् 18 महीने की देरी से उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित किया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सेवा प्रदाताओं के नाम सूची में लिखने की प्रक्रिया में अधिक समय लगा जिसके कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई।

### 2-1-3 ; क्त uk foYk

#### 2-1-3-1 ; क्त uk fuf/k, क ds vUrXZ fujarj cpr

2009-14 के दौरान मा.सं.वि.मं. व रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा अनुमोदित तथा जारी की गई निधियाँ, और किए गए वास्तविक व्यय का विवरण रkydk 2-1-1 में निम्नवत है:

रkydk 2-1-1% vkaVr] t kjh dh xbZfuf/k क vK oKrfod 0 ; 2009&14½

₹ djkm-e½

o"Z	ekl afo- ea fuf/k क dk vQ f; r vf/k कक	ekl afo-ea )kj k t kjh dh xbZ fuf/k क	jkjk{ks fn-l - )kj k t kjh dh xbZfuf/k क	dy mi yC/k fuf/k क	0 ;	cpra ¼ fr' krk½
2009-10	33.27	19.80	20.32	73.39	61.60	11.79 (16)
2010-11	11.79	85.53	20.69	118.01	94.96	23.05 (20)
2011-12	23.05	65.62	22.21	110.88	107.83	3.05 (3)
2012-13	3.05	85.24	20.67	108.96	99.35	9.61 (9)
2013-14	9.61	99.48	37.72	146.81	117.09	29.72 (20)
<b>dy</b>	<b>80.77</b>	<b>355.67</b>	<b>121.61</b>	<b>558.06</b>	<b>480.83</b>	<b>77.23 (14)</b>

स्रोत: निदेशालय द्वारा दी गई सूचना

इस प्रकार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर बचतें हुई, जो 20 प्रतिशत तक थीं।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि मा.सं.वि.मं. की ओर से निधियों के किश्त के अनुदान में हुई देरी के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ।

#### 2-1-3-2 fuf/k, क dh njh l si Vr , oami ; क

म.भो. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मा.सं.वि.मं. द्वारा प्रत्येक वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर के दौरान निधियों की दूसरी किश्त, पहली किश्त में किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की जानी चाहिए और राज्य वित्त विभाग को योजना निधियाँ शीघ्र जारी करनी चाहिए। दिल्ली में, निदेशालय वित्त विभाग को एजेंसीवार आबंटन का प्रस्ताव अनुमोदन के लिये प्रस्तावित करता है और अनुमोदन मिलने के बाद, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी करता है। लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि मा.सं.वि.मं. से निधियों की देरी से प्राप्ति हुई थी और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी नहीं हुई थीं/निधियों के जारी होने में देरी हुई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- (i) वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2010-11 के लिये अप्रैल 2011 में मा.सं.वि.मं. से ₹ 30.49 करोड़ की निधियाँ प्राप्त की, जिसका 2010-11 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 5.83 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 27.32 करोड़ क्रमशः फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया गया था जिसका सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में उपयोग नहीं किया जा सका।
- (ii) वित्त विभाग द्वारा जनवरी 2014 में प्राप्त, वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 10.45 करोड़ की निधियों को, 31 मार्च 2014 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी नहीं किया गया था।
- (iii) निदेशालय ने दि.न.नि., न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. को 29 मार्च, 31 मार्च और 30 मार्च 2011 को क्रमशः ₹10.11 करोड़, ₹ 78.80 लाख और ₹ 4.98 लाख जारी किया था परन्तु इन एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त किया गया (अप्रैल 2011)।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि मा.सं.वि.मं. से निधियों की प्राप्ति के पश्चात निधियाँ जारी करने में कई चरण लग जाते हैं जो कि अपरिहार्य देरी का कारण बना। इसने आगे कहा कि मा.सं.वि.मं. एवं वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से समय पर निधियाँ प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

### 2-1-3-3 i zaku] fuxjkuh , oaeW; kudu fuf/k dk de mi ; kx

मा.सं.वि.मं. के परिपत्र (जून 2010) के अनुसार, प्रबन्धन, निगरानी एवं मूल्यांकन (प्र.नि.मू.) के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान के 50 प्रतिशत का उपयोग विद्यालयों द्वारा स्टेशनरी और साबुन इत्यादि की खरीद पर और 50 प्रतिशत का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श्रमशक्ति को किराये पर लेने, बाह्य निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रचार इत्यादि पर करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्र.नि.मू. के अन्तर्गत मा.सं.वि.मं. द्वारा जारी किए गए ₹ 12.01 करोड़ के प्रति केवल ₹ 4.69 करोड़ का उपयोग किया। 2009-14 के दौरान निधियों का 35 से 84 प्रतिशत तक कम उपयोग किया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि प्र.नि.मू. निधियों के उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पुनः निर्देश दिया जाएगा एवं निदेशालय भी इस मामले पर और अधिक ध्यान देगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग ने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इस मुद्दे के उठाए जाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया।

### 2-1-4 fo | ky; kaeacPpksulekdu ij iHko

#### 2-1-4-1 ulekd rFk l fefyr fd, x, cPps

2009-14 की अवधि के दौरान नामांकित बच्चों तथा जिन्होंने म.भो. का लाभ उठाया, का विवरण rkydk 2-1-2 में दर्शाया गया है:

## रकम 2-1-2% के लिए प्रारंभिक शिक्षण के लिए बच्चों के नामांकन (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखा प्रतिवेदन

1/4 अंक के लिए

वर्ष	प्रारंभिक शिक्षण के लिए नामांकन			उच्च प्राथमिक शिक्षण के लिए नामांकन			कुल नामांकन
	बच्चों के नामांकन	बच्चों के नामांकन	बच्चों के नामांकन	बच्चों के नामांकन	बच्चों के नामांकन	बच्चों के नामांकन	
2009-10	11.75	6.98	18.73	8.23	4.89	13.12	70
2010-11	11.31	4.90	16.21	8.14	3.53	11.67	72
2011-12	11.53	6.68	18.21	7.84	4.54	12.38	68
2012-13	11.61	7.13	18.74	7.55	4.64	12.19	65
2013-14	11.34	7.12	18.46	7.37	4.63	12.00	65

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कुल नामांकन 2009-10 के 18.73 लाख से कम होकर 2010-11 में 16.21 लाख हो गया, इसके बाद यह 2012-13 में बढ़कर 18.74 लाख हो गया और पुनः घटकर 2013-14 में 18.46 लाख हो गया। म.भो. का लाभ उठाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 2009-10 के 70 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में जब यह 72 प्रतिशत थी को छोड़कर 2013-14 में 65 प्रतिशत हो गई। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निदेशालय ने विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिये न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किया था न ही नामांकन बढ़ाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कदम उठाया था। नामांकन में बढ़ोत्तरी करने के लिए, 40 प्राथमिक विद्यालयों में से 21 प्राथमिक विद्यालयों ने प्रवेश मेला<sup>6</sup> तथा प्रभात फेरी<sup>7</sup> इत्यादि का आयोजन जुलाई माह में किया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल उन विद्यार्थियों को म.भो. दिया जाता है जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त, दि.न.नि./निदेशालय के विद्यालयों में "दाखिला अभियान<sup>8</sup>" के लिए अप्रैल के महीने में विज्ञापन जारी करके नामांकन बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को नामांकन बढ़ाने के लिए संवेदनशील बनाया जाता है।

### 2-1-4-2 प्रारंभिक शिक्षण के लिए नामांकन

2009-14 के दौरान, चयनित प्राथमिक विद्यालयों में से 5749 बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया जबकि चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 1235 बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया। वार्षिक तौर पर, चयनित प्राथमिक विद्यालयों में 1306 से 1007 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 97 से 362 तक बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया था। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में उठाया गया था।

कुल 60 चयनित विद्यालयों में से, 29 प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के वि.प्र. ने

<sup>6</sup>प्रवेश शिविर

<sup>7</sup>अध्यापकों की विद्यार्थियों के साथ प्रभात फेरी

<sup>8</sup>नामांकन अभियान

बच्चों के विद्यालय छोड़ने के लिए गरीबी, भाई-बहनों के देख-रेख का उत्तरदायित्व, आवास का बदलना, इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि अधिकतम प्रतिवेदित विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक सम्भाव्यता का कारण प्रवासी मुद्दे थे।

### 2-1-4-3 फो | ky; kaeacPpladh mi fLFfr ij iHko

निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से यह प्रदर्शित हुआ कि योजना का विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर मिश्रित प्रभाव पड़ा था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में औसत उपस्थिति 2009-10 के 74 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 66 प्रतिशत हो गई जबकि यह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2009-10 के 74 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 78 प्रतिशत हो गई। चूँकि योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति को बढ़ाना था, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति में घटती प्रवृत्ति से संकेतित होता है कि योजना उपस्थिति पर वांछित प्रभाव नहीं डाल सकी। उपस्थिति में घटती प्रवृत्ति के मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि शिक्षा का अधिकार (शि. का अ.) अधिनियम 2009 के अनुसार कोई न्यूनतम उपस्थिति मानदण्ड नहीं है। इनका उत्तर घटती प्रवृत्ति को रोकने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

### 2-1-5 cPplads iKkf.kd Lrj eal qkj yk t kus ds l EcUk ea fØ; kdyki la dk eV; kdu

#### 2-1-5-1 [kk| kUkka dk vlcVr] mBk rFlk mi ; ks

(i) [kk| kUkka dk mi ; ks% भारत सरकार द्वारा योजना में प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यालय दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। खाद्यन्न का.अ.बो. द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर मा.सं.वि.मं. के द्वारा आबंटित किया जाता है। 2009-14 के दौरान दिल्ली में सभी छः एजेंसियों के द्वारा आबंटित, उठाए तथा उपयोग किए गये खाद्यान्नों की समग्र स्थिति, rkydk 2-1-3 में दी गई है।

#### rkydk 2-1-3% vlcVr] mBk rFlk mi ; ks fd, x, [kk| kUk

कैक-क एलवुद वु एड

o"lZ	cPpladh l d; k %i Nys o"lZ ds 30 fl rEcj rd½		vFk 'k'k		vkcVr fd; k x; k [kk  kUk		mBk k x; k [kk  kUk		mi ; ks fd; k x; k [kk  kUk	
	i kFfed	mPp i kFfed	i kFfed	mPp i kFfed	i kFfed	mPp i kFfed	i kFfed	mPp i kFfed	i kFfed	mPp i kFfed
2009-10	1175365	698118	-2021.57	0	20290.86	21162.84	17929.22	7666.43	16124.67	7452.37
2010-11	1131264	489944	-217.02	214.06	18899.98	17935.94	15051.95	13330.67	15312.96	12831.84
2011-12	1152596	668204	-478.025	712.89	18900	15787.1	16388.6	14148.24	16094.25	13724.69
2012-13	1161129	713378	-183.67	1136.45	17262	14722.22	15696.4	11805.32	14692.55	13479.11
2013-14	1133901	711763	818.18	-535.48	14390.58	14748.52	13621.57	14703.1	14330.58	13369.17
dy	5754255	3281407	-2082.105	1527.92	89743.42	84356.62	78687.74	61653.76	76555.01	60857.18

स्रोत: शिक्षा निदेशालय

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान, छः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 174100.04 मीट्रिक टन के आबंटन के प्रति केवल 140341.50 मीट्रिक टन खाद्यान्न (81 प्रतिशत) उठाया गया था। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि प्रेक्षण रिकार्ड की बात है। यह भी कहा गया कि खाद्यान्नों को बच्चों की उपस्थिति के आधार पर म.भो. की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उठाया गया था। सरकार का दावा सही नहीं है क्योंकि अथ शेष में ऋणात्मक आँकड़ों से संकेतित होता है कि सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के खाद्यान्नों का उपयोग करना था।

(ii) [क] कृषि एवं पशुधन विभाग म.भो. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई आकस्मिक अत्यावश्यकताओं के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु एक महीने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार रखे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं ने एक महीने के लिए निर्धारित सुरक्षित भंडार का रख-रखाव नहीं किया था क्योंकि उन्होंने भोजन देने के 30 से 50 दिनों के पश्चात खाद्यान्नों को प्राप्त किया था। निदेशालय ने खाद्यान्नों के उठाव में देरी का कारण प्रशासनिक कारणों को बताया (जनवरी 2015)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.भो. मानकों के अंतर्गत एक महीने का बफर स्टॉक एक कोडल आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, सेवाप्रदाताओं द्वारा स्वयं के खाद्यान्नों का प्रयोग, उपयोग किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि अब खाद्यान्नों को प्रत्येक महीने अग्रिम रूप में उठाया जाता है एवं सेवा प्रदाताओं के बीच वितरित किया जाता है तथा सेवा प्रदाताओं को बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया जाएगा।

(iii) जल संयंत्रों का आ.बो. ने अपनी बैठक (अप्रैल 2012) में, वि.सं.अ.के.<sup>9</sup> द्वारा फील्ड-दौरों के परिणाम पर टिप्पणी की, जिसमें पाया गया कि उठाव के समय खाद्यान्न 'ए' ग्रेड के रूप में प्राप्त किये जा रहे थे। लेकिन उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न म.भो. रसोईघर में नहीं पहुँचा। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक सेवा प्रदाता (मैसर्स मैत्री रिसर्च तथा डेवलपमेंट फाउंडेशन) के केन्द्रीय रसोईघर में उपलब्ध खाद्यान्नों का उपलब्ध स्टॉक उचित औसत गुणवत्ता (उ.औ.गु.) का नहीं था। चावल निम्न गुणवत्ता का, कीड़ों से भरा तथा अखाद्य तत्वों सहित था जिसमें काफी सफाई की जरूरत थी। विशेष सचिव (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दि.स. ने बैठक (3 अप्रैल 2012) में सूचित किया कि मामले की जाँच की जा रही थी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, पाया कि निदेशालय ने चूककर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि ई-निविदा के माध्यम से जाँच प्रयोगशाला का मनोनयन प्रक्रियाधीन है। इनका उत्तर, हालाँकि, वि.सं.अ.के. के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई पर मौन है।

## 2-1-5-2 [क] कृषि एवं पशुधन विभाग

(i) [क] कृषि एवं पशुधन विभाग चयनित विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पकाए गए भोजन की आपूर्ति में व्यवधान के निम्नलिखित मामलों

<sup>9</sup>विकास संघों के अध्ययन हेतु केन्द्र

का पता चला:

- 25 नवम्बर 2009 को एस.के.वी. विद्यालय, त्रिलोकपुरी में सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुवीर सिंह सेवा समिति) द्वारा दूषित भोजन की आपूर्ति के कारण 126 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया था और भोजन की आपूर्ति 10 दिनों के लिए रोक दी गई थी।
- जीबीएसएस विद्यालय, डेरा गाँव में चार दिनों तक पकाए गए भोजन की आपूर्ति नहीं की गई थी। प्रधानाचार्य ने बताया कि सेवा प्रदाता का वाहन खराब हो जाने के कारण भोजन की आपूर्ति नहीं हो पायी थी और इसके लिए उसने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी।
- चयनित विद्यालयों में, पकाए गए भोजन की गुणवत्ता में कमी के कारण 2009-10 में आठ अवसरों पर एवं 2010-11 में एक दिन के लिए पकाए गए भोजन को वापस कर दिया गया था।
- मई 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान, कुल 55216 (45 प्रतिशत) पकाए गए भोजन को सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटी माइन्स के विद्यार्थियों द्वारा नहीं लिया गया था, यद्यपि विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 123275 थी। प्रधानाचार्य ने म.भो. न लेने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन की कम गुणवत्ता को उत्तरदायी ठहराया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुवीर सिंह सेवा समिति) को पैनल से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गाँव डेरा विद्यालय में म.भो. की गैर-आपूर्ति के मामले में, चार दिनों का भुगतान उसके बिल से काट लिया गया था। आठ विद्यालयों में भोजन के वापसी के मामले में यह कहा गया कि म.भो. समिति भोजन परोसने से पहले सतर्क थी, इस प्रकार कम गुणवत्ता का भोजन बच्चों को नहीं दिया गया था। भाटी माइन्स विद्यालय के मामले में, यह कहा गया कि विद्यार्थियों ने म.भो. लेने में रुचि नहीं ली थी, परन्तु अब सभी विद्यार्थी भोजन ले रहे हैं। इनका उत्तर म.भो. की आपूर्ति में व्यवधान को रोकने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

(ii) ~~fofu/kzjr fnukal s de fnukard Hkt u dh vki~~ 200 नमूना जाँच मामलों<sup>10</sup> में से 169 में, का.अ.बो. द्वारा निर्धारित एक वर्ष में 210 कार्य दिवसों के लक्ष्य के प्रति 179 से 209 कार्य दिवसों तक के लिए भोजन की आपूर्ति की गई थी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, सभी 76 नमूना जाँच मामलों में, 220 दिनों (2009-10 के लिए 210 दिन) के लक्ष्य के प्रति 160 से 206 दिनों तक के लिए भोजन की आपूर्ति की गई थी। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि कभी-कभी विभिन्न कारणों से म.भो. वापस कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, आपूर्ति किए गए म.भो. के दिनों की संख्या कम हो गई थी। इसने आगे कहा कि पू.दि.न.नि. एवं. द.दि.न.नि. ने एक वर्ष में 200 दिनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि का.अ.बो. द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

<sup>10</sup>40 चयनित प्राथमिक विद्यालय × 5 वर्ष = 200 मामले

(iii) गै.स.सं. के नियोजन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार, गै.स.सं. का निष्पादन विश्वसनीय मूल्यांकन पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए एवं अगले वर्ष के लिए गै.स.सं. के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण, निष्पादन पर निर्भर करेगा। अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदाताओं को विनिर्धारित पोषण मूल्य<sup>11</sup> के पके भोजन की आपूर्ति करनी थी। आगे यह अनुबंध था कि यदि विशेष व्यंजन सूची में पोषण मूल्य में म.भो. का नमूना प्रतिवेदन लगातार असफल होता है तो अनुबंध रद्द हो जायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-14 की अवधि के दौरान श्री.रा.औ.अ.सं.<sup>12</sup> द्वारा 37 सेवा प्रदाताओं के पके हुए भोजन के 2102 नमूनों की जाँच की गई थी, जिनमें से 1876 नमूने (89 प्रतिशत) असफल हुए। 2013-14 के लिए निदेशालय के चयनित जिलों के मामले में, असफलता की दर 100 प्रतिशत थी। निदेशालय ने इन 37 चूककर्ता सेवा प्रदाताओं पर कुल ₹ 77.25 लाख का अर्थदण्ड लगाया। इसमें से इसने 31 सेवा प्रदाताओं के आपूर्ति आदेशों को 31 मार्च 2014 को विस्तारित किया। इसमें वे 12 सेवा प्रदाता भी शामिल थे जिन पर पिछले चार वर्षों से प्रतिवर्ष अर्थदण्ड लगाया जा रहा था, जिससे लगातार असफलता का संकेत होता है।

द.दि.न.नि. में 2012-14 के दौरान 137 में से 44 नमूने विफल रहे जबकि पू.दि.न.नि. में 2011-14 के दौरान 249 में से 113 नमूने निर्धारित कैलोरी व प्रोटीन मूल्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. ने निम्न कोटि के भोजन की आपूर्ति के लिए सेवा प्रदाताओं पर न तो कोई जुर्माना उद्ग्रहित किया और न ही उनकी सेवाओं को बन्द किया। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि पू.दि.न.नि. ने सभी सेवा प्रदाताओं को नमूनों की असफलता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है एवं निदेशालय द्वारा अपनायी गई नीति के अनुरूप सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। हालाँकि, इनका उत्तर चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के आपूर्ति आदेशों के विस्तार के कारणों के संबंध में मौन है।

(iv) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, के अनुसार सेवा प्रदाताओं को खाद्य सुरक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है। आगे, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को दि.न.नि. के स्वास्थ्य विभाग एवं अग्नि विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। अन्य अनुमतियों एवं अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों को भी प्राप्त किया जाना था। पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इस मुद्दे के उठाए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान आवश्यक लाइसेंस अथवा अनुमतियों/प्रमाण-पत्रों को किसी सेवाप्रदाता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि 23 सेवा प्रदाता (31 में से) आवश्यक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाताओं को नये सिरे से निर्देश जारी किये जाएंगे। हालाँकि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा में इस मुद्दे के उठाए जाने के बाद लाइसेंस प्राप्त किए गए थे।

<sup>11</sup>(i) प्राथमिक विद्यालयों में 450 कि.कैलोरी एवं प्रोटीन का 12 ग्राम (ii) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति भोजन 700 कि.कैलोरी एवं प्रोटीन का 20 ग्राम

<sup>12</sup>श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान

(v) निदेशालय ने मा.भो. योजना के कार्यान्वयन हेतु पालन किए जाने वाले सामान्य निर्देशों को जारी किया (दिसम्बर 2009, सितम्बर 2010 एवं जनवरी 2012)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

1/2 पूर्वी जिले के शि.अ. (क्षेत्र-I)<sup>13</sup> एवं शि.अ. (क्षेत्र-III)<sup>14</sup> के निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि या तो कीट नियंत्रण नहीं किया गया था अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा इस संबंध में अभिलेख नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा रसोईघरों में नियमित धूम्रीकरण और कीट नियंत्रण पर आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका।

1/2 अनुबंध के अनुसार, सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित था कि अपने-अपने रसोईघरों में जल शोधन प्रणाली की स्थापना एवं उसका रख-रखाव करें। संबंधित उ.नि.शि. तथा शि.अ. के निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि- (i) मैसर्स जन चेतना जागृति शैक्षणिक विकास मंच, (ii) मैसर्स दलित प्रहरी तथा (iii) मैसर्स भारतीय मानव कल्याण परिषद के रसोईघरों में जल शोधन प्रणाली स्थापित नहीं थी अथवा काम नहीं कर रही थी।

1/2 नियमित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दौरों में लेखापरीक्षा ने देखा कि भोजन वितरकों ने कुछ विद्यालयों में ऐप्रन, हेडगियर्स तथा दस्ताने नहीं पहने थे। साथ ही, 24 प्राथमिक तथा चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें पहचान पत्र भी जारी नहीं किए गए थे।

1/2 निदेशालय द्वारा रसोइया-सह-सहायक (र.स.स.) को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। (क) से (ग) तक उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। रसोइया-सह-सहायक के संबंध में, यह कहा गया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा नियोजित 60 र.स.स. की एक सूची, पर्यटन मंत्रालय, भा.स. के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए फरवरी 2014 में मा.सं.वि.मं. को अग्रपिठ की गई थी, परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

### 2-1-5-3 निरीक्षण रिपोर्ट की त्रुटि; त्रुटि/त्रुटि

(i) निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता म.भो. को पकाने के लिए द्विपोषक नमक, जैसा कि दिशा-निर्देशों में अनुबंध है, का प्रयोग नहीं कर रहे थे। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सभी सेवा प्रदाताओं को नये सिरे से निर्देश जारी किये जाएंगे।

(ii) निरीक्षण रिपोर्ट में म.भो. दिशा-निर्देशों (2006) में सूक्ष्म-पोषक तत्वों के अनुपूरण तथा दवा देकर-(क) कीड़ों को मारने की छमाही खुराक तथा विटामिन-ए अनुपूरण, (ख) आयरन, फोलिक एसिड तथा जिंक का साप्ताहिक अनुपूरण, तथा (ग) सामान्य कमियों के आधार पर अन्य उपयुक्त अनुपूरण का प्रावधान है।

सरकारी विद्यालयों में चाचा नेहरू सेहत योजना के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

<sup>13</sup>नवम्बर व दिसम्बर 2010 एवं नवम्बर 2011

<sup>14</sup>अप्रैल एवं अगस्त 2013



चलाया जाता है। दि.न.नि. के विद्यालयों में, यह संबंधित स्वास्थ्य विभागों द्वारा चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा सूक्ष्म-पोषक तत्वों, विटामिन ए, कीड़े मारने की दवाएँ, फौलिक एसिड तथा जिंक टैब्लेट्स, विद्यार्थियों को बाँटे जाते हैं। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दर्शाया गया है कि-

1/4 1/2 नौ चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2009-14 की अवधि के दौरान आयरन तथा फौलिक एसिड के टैब्लेट्स एक से पाँच बार दिए गए जबकि चार विद्यालयों में वितरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। 13 विद्यालयों में, कीड़े मारने की दवा एक से पाँच बार दी गई तथा चार विद्यालयों में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

1/4 1/2 2009-14 की अवधि के दौरान 16 चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, आयरन तथा फौलिक एसिड के टैब्लेट्स केवल एक से पाँच बार दिए गए, जबकि चार विद्यालयों में ये वितरित नहीं किए गए। 32 विद्यालयों में, 2009-14 के दौरान कीड़े मारने की दवा एक से पाँच बार दी गई थी। छः विद्यालयों में, टैब्लेट्स के वितरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि साप्ताहिक आयरन फौलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम विद्यालय के कक्षाध्यापकों/नोडल अध्यापकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इस संबंध में अभिलेखों को रजिस्ट्रों में एवं ऑनलाइन तैयार किया जाता है। उत्तर से वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण संबंधित विद्यालयों द्वारा तैयार किए गए पंजीयकों एवं वि.प्र. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर है।

(iii) **cPpla dh LokLF; &t lp%** 2009-14 की अवधि में 60 चयनित विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार, 66524 बच्चों को शामिल करते हुए कुल 513 स्वास्थ्य जाँच कैंप लगाए गए थे। यह देखा गया कि दो प्राथमिक तथा चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, कोई स्वास्थ्य जाँच कैंप नहीं लगाया गया था। दो प्राथमिक विद्यालयों तथा 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार भी कैंप नहीं लगाए गए थे। इन स्वास्थ्य कैंप से संबंधित अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता है कि पाँच प्राथमिक विद्यालयों के 412 बच्चे कम वजन के पाए गए तथा 10 प्राथमिक विद्यालयों के 1187 बच्चे एनीमिया के शिकार थे। विशेषकर एमसीपी विद्यालय, छतरपुर में, एनीमिक बच्चों की संख्या 2012-13 में अधिकतम 40 प्रतिशत (900 में से 360) तथा 2013-14 में 28 प्रतिशत (801 में से 224) थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि चाचा नेहरू सेहत योजना के अन्तर्गत, नवंबर 2011 से दिसंबर 2014 तक दिल्ली सरकार के विद्यालयों एवं सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न विद्यालयों में कुल 17.66 लाख विद्यार्थियों के किसी भी रोग, कमी एवं अशक्तता की जाँच की गई थी। उत्तर से नियमित स्वास्थ्य-जाँच के गैर-संचालन के मुद्दे का पता नहीं चलता है।

## 2-1-6 fuxjkuh vls eW; kdu

### 2-1-6-1 l pkyu&l g&fuxjkuh l fefr dk fuekZk vls bl dh cBda

म.सं.वि.मं. का परिपत्र (30 अगस्त 2010), म.भो. योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तरों पर संचालन-सह-निगरानी समिति (सं.नि.स.) की स्थापना का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सं.नि.स. ने वर्ष 2009-14 के दौरान, न्यूनतम 10 बैठकों (छः माह में एक बार) के प्रति केवल चार बार बैठकें आयोजित की। इसी प्रकार, 2009-14 के दौरान, क्षेत्रीय सं.नि.स. की 50 बैठकों के लक्ष्य के प्रति, दक्षिणी जिले के क्षेत्र 23 और क्षेत्र 24 में क्रमशः 18 और 5 बैठकों का आयोजन हुआ। पूर्वी जिले के तीन क्षेत्रों में, क्रमशः 18, 16 और 7 बैठकों का आयोजन हुआ। पू.दि.न.नि. और द.दि.न.नि. ने क्षेत्र या जिले स्तर पर किसी सं.नि.स. का गठन नहीं किया गया।

60 चयनित विद्यालयों में से, तीन प्राथमिक और चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय सं.नि.स. गठित नहीं की गई थी। सात प्राथमिक और सात उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यद्यपि सं.नि.स. गठित हुईं, परन्तु किसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ। 28 प्राथमिक विद्यालयों में, मासिक बैठकों की संख्या पाँच और 120 के मध्य थी और तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यह एक और 30 के मध्य थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि राज्य सं.नि.स. की बैठकें प्रत्येक छः माह में आयोजित की जाएंगी तथा क्षेत्रीय एवं विद्यालय स्तर पर सं.नि.स. की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। आगे, इसने यह कहा कि पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. ने विद्यालय स्तरों पर म.भो. के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया है। तथापि तथ्य यह है कि पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. में कोई क्षेत्रीय सं.नि.स. नहीं थीं।

### 2-1-6-2 efl d fuxjkuh fj i k/dks r\$ kj u djuk

उ.नि.शि. को क्षेत्रीय और विद्यालय स्तर पर म.भो. समिति के कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी और इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक शिक्षा (म.भो.) को ई-मेल के द्वारा मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना चाहिए थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप नि.शि. द्वारा मुख्यालय को मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि इस संबंध में जिलों के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएँगे।

### 2-1-6-3 dPps [ k| kUka dh xqloYk l sl af/kr ekun. Ma dh x\$ &vuq kyuk

मा.सं.वि.मं. ने सभी राज्यों को निर्देश परिचालित किए (फरवरी 2010) कि भा.खा.नि. के गोदामों से उठाए गए कच्चे खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए भा.खा.नि. को समय से भुगतान किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2009-14 के दौरान निदेशालय एवं पूर्वी दि.न.नि. द्वारा भा.खा.नि. के साथ इस प्रकार का कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भा.खा.नि. के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में नमूनों के उठाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।
- खाद्यान्नों के उठाव, भुगतान एवं गुणवत्ता के संबंध में भा.खा.नि. के साथ नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं

नमूनों के संयुक्त निरीक्षण एवं संयुक्त उठाव से संबंधित मुद्दे पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाए गए थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि जरूरत के अनुसार, बैठकों को आयोजित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे जैसा कि विनिर्धारित था।

#### 2-1-6-4 fo | ky; kdk fu; fer ekf d fujhkk u fd; k t kuk

निदेशालय द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार, सभी शि.अ. को निगरानी उद्देश्यों हेतु माह में कम से कम एक बार म.भो. के वितरण के समय निरीक्षण करना था। इस प्रकार के दौरों के बारे पूछे जाने पर, दक्षिणी जिले के शि.अ. (क्षेत्र 23 और 24) और पूर्वी जिले के क्षेत्र 1, 2 और 3 के शि.अ. ने कहा (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि उन्होंने आवश्यकतानुसार विद्यालय का दौरा किया। हालाँकि, विद्यालय-वार निरीक्षणों का विवरण शि.अ. के पास उपलब्ध नहीं था। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि जिलों के सभी उ.नि.शि. एवं क्षेत्रों के शि.अ. को सामान्य अनुदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 2-1-6-5 m-fu-f'k vks f'kv- }kjkl kZkdk de fujhkk djuk

उ.नि.शि. को अपने क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के रसोईघरों का माह में कम से कम एक बार और शि.अ. को पाक्षिक निरीक्षण करना चाहिए था। 2012-14 के दौरान 60 निरीक्षणों के लक्ष्य के प्रति केवल सात निरीक्षण किए गए जबकि 2009-12 के लिए निरीक्षणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उ.नि.शि. (दक्षिणी) ने 2009-14 की अवधि के दौरान रसोईघरों का केवल पाँच बार निरीक्षण किया था। दक्षिणी जिले (क्षेत्र 23 और 24) के शि.अ. और पूर्वी जिले के क्षेत्र 1, 2 और 3 के शि.अ. द्वारा किए गए निरीक्षणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि वर्तमान आदेश के अनुसार जिलों के सभी उप नि.शि. एवं क्षेत्र के शि.अ. को रसोईघरों का दौरा करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 2-1-6-6 f'kdk rkdh l qokkZ

निदेशालय के परिपत्र (13 सितम्बर 2010) के अनुसार, सभी विद्यालय प्रमुखों को शिकायतों/समस्याओं/सुझावों के लिए एक पंजिका रखनी चाहिये। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने, हालाँकि, दर्शाया कि 40 चयनित प्राथमिक विद्यालयों में से 13 और 20 चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 10 ने, इस तरह की कोई पंजिका नहीं बनायी थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि म.भो. से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए जिलों के उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने हेतु अप्रैल 2014 एवं जनवरी 2015 में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

#### 2-1-7 fu"d"K

निदेशालय, का.अ.बो. द्वारा लक्षित वै.न.शि./शि.गा.यो. केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों को शामिल करने में असफल रहा। इसने स्कीम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी। कुल आबंटित बजट में निरंतर बचतें थीं एवं मा.सं.वि.मं. द्वारा निधियों के जारी करने में देरी हुई थी। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति कम हो गई थीं एवं म.भो. के अंतर्गत बच्चों का आच्छादन भी कम हो गया था। सेवा प्रदाताओं ने एक माह के लिए निर्धारित खाद्यान्न का बफर स्टॉक नहीं रखा। पकाये हुये भोजन की आपूर्ति में व्यवधान/रूकावट के मामले थे या कई अन्य कारणों से जैसे- आस्थगित आपूर्ति,

सेवाप्रदाताओं के वाहन को नुकसान और निम्न स्तर के भोजन की आपूर्ति के कारण विद्यार्थियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। पकाए गए भोजन के अधिकांश नमूने मानक पोषण मूल्य की पूर्ति करने में विफल रहे। निदेशालय ने उन आपूर्तिकर्ताओं के आपूर्ति आदेश को विस्तारित किया जिनको बार-बार अर्थदण्ड लगाया जा रहा था। विद्यालयों में, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण नहीं किया गया था। उ.नि.शि. और शि.अ. के स्तर पर खाद्यान्नों को उठाने और लाने ले जाने, रसोई घरों और पके भोजन को वितरित करने में निगरानी एवं निरीक्षण की कमी थी।

### 2-1-8 निरीक्षण

सरकार को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

- (i) वै.न.शि. और शि.गा.यो. केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों के नामांकन की स्थिति की वार्षिक समीक्षा करें,
- (ii) नामांकन को बढ़ाने के लिए जन-सामान्य के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 'दाखिला अभियान' एवं 'प्रभात फेरी' जैसे और अधिक कार्यक्रमों को संचालित करें,
- (iii) सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूरित खाद्य विनिर्धारित मानक पोषण मूल्य के अनुरूप हों, और
- (iv) विद्यालयों, रसोईघरों के नियमित निरीक्षण द्वारा निगरानी प्रक्रिया को मजबूत बनाएं तथा राज्य, क्षेत्र एवं विद्यालय स्तरों पर सं.नि.स. की बैठकें आयोजित करें।

## xg foHkx

### 2-2 tsy izaku

तिहाड़ का केन्द्रीय कारागार, जिसमें नौ जेल एवं रोहिणी की 6250 कैदियों की कुल क्षमता वाली जनपद जेल शामिल है, एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। जेलों का प्रबंधन दिल्ली कारागार अधिनियम 2000 के अन्तर्गत होता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है :

fof' k'Vrk ;

- *tsy 6250 dh {lerk ds eqllcys 14209 ds h gkus ds dlj. k tsy vR; a HhM; ; qä FhA ujs/kj cijlsyk , oaf?kVkj uh ea Hhfe vf/kxg. k eanjh ; k vf/kxg. k u gkus ds dlj. k ubZ tsy dk iZrkfor fuelZk dk kZbr ughags l dk e. Myh tsy dk fuelZk vo/kj. kj culoV , oavo' ; drkvh ea ckj & ckj cnyko ds dlj. k ijk ughags l dk*  
*½ § kxhQ 2-2-1] 2-2-4-1 (i) , oa(ii)*
- *l q {kk mi dj. ka t s s l hl h/hoh ij vR; k/kd [kpZ djus ds chot w] ifrcf/kr oLrq/ka ds izsk ij fu; æ. k vi; kZr FhA*  
*½ § kxhQ 2-2-3-5 rFk 2-2-6-1½*
- *1% ds vHh'V vuqkr ds eqllcys l loh-r l d; k ds vuq kj xhM deZkj; ka, oadSn; ka dk vuqkr 1%1 l s 1%4 , oaokLrfod ink l hu l d; k ds vuq kj 1%6 l s 1%21 FhA*  
*½ § kxhQ 2-2-3-6½*
- *fpdRl dk fpdfRl k deZkj; ka, oai z sx' hkyk l fo/kv/ka dh deh ds dlj. k 93224 ds h 2009&14 ds nkf hu clgh vLi rkyl ea Ht sx; ; ft ueal s 77232 doy clg; fpdfRl k l ok ds fy, Ht sx; ;*  
*½ § kxhQ 2-2-4-4½*
- *QDVh l pkyu ds yf/ks ughacuk; sx; ; l fonk inku djus , oaykr fu/kj. k ea vfu; ferrk/ka ds dlj. k ifjgk; Z?kVs ds ekeys i k; sx; ;*  
*½ § kxhQ 2-2-5-1½*

### 2-2-1- Hfedk

तिहाड़ स्थित दिल्ली के केन्द्रीय कारागार में 5200 कैदियों की कुल क्षमतायुक्त नौ जेलें हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। रोहिणी के जिला कारागार में 1050 कैदियों की क्षमता है। यह जेल दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासित होती है, जो 25 अक्तूबर 2004 से कारागार अधिनियम 1894 की जगह प्रभाव में आया। 31 मार्च 2014 तक 10849 विचाराधीन कैदी, 3354 अपराधी एवं 06 सुधार बन्धकों सहित 6250 कैदियों की क्षमता के प्रति कुल 14209 कैदी थे।

#### 2-2-1-1 l xBukRed <kpk

दिल्ली कारागार पूर्णतया रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। कारागारों का महानिदेशक जेल विभाग का प्रमुख हैं, जिनके सहायक कारागार

के अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक हैं। एक जेल अधीक्षक नौ जेलों में से प्रत्येक जेल का प्रमुख होता है एवं उपअधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य संरक्षक एवं संरक्षक उसकी सहायता करते हैं। एक निवासी चिकित्सा अधिकारी सभी जेलों के चिकित्सीय प्रशासन की अध्यक्षता करता है।

जेल के कर्मचारीगण कैदियों की अभिरक्षा का कर्तव्य निभाते हैं जबकि तमिलनाडु विशेष पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस एवं केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल बाहरी सुरक्षा, गश्त, तलाशी, आदि का ध्यान रखते हैं। दिल्ली सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी कैदियों को न्यायालय एवं अस्पताल ले जाने में मार्गरक्षी का कार्य संभालती है।

### 2-2-1-2 यक्षि जक्षक मिस :

लेखापरीक्षा उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली था,
- कैदियों की हिरासत एवं अभिरक्षा सुरक्षित और संरक्षित थे,
- दिल्ली कारागार नियमावली में दी गई सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार कैदियों को मुहैया कराए जा रहे थे,
- सुधार एवं पुनर्वास की गतिविधियाँ अधिनियम तथा नियमों के उद्देश्यों के अनुरूप थी एवं
- योजनाएँ एवं परियोजनाएँ मितव्यय, कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से लागू की गई।

### 2-2-1-3 यक्षि जक्षक दक्षक-

निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 की अवधि के लिए अप्रैल तथा सितंबर 2014 में की गई थी। तिहाड़ जेल परिसर की नौ जेलों में से चार जेल (जेल सं. 1, 2, 3 व 6) एवं रोहिणी जिला जेल जिनमें मुख्य भण्डार, फैंक्ट्री इकाई, शस्त्रागार एवं केन्द्रीय जेल अस्पताल सम्मिलित हैं, विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिए चुने गये। कारागार विभाग एवं जेलों का निर्माण व रखरखाव देखने वाले लोक निर्माण विभाग के पांच मंडलों के अभिलेखों की भी जांच की गई। पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं में, जो मार्च 2005 में समाप्त वर्ष (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) के प्रतिवेदन में छपी थी, जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या पर चर्चा हुई। निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली की चर्चा के लिए (मई 2014) डी.आई.जी. (कारागार) के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया था।

सरकार को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप प्रस्तुत किया गया एवं समाप्ति सम्मेलन (मार्च 2015) में महानिदेशक (कारागार) के साथ चर्चा की गई एवं सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार एवं तत्पश्चात महानिदेशक (कारागार) से प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिवेदन में सम्मिलित की गईं।

### 2-2-1-4 यक्षि जक्षक दक्षक

लेखापरीक्षा को निम्नलिखित स्रोतों की कसौटी पर परखा गया है :

- दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000,
- दिल्ली जेल नियमावली,
- सामान्य वित्तीय नियम, एवं
- समय-समय पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश एवं अनुदेश।

## यस कि जह कि फु "द" ल

### 2-2-2 foYkt izaku

दिल्ली कारागार का 2009-14 की अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय rkydk 2-2-1 में दिये गये हैं :

rkydk %2-2-1 ct V vlcVu , oaQ ; ½kt Lo½

₹ djM+e½

o"l	; kt ukxr			xš ; kt ukxr		
	vloVu	Q ;	cpr	vloVu	Q ;	Qpr
2009-10	3.15	3.03	0.12	111.75	111.02	0.73
2010-11	4.48	4.45	0.03	114.73	114.33	0.40
2011-12	8.36	8.29	0.07	132.58	132.08	0.50
2012-13	14.50	13.57	0.93	155.89	155.30	0.59
2013-14	12.10	10.27	1.83	164.16	139.27	24.89

स्रोत: सूचना कारागार मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई।

2009-13 की अवधि में लगभग सभी आवंटित निधियों का उपयोग हो गया था। हालांकि वर्ष 2013-14 के दौरान 15 प्रतिशत की बचत हुई।

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताएँ निम्न पैराग्राफों में दी गई हैं।

(i) ty iHkj ladsfy, ₹ 1-30 djM+dk vfrfjä Hxrk%दिल्ली जल बोर्ड के दिसंबर 2009 की अधिसूचना के अनुसार यदि सरकारी कार्यालयों ने वर्षा जल के संरक्षण एवं/या बेकार पानी के पुनः प्रयोग के उपायों को अपनाया है तो वह पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट के पात्र हैं। हालांकि तिहाड़ जेल परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली एवं सीवर संशोधन संयंत्र काम कर रहे थे, किन्तु विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड से छूट का दावा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अवधि 2010-14 के दौरान ₹ 1.30 करोड़ (₹ 8.64 करोड़ का 15 प्रतिशत) अधिक भुगतान करना पड़ा।

महानिदेशक (कारागार) का कथन है कि विभाग ने लोक निर्माण विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं मामला (जनवरी 2015) दिल्ली जल बोर्ड को जनवरी 2010 से छूट का अनुदान प्राप्त करने के लिए पेश कर दिया है।

(ii) t qZl dk vfu; fer fgl k&fdrk %2009-14 के दौरान कारागार विभाग ने आपूर्तिकारों पर विलम्ब से आपूर्ति के लिए ₹ 1.41 करोड़ का जुर्माना लगाया। हालांकि जुर्माने को अलग से प्राप्ति मानने के बजाय विभाग ने कुल व्यय को (कुल भुगतान राशि-जुर्माना) संबंधित शीर्ष 2056, जेल-आपूर्तियाँ एवं सामान के अंतर्गत डाला।

महानिदेशक (कारागार) ने अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का भविष्य में पालन किया जायेगा।

(iii) dšh dY; k k dšk ½ds-dk½ea vfu; fer t ek%दिल्ली जेल नियामावली के नियम 13 का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पास जेल में प्रवेश करने के पश्चात पाई गई प्रतिबंधित वस्तु जब्त की जाएगी एवं जब्त धनराशि तथा जब्त वस्तुओं की बिक्री से

प्राप्त धनराशि सरकार के उचित शीर्ष के अंतर्गत जमा करानी होगी। जाँच एवं जब्ती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि जेल 1, 2 एवं 3 के कैदियों से जब्त ₹ 3.39 लाख की राशि एवं 'पुरानी रोटियों' को बेचकर प्राप्त धनराशि सरकारी खाते के बजाय कैदी कल्याण कोष में जमा कराई गई।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं आश्वस्त किया है (मार्च 2015) कि जब्त धनराशि अब अलग रहेगी न कि कैदी कल्याण कोष में।

(iv) ₹ 13.73 करोड़ का निर्माण विभाग ने जिला जेल रोहिणी के भवन का निर्माण किया, जिसने अक्टूबर 2004 में काम करना आरम्भ कर दिया। क्योंकि भवन में पानी का अस्थायी कनेक्शन था, कार्यपालक अभियंता (लो.नि. वि.) ने मार्च 2006 में स्थायी पानी का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. को पूर्णता एवं कब्जा प्रमाणपत्र (फार्म डी) जारी करने के लिए आवेदन किया, जो सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था। जिसके परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. सामान्य दर से तीन गुनी दरों पर जुर्माने के तौर पर पानी के बिल जारी करता रहा। हालांकि रोहिणी जिला जेल ने सामान्य दर पर जल प्रभार अदा किया। जेल प्राधिकरण द्वारा पानी के स्थायी कनेक्शन के लिए असमर्थता के परिणामस्वरूप (दिसंबर 2013 तक)<sup>15</sup> जुर्माने के रूप में ₹ 13.73 करोड़ की देयता बन चुकी थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में समाप्ति-सह-अधिमोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे यह कहा गया कि अग्निशामक के निविदा दस्तावेज को पुनरीक्षण हेतु प्रभागीय अधिकारी, डीएफएस को सितम्बर 2012 में भेजा गया था लेकिन वह प्रतीक्षित था। हालांकि विभाग द्वारा शीघ्र एनओसी प्राप्त करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

### 2-2-3 अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, जेलों में कैदियों के हिरासत एवं सुरक्षा के लिए उच्चरदायी है।

अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जेल अधीक्षक कैदियों की सुरक्षित हिरासत एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। कैदियों की नज़रबंदी की शर्तें एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों एवं जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। कैदियों की हिरासत एवं नज़रबंदी के दौरान पाई गई कमियों का नीचे पैराग्राफ में वर्णन किया गया है:

#### 2-2-3-1 अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, जेलों में कैदियों के हिरासत एवं सुरक्षा के लिए उच्चरदायी है।

प्रावधानों के तहत दण्ड संहिता की धारा 436 ए निर्धारित करती है कि जहाँ छानबीन के दौरान किसी कानून के तहत एक अपराध की जाँच या मुकदमे (ऐसा अपराध न हो जिसकी सजा मृत्युदण्ड हो) में कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा से आधी कैद की सजा काट चुका है, ऐसा व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत राशि या उसके बिना रिहा हो सकता है। गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने भी इस मामले में भीड़ कम करने के विचार से एडवाईज़री (मई 2011) जारी की थी।

<sup>15</sup>अवधि जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान बिल बनाए गए



दिल्ली कारागार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सुनवाई के दौरान 51 वि.कै.<sup>16</sup> (31 अगस्त 2014) को कानून के तहत उन पर आरोपित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड की आधी से अधिक अवधि के लिए कैद में रखा गया। सुनवाई के दौरान कैदियों को बिना पुनरावलोकन इतनी लम्बी अवधि के लिए हवालात में रखना अपराध दण्ड संहिता एवं गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुरूप नहीं था।

जवाब में महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि मामला जेल प्राधिकरण की सीमा के अन्दर नहीं आता है एवं न्यायालयों को निर्णय लेना है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा मई 2011 में विशिष्ट एडवाइजरी जारी करने के बावजूद जेल प्राधिकरण ने न्यायालय को वि.कै. की लिस्ट सितंबर 2014 में ही जमा करायी।

### 2-2-3-2 vfrfK ckMZ

दिल्ली कारागार (कारागार अतिथि) नियमावली, 1988 में विशेष रूप से अतिथि बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसका पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है जो एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसके द्वारा सभ्य समाज जेल की दशाओं एवं प्रशासन पर नजर रख सकता है। जबकि ऐसा कोई बोर्ड गठित ही नहीं हुआ।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि बोर्ड का गठन मार्च 2014 में हुआ था। हालांकि जवाब बोर्ड के गठन में हुए विलंब के कारण व परिस्थितियों के बारे में वर्णन नहीं करता है।

### 2-2-3-3 fgjkl r , oadsh eal j{lk dh deh

दिल्ली कारागार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 2009-14 (कैलण्डर वर्षों) के दौरान बीमारी, आत्महत्या, साथी कैदियों द्वारा हमले एवं जेल परिसर में दुर्घटना इत्यादि के कारण 146 मृत्यु के मामले हुए। इस प्रकार कारागार अधिकारीगण जेल में कैदियों के सुरक्षित हिरासत व नज़रबंदी को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि दिल्ली कारागार में बंदियों की संख्या की तुलना में केवल 146 मृत्यु के मामले (0.01 प्रतिशत) पांच वर्ष की अवधि में घटे एवं उनमें से कुछ ही आत्महत्या या साथी बंदियों द्वारा हमले के कारण घटे। भविष्य में ऐसी घटनाएँ टालने के लिए पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।

### 2-2-3-4 dsh; kdk bfrgkl i=d

दिल्ली कारागार (कैदी सम्पत्ति, इतिहास, चिकित्सा इत्यादि) नियमावली 1988 के नियम 17 एवं 19 के अनुसार प्रत्येक अपराधी को एक इतिहास पत्रक दिया जाता है जिसमें इतिहास पत्रक में अन्य बातों के साथ-साथ फैसले की प्रति की प्राप्ति, न्यायालय में दायर अपील के प्रेषण की तिथि, प्रत्येक अनुमोदित साक्षात्कार, निजी पत्रों की प्राप्ति व प्रेषण की रसीद, अपीलीय न्यायालय के आदेश का सार, अपील करने के लिए स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पहले नहीं की गई अपील के साक्ष्य एवं अपील का परिणाम इत्यादि उल्लिखित होते हैं। पाँच जेलों के (केन्द्रीय कारागार-1, 2, 3, 6 एवं जिला जेल रोहिणी) कैदियों की इतिहास

<sup>16</sup>विचाराधीन कैदी

पत्रावली की नमूना जाँच के दौरान पूरे ब्यौरे अद्यतन स्थिति सहित दर्ज नहीं पाये गये। इसलिए लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि प्रत्येक जरूरतमंद कैदी को विधिक सहायता प्रदान की गई या नहीं।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि जुर्माने के साथ सुनाई गई सजा, चिकित्सीय विवरण, प्रदान की गई सुविधाएँ, आवंटित मजदूरी, छूट एवं रिहाई की अनुमानित तिथि इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियाँ इतिहास पत्रक में दर्ज कर दी गई हैं। जबकि प्रत्येक अपराधी के लिए कारावकाश/गैर हाजिरी का विवरण एक अलग फाइल में दिया जाता है। जवाब इस वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है क्योंकि कैदियों के पास उपलब्ध इतिहास पत्रक में यह विवरण नहीं था।

### 2-2-3-5 ifrcf/kr oLrvkadsioškij vi; kR fu; a. k

10 में से छः जेलों की खोज एवं जब्ती पंजिकाओं की नमूना जाँच एवं लेखापरीक्षा में दी गई सूचना से पता चला कि प्रतिबंधित वस्तुएँ, जैसे मोबाइल फोन, देशी निर्मित पिस्टल, मुद्रा, नशीले पदार्थ, ब्लेड, रस्सियाँ इत्यादि कैदियों से जब्त किये गये। जब्ती से इंगित हुआ कि बंदियों एवं मुलाकातियों के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया होने के बावजूद प्रतिबंधित वस्तुएँ कैदियों तक पहुँचीं।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि कैदियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएँ शारीरिक गुहिकाओं में छिपाकर एवं उनको निगलकर जेल के अन्दर ले जाई जाती हैं। बंदियों एवं कर्मचारियों की सम्पूर्ण जाँच के लिए एक्स-रे आधारित सम्पूर्ण शरीर स्कैन प्रक्रियाधीन है, जो वस्तुओं को शारीरिक गुहिकाओं में छिपाने की संभावनाओं को और कम करेगी।

### 2-2-3-6 vi; kR l g{kk mik , oaQ oLFkk j

सुरक्षा प्रक्रियाओं के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से पता चला है कि जेल द्वारा अपनायी गई बहुत सी प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ वर्तमान स्थिति में सुरक्षा व सतर्कता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी जैसा नीचे विस्तार से दिया गया है :

- एक वार्ड से दूसरे वार्ड, वार्ड से ड्योढ़ी (मुख्य जेल प्रवेश द्वार) एवं वार्ड से चक्कर (नियंत्रण कक्ष) तक कोई संचार पद्धति नहीं थी (इंटरकाम या टेलीफोन लाइन) जो गंभीर रूप से किसी आपातकालीन स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया में देरी कर सकती थी।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित आदर्श कारागार नियमावली में बताया गया है कि निगरानी कर्मचारियों एवं कैदियों के बीच अभीष्ट अनुपात 1:6 होना चाहिए। जबकि संस्तुत संख्या अनुसार अनुपात 1:11 से 1:14 था एवं पदासीन अनुपात 1:16 से 1:21 था।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि कारागार कर्मचारियों के सभी संवर्गों में अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका था। कैदियों एवं कर्मचारियों का असंगत अनुपात कारागार की अत्यधिक भीड़ एवं कर्मचारियों की कमी का कारण था। मामला पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा (मार्च 2005) में चिह्नांकित किया गया था किन्तु निगरानी कर्मचारियों एवं कैदियों के बीच का अनुपात असंगत ही बना रहा।

## 2-2-4 दंडन; लक्ष्मण लक्ष्मण, ओ.ए.ए.ए.ए.ए.

### 2-2-4-1 दंडन; लक्ष्मण लक्ष्मण, लक्ष्मण, ओ.ए.ए.ए.ए.

(i) वरुण लक्ष्मण लक्ष्मण प्रति वर्ष 31 दिसंबर को तिहाड़ परिसर एवं रोहिणी जेल में वास्तविक कारागार जनसंख्या की जेल की निर्दिष्ट क्षमता के साथ तुलना में कुल भीड़-भाड़ 174 से 217 प्रतिशत तक होने के संकेत मिले हैं।

महानिदेशक (कारागार) ने (मार्च 2015) माना एवं कहा कि कारागार विभाग द्वारा और अधिक जेलों का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) वरुण लक्ष्मण लक्ष्मण जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या से वास्तविक रूप से निपटने का एकमात्र तरीका शीघ्रता से नया जेल स्थान सृजन करना व अधिग्रहित करना था। जबकि देखा यह गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 491.50 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध 68 प्रतिशत की बचत के साथ ₹ 305.32 करोड़ का व्यय हुआ।

मण्डोली, नरेला, बपरोला एवं घिठोरनी में निर्माण के लिए नई जेलों का प्रस्ताव दिया गया (जनवरी 1981)। जबकि निधि उपलब्ध होने के बावजूद अगस्त 2014 तक 33 वर्ष तक की लम्बी अवधि बीतने के बाद भी भूमि अधिग्रहण में देरी/न होने के कारण (नरेला, बपरोला, घिठोरनी), विचारधाराओं, बनावट एवं प्रस्तावित आवश्यकताओं (मण्डोली) में बार-बार बदलाव के कारण उनमें से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए अत्यधिक भीड़ की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।

महानिदेशक (कारागार) ने समाप्ति सम्मेलन (मार्च 2015) के दौरान नई जेलों के निर्माण में शीघ्रता दिखाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि अन्य एजेंसियाँ, जैसे भू.अ.प., दि.वि. प्रा. एवं लो.नि.वि. इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। हालांकि तथ्य यही है कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित होने के बावजूद जेलों में भारी भीड़ थी।

### 2-2-4-2 दंडन; लक्ष्मण लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण

दिल्ली कारागार नियमावली (कैदी स्थानांतरण, भोजन, कपड़े एवं सफाई) 1988 के नियम 74 के अनुसार महानिदेशक (कारागार) दिल्ली प्रशासन की पूर्व सहमति के साथ प्रत्येक श्रेणी के कैदी को प्रदान की जाने वाली खुराक का मापदण्ड निश्चित करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कारागार विभाग के अभिलेखों में प्रदान की गई खुराक एवं उसके हिसाब में निम्नवर्णित अनियमितताएँ थीं :

(i) लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण जिस जेल के कैदियों को जिस दिन न्यायालय में पेश करना होता था संबंधित जेल के लंगर गोदाम का दोपहर के भोजन एवं शाम की चाय का कच्चा माल अनुपातिक रूप में कम करना आवश्यक था। लंगर गोदाम एवं 2009-14 में प्रतिवर्ष के मार्च महीने के दैनिक खुराक पत्र के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि जेल सं. 1, 3 एवं जिला जेल रोहिणी में कोर्ट ले जाये गये कैदियों से संबंधित कच्चा माल कम नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की खपत की 6196 किलो सब्जियाँ, 640.08 किलो चायपत्ती, 1068 लीटर दूध एवं 534.08 किलोग्राम चीनी का अधिक आकलन हुआ।

अपने जवाब में महानिदेशक (कारागार) ने स्वीकार किया (मार्च 2015) कि वर्ष 2010 से 2013 के दौरान उन कैदियों के लिए चायपत्ती, दूध, चीनी एवं बिस्कुटों की कटौती नहीं की गई जो न्यायालय में पेश किये गये थे। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2014 के लिए उनके हिस्से के दूध, चीनी एवं चायपत्ती प्राप्त नहीं किये गये थे। हालांकि विभाग अपने इस दावे, कि वर्ष 2014 में राशन की कटौती नहीं की गई थी, के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जब लेखापरीक्षा हेतु मार्च 2015 में जवाबों के सत्यापन के लिए जेल का पुनः दौरा किया गया।

(ii) **वर्ष 2009-14 के प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने के लंगर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि जेल सं. 1, 2 एवं 3 में विक्रेता के बिलों के आधार पर प्राप्त दूध की मात्रा 2-1½ एवं खुराक पत्र के अनुसार उपयोग में लाये दूध की मात्रा में 46331 लीटर का अन्तर था जिसकी कीमत ₹ 9.44 लाख थी।**

महानिदेशक (कारागार) का कथन है कि (मार्च 2015) लेखापरीक्षा में, कठिन परिश्रम करने वाले अपराधियों के लिए प्राप्त दूध की गणना नहीं की गई, जिन्हें 300 मि.ली. दूध दिया जाता है। यह स्वीकार किया गया कि इस संबंध में कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था और यह कि मामला आवश्यक आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था। हालांकि तथ्य यही रहा कि दैनिक खुराक पत्रक में इस अतिरिक्त दूध की मात्रा नहीं दर्शायी गई थी।

### 2-2-4-3 **वर्ष 2009-14 के दौरान दिल्ली कारागार प्राधिकरण ने एगमार्क गेहूँ का आटा (19644.73 किग्रा) एवं दालें (12696.51 किग्रा) विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से संविदा दर पर खरीदे। हालांकि लेखापरीक्षा में देखा गया कि दिल्ली कारागार के मुख्य गोदाम में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे कि आटा व दाल एगमार्क किसिम के थे। जेलों द्वारा प्राप्त दालों की एगमार्क प्रयोगशाला प्रतिवेदनों में प्राप्तकर्ता/पैक करने वालों के नाम नहीं लिखे गये थे। यहाँ तक कि अभिलेखों में प्रयोगशाला प्रतिवेदनों के फार्म भी रिक्त पाये गये। आटे से संबंधित कोई प्रयोगशाला प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उचित अभिलेखों का अभाव में लेखापरीक्षा जेल के अभिलेखों को एगमार्क जारी प्राधिकरण के अभिलेखों के साथ सत्यापित करने में असमर्थ था।**

अपने जवाब में महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि यह कृषि विपणन निदेशालय की ओर से प्रक्रियात्मक दोष था और दिल्ली कारागार का इससे कोई लेनादेना नहीं है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार जेल प्राधिकारियों को सामान की गुणवत्ता सत्यापित करनी थी।

### 2-2-4-4 **तिहाड़ जेल की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति जेल परिसर के अन्दर बने 150 बिस्तर के अस्पताल से होती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जेल में दवाखाने हैं। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पताल आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं था, क्योंकि**

तिहाड़ जेल की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति जेल परिसर के अन्दर बने 150 बिस्तर के अस्पताल से होती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जेल में दवाखाने हैं। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पताल आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं था, क्योंकि

18 से 62 प्रतिशत तक चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की कमी थी। अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एण्डोस्कोपी, ईकोकार्डियोग्राफ, 24 घंटे कार्यरत जीव रसायन, सूक्ष्म प्राणी विज्ञान एवं रोग लक्षण विज्ञान प्रयोगशाला, शल्य चिकित्सक से लैस पूर्ण सुसज्जित आपरेशन कक्ष, जैसी सुविधाओं का अभाव था।

परिणामस्वरूप अस्पताल ओ.पी.डी. तक के लिए कैदियों को बाहरी अस्पताल में भेजने के लिए विवश था। 2009-14 के दौरान 93224 मौकों पर कैदी बाहरी अस्पतालों में भेजे गये, इनमें से 77232 मामले कुल भेजे गए मामलों का 82 प्रतिशत बाह्य रोगी विभाग में चिकित्सा के लिए भेजे गये। इन मामलों में एम्बुलेंस सशस्त्र मार्गरक्षक भी सम्मिलित थे जिसकी वजह से अतिरिक्त खर्च एवं सुरक्षा जोखिम दोनों बढ़े।

आगे रोगियों के चिकित्सा अभिलेखों/प्रतिवेदनों को रखने की उचित प्रणाली नहीं थी। चिकित्सा अभिलेख थैलों में पैक थे जिसके कारण किसी रोगी के आवश्यक अभिलेखों को शीघ्र ढूँढना असम्भव हो जाता है।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि केन्द्रीय कारागार अस्पताल प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है। जवाब लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करता है।

## 2-2-5 दस; कडक ल क्क , oai qok

कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास तथा उन्हें विभिन्न कौशल सिखाने के लिए जिससे वे जेल से रिहाई पर अपनी आजीविका कमा सकें, दिल्ली कारागार बढईगिरी, रासायनिक, कागज, बुनाई, सिलाई, बेकरी स्कूल, प्रसाधन एवं कपड़ा देखभाल उत्पाद, इत्यादि जैसे विभिन्न कारखाना इकाइयाँ जेल परिसर के अन्दर चलाता है।

लेखापरीक्षा ने इन सुधार एवं पुनर्वास की प्रक्रियाओं के प्रबंधन में विभिन्न अनियमितताएँ पायी जिनका विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

### 2-2-5-1 QSDV, कडक izkk u

फैक्ट्री केन्द्रीय कारागार-2 तिहाड़ जेल के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

(i) QSDVh LVKQ dh del% फैक्ट्री स्टाफ की कमी के कारण बढईगिरी, रसायन, सिलाई एवं कागज फैक्ट्री इकाइयाँ कैदियों एवं गैर तकनीकी स्टाफ द्वारा स्वयं किसी मार्ग दर्शन के बिना चलाई जा रही थी।

महानिदेशक (कारावास) का कथन (मार्च 2015) है कि समाप्ति सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यमिक उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों से कैदियों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी स्टाफ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) [krlkdk x\$ fuekZk% जेल-2 में कारखानों के संचालन के लिए न तो अंतिम लेखा (प्राप्ति व भुगतान खाता, आय व व्यय खाता और बैलेंस शीट) और न ही प्रोफार्मा खाते बनाए जा रहे थे, जिसमें प्रारंभिक जमा, शेष जमा, माल की खरीद व बिक्री दर्शाई जाती है। उचित अभिलेखों की गैर मौजूदगी में लेखापरीक्षा कच्चे माल के शेष भंडारण एवं तैयार

व आंशिक तैयार माल के समायोजन का सत्यापन नहीं कर सका।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि आधारभूत अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा था और अपव्यय अधिक मात्रा में है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरिव्यय प्रभार की गणना करने के लिए कारखानों के पास कच्चे माल व अन्य व्यय की यूनिट-वार क्रय के आँकड़े नहीं थे। इसके अलावा उत्तर के सत्यापन के दौरान शेष माल में अंतर में समाधान के समर्थन में कोई भी रिकॉर्ड लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) यक़र fu/क़.क दक़ xyr rjhdk vi ukus ds dkj .k uqll ku% अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मिरंडी लकड़ी के डूअल डेस्क को छोड़कर, सभी वस्तुओं का लागत निर्धारण श्रम लागत को जोड़कर और फिर उत्पादन संबंधी उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय और आकस्मिकता उपरिव्यय प्रभारित करके किया गया था। हालांकि मिरंडी लकड़ी के डूअल डेस्क के मामले में विभाग ने लागत निर्धारण का एक अलग तरीका अपनाया। इस तरीके के तहत डेस्क की कीमत ₹ 54.13 से ₹ 375 तक प्रति डेस्क कम हो गई। वर्ष 2009-14 के दौरान 230048 डूअल डेस्क कम दरों पर सरकारी विभागों को बेचे गए जिसके परिणामस्वरूप जेल को ₹ 5.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में (मार्च 2015) कहा कि डूअल डेस्क का ऑर्डर शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से एक थोक क्रयादेश था। कारागार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त लागत को तय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लागत निर्धारण न लाभ न हानि के आधार पर किया गया और उपरिव्ययों में शामिल कारकों को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

(iv) vki R dk xj&l R ki u% दिल्ली जेल नियमावली के पैरा 91 में यह अधिदेश है कि प्रत्येक वस्तु जो जेल के अन्दर या बाहर से हो कर गुज़रती है और सभी सामान, उपकरण, दुकानों या अन्य वस्तुओं का पर्याप्त विवरण जैसे नाम, संख्या या वजन आदि और यथावश्यक ऐसे अन्य ब्यौरे यथास्थिति दर्ज किये जाने चाहिए।

कारखानों और मुख्य स्टोर के लिए आपूर्तियों के चालानों की जाँच में पता चला कि सामग्री की मात्रा, ट्रक नम्बर या जेल कारखाने में माल पहुँचाने में परिवहन के साधन का चालानों में उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा में इस विवरण का रजिस्टर-16ए में से जाँच नहीं की जा सकी जिसका रखरखाव जेल के द्वार पर जेल अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि सभी चालानों में ट्रक नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी रखना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(v) ₹ 3-78 djkm+dk ifjgk ZQ ; % जेल विभाग ने दूसरे विनिर्देशों<sup>17</sup> की मिरंडी लकड़ी सहित विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए द्वि-बोली प्रणाली में ई-निविदाओं (नवम्बर 2010) को आमंत्रण दिया था। कारागार विभाग ने इन मदों की आपूर्ति करने के लिए सबसे कम

<sup>17</sup>(i) मिरंडी लकड़ी की आपूर्ति (सूखी सिल्ली) – 10000 घन फुट (6' या 3'x11''x9'') (ii) मिरंडी लकड़ी के 1,00,000 पट्टे (3'x 11''x 1''), और (iii) 550 किलो प्रति घन फुट के घनत्व के साथ मिरंडी लकड़ी के 3,00,000 पट्टे (3'x 9''x 1'')।

बोली लगाने वाले बोलीकर्ता मैसर्स जगदम्बा सेल्स को यह आर्डर सौंपा। हालांकि, फर्म ने लकड़ी के लिए प्रतिभूति जमा व समझौता पेश करने से इस दलील पर मना कर दिया कि निविदा में उसने 3 फुट की लंबाई या बराबर गुणकों में सिल्ली/तख्ते आपूर्ति करने के लिए उद्धृत किया था जबकि निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) एवं उसके बाद स्वीकृति पत्र में तीन/ छः फीट लम्बाई की सिल्ली एवं तीन फीट लम्बे तख्ते उद्धृत थे। नतीजतन सम्पूर्ण निविदा निरस्त की गई एवं जेल विभाग ने कम्पनी द्वारा जमा की गई ₹ 35.85 लाख की ईएमडी को जब्त कर लिया।

जिन वस्तुओं के लिए पिछली निविदा सूचना में मैसर्स जगदम्बा सेल्स निम्नतम बोलीकर्ता था, उनके लिए जुलाई 2011 में निविदाओं को लकड़ी सहित पुनरामंत्रण किया गया। नई निविदा आमंत्रण सूचना में विभाग ने आवश्यक विनिर्देशों को छः/नौ फीट लम्बाई की सिल्ली और तीन फिट लम्बे तख्ते या उसके गुणांक जो पहली बोली में मैसर्स जगदम्बा सेल्स द्वारा प्रस्तुत किये गये, के जैसे थे। नई निविदा में मैसर्स डाइनेस्टी मिरंडी लकड़ी आपूर्ति के लिए सबसे निम्न बोलीकर्ता था, जिसे आर्डर प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि पुनर्निविदा के बाद मैसर्स डाइनेस्टी से प्राप्त लकड़ी की कुल कीमत विभाग द्वारा मैसर्स जगदम्बा की बोली स्वीकार करने पर जो कीमत होती, उससे 67 प्रतिशत ऊपर थी। इस तरह विनिर्देशों में बदलाव करके मैसर्स जगदम्बा की बोली को निरस्त करने एवं उन्हीं विनिर्देशों की लकड़ी मैसर्स डाइनेस्टी से पुनः निविदा निकालने के बाद प्राप्त करने के कारण राजस्व पर ₹ 3.66<sup>18</sup> करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अन्तर, मैसर्स जगदम्बा द्वारा प्रस्तुत कीमत एवं वह कीमत जिस पर सामान खरीदा गया, के बीच का अन्तर था। आगे जाँच में पाया गया कि मैसर्स जगदम्बा सेल्स के ईएमडी की जब्ती का मामला मध्यस्थ को सौंपा गया था जिन्होंने निर्णय कम्पनी के पक्ष में लिया। जेल विभाग द्वारा ₹ 12.19 लाख के ब्याज के साथ ₹ 35.85 लाख की ईएमडी को लौटाना पड़ा। जिस कारण विभाग को लकड़ी जुटाने में ₹ 3.78 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा। महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा लगाया गया नुकसान का अनुमान सही नहीं था क्योंकि प्रचलित बाजार दरों के आधार पर निविदा प्रदान की गई थी और पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और बोली लगाने की निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालांकि जवाब समान विनिर्देशों एवं ऊँची कीमतों पर लकड़ी उपलब्ध कराने की पुष्टि नहीं करता है।

### 2-2-5-2 i hfMx dY; k k fuf/k

दिल्ली कारागार (कैदी स्थानांतरण, मजदूर एवं जेल उद्योग, खाद्य, स्वच्छता एवं वस्तु) नियमावली 1998 के नियम 39-ए के अनुसार प्रत्येक जेल को एक "पीड़ित कल्याण निधि" (पी.क.नि.) का निर्माण करना है जिसमें कैदियों द्वारा अर्जित पगार की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होती है जिससे अपराध से पीड़ित या उनके वैध उत्तराधिकारियों (मृत्यु की स्थिति में) को मुआवजे का भुगतान किया जा सके। हालांकि दस में से दो जेलों (जेल

<sup>18</sup>(10000 × 1050 - 10000 × 595) = ₹ 45.50 लाख, (22916 × 1025 - 1,00,000 × 138) = ₹ 96.89 लाख और (56250 × 1010 - 3,00,000 × 115) = ₹ 2.23 करोड़। कुल = ₹ 3.66 करोड़

संख्या 8 एवं 9) ने पी.क.नि. का रखरखाव नहीं किया गया। पीड़ित कल्याण समिति द्वारा मुआवजे की माँग पर विचार एवं अनुमोदन किया जाता है। पीड़ित कल्याण समिति की आठ बैठकों में केवल 172 दावों पर विचार हुआ एवं 137 दावे मुख्यतः जेल सं. 2 से संबंधित, जुलाई 2010 से जून 2013 तक की अवधि के लिए समिति द्वारा अनुमोदित किये गये।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है और कहा (मार्च 2015) है कि कारागार प्राधिकारियों ने वांछनीय पीड़ितों की पहचान के मामले को पुलिस विभाग एवं कल्याण अधिकारियों/गैर सरकारी संस्था की भागीदारी माध्यम से तथा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उठाया है।

### 2-2-5-3 कैदी कल्याण कोष का उद्देश्य

कैदी कल्याण कोष का उद्देश्य जेल में कैदियों को उनके कारावास के दौरान विभिन्न प्रकार की सामूहिक कल्याण गतिविधियों जैसे शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय आदि के लिए सहायता प्रदान करना एवं योग्य कैदियों को उनकी रिहाई के बाद या तो अनुदान के रूप में नकद या व्यापार के लिए उपकरण या कपड़ों के रूप में सहायता प्रदान करना है। इस कोष के लिए निधि कैदियों, सार्वजनिक दान या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से स्वैच्छिक दान से संचित की जानी थी।

(i) कैदी कल्याण कोष का उद्देश्य जेल में कैदियों को उनके कारावास के दौरान विभिन्न प्रकार की सामूहिक कल्याण गतिविधियों जैसे शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय आदि के लिए सहायता प्रदान करना एवं योग्य कैदियों को उनकी रिहाई के बाद या तो अनुदान के रूप में नकद या व्यापार के लिए उपकरण या कपड़ों के रूप में सहायता प्रदान करना है। इस कोष के लिए निधि कैदियों, सार्वजनिक दान या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से स्वैच्छिक दान से संचित की जानी थी।

कैदी कल्याण कोष अधीक्षक की अध्यक्षता में जेल कर्मचारियों और कैदियों को मिलाकर बनी कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। जहाँ समिति को प्रत्येक माह में एक बार मिलना था वहाँ वर्ष 2009-14 के दौरान यह देखा गया कि समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी और मामलों पर निर्णय अधीक्षक/महानिदेशक (कारागार) के स्तर पर लिया गया था।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2015) कि विभाग द्वारा कैदी कल्याण कोष से कैदीन के कार्यकलापों को अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। प्रत्येक जेल (कारागार) द्वारा कैदी कल्याण कोष की कार्यकारी समिति की समयोचित बैठकों का आयोजन करने के लिए निर्देशों को जारी किया गया।

(ii) दिल्ली कारागार (कैदी कल्याण कोष, अपील, याचिका, साक्षात्कार और संप्रेषण) नियम, 1988 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि कैदी कल्याण कोष के खातों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा जाँच की जाएगी। हालांकि यह पाया गया कि जेल 1, 2, 3, तथा जिला जेल रोहिणी में कैदी कल्याण कोष के अंतिम लेखे केवल 2012-13 तक और जेल 6 में 2010-11 तक संकलित किए गए थे। केन्द्रीय जेल-2 के लेखों को छोड़ कर जिनकी जाँच वर्ष 2012-13 तक की जा चुकी है, आंतरिक लेखापरीक्षक निदेशालय



द्वारा लेखों की जाँच वर्ष 2009-14 की अवधि में नहीं की गई है।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि सभी जेलों के कैदी कल्याण कोष की लेखापरीक्षा के मामले पर लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ चर्चा की जाएगी। हालांकि उत्तर में सभी जेलों द्वारा पीडब्ल्यूएफ के खातों के रखरखाव में बकाया राशि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(iii) अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि ऐसे खर्च जो कोष के उद्देश्यों के अनुसार नहीं थे, कैदी कल्याण कोष में दर्ज किए गए, जैसे गैर सरकारी संगठनों का परिवहन व्यय, मरम्मत व रखरखाव, अन्य जेलों/ कर्मचारियों/ पीडब्ल्यूडी या जिला सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों का अग्रिम, डाटा एंट्री ऑपरेटरों/ पैरा-मेडिकल स्टाफ को वेतन, योग, कंप्यूटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, कार्यालय खर्च आदि कुछ उदाहरण हैं :

- सितम्बर 2013 में जेल मुख्यालय के गेट नं 1 पर फव्वारे के निर्माण कार्य के लिए ₹ 3 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था।
- जेल मंत्रालय के विभिन्न स्नानागारों की मरम्मत और रसोईघर के काम के लिए ₹ 22.17 लाख का भुगतान किया गया था, और
- ₹ 14.42 लाख की एक टाटा स्टार बस खरीदी गई थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि जेल अधीक्षकों को निर्धारित उद्देश्यों के लिए सख्ती से निधि का उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे।

(iv) जेलों में दो प्रकार की कैदीनों का संचालन हो रहा है- तरल और शुष्क। लेखापरीक्षा जाँच में यह देखा गया कि इन कैदीनों के संचालन के संबंध में दिल्ली जेल नियमावली में न ही कोई प्रावधान था और न ही इन्हें संचालित करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के गृह/वित्त विभाग से कोई स्वीकृति ली गई थी। दिल्ली वैट अधिनियम (चतुर्थ अध्याय) की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि विक्रेता की कर योग्य राशि ₹ 10 लाख होगी (28 मार्च 2013 से संशोधित राशि ₹ 20 लाख)। तिहाड़ जेल परिसर और रोहिणी जेल में संचालित प्रत्येक कैदीन का वार्षिक कारोबार ₹ 20 लाख से अधिक पाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी अधिनियम के तहत व्यापार व कर विभाग से पंजीकृत नहीं था।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि विभाग के पास इस संबंध में सरकार के अनुमोदन से संबंधित विवरण देने के लिए दस्तावेज़/फाईल नहीं थे। लेकिन, व्यापार एवं कर विभाग से पंजीकरण का मामला विचाराधीन था।

#### 2-2-5-4 कैदी कल्याण कोष में जमा राशि का संचालन

विभाग द्वारा केन्द्रीय जेल तिहाड़ के सीपीआरओ गेट संख्या 3 व 4 और दिल्ली जेल रोहिणी के सीपीआरओ गेट पर कैदीनों के रिश्तेदारों और मुलाकातियों के मोबाइल फोन व अन्य वस्तुओं को ₹ पाँच प्रति आइटम की दर से जमा करने के लिए पैसे एकत्र किए जा रहे थे और एकत्र की गई राशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा की गई। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जेल रोहिणी में मार्च 2007 से ₹ 23.21 लाख और तिहाड़

जेल में जुलाई 2009 से ₹ 32.19 लाख एकत्र किए गए थे। न तो कर्मचारी कल्याण कोष के रखरखाव के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन मिला था और न ही मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को जमा करने के लिए पैसे चार्ज करने और उसे कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करने के लिए कोई भी कार्यकारी आदेश था।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि सीपीआरओ 1, सीपीआरओ 4 एवं डीजेआर में मुलाकातियों से शुल्क की वसूली की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

### 2-2-5-5 u' k&efä dH

विभाग ने मादक द्रव्यों के उपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए यूएनओडीसी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से जेल-3 में 120 बिस्तरों के ओपिओड प्रतिस्थापन उपचार का उद्घाटन किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाई गई कमियाँ निम्न प्रकार हैं :

(i) व्यक्ति वृत्त, मरीजों को उपलब्ध कराई गई काउंसलिंग का विवरण, पूरे उपचार कार्यक्रम में रोगी की भागीदारी और सुधार के संबंध में जानकारी, प्रतिक्रिया एवं सेवामुक्ति परामर्श प्रपत्र रिकॉर्ड में पाए नहीं गए। दूसरे नशा-मुक्ति केन्द्र में मरीजों को दवाओं के वितरण और हर दवा का हिसाब रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(ii) आवश्यक दवाएँ एक महीने से लेकर 34 महीनों की अवधि तक के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

जवाब में महानिदेशक (कारागार) का कथन है कि (मार्च 2015) दस्तावेज एवं पंजीकरण जेल अस्पताल नीति के अनुसार रखे जाते हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जवाबों के सत्यापन के दौरान जेल अस्पताल नीति की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा में प्रदान नहीं की गई थी। आगे लेखापरीक्षा में उठाये गये मामलों पर कोई जवाब नहीं था।

### 2-2-6 ; kt ukvkvk ifj; kt ukvkd dk kZ; u

#### 2-2-6-1 l hl h/hoh i z kkyh dh LFki uk eanjh vkj fu; æ. k ea deh

सुरक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर कैदियों, मुलाकातियों और जेल कर्मचारियों की गतिविधियों पर चौबीस घण्टे नज़र रखने के लिए फरवरी 2007 में जेल विभाग द्वारा सीसीटीवी प्रणाली के प्रतिष्ठापन की पहल की गई थी। ₹ 2.63 करोड़ की लागत में केन्द्रीय जेल तिहाड़ तथा जिला जेल रोहिणी में 258 कैमरों के साथ सीसीटीवी प्रणाली के प्रतिष्ठापन का पहला चरण मई 2008 में पूरा किया गया। द्वितीय चरण जो कि 233 कैमरों के लिए सितम्बर 2009 में शुरू किया गया था तथा जिसकी निविदा लागत ₹ 2.81 करोड़ थी मार्च 2015 तक प्रगति पर था। निम्नलिखित प्रेक्षित किया गया :

(i) जेल विभाग ने 20 मदों पर चार प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से वैट/ बिक्री कर के कारण पहले चरण के विक्रेता को ₹ 9.26 लाख का अतिरिक्त भुगतान (मार्च 2008) किया।

(ii) पहला चरण 212 दिनों की देरी के साथ (मई 2008) पूरा हुआ था और द्वितीय चरण

8 जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था लेकिन यह (मार्च 2015) प्रगति में था। विभाग ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार देरी के लिए ₹ 24.23 लाख<sup>19</sup> की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए कोई पहल नहीं की थी।

(iii) द्वितीय चरण के लिए निविदा आमंत्रित करते समय विभाग ने प्रमुख सचिव, गृह द्वारा की गई स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद काम के दायरे में नई सीसीटीवी प्रणाली के उचित व सहज एकीकरण के प्रावधानों को शामिल नहीं किया था।

(iv) दिए गए प्रशिक्षण के कार्यक्रम से संबंधित और सीसीटीवी प्रणाली संचालित करने के लिए प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों की संख्या का कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जेल मुख्यालय और जेलों के सभी 12 सीसीटीवी मुख्य और उप-नियंत्रण कक्ष ज्यादातर खाली रहते थे और समर्पित कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे निगरानी भी नहीं की जा रही थी। इस प्रकार परियोजना के पूरा होने में देरी और जेल प्रशासन की ओर से निगरानी की कमी के कारण कैदियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित अभिरक्षा से समझौता करना पड़ा।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि फेज-I के प्रतिष्ठापन में देरी के लिए परिनिर्धारित हर्जाना वसूल किया जा चुका था और फेज-II में देरी के लिए परिनिर्धारित हर्जाना वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया था। सीएसटी मामले पर व्यापार और कर विभाग से चर्चा की जा रही थी। यह भी कहा गया कि स्टाफ की कमी के कारण उप-नियंत्रण कक्षों को चौबीस घंटे नहीं चलाया जा रहा था, हालांकि मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष टीएसपी के अधिकारियों की सहायता से चलाया जाता है।

### 2-2-6-2 **ekky by Qku t 5j dk vl rkk ud fu"i knu**

फोन जैमर प्रतिबंधित मद हैं तथा केवल मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। 2008-14 के दौरान मैसर्स बीईएल ने ₹ 5.81 करोड़ में दिल्ली कारागार के 10 जेलों में 32 फोन जैमर स्थापित किए। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि प्रत्येक जेल में आवश्यक जैमर की संख्या सुनिश्चित करने तथा क्या वह उपकरण आवश्यकता को पूरा करेगा, इससे संबंधित कोई व्यवहार्यता अध्ययन या क्षेत्र परीक्षण नहीं किया गया। मई 2014 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को रिपोर्टिंग करते समय विभाग ने स्पष्ट किया कि जैमरों का प्रदर्शन असंतोषजनक था क्योंकि जहाँ जैमर स्थापित किए गए थे, उसके आसपास के क्षेत्र में भी मोबाइल फोन काम कर रहे थे। इस प्रकार ₹ 5.81 करोड़ के निवेश के बावजूद, सुरक्षा पर समझौता होने के अलावा, जेल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि कारागार विभाग द्वारा सबसे अच्छी उपलब्ध तकनीक का चयन किया गया था हालांकि जैमरों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था और मामला अक्टूबर 2013 में मैसर्स बी.ई.एल. के साथ उठाया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा

<sup>19</sup> ₹12.45 लाख (संविदा की कुल कीमत का 5% अर्थात् ₹ 24900111) + ₹ 11.78 लाख (₹ 23562747 का 5%)

टिप्पणी की पुष्टि करता है परन्तु इसमें मैसर्स बी.ई.एल. द्वारा किए गए प्रणाली की समीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा गया था।

### 2-2-6-3 olfM; ks dkWY qI x izkkyh dk de mi ; ks

जनवरी 2001 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित कारणों से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के प्रावधानों में संशोधन के द्वारा कैदियों को न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के माध्यम से पेश करने की पहल की- (अ) जिला सशस्त्र पुलिस (डीएपी) कर्मियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए तथा इसके प्रभाव से ₹ 4.50 करोड़ की वार्षिक बचत करने के लिए, जहाँ इन कर्मियों को (कुल 1200 से 1400 में से) 350 से 400 कैदियों की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत रिमांड के विस्तार के लिए न्यायालय तक लाने व न्यायालय से ले जाने में अनुरक्षण में दैनिक रूप से लगे रहना पड़ता था। (ब) कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए।

वर्ष 2009-14 के दौरान जेल 1, 2, 4, 5, 6 व डीजीआर के अभिलेखों की जाँच से यह पता चला है कि कुल पेशी में से वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली द्वारा कैदियों की पेशी 7 से 10 प्रतिशत के बीच रही जो कि अपेक्षित 30 प्रतिशत से काफी नीचे रही।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि जेल प्राधिकारी किसी भी कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से केवल न्यायालयों के आदेश पर ही, न कि अपने दम पर, न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ न्यायालय के आदेश के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैदियों को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका।

### 2-2-6-4 LekVZdkMZizkkyh

कैदीन में व्यापार की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत और कारगर बनाने के लिए मार्च 2012 में स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू की गई। प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए व्यय कैदी कल्याण कोष से किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने कोडल औपचारिकताओं का पालन किए बिना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह/आईटी/वित्त विभागों के पूर्व अनुमोदन के बिना नामांकन के आधार पर मैसर्स वन कार्ड सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का 'स्मार्ट ई-पर्स कार्ड फ्रेमवर्क सिस्टम' के कार्यान्वयन के लिए चयन कर लिया। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रणाली में प्रत्येक कैदी के लिए कार्डों को लेन-देन पासवर्ड से सुरक्षित किया जाना था, लेकिन यह सुविधा स्मार्ट कार्डों में उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन एक खोया या मिसप्लेस्ड कार्ड किसी अन्य कैदी द्वारा आसानी से किसी भी प्रतिबंध के बिना इस्तेमाल किया जा सकता था।

महानिदेशक (कारागार) ने समाप्ति सम्मेलन में कहा कि कैदियों द्वारा हैंड हेल्ड डिवाइस के दुरुपयोग से बचने के लिए स्मार्ट कार्डों में ट्रांजैक्शन पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पासवर्ड की अनुपस्थिति में खोए हुए कार्डों के दुरुपयोग की संभावना होती है।

## 2-2-7 fofo/k

### 2-2-7-1 frgkM+ty iflj dh ejEer vj\$ j[kj[ko

लो.नि.वि. के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी डिवीजन तिहाड़ जेल परिसर के निर्माण व मरम्मत के कार्य पर ध्यान देते हैं। जेल विभाग ने कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी दी, परन्तु उचित निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रेक्षण किये :

- **dk; k ds fu"i knu ea njl%** विद्युत डिविजन एम-151/एम-353 और सिविल डिविजन के एम-132/ एम-332 के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पता चला कि के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली की धारा 29.1, जिसमें निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न करने का प्रावधान है, का पालन नहीं किया गया था क्योंकि निर्माण एवं रखरखाव के कार्यों में छः से 22 महीनों की देरी हुई।
- **dk; k dsfy, , , MbZl l svf/kd Hqrku%** विद्युत एवं सिविल डिविजनों के अभिलेखों की निरीक्षण जाँच में यह पाया गया कि 24 मामलों में के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जेल विभाग से प्राप्त एए एंड ईएस की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक में ठेकेदारों को भुगतान किया गया।
- **yk d fueZk foHkx l si Hr l kexh dk x\$ yj k&t k k%** जेल अधिकारियों द्वारा पीडब्ल्यूडी से जेल परिसर की मामूली मरम्मत करने और रखरखाव के लिए सामग्री स्वयं प्राप्त की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान जेलों में सिविल डिविजन एम-132 द्वारा ₹ 3.36 करोड़ की विभिन्न सामग्री जैसे सीमेंट, ईट, रेत, सिंथेटिक एनामेल पेंट आदि की आपूर्ति की गई। हालांकि सामग्री की प्राप्ति या खपत दोनों में से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जिससे उनका अन्त उपयोग सत्यापित नहीं किया जा सका।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि उचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया जा रहा था। हालांकि सत्यापन होने पर यह देखा गया कि रिकॉर्ड पूरे नहीं थे जैसा कि कारागार द्वारा दावा किया गया था।

### 2-2-7-2 ekuo l á k/ku izáku

31 जनवरी 2014 को विभाग में दी गई पदासीन कर्मचारी एवं संस्वीकृत संख्या नीचे rkfydk 2-2-2 में निम्न प्रकार है :

रक्यदक 2-2-2 %ल लोह-र ल ढ; क , oainkl hu deऒkjh

deऒkjh izlkj	l लोह-र ल ढ; क	inlk hu deऒkjh	fjfa; k	fjfa; k i fr'kr
संवर्ग कर्मचारी	1357	982	375	27.63
चिकित्सक	110	64	46	41.82
पराचिकित्सक	108	88	20	18.52
श्रेणी IV (चिकित्सा)	81	31	50	61.73
तकनीकी कर्मचारी	10	0	10	100.00
वायरलैस कर्मचारी	05	0	05	100.00
सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी	03	03	0	0.00
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	154	109	45	29.22
फैक्ट्री कर्मचारी	08	03	05	62.50
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	116	72	44	37.93

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि कल्याण अधिकारी, सहायक संवीक्षक, जेल अधीक्षक एवं अधीक्षिका के संवर्गों में रिक्तियां 31 से 44 प्रतिशत थी। डाक्टरों, पराचिकित्सा, मंत्रालयी, फैक्ट्री एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में रिक्तियाँ 18 से 63 प्रतिशत थीं। अध्यापक एवं वायरलैस कर्मचारी संवर्ग के सभी पद रिक्त थे।

महानिदेशक (कारागार) ने (मार्च 2015) विभिन्न संवर्गों में रिक्ति की स्थिति स्वीकार की और डीएसएसएसबी द्वारा सीधी भर्ती के पदों के नहीं भरे जाने को तथा पात्र अधिकारियों की गैर उपलब्धता/संबंधित विभागों द्वारा उनकी गैर नियुक्ति को जिम्मेदार ठहराया।

**2-2-7-3 oSkfud vl\$ vlarfjd ys lki jhkk**

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली धोखाधड़ी, दुरुपयोग और कुप्रबंधन के खिलाफ कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों, सुरक्षा उपायों का पालन करने का उचित आश्वासन प्रदान करती है और उच्च आधिकारियों के लिए विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंध सूचना प्रदान करती है।

दिल्ली कारागार के संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा की गई सांविधिक लेखापरीक्षा जाँच के 26 पैरों सहित छः निरीक्षण रिपोर्ट 31 मार्च 2014 तक अप्राप्त थी। इससे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र और समय पर अनुपालन के लिए एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत मिला। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय ने वर्ष 2010-14 के दौरान विभाग की कोई भी लेखापरीक्षा जाँच आयोजित नहीं की थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि शेष पैरा के निपटान हेतु लेखापरीक्षा के साथ मुद्दे को यथासमय उठाया जाएगा। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में यह कहा गया कि मामला आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ उठाया गया था।

## 2-2-8 fu"d"K

जेलों में भीड़-भाड़ थी जिसके मुख्य कारण अतिरिक्त जेल भवनों/ बैरकों का गैर निर्माण, निर्माण में देरी थी। विभाग सभी संवर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा था। कारखानों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण जेल प्रशासन की कैदियों के भविष्य में पुर्नस्थापन के लिए उनमें आवश्यक प्रभावशाली दक्षता विकसित करने की क्षमता के साथ समझौता हुआ। सुरक्षा पर विशाल खर्च होने के बावजूद छः जेलों की नमूना जाँच में कैदियों के पास प्रतिबंधित वस्तुएँ रखने के मामले पाये गये। निगरानी कर्मचारियों की तैनाती एवं कैदियों के बीच असंगत अनुपात एक सुरक्षा जोखिम था। जेल अस्पताल में पर्याप्त कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी थी एवं बाह्य अस्पतालों को भेजे गये अधिकांश मामले ओ.पी.डी. चिकित्सा के थे। कारखाना ईकाईयाँ एवं कल्याण कोष वर्तमान प्रावधानों की पुष्टि के बिना चलाये जा रहे थे।

## 2-2-9 fl Qkf' k

जेल विभाग में निम्न पर विचार हो सकता है :

- (i) नई जेलों के निर्माण के लिए लंबित प्रस्तावों के शीघ्र प्रसंस्करण तथा निर्माणाधीन कार्य के लिए लो.नि.वि. और दि.वि.प्रा. के साथ घनिष्ठ तालमेल में तेजी लानी चाहिए,
- (ii) कैदियों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर दिल्ली कारागार की संस्वीकृत संख्या का पुनरावलोकन होना चाहिए,
- (iii) फ़ैक्ट्री इकाई एवं कल्याण कोष से संबंधित अभिलेखों/खातों का उचित रख-रखाव, एवं
- (iv) जेल अस्पताल की अवसंरचना एवं सुविधाओं में सुधार होना चाहिए एवं पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी तथा चिकित्सक तैनात होने चाहिए।

मामला दिसम्बर 2014 में सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2015)।

1 ek t dY; k k foHkx

2-3 v'kä Q fä; k ds dY; k k grq; kt uk ;

समाज कल्याण विभाग अशक्तता अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय है और यह अशक्त व्यक्तियों (अ.व्य.) के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

fof' k'Vrk ;

- foHkx us fnYyh ea fuokl djus okys v'kä Q fä; k dk foLrè Mvkcd j[kus dsfy, ?kj&?kj t kdj dkbZLora l oZk k ughafd; H cfYd t ux. kuk vk dMoi j fuHj jgkA bl usv'kä Q fä; k ds seylek dk l ek ku djus grqjkt; v'kärk ulfr dks fodfl r ughafd; k  
¼\$ kxkQ 2-3-2-1 rFlk 2-3-2-2½
- foHkx ds ikl foYhr yHk dsfy, mudh l rr ik=rk dks l fuf' Pkr djus grqy HkEk k ds l R; ki u dsfy, dkbZulfr ugha FkA  
¼\$ kxkQ 2-3-4-1½
- vk kk fdj. k dk Mydl | t k fd ekuf l d : i l sfodyk Q fä; k ds fy, g\$ vi uh 350 dh {lerk dsfo: ) 970 fuokl ; k l svf/Hkjr g\$ t cfd bl ds ikl 502 dh vko'; drk dsfo: ) doy 215 n\$ k Hky djus okyk LVkQ g\$  
¼\$ kxkQ 2-3-5 (i) , oa(iii)½
- jkt; l elb; l febr , oajkt; dk Zlkjh l febr fofu/Hkjr cBdk dk vk kt u fu; fer : i l sugladj jgs FkA jkl -l - usuoEcj 2004 ea vi uh LFki uk ds ckn l sfou/Hkjr 20 cBdk ea l sdoy plj cBdk dk vk kt u fd; k v\$ jkdkl - us vf/ku; e ds vlrxZ fofu/Hkjr 40 cBdk ea l sdoy , d cBd dk vk kt u fd; k  
¼\$ kxkQ 2-3-7-1½
- foHkx fnYyh ea 52330 v'kä cpl dsfy, 1250 dh {lerk okys doy N%Ldy k dks pykrk g\$ ; g\$ rd fd ; sLdy Hh 50 प्रतिशत l svfeld 'k\$kd LVkQ dh deh dk l leuk dj jgs FkA  
¼\$ kxkQ 2-3-7-3½
- l jdkjh Houka, oal kZ fud LFkula ev'kä Q fä; k dsfy, l foèkkv dh deh FkA  
¼\$ kxkQ 2-3-7-6½

2-3-1 iLrkouk

संसद ने अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अधिनियम) को अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभाव में



आया। बाद में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिसम्बर 2001 में दिल्ली अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) नियम, 2001 को अधिसूचित किया। समाज कल्याण विभाग (विभाग) अशक्त व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

### 2-3-1-1 लक्षित क्षेत्र

विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव है, जो एक निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, नौ उपनिदेशकों एवं 10 जिला अधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। मंत्री (समाज कल्याण) की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति अशक्त व्यक्तियों के नीतिगत मामलों की देखभाल करती है और राज्य कार्यकारी समिति समन्वय समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करती है। एक स्वतंत्र आयुक्त (अशक्तता) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के वंचित से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के अलावा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./अल्पसंख्यक/विकलांग वित्त एवं विकास निगम (निगम) अशक्त व्यक्तियों के लिए आर्थिक विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहन देने के लिए अर्थप्रबन्ध करता है।

### 2-3-1-2 यशस्वी पहलें ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- नीति निर्धारण और अशक्त व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए उचित योजना प्रणाली अस्तित्व में थी।
- वित्तीय प्रबंधन दक्ष था।
- योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावी था, तथा
- अधिनियम के प्रावधानों को यथोचित लागू किया जा रहा था।

### 2-3-1-3 यशस्वी पहलें , आर्थिक , सामाजिक

विभाग के मुख्यालय, कार्यालय आयुक्त (अशक्तता), जिला कार्यालयों एवं विभाग के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के अभिलेखों की जाँच करते हुए 2009-14 की अवधि को सम्मिलित करने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2014 के दौरान आयोजित हुई। निगम के द्वारा अशक्त व्यक्तियों को बढ़ायी गई वित्तीय सहायता से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की गई। प्रवेश सम्मेलनों का आयोजन प्रधान सचिव, आयुक्त एवं निगम के प्रबंधक (वित्त) के साथ किया गया था (26 मई 2014, 2 जून 2014 एवं 13 जून 2014)। इस पर उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा का मसौदा प्रतिवेदन सरकार को 9 अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था। एक निर्गम सम्मेलन का आयोजन भी 5 मार्च 2015 को किया गया था, जिसमें निदेशक (समाज कल्याण) से मसौदा प्रतिवेदन पर सरकार से विचार भेजने का अनुरोध किया गया, हालाँकि, उनके जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2015)। उक्त विषय पर समीक्षा मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया (पूर्व प्रतिवेदन)।

### 2-3-1-4 ys kki jhkk eki n. M

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णसहभागिता) अधिनियम, 1995,
- दिल्ली अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) नियम, 2001,
- विभाग की वार्षिक योजना एवं आयुक्त (अशक्तता) की वार्षिक रिपोर्ट, और
- सामान्य वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई नीतियों, निर्देश, आदेश एवं दिशा-निर्देश।

### ys kki jhkk fu"d"K

#### 2-3-2 ; kt uk

##### 2-3-2-1 v'kä Q fä; kdk l ožk k u fd; k t luk

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या 167.53 लाख थी, जिसमें से 2.35 लाख व्यक्ति (1.40 प्रतिशत) एक अथवा अन्य प्रकार की अशक्तता से पीड़ित थे।

अशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों की 11 वीं, एवं 12 वीं राष्ट्रीय बैठक (जुलाई 2012 एवं अगस्त 2013) में विशिष्ट लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के यथार्थ लक्ष्यों के लिए विस्तृत डेटाबेस को सुनिश्चित करने हेतु समस्त राज्यों में प्रत्येक पाँच वर्ष में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने की सिफारिश की गई। अशक्तता प्रमाण-पत्रों के निर्गमन के संबंध में राज्यों का निष्पादन जनगणना आँकड़ों पर न होकर घर-घर जाकर सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए था। हालाँकि, विभाग ने कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं करवाया और अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु नीतियों एवं योजनाओं को बनाने के लिए जनगणना के आँकड़ों पर पूर्णतया निर्भर रहा जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में केवल एक ही बार हो सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि मापदण्ड जिस पर जनगणना आँकड़ा संग्रह किया गया, की जाँच की जायेगी एवं उसके बाद पुनरावृत्ति से बचने के लिए घर-घर जाकर सर्वे भी किया जाएगा।

##### 2-3-2-2 jkT; v'kärk ulfr

अधिनियम की धारा 18(2)(ख) में यह अनुबंध है कि राज्य समन्वय समिति को अशक्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निवारण करने हेतु एक राज्य नीति विकसित करनी चाहिए। हालाँकि, विभाग ने सितम्बर 2014 तक नीति को अंतिम रूप नहीं दिया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि आयुक्त (अशक्तता) के द्वारा अग्रेषित मसौदा नीति की जाँच चल रही है एवं जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

##### 2-3-2-3 v'kä Q fä; kdsfy, cek ; kt uk

अधिनियम की धारा 67 में यह उपबंध है कि सरकार को अपने अशक्त कर्मचारियों के लाभ

के लिए बीमा योजना बनानी चाहिए। हालाँकि, सरकार ने इस संबंध में न तो कोई नीति बनाई थी और न ही उनके पास कोई योजना थी।

अपने उत्तर में, विभाग ने बीमा योजना को राज्य अशक्तता नीति में शामिल करने हेतु आश्वस्त किया (मार्च 2015)। तथ्य यह है कि पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद, इस मामले का समाधान नहीं हुआ।

### 2-3-3 foYkt izaku

2009-14 के दौरान अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए वर्षवार बजट प्रावधान तथा विभाग द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार दिया गया है-

rkfydk 2-3-1 %v'kä Q fä; kds dY; k k dsfy,  
ct V vlcÄu vls okLrfod Q ;

₹ djM-e½

o"K	; kt uk				xS&; kt uk			
	ct V vuøku	l äM/kr vkoÄu	Q ;	cpr@ vfrfjä	ct V vuøku	l äM/kr vlcÄu	Q ;	cpr@ vfrfjä
2009-10	5.50	9.48	9.10	0.38	14.01	13.05	11.73	1.32
2010-11	28.65	28.25	18.92	9.33	19.36	16.00	15.06	0.94
2011-12	30.45	34.67	28.38	6.29	15.90	17.06	15.32	1.75
2012-13	65.58	73.19	72.15	1.04	19.22	21.87	20.89	0.98
2013-14	95.20	98.36	91.58	6.78	25.94	25.61	21.66	3.95
dy	225.38	243.95	220.13	23.82	94.43	93.59	84.66	8.93

स्रोत:- समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

2009-14 की अवधि के लिए योजना में 9.76 प्रतिशत की बचत थी और गैर-योजना में 9.54 प्रतिशत की। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2012-13 से बजट आबंटन में भारी वृद्धि हुई थी। वृद्धि के मुख्य कारण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, थे- (i) पाँच हाफ-वे होम का निर्माण (ii) वित्तीय सहायता में ₹ 1000 से ₹ 1500 तक प्रतिमाह की वृद्धि, और (iii) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि।

### 2-3-3-1 dk Zdk xS&dk kZb; u&f' kkk l gk d l lexh ds: i esfuekZk %ckyk½

विभाग ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अपने छः स्कूलों में बाला योजना के कार्यान्वयन के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. (फरवरी 2010) को ₹ एक करोड़ जारी किए। डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने दो स्कूलों के लिए ₹ 61.74 लाख तक का अनुमान प्रस्तुत किया (मई 2010)। एक शिकायत प्राप्त हुई (अगस्त 2010) कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. ऐसे कार्य कर रहा है जो बाला मानदंडों के अन्तर्गत नहीं आते। विभाग ने डी.एस.आई.आई.डी.सी. को कार्य रोकने के लिए कहा (सितम्बर 2010) और डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने बाला मानदंडों से संबंधित समझौते को समाप्त कर दिया (मई 2011)। इस प्रकार, निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के कारण जारी निधियों के उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. को 'बाला योजना' के अन्तर्गत किये गये कार्य की लागत का ब्यौरा देने को कहा गया (मार्च 2015) ताकि वापस माँग के लिए निधियों का आकलन किया जा सके।

### 2-3-4 v'kä 0 fä; k ds fy, dY; k kdjh ; kt ukvkd dk k; u

विभाग विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए आठ योजनाएँ चला रहा था। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है :

#### 2-3-4-1 fof' k'V vko'; drk okys 0 fä; k dks foYkt; l gk rk

योजना के अन्तर्गत अशक्त व्यक्तियों के बैंक खाते में ₹ 1500 प्रतिमाह की दर से भत्ता, त्रैमासिक रूप से प्रेषित किया जाता है, बशर्ते कि उनकी अशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो, आवेदन से पूर्व दिल्ली में कम से कम पाँच वर्ष का निवास प्रमाण हो और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 75000 से कम हो। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2008-09 में 1988 से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 45471 हो गई, जिसमें 43483 की निवल वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान योजना पर ₹ 190.01 करोड़ के आबंटन (2009-14) के विरुद्ध ₹ 189.63 करोड़ का व्यय हुआ।

योजना के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी विभागीय अन्वेषकों अथवा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किये गए अन्य अधिकारियों के माध्यम से सभी संस्वीकृत किए गए मामलों एवं संदेहास्पद मामलों के पाँच प्रतिशत का सत्यापन कर सकता है। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि विभाग ने योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं किया। इसने तीन तिमाही (अक्टूबर 2011 से जून 2012) के दौरान सभी संस्वीकृत मामलों में से केवल 391 मामलों (पाँच प्रतिशत) को चयनित किया और उन्हें सत्यापन के लिए अपने 10 जिला कार्यालयों में अग्रेषित (अक्टूबर 2012) किया। जिला कार्यालयों ने सितम्बर 2014 तक केवल 42 मामलों में सत्यापन की सूचना दी। सत्यापन के आधार पर 42 मामलों में से 31 (74 प्रतिशत) मामलों में वित्तीय सहायता रोक दी गई थी। स्टाफ की कमी के कारण शेष 349 मामलों का सत्यापन रोक दिया गया था। इस प्रकार, मामलों के गैर-सत्यापन के कारण मामलों की प्रामाणिकता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि सितम्बर से दिसम्बर 2014 के बीच लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया एवं 18122 लाभार्थियों का धन-प्रेषण रोक दिया गया क्योंकि वे दिये गये पते पर नहीं पाये गये। स्थानान्तरित हो गये थे/अयोग्य/डुप्लीकेट थे। तथ्य यह है कि योजना के अनुसार विभाग ने सत्यापन को जारी रखा होता तो अयोग्य व्यक्तियों को ₹ 2.72 करोड़<sup>20</sup> मासिक लाभ से बचा जा सकता था।

#### 2-3-4-2 v'kä 0 fä; k ds i qokl ds fy, jk'Vt dk De ¼-0 -igkdk½ ; kt uk

इस योजना का उद्देश्य अशक्त व्यक्तियों के लिए एक जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना एवं समुदाय-आधारित पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया-कलापों को तेज करना है।

<sup>20</sup>18122 × ₹1500 = ₹ 2.72 करोड़

योजना के अन्तर्गत अशक्तता कैम्प भी आयोजित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों को प्रेक्षित किया गया :

i) **ft yk v'kärk i qokl dšæ dh xš&LFki uk%** जिला अशक्तता पुनर्वास केन्द्रों (जि.अ.पु.के.) की स्थापना करने का उद्देश्य अवसंरचना निर्माण के माध्यम से जमीनी स्तर पर अशक्त व्यक्तियों को विस्तृत सेवाएँ उपलब्ध कराना है। राज्य समन्वय समिति के द्वारा अक्टूबर 2007 में आयोजित बैठक में जि.अ.पु.के. के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। योजना के अन्तर्गत, एक नोडल एजेंसी को प्रायोगिक आधार पर जिला-उत्तर में चिन्हित किया जाना था, जिसे गैर-सरकारी संगठनों एवं अशक्तता से संबंधित विषयों के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों के साथ जुड़ना था और अशक्त व्यक्तियों के लिए एकल खिड़की सूचना-सह-सुविधा केन्द्र को स्थापित करना था। विभाग ने 2009-10 में अशक्त व्यक्तियों के संपूर्ण पुनर्वास के लिए दिल्ली के सभी जिलों में प्रबंध करने हेतु चार जोनों में चार जि.अ.पु.के. को स्थापित करने की योजना बनायी। हालाँकि, विभाग ने जि.अ.पु.के. की स्थापना के लिए बजट आबंटित करने के बावजूद सितम्बर 2014 तक न तो किसी नोडल एजेंसी को चिन्हित किया और न ही कोई जि.अ.पु.के. को स्थापित किया। यह मामला पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जि.अ.पु.के. को प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार को निधियों की संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया था, परन्तु अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्राथमिकता इस प्रकार के केन्द्रों को ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रारम्भ करने की थी।

ii) **v'kärk dšæ%** विभाग द्वारा सहायता एवं उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अशक्तता कैम्प एवं जागरूकता, अशक्तता प्रमाण-पत्रों के प्रचालन, डीटीसी बस पास एवं अशक्तता पहचान पत्रों के लिए सामान्य अशक्तता कैम्प का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान लक्षित एवं वस्तुतः आयोजित कैम्पों की संख्या **rkfydk 2-3-2** में दी गई है।

**rkfydk 2-3-2 %dšæ ldk y{; , oami yfC/k**

o"K	fo' kšk dšæ			l keli dšæ		
	y{;	okLrfod	ykkkEk ladh l d; k	y{;	okLr- fod	ykkkEk ladh l d; k
2009-10	20	19	4391	14	6	विभाग के पास उपलब्ध नहीं
2010-11	20	19	3281	10	शून्य	
2011-12	20	11	1424	10	12	
2012-13	10	09	1431	12	9	
2013-14	10	09	703	12	6	
<b>; lsk</b>	<b>80</b>	<b>67</b>	<b>11230</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	

उपर्युक्त तालिका से इंगित होता है कि 2009-14 के दौरान, लक्षित 80 विशेष कैम्पों के विरुद्ध केवल 67 विशेष कैम्प (84 प्रतिशत) एवं लक्षित 58 सामान्य कैम्पों के विरुद्ध केवल 33 सामान्य कैम्प (57 प्रतिशत) आयोजित किए गए थे। इसलिए, इसके वार्षिक लक्ष्य में कमी के बावजूद विभाग उसे प्राप्त नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि कैम्पों का सीमित संख्या में आयोजन किया गया क्योंकि विभिन्न विभागों व गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि विभाग के द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

### 2-3-4-3 cf/kj , oaew fo | ky; k d k mUk; u

इस योजना के अन्तर्गत, विभाग ने 2009-14 के दौरान बधिर एवं मूक के लिए चार विद्यालय (तीन प्राथमिक एवं एक माध्यमिक विद्यालय) के उन्नयन की योजना बनायी, जिसके लिए ₹ 1.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था एवं केवल ₹ 0.89 करोड़ खर्च किया गया। हालाँकि, केवल एक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि दो और विद्यालयों का उन्नयन किया गया (एक माध्यमिक स्तर तक एवं दूसरा 10वीं स्तर तक बढ़ाया गया) परन्तु तदनुसार इन विद्यालयों की नामावली बदलने की आवश्यकता है। हालाँकि जवाब इन उन्नत विद्यालयों के काम पर मौन था।

### 2-3-4-4 l kelt d , oa'kjlfjd : i l sofpr 0 fä; k dsfy, jk'; dk Øe

योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं शारीरिक रूप से वंचित समूहों को समुदाय के साथ जोड़ना एवं उनसे संबंधित दस्तकारी अथवा परम्परागत पेशेवर व्यवसायों में उन्हें दक्ष करना है। योजना के अन्तर्गत, इन समूहों द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई जानी है। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि योजना के अन्तर्गत क्रियाकलाप नहीं किया गया। आगे, विभाग ने 2009-14 के दौरान, अशक्तता कैम्पों के प्रचार पर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ₹ 53 लाख में से ₹ 21 लाख का व्यय किया गया, जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं था।

अपने जबाव में विभाग ने इस शीर्ष के अन्तर्गत निधियों का सही ढंग से उपयोग करने का आश्वासन दिया (मार्च 2015)।

### 2-3-4-5 gkQ&os gke dk fuekzk

हाफ-वे होम की संकल्पना पर विचार उन व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए सुविधा प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु की गई थी जिनकी मानसिक बीमारी का अस्पताल से सेवामुक्त होने के बाद इलाज किया जाना था व नियंत्रण करना था। इस योजना में लाभार्थी एवं उनके परिवारों का समाज में उनके पुनः एकीकरण तथा चिकित्सा सलाह अथवा इलाज हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श भी शामिल था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि सरकार के निर्देशों पर (दिसम्बर 2011) विभाग को पाँच हाफ-वे होम (रोहिणी में तीन तथा द्वारका एवं नरेला में एक-एक) को निर्मित करने थे। डीएसआईआईडीसी के साथ अनुबंध के अनुसार इन घरों को जिसके लिए ₹ 47.63 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति जुलाई 2012 को जारी की गई थी, दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का अनुबंध किया गया था। हालाँकि, इन्हें सितम्बर 2014 तक पूरा नहीं किया गया। इस प्रकार, विकलांग व्यक्ति विचारित सुविधाओं से वंचित थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि तीन हाफ-वे होम पूरे हो गए एवं दो मार्च 2015 के अंत तक पूरे हो जायेंगे, यह जोड़ते हुए कि इन घरों को शुरू होने के लिए सोसाइटी के गठन हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

### 2-3-4-6 cf/kj , oaewd fo | kEk, kadsikB~k&i qrdka, oaonlZdh fu%kyd vki vE

2009-10 के शैक्षणिक सत्र में आरम्भ हुई योजना के अन्तर्गत विभाग अपने द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में कक्षा XII (पूर्व-प्राथमिक को शामिल करते हुए) तक के सभी बधिर एवं मूक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति एवं वर्दी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए, कक्षा VIII तक के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं, जबकि पाठ्य-पुस्तकों को खरीदने के लिए कक्षा IX एवं X के प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 600 तथा कक्षा XI एवं XII के प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 800 नगद रूप में दिए जाते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रति विद्यार्थी को वर्दी हेतु ₹ 500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्दी हेतु आर्थिक सहायता की दरें जून 2011 से संशोधित करके नर्सरी से कक्षा V तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष ₹ 500, कक्षा VI से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए ₹ 700 तथा कक्षा IX से XII तक के विद्यार्थियों के लिए ₹ 900 संशोधित की गई। 2009-14 के दौरान सम्मिलित किए गए छात्रों की कुल संख्या 937 व 1140 के बीच थी। ₹ 45.12 लाख के आबंटन के विरुद्ध अवधि 2009-14 के दौरान ₹ 40.90 लाख का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों को जुलाई अथवा अगस्त माह में वितरित की जाती थीं, जबकि शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू होता है। पुस्तकों के वितरण में देरी के कारण विद्यार्थियों को तीन से चार माह तक पुस्तकों से वंचित होना पड़ता है और उनके अध्ययन में प्रत्यक्ष रूप से बाधा पहुँचती है। आगे, पुस्तकों एवं वर्दी के लिए राशि के वितरण के बाद इसके उपयोग की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु कोई तंत्र नहीं था। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि अप्रैल के अन्त तक किताबों व वर्दियों के खरीद हेतु एवं विद्यार्थियों के बीच उसके वितरण हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

### 2-3-4-7 cf/kj , oaewd fo | kEk, kadsfy, feM&Mshy dk Øe eanjh

विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में यह योजना मूक एवं बधिर विद्यार्थियों हेतु तथा कक्षाओं में अनुपस्थितियों की संख्या में कमी लाने हेतु पोषण संबंधी सहायता एवं प्रत्येक दिन वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्रत्येक दिन न्यूनतम 300 कैलोरी मात्रा का भोजन तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराती है। मिड-डे मील कक्षा XII तक के सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष चार वर्षों (2009-13) के लिए ₹ 5 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया था, परन्तु योजना शुरू नहीं की जा सकी। शिक्षा विभाग, दि.रा.सा.क्षे.स. के सहयोग से योजना आखिर में नवम्बर 2013 में शुरू की गई। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि योजना 2009-13 में विक्रेताओं के निश्चित न दिये जाने के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकी। जवाब से पुष्टि होती है कि 2009-13 के दौरान छात्रों को पोषण सहायता प्रदान नहीं की गई।

### 2-3-4-8 ^vkJ; dk Zkkyk ; kt uk\*

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आश्रय कार्यशाला को 50 अशक्त श्रमिकों की संस्वीकृत संख्या के साथ वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़ाकर 100 तक किया जाना था। योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अशक्त श्रमिकों

को लघु अवधि के प्रशिक्षण<sup>21</sup> (10 से 15 दिनों की अवधि) की व्यवस्था की जानी थी। जिसके बाद अच्छी प्रवीणता प्राप्त करने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना था और खुले बाजार में रोजगार पाने में मदद की गयी। हालाँकि, यह प्रेक्षित किया गया कि कार्यशाला सितम्बर 2014 तक कोई प्रशिक्षण मुहैया नहीं करा रहा था, कार्यशाला में केवल पाँच श्रमिक थे जिसे शुरू में प्रशिक्षित किया गया था (30 वर्ष पहले), जबकि अवधि 2009-14 के दौरान विभाग ने वेतन, मजदूरी एवं दूसरे व्यय पर ₹ 1.13 करोड़ व्यय किये। इस प्रकार, योजना अपने वास्तविक स्वभाव में कार्यान्वित नहीं की गई और अपने लक्षित विषय को खो दिया। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि योजना की समीक्षा की जाएगी एवं अशक्तों की आवश्यकता की उपयुक्तता के पुनर्गठन पर निर्णय लिया जाएगा।

### 2-3-5 vk lk fdj.k dkW ydl dk izaku

विभाग आशा किरण कॉम्पलेक्स, रोहिणी में मन्द बुद्धि लोगों के लिए चार गृह/संस्थान<sup>22</sup> चला रहा है। कॉम्पलेक्स में रहने वालों को सुविधायें मुहैया कराने में प्रबन्धन की स्थिति आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) {kerk l s vf/kd fuokl h कॉम्पलेक्स में 350 की अभिकल्पित क्षमता के विरुद्ध औसतन 970 निवासी है। 2009-10 के दौरान कॉम्पलेक्स में 57 लोगों की मौत से एक मिनिस्ट्रियल समिति ने इन गृहों की भीड़ हटाने की अनुशंसा की (फरवरी 2010)। पुनः मुख्यमंत्री की बैठक (फरवरी 2011) में यह फैसला लिया गया कि आशा किरण गृहों में रह रहे निवासियों को तुरन्त भिक्षु गृह, लामपुर में भेजा जाये। परन्तु विभाग के द्वारा कॉम्पलेक्स को असंकुलित करने हेतु सिवाय कॉम्पलेक्स में दो 80 बिस्तरों वाले शयनागार के निर्माण के व दूसरे क्षेत्रों में 186 निवासियों को स्थानान्तरित करने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये (सितंबर से दिसंबर 2013)। इनमें से 26 निवासियों को चिकित्सा कारणों से वापस स्थानान्तरित करना पड़ा।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि नरेला, हरिनगर, एवं बसंत कुंज में मंदबुद्धि लोगों के लिए तीन नये गृह निर्माणाधीन हैं। तथ्य यह है कि 2009-14 के दौरान कुल 148 लोगों की मृत्यु हुई जो आशा किरण कॉम्पलेक्स की भीड़ हटाने के प्रति विभाग की ओर से ढिलाई का संकेत देता है।

(ii) , fcyd dh mi yC/krk% लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कॉम्पलेक्स में 949 निवासी हेतु वर्ष 2013-14 के दौरान 24 घंटों के लिए एक एम्बुलेंस व कार्यालय अवधि में रोगियों को ले जाने के लिए दो गाड़ियाँ उपलब्ध थीं जिनमें से 469 गंभीर व पूरी तरह से मंदबुद्धि थे एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण 8607 बार रोगियों/निवासियों को ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा इत्यादि के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। अपने जवाब में विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जब कभी भी आवश्यक हो, एम्बुलेंस सेवाएँ प्रदान करने वाले हेतु कैट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2014)।

<sup>21</sup>यांत्रिक एवं वैद्युतीय सामान, कटाई एवं सिलाई, जिल्द एवं सामान पैक कार्य इत्यादि को एकत्र करना

<sup>22</sup>(i) अति गंभीर मंदबुद्धि व्यक्तियों (व्यस्क एवं बालक) का संस्थान, (ii) मंदबुद्धि व्यस्कों के लिए गृह (iii) मंदबुद्धिजन (बालक) के लिए गृह एवं (iv) मंदबुद्धि जन (वयस्क) के लिए स्कूल एवं गृह



(iii) कॉम्प्लेक्स में 260 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 215 देख-भाल कर्मचारी तैनात थे साथ ही 45 की कमी थी। जैसा कि विभाग द्वारा गणना की गई कॉम्प्लेक्स में निवासियों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता 502 है। कॉम्प्लेक्स में रहने वालों को शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जुलाई 2013 में 391 पद बनाये गये थे एवं 379 और पदों हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

(iv) बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) व बाल अधिकार के संरक्षण हेतु दिल्ली आयोग (डीसीपीसीआर) के आशा किरण कॉम्प्लेक्स पर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन (अक्टूबर 2012) के कारण जो कुपोषण, चर्मरोग आदि के उच्च प्रचलन को इंगित किया, कॉम्प्लेक्स की नियंत्रण परिषद् ने अपनी मीटिंग में (जनवरी 2013) चर्चा की व फ़ैसला किया कि निवासियों को दिया जाने वाला पोषाहार महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अभ्युक्तियों व निर्णयों के बावजूद, कॉम्प्लेक्स में रहने वालों को दिये जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता को देखने हेतु कॉम्प्लेक्स में आहार विशेषज्ञ नहीं थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि विशेष आहार निवासियों को दिया गया जैसा चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया। निर्धारित आहार सूची का लो.ना.ज.प्र. अस्पताल आहार विशेषज्ञ से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुनरीक्षण किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। निवासियों को दिये जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता की निरीक्षण या सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं होने के कारण जवाब स्वीकार्य नहीं हैं।

### 2-3-6 रा.रा.क्षे.दि.स. ने (फरवरी 1998) दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/अक्षमता वित्त व विकास निगम (निगम) को राष्ट्रीय अक्षमता वित्त व विकास निगम (रा.अ.वि. व वि.नि.) के राज्य एजेंसी (रा.प्र.ए.) के रूप में नामित किया जिसने मई 2003 से कार्य शुरू किया। रा.अ.वि. व वि.नि., लक्षित समूहों हेतु दिये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान हेतु योजना के अतिरिक्त ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं जैसे कि-समेकित ऋण, शिक्षा ऋण, लघु उद्योग को स्थापित हेतु ऋण, यात्रा ऋण इत्यादि चला रहा है।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने (फरवरी 1998) दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/अक्षमता वित्त व विकास निगम (निगम) को राष्ट्रीय अक्षमता वित्त व विकास निगम (रा.अ.वि. व वि.नि.) के राज्य एजेंसी (रा.प्र.ए.) के रूप में नामित किया जिसने मई 2003 से कार्य शुरू किया। रा.अ.वि. व वि.नि., लक्षित समूहों हेतु दिये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान हेतु योजना के अतिरिक्त ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं जैसे कि-समेकित ऋण, शिक्षा ऋण, लघु उद्योग को स्थापित हेतु ऋण, यात्रा ऋण इत्यादि चला रहा है।

निगम के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित कमियाँ पता चली :

- अशक्तजनों हेतु आर्थिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत 2009-14 के दौरान वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति सिर्फ 6.33 प्रतिशत (भौतिक) व 3.53 प्रतिशत (वित्तीय) थी। इसी अवधि के दौरान इसने अशक्तजनों के लिए किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित नहीं किया। मांगे जाने पर भी (जून 2014) लक्ष्यों के कम प्राप्ति के कारणों को लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- निगम ने रा.अ.वि. व वि.नि. योजना के प्रचार/जागरूकता हेतु कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि इसके परिसरों में अशक्तजनों के दिशा-निर्देश हेतु कोई संकेत चिह्न भी नहीं लगाये गये। फरवरी 2013 में

आयुक्त की बैठक में उठाये गये मुद्दों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रतिवेदन में निगम ने कहा कि एक विज्ञापन की लागत ₹ 5 से 6 लाख थी और इसके भुगतान न होने के कारण वह पृथक रूप से अशक्तजन श्रेणी के विज्ञापन को जारी नहीं कर सकता है। इसलिए योजनाओं के संबंध में प्रचार और जागरूकता सृजन की कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि भविष्य में ऋण योजना के जागरूक होने के प्रावधान के लिए एवं पर्याप्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निगम से अनुरोध किया जा रहा है (फरवरी 2015)।

- **1 eib; dh del%** समाज कल्याण विभाग व निगम के बीच कोई समन्वय नहीं था क्योंकि रा.अ.वि. व वि.नि. द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान व उन तक पहुँचने पर दोनों एजेंसियों के बीच कोई पत्राचार नहीं था। विभाग ने निगम से भविष्य में समन्वय रखने के लिए आश्वस्त किया (मार्च 2015)।

### 2-3-7 v'kärk vf/kfu; e| 1995 dk dk kb; u

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति पर परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 2-3-7-1 jkt; 1 eib; 1 febr ¼kl -1 -½o jkt; dk Zlkjh l febr ¼kdkl -½dh cSdlæadfe; k

राज्य समन्वय समिति (रा.स.स.) एवं राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) को नवम्बर 2004 में गठित किया गया अर्थात् नियम 2001 की अधिसूचना के तीन वर्षों के बाद। जून 2014 तक राज्य समन्वय समिति ने गठित होने के बाद निर्धारित<sup>23</sup> 20 बैठकों के विरुद्ध सिर्फ चार बैठक करायीं (अप्रैल 2005, नवम्बर 2006, अक्टूबर 2007 व जुलाई 2012)। इसी प्रकार, राज्य कार्यकारी समिति ने निर्धारित 40 के विरुद्ध फरवरी 2013 में एक ही बैठक की। विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2015) कि समिति ने 2007-11 के दौरान सक्रिय भूमिका अदा नहीं की। चूंकि दोनों समितियों का 2012 में पुनर्गठन हुआ, समितियों के पुनर्गठन/फाईल कार्रवाई के कारण आवश्यक संख्या में बैठकें नहीं हो पाईं।

#### 2-3-7-2 okk i fronu dk i Zrfrdj. k

धारा 65 अनुबन्ध करता है कि आयुक्त (अशक्तता) राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार व प्रस्तुत करेगा, जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि आयुक्त (अशक्त) ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए अगस्त 2013 में विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष नहीं रखा गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रतिवेदन नहीं रखा जा सका एवं आश्वस्त किया कि प्रक्रिया शुरू की जायेगी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह मूद्दा पूर्व के प्रतिवेदन में उठाया गया था।

<sup>23</sup>अधिनियम की धारा 17 एवं 21 के अनुसार, रा.स.स. को प्रत्येक छमाही में कम से कम एक मीटिंग रखना था व रा.का.स. को तिमाही में एक।

### 2-3-7-3 v'kät ulödsfy, 'kfk.kd vol j'puk dk fodk

अधिनियम के अनुसार सरकार को 18 वर्ष तक के अशक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अशक्तजनों हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ाने व व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ विशेष स्कूल को लैस करने हेतु प्रयास करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा जाँच निम्न दर्शाती है :

- यद्यपि अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत आवश्यक है, विभाग ने अशक्त बच्चों हेतु किसी अनौपचारिक शिक्षा योजना को शुरू नहीं किया। जैसाकि अधिनियम के धारा 28 व 29 के अंतर्गत बताया गया है कि विभाग ने नई सहायक युक्तियाँ, शिक्षण सहायता के विकास हेतु कोई अनुसंधान शुरू नहीं किया।
- विभाग के द्वारा व्यापक शिक्षण योजना जैसा कि अधिनियम की धारा 30 में जरूरी है, को लागू नहीं किया गया। दिल्ली (जनगणना 2011) में 52330 अशक्त बच्चों के विरुद्ध इन स्कूलों के पास कुल 1250 छात्रों की क्षमता के साथ विभाग दो से अधिक दशक पहले अशक्त बच्चों के लिए निर्मित व स्थापित केवल छः स्कूलों को संचालित करता था। जुलाई 2014 तक, इन स्कूलों में शैक्षणिक स्टाफ की अत्याधिक कमी (50 प्रतिशत) थी,
- विभाग जून 2014 तक मंद बुद्धि बच्चों के लिए विद्यालय हेतु मई 2010 में उस्मानपुर में आर्बटिट 4525 वर्ग मी. माप के प्लॉट का अधिपत्य हासिल नहीं कर सका, क्योंकि वह समय से व पूर्ण भुगतान करने में असफल रहा, इसके परिणामस्वरूप योजनागत स्कूल का निर्माण नहीं हो सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जैसा कि अधिनियम के धारा 27, 28, एवं 29 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, शिक्षा विभाग आवश्यक कदम उठा रहे थे। धारा 30 के प्रावधान पर यह कहा गया कि व्यापक शिक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी परन्तु अशक्त विद्यार्थियों को कुछ सुविधायें प्रदान की जा रही थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है न कि शिक्षा विभाग की। आगे, ये मुद्दा पूर्व के प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

### 2-3-7-4 v'kälödsjkt xkj dsfy, i'ho/ku

अधिनियम की धारा 32, 33 व 61 प्रत्येक संस्था में अशक्तों की नियुक्ति व तीन प्रतिशत पदों की पहचान व आरक्षण प्रदान करती है जिस हेतु आयुक्त (अशक्त) सभी विभागों के साथ समन्वय रखेगा। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि आयुक्त (अशक्त) आठ बड़े विभागों<sup>24</sup> में आरक्षण की स्थिति की समीक्षा (जनवरी 2013) की। समीक्षा ने प्रदर्शित किया कि 1996 से केवल अशक्तों के लिए 2239 रिक्त पदों के विरुद्ध, 1336 पदों के पिछले बकाया को छोड़कर (आरक्षित पदों के 60 प्रतिशत) केवल 1253 भरे गये। इसके जवाब में आयुक्त (अशक्त) ने कहा (जुलाई 2014) कि बाकी बचे विभागों में समीक्षा का कार्य चल रहा है। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि तीन प्रतिशत पदों की पहचान व आरक्षण हेतु पत्र सचिव (सेवाएँ), रा.रा.

<sup>24</sup>तीन दि.न.नि., न.दि.न.प., स्वा एवं प.क., शि.वि. एवं सेवा विभाग

क्षे.दि.स. को भेजा जा चुका है (फरवरी 2015)। तथ्य यह है कि विभाग ने पूर्व के प्रतिवेदन में यह मुद्दा उठाये जाने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

### 2-3-7-5 f'kd k r l qkj ra-

लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि आयुक्त के कार्यालय में अशक्तजनों द्वारा शिकायतों की प्राप्ति व निपटान को देखने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। जैसा कि अधिनियम के धारा 62 एवं नियम 49 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा में प्रदान की गई शिकायत फाइलों की जाँच रिपोर्ट दिखाती है कि 2009-14 के दौरान आयुक्त कार्यालय में (दुबारा आयी शिकायतों को शामिल करके) कुल 446 परिवाद/शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 3 से 56 महीनों तक लम्बित 119 शिकायतों पर निर्णय (जून 2014) बकाया थे। आयुक्त ने कहा (जुलाई 2014) कि 2014-15 की अवधि के लिए शिकायत रजिस्टर तैयार कर लिया गया है। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि ऑनलाइन शिकायत की स्थिति जानने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के सू. प्रौ. विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।

### 2-3-7-6 l jdkjh Hou o l koZ fud LFkulaeav'käkgqrqHkfrd l fo/kvldk i to/ku

धारा 44 से 47 अनुबन्ध करता है कि अशक्तों के लाभ हेतु रेल डिब्बों, बसों, प्रसाधनों, हवाईजहाजों, प्रतीक्षालयों आदि में आसानी से पहुँच हेतु राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों को सुविधा मुहैया करने हेतु नियम बनाने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों/भवनों में अशक्तों हेतु उपलब्ध सुविधाओं की सीमा निर्धारित करने हेतु, लेखापरीक्षा विभाग के दो जिला कार्यालयों (पूर्व व उत्तर पूर्व) के चारों ओर स्थित 10 सरकारी स्कूलों<sup>25</sup>, चार सामुदायिक भवनों<sup>26</sup>, दो डी.सी. कार्यालयों (शास्त्री पार्क व कंझावाला), चार सार्वजनिक पार्कों<sup>27</sup> व चार बैंकों/एटीएम का सर्वे कराया। इसके साथ चार रेलवे स्टेशनों<sup>28</sup> व दो अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों<sup>29</sup> का दौरा भी किया गया। सर्वे के निष्कर्षों को rkydk 2-3-3 में दर्शाया गया है:

<sup>25</sup>(i) आर.एस.के.वी. लक्ष्मीनगर (ii) जीजीएसएस, ललिता पार्क (iii) जी सह-शिक्षा एसएसएस, शिवपुरी (iv) आरपीवीवी, गाँधी नगर (v) सर्वोदया बीवी, रायगढ़ कालोनी (vi) एस वी, सेक्टर-3 रोहिणी (vii) आर पी एस के वी रिठाला (viii) सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-2 रोहिणी (पग) जीजीएसएसएस, अवन्तिका व (x) एस के वी, अवन्तिका, सेक्टर-1 रोहिणी।

<sup>26</sup>सामुदायिक भवन-(i) ब्लॉक 2, गीता कालोनी (ii) ब्लाक 10, गीता कालोनी (iii) सेक्टर-5, रोहिणी व (iv) सेक्टर-7, रोहिणी

<sup>27</sup>(i) विश्वकर्मा पार्क, किशन कुँज, (ii) वीर सावरकर पार्क, 14 ब्लॉक, गीता कालोनी, (iii) पार्क, सेक्टर-4, रोहिणी व (iv) दीनबन्धु छोटू राम पार्क, सेक्टर-6, रोहिणी

<sup>28</sup>रेलवे स्टेशन-किशनगंज, हजरत निजामुद्दीन, नरेला व नई दिल्ली

<sup>29</sup>बस अड्डा- सराय काले खाँ, व आईएसबीटी कश्मीरी गैट

### रकम 2-3-3 %1 ओडि मि य/क क

Øe l a	Hou@LFku ft l ea l ožfd; k x; k	l ņo/k; a t k s mi yC/k ughaš		
		jŃil	, fyosj ; k fyIV	v'kã ykka grqi ž kku
1	स्कूल-10	02	10	05
2	बैंकों/एटीएम-04	04	-	04
3	डीसी कार्यालय- 02	-	01	01
4	सामुदायिक भवन- 04	03	04	04
5	रेलवे स्टेशन- 04	04	04	04
6	बस अड्डे- 02	-	-	01
7	सार्वजनिक पार्क - 04	04	-	04
<b>dy</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>23</b>

उपरोक्त आँकड़ा दर्शाता है कि 17 भवनों/स्थानों में रैम्प नहीं थे, 19 में एलिवेटर्स/लिफ्ट नहीं थे व 23 में व्हील चेयर वाले अशक्तों के लिए प्रसाधन तक पहुँचने की सुविधा नहीं थी। आगे, यह सामने आया कि जो विभाग उक्त सुविधाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, उनके अपने कार्यालय भवनों में भी ये सुविधायें<sup>30</sup> उपलब्ध नहीं थी। कालकाजी में मूक बधिर स्कूल के लिए विभाग के नवनिर्मित तीन मंजिला भवन में प्रसाधन के प्रावधान नहीं थे। यह अशक्तों के विरुद्ध पक्षपात को दूर करने के लिए सुविधायें मुहैया करने हेतु विभाग की लापरवाही दर्शाता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि मुख्यालय एवं दूसरे स्थानों पर आशक्तों के लिए सुविधाएँ मुहैया करने हेतु कदम उठाये गये हैं। तथ्य यह है कि पूर्व के प्रतिवेदन में उठाये जाने के बावजूद इस संबंध में सही कदम उठाये जाने बाकी है।

### 2-3-8 vU, fclhq

(i) ?kja, oal LFkuack fujhk k %अवधि 2009-14 हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2012 तक कोई निरीक्षण आयोजित नहीं किया गया उसके बाद अप्रैल 2014 (24 माह) 12 अशक्त व्यक्तियों के घरों व संस्थानों के 576 निरीक्षणों<sup>31</sup> की तुलना में सिर्फ 32 निरीक्षणों का आयोजित किया गया जो कि सिर्फ 6 प्रतिशत बनता है। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि डीएसडब्लूओ ने संस्थानों का नियमित निरीक्षण व निगरानी आयोजित की। जवाब निरीक्षणों के गैर/कम संचालन पर लेखापरीक्षा की दृष्टि से सुस्पष्ट नहीं है।

(ii) 'kn 'fodyark\* dk iz k %कम से कम कार्यालयी पत्राचार, कार्यालयी प्रतिवेदनों, सरकारी संस्थानों, संगठनों इत्यादि के सन्दर्भ में 'विकलांगता' अभिव्यक्ति के प्रयोग को अनुत्साह व प्रतिबंधित करने हेतु सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार

<sup>30</sup>एलिवेटर्स अथवा लिफ्ट, ब्रेल संकेत, रैम्प इत्यादि

<sup>31</sup>अप्रैल 2012 से महीना में कम से कम दो बार जरूरी है अर्थात् 12 घरों/संस्थानों × 24 महीने × 2 निरीक्षणों

से प्राप्त पत्र (फरवरी 2012) के उल्लेख में विभाग ने निर्देशों के अनुपालन हेतु मार्च 2012 में निगम को एक पत्र पृष्ठांकित किया। फिर भी, 'विकलांगता' अभिव्यक्ति निगम अपने पत्राचारों, कार्यालयी प्रतिवेदनों में लगातार प्रयोग करता रहा। प्रतिबंध के बावजूद विभाग स्वयं वित्त विभाग से शीर्ष 'विकलांगता' कल्याण (मांग संख्या 8 के मुख्य शीर्ष-2235) में लगातार अनुदान प्राप्त करते रहे।

अपने जवाब में, विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि निगम को अपने नाम बदलने को कहा जा रहा है (फरवरी 2015) एवं मुख्य शीर्ष 2235 मांग सं. 8 'विकलांग के कल्याण' से 'अशक्तों के सशक्तीकरण' में बदलने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

### 2-3-9 fu"d"K

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे अशक्त लोगों हेतु एक व्यापक डेटाबेस के लिए घर-घर जाकर स्वतंत्र सर्वे का आयोजन नहीं किया। इसने राज्य अशक्त नीति को अशक्तजनों से सम्बन्धित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित नहीं किया एवं जिला अशक्त पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने में असफल रहे। वित्तीय लाभों हेतु उनकी लगातार योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन हेतु विभाग के पास कोई नीति नहीं है। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए घरों में अधिक संख्या में लोग थे एवं उनके देखभाल हेतु अपर्याप्त वाहन एवं देखरेख कर्मी थे। दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/विकलांगता वित्त एवं विकास निगम अशक्तजनों हेतु आर्थिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक के साथ-साथ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत जरूरी है, राज्य समन्वय समिति व राज्य कार्यकारी समिति निर्धारित 20 व 40 बैठकों की तुलना में केवल चार व एक बैठक करवा सकीं। 52330 अशक्त बच्चों के लिए 1250 की क्षमता वाले केवल छः स्कूल ही उपलब्ध थे जबकि अनौपचारिक शिक्षा हेतु योजना नहीं थी। रैम्प, सुलभ शौचालय, एलिवेटर्स या लिफ्ट आदि सुविधाएँ सभी सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों में मुहैया नहीं करायीं गयी थीं।

### 2-3-10 fl Qkf' k

#### l jdkj dj l drh g&

- (i) अशक्तजनों की संख्या, उनके प्रकार एवं श्रेणी को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सर्वे की पद्धति पर विचार करना,
- (ii) रा.अ.वि.व वि.नि./रा.प्र.ए. द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं की योजनाओं का प्रचार करना व उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु अशक्तों को उत्साहित करने के लिए कदम उठाना,
- (iii) मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए घरों को असंकुलित किया जाय एवं उन्हें पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जाए, एवं
- (iv) सभी स्थानों इत्यादि में उनके अनौपचारिक/व्यापक शिक्षा एवं अशक्तों के लिए सुविधाओं को शामिल करते हुए अशक्त बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय स्थापित कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना।

मामला सरकार को अक्टूबर 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## 'lgjh fodkl foHkx

### 2-4 fo/ku l Hk l nL; LFkkuh {ls= fodkl ; kt uk

सादृश्य एमपीलैड योजना के अनुरूप रा.रा.क्षे.दि.स. ने भी दिल्ली में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण व संवर्धन हेतु एक योजना कार्यक्रम 'विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (एमएलएलैड योजना) शुरू की। प्रारंभ में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹ 1.00 करोड़ रखा गया था, जो कि बाद में धीरे-धीरे बढ़कर ₹ 4.00 करोड़ तक हो गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

#### fof' k'Vrk ;

- एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों में बहुत सी कमियों के कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता व पारदर्शिता का अभाव रहा। बहुत से संशोधनों के परिणामस्वरूप एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों का प्रभाव क्रमशः कम हो गया।  
(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.1)
- श.वि.वि. ने आवश्यक पूर्व अर्हताओं को सुनिश्चित किए बिना ₹ 39.90 करोड़ के 248 निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्रदान की।  
(पैराग्राफ 2.4.4.2 एवं 2.4.5.4)
- योजना के अंतर्गत कार्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आरंभ किया गया था। तथापि, ₹ 277.36 करोड़ के व्यय वाले 3160 निर्माण कार्यों में 60 प्रतिशत निधियाँ वर्तमान परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुधार पर खर्च की गईं तथा ₹ 61.94 करोड़ के व्यय वाले 585 निर्माण कार्य दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं थे।  
(पैराग्राफ 2.4.5.1)
- कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों में बहुत-सी अनियमितताएँ जैसे कि व्यय का आधिक्य, संस्वीकृत कार्यों का अप्राधिकृत रद्दीकरण/समापन, कार्यों के सौंपने एवं समापन में देरी, निविदाओं को बिना आमंत्रित किए कार्य को सौंपना इत्यादि थीं।  
(पैराग्राफ 2.4.7)
- श.वि.वि. ने योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा था। इसने योजना निधियों की लेखापरीक्षा एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण हेतु किसी तंत्र को स्थापित नहीं किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था।  
(पैराग्राफ 2.4.8.1, 2.4.8.2 एवं 2.4.8.3)

## 2-4-1 निष्पादन

रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 1994-95 में एक योजनागत स्कीम रूपरेखा तैयार की जिसका नाम 'विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' है जिसे आमतौर पर एम.एल.ए.एल.ए.डी. एस. (स्कीम) के रूप में जाना जाता है, तथा इसे 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढीकरण व वृद्धि' शीर्षक के साथ अपनी वार्षिक योजना में जोड़ा। रा.रा. क्षे. दिल्ली को सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों व 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (वि.स.नि.क्षे.) में बाँटा गया है। आरंभ में, प्रतिवर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र ₹ 1.00 करोड़ नामोद्दीष्ट किया जाता था, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रति वर्ष प्रति वि.स.नि.क्षे. ₹ 4.00 करोड़<sup>32</sup> कर दिया गया।

इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नोक्त थीं :

- प्रत्येक विधान सभा सदस्य वैयक्तिक कार्य हेतु ₹ 2.00 करोड़ की अंतिम सीमा के साथ एक वर्ष में ₹ 4.00 करोड़ के लघु पूँजीगत कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।
- इस योजना के अन्तर्गत कार्य मुख्यतः सरकारी या स्थानीय निकाय की भूमि पर स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण हेतु होना चाहिए।
- इस योजना के अन्तर्गत कार्य दिल्ली के सभी तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को शामिल करते हुए, विधान सभा सदस्य के द्वारा चयनित किसी भी सरकारी विभाग व एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।
- विधान सभा सदस्यों के द्वारा अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियाँ एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा अनुमानित निधियाँ, शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) के द्वारा इसके बजट के अन्तर्गत, योजना के लिए वार्षिक आबंटन में से सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं।
- योजना के अन्तर्गत निधियों को गैर-व्यपगमनीय समझा व माना जाएगा एवं अप्रयुक्त निधियों को आगे के वर्षों में उपयोग किया जा सकता है।

### 2-4-1-1 निष्पादन प्रक्रिया

योजना के लिए निधियाँ श.वि.वि. के बजट के अंतर्गत आबंटित की जाती हैं। सचिव श.वि. वि., बजट नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते योजना के लिए प्रशासनिक प्रमुख है जिसकी अपर सचिव (एमएलएलैडस) एवं श.वि.वि. की योजना शाखा के उप-निदेशकों व सहायक निदेशकों के द्वारा सहायता की जाती है। दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.एवं बा.नि.वि.) तथा नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.पा.) योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।

### 2-4-1-2 निष्पादन प्रक्रिया:

निष्पादन लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि क्या:

<sup>32</sup>(i) 1994-1995- ₹ 1 करोड़, (ii) 1999-2000- ₹ 1.40 करोड़, (iii) 2000-2001-₹1.90 करोड़, (iv) 2004-2005- ₹ 2 करोड़ एवं (v) 2011-2012- ₹ 4 करोड़



- योजना के कुशल तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश पर्याप्त रूप से उचित हैं,
- कार्यों की आयोजना व संस्वीकृति, योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप था एवं योजना के सही मायने के अनुरूप था,
- योजना निधियों का प्रबंध प्रभावी एवं कुशल था और
- कार्यों का कार्यान्वयन प्रभावी, दक्ष एवं विद्यमान नियमों के फ्रेमवर्क, वित्तीय औचित्य की प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों के अन्दर था।
- कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी को शामिल करते हुए, आंतरिक नियंत्रण तंत्र उपयुक्त था।

### 2-4-1-3 यक्षिणक्षेत्रीय विकास कार्य

2009-14 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा सचिव एवं विभाग के अधिकारियों तथा योजना के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों के साथ मई 2014 में हुए प्रवेश सम्मेलन के साथ आरंभ हुई। मई 2014 से अक्टूबर 2014 के दौरान श.वि.वि., दि.न. नि. के मुख्यालयों, दि.ज.बो., सिं. एवं बा.नि.वि. एवं न.दि.न.पा. के अभिलेखों की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने निधियों के उपयोग के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों के शीर्ष 59 संभागों<sup>33</sup> को चयनित किया था, जिनमें 10821 निर्माण कार्यों में से 933 निर्माण कार्यों<sup>34</sup> से संबंधित अभिलेखों को उनकी अनुमानित लागत के आधार पर, विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

मार्च 2005 (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) को समाप्त अवधि के प्रतिवेदन में इस विषय पर अंतिम संवीक्षा को शामिल किया गया था लेकिन लो.ले.स. में इस पर चर्चा नहीं हुई।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं को दिसम्बर 2014 में सरकार के पास भेजा गया था तथा 20 फरवरी 2015 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विशेष सचिव, श.वि.वि. एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इस पर भी चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन में अभिव्यक्त हुए सरकार के विचारों एवं बाद में प्राप्त हुए विचारों का ध्यान रखा गया व उचित ढंग से रिपोर्ट में शामिल किया गया।

### 2-4-1-4 यक्षिणक्षेत्रीय एन.एम.

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये हैं :

- योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधानों एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य प्रशासनिक एवं कार्यकारी निर्देशों,

<sup>33</sup>धन मूल्य के आधार पर सिं. एवं बा.नि.वि. के 100 प्रतिशत संभागों व शेष अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों में से प्रत्येक के कुल संभागों का 50 प्रतिशत

<sup>34</sup>(i) ₹ 5 लाख तक-2 प्रतिशत (ii) ₹ 5 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक-सर्वोच्च लागत वाले 10 प्रतिशत, (iii) ₹ 20 लाख से अधिक तथा ₹ 50 लाख तक-सर्वोच्च लागत वाले 50 प्रतिशत, और (iv) ₹ 50 लाख से अधिक- 100 प्रतिशत

- सामान्य वित्तीय नियमों, सिविल लेखा नियमावली, के.लो.नि.वि. नियमावली एवं भारत सरकार के अन्य वित्तीय नियमों, और
- एमपीलैड योजना से संबंधित प्रावधान।

## यस कि ज कि फु "द" क

### 2-4-2 , e, y, yM ; kt uk ds fn' k&funZka eadfe; k

एमपीलैड योजना के अनुरूप एमएलएलैड योजना रा.रा.क्षे. दिल्ली में शुरू की गई थी। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य भी समान है अर्थात् जन प्रतिनिधियों (लोकसभा एवं विधान सभा सदस्यों) को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासवादी प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार देता है। एमएलएलैड योजना के मामले में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार नीतिगत मामलों का निपटान करता है एवं राज्यों में सीधे जिला प्रमुखों को निधियाँ जारी करता है। प्रत्येक राज्य में एक विभाग को योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जबकि जिला प्रमुखों को कार्यों की संस्वीकृति एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके विपरीत, रा.रा.क्षे.दि. में, जिला प्राधिकारी एमएलएलैड योजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन श.वि.वि. अकेले सभी तीन घटकों अर्थात् (i) नीति निर्माण करना (ii) परियोजनाओं की संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन, तथा (iii) योजना कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण व निगरानी के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है।

दोनों योजनाओं के दिशा-निर्देशों की तुलना दर्शाती है कि एमएलएलैड योजना बहुत सी कमियों के कारण प्रभावित हुई, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता व पारदर्शिता का अभाव रहा। दिशा-निर्देशों के दो समूहों में प्रावधानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दों में से कुछ की तुलना **vuyXud 2-2** में दी गई है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि वह नीति का अनुमोदन करता है और उसी के अनुरूप संस्वीकृति प्रदान करता है। कार्यों की निगरानी अलग से कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा की जानी चाहिए। श.वि.वि. ने यह कहा कि दिशा-निर्देशों में एमपीलैड योजना दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाएगा।

### 2-4-2-1 , e, y, yM ; kt uk fn' k&funZka dk Øfed : i l si kko de gkuk

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में कई संशोधन हुए हैं, एवं प्रत्येक संशोधन के कारण उनका प्रभाव कम हो गया। योजना दिशा-निर्देश-2012 एवं पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अध्ययन दर्शाता है कि दिशा-निर्देशों ने प्रत्येक संशोधन के साथ अपना प्रभाव खो दिया है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को वापस ले लिया गया था, जिसने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन व निगरानी को प्रभावित किया है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं:

Ø-l a	okl fy; sx; siko/ku	i Hko
1.	किसी अनुलिपीकरण से बचने के लिए, स्थानीय निकायों/विभागों को प्रमाणित करना है कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। (दिशा-निर्देश 2002-03)	कार्यों के अनुलिपीकरण की संभावना
2.	विधान सभा सदस्यों से परामर्श के पश्चात्, श.वि.वि. को कार्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करना है (दिशा-निर्देश 2002-03)। आधिकारिक व विशिष्ट समस्या से बचने के लिए, उन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके भूमि/संपत्ति/क्षेत्राधिकार पर कार्य निष्पादित किया जाना है। (दिशा-निर्देश 2006)।	विधान सभा सदस्य एजेंसी का चयन करता है। कुछ प्रकरणों में, एजेंसियों के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अधिदेश एवं भूमि/क्षेत्राधिकार का स्वामित्व नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट व क्षेत्राधिकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
3	कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु प्रधान सचिव (श. वि.वि.) के अधीन एक निगरानी समिति का गठन। (दिशा-निर्देश 2000-01)।	निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं है।
4	किसी कार्य को आरंभ करने से पहले सम्बन्धित स्थानीय निकाय/एजेंसी के द्वारा कार्यों के रखरखाव व अनुरक्षण हेतु प्रावधान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। (दिशा-निर्देश 2000-01)	योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के भावी रख-रखाव व अनुरक्षण के लिए आश्वासन नहीं।

समापन सम्मेलन (फरवरी 2015) में, विशेष सचिव ने यह आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ एमपीएलएडी स्कीम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार एवं स्कीम दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन हेतु रखी जाएँगी।

### 2-4-3 ; kt uk ds varxZ fu/Wj r dk lgrqv k kt uk dk vHko

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्य, रा. रा.क्षे.दि.स. के स्थानीय निकायों एवं विभागों के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों व परियोजनाओं के सामान्य पैटर्न की पुष्टि करें। हालाँकि, दिशा-निर्देशों में विनिर्धारित तरीकों के अनुसार, योजना के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाने के लिए स्थानीय निकायों अथवा श.वि.वि. में इस प्रकार का कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। व्यवहार में, विधान सभा सदस्यों ने अल्पावधि उपायों के रूप में अलग से कार्य दर कार्य के आधार पर प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और श.वि.वि. ने उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं सरकारी व स्थानीय निकायों के कार्यक्रमों के साथ उनके जुड़ावों को बिना सुनिश्चित किए ही संस्वीकृत किया।

निर्माण कार्यों में तदर्थता के मामले को पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया। तथापि, श.वि. वि. ने इस संबंध में सुधारक कार्रवाई आरंभ नहीं की।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलएलैड योजना का मूलतः अर्थ क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है जिसका विधान सभा सदस्यों के द्वारा बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. को उन योजना कार्यों को संस्वीकृत करना था जो कि सरकारी एवं स्थानीय निकायों के सामान्य पैटर्न एवं कार्यक्रमों के अनुरूप हों।

## 2-4-4 iZrkokadh l oHkk , oal l oH-fr

### 2-4-4-1 iZrkokadh l eppr l oHkk dk vHko

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देश में अनुबन्ध है कि एमएलए अपने द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों के जारी होने के लिए प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को कार्य के ब्यौरों, इसके स्थान-निर्धारण, ब्यौरेवार लागत अनुमान एवं योजनागत परिव्यय के साथ लिखित निवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच से, हालाँकि, यह पता चलता है कि एमएलए के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में अनुमोदित योजनागत परिव्यय, कार्य के विशिष्ट स्थान-निर्धारण एवं ब्यौरेवार लागत अनुमान शामिल नहीं थे। शहरी विकास विभाग ने, विनिर्धारित दस्तावेजों पर बल देने के बजाय प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने के उत्तरदायित्व से अपने आप को मुक्त रखा तथा इस प्रकार की संवीक्षा का दायित्व संस्वीकृत पत्रों में निम्नलिखित शर्तों को सम्मिलित करते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया था:

- (i) कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रस्तावित कार्य के स्थान की जाँच करना था एवं सुनिश्चित करना था कि यह अप्राधिकृत कालोनी में स्थित न हो।
- (ii) कार्यान्वयन एजेंसी तकनीकी एवं वित्तीय संवीक्षा तथा प्रत्येक कार्य के लिए ब्यौरेवार अनुमान के लिए उत्तरदायी होगी।
- (iii) एजेंसियों के द्वारा कार्य के अनुमोदित मदों पर निधियों का उपयोग, स्कीम के पूर्णतया मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

आगे, श.वि.वि. के पास, कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा इन शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि श.वि.वि. में प्रस्तावों की जाँच के तंत्र में और अधिक सुधार अतिरिक्त स्टाफ को नियोजित करके एवं एमएलएलैड योजना के लिए एक तंत्र को विकसित करके किया जाएगा। इनके उत्तर से स्वयं पुष्टि होती है कि श.वि.वि. में प्रस्तावों की संस्वीकृति देने से पहले समुचित रूप से संवीक्षा नहीं की जाती है।

### 2-4-4-2 vko'; d i vZvko'; drkva dks fcuk l fuf' Pkr fd, dk k dh l oH-fr

एमएलएलैड योजना की प्रमुख विशिष्टताओं में से एक विशिष्टता यह है कि जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी विभागों में लागू विभागीय प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक संस्वीकृति दी जाएगी। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि श.वि.वि. ने कार्यों को संस्वीकृति देते समय योजना के इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। कुछ दृष्टान्त नीचे दिये गए हैं:

- (i) ₹ 19.53 करोड़ लागत के स्ट्रीट लाइटों के 179 निर्माण कार्यों को 2012-14 के दौरान संस्वीकृति दी गई थी। न तो स्ट्रीट लाइट की अतिरिक्त आवश्यकता का न ही प्रकाशीय उपकरण के विशेष विवरणों को संस्वीकृति से पहले सत्यापित किया गया था।

- (ii) वर्ष 2009-13 के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों से बिना आवश्यक अनुमति प्राप्त किए ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को हैण्डपम्पों को लगाने के लिए ₹ 94.70 लाख संस्वीकृत किये गये थे। अतः कार्यों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था। निधियाँ सिं. एवं बा.नि.वि. के पास अप्रयुक्त रहीं।
- (iii) भूमि, जहाँ इन कार्यों को पूरा किया जाना था, के स्वामित्व का बिना सत्यापन किए ही सितम्बर 2013 में दो सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए ₹ 2.83 करोड़ की राशि को संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि भू-स्वामी एजेंसी ने अपनी भूमि पर भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी थी।
- (iv) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पथों, गलियों एवं सड़कों को तैयार करना नियंत्रण में नहीं आता था, परन्तु शहरी विकास विभाग ने इसे भू-स्वामी एजेंसियों से प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना ही सड़कों, पथों, गलियों इत्यादि को मजबूती प्रदान करने के लिए ₹ 5.73 करोड़ के 24 कार्यों को संस्वीकृत किया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि संस्वीकृति आदेशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को भूस्वामी विभागों से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित था। यह उत्तर इसकी पुष्टि करता है कि संस्वीकृतियाँ आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना जारी की गईं जबकि यह पैराग्राफ में उठाए गए अन्य मुद्दों पर कोई जानकारी नहीं देता।

## 2-4-5 लोह-फर; लोह-फर; लोह-फर; लोह-फर

### 2-4-5-1 लोह-फर; लोह-फर; लोह-फर; लोह-फर

योजना दिशा-निर्देश विनिर्धारित करते हैं कि योजना के अन्तर्गत कार्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों की भूमि पर मुख्यतः स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु होना चाहिए। राजस्व प्रकृति एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत व रखरखाव पर व्यय अनुज्ञेय नहीं है। लेखापरीक्षा ने 2012-14<sup>35</sup> की अवधि के दौरान योजना व्यय संस्वीकृति का विश्लेषण किया और देखा कि एमएलए की सिफारिशों पर, श.वि.वि. ने इस अवधि के दौरान ₹ 462.17 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल 4832 कार्यों की संस्वीकृति दी थी। स्कीम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों की प्रकृति एवं स्वीकार्यता के आधार पर, लेखापरीक्षा में इन कार्यों को तीन परस्पर विशिष्ट श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया, जैसा कि नीचे रकम 2-4-1 में दिया गया है:

<sup>35</sup>2009-12 की अवधि के दौरान शहरी विकास विभाग के द्वारा संस्वीकृत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

रक्यदक 2-4-1%2012&14 दस नक्षु fu"i knr fd, x, dk k dk foHkt u

1/4 djM-e2/2

Øe l a	en	dk Zdh l d ; k	Q ;	i fr' kr
1.	अनुज्ञेय कार्य	1087	122.87	26.59
2.	दिशा-निर्देशों में गैर-विनिर्दिष्ट कार्य	585	61.94	13.40
3.	विद्यमान परिसंपत्तियों के रखरखाव व सुधार हेतु निर्माण कार्य	3160	277.36	60.01
	<b>dy</b>	<b>4832</b>	<b>462.17</b>	<b>100</b>

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिफारिश एवं संस्वीकृत किए गए कार्यों का प्रतिरूप, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य रूप से एक समान था, अर्थात् एमएलए ने नई अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रयत्न करने के बजाय विद्यमान संरचनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए स्कीम निधियों के उपयोग करने को प्राथमिकता दी। जैसा कि तालिका में दिए गए आँकड़ों से इंगित होता है कि संस्वीकृत निधियों का 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों (जैसे कि पथों, सड़कों, जल-रेखा, सीवर, नालियों इत्यादि की मरम्मत) हेतु उपयोग किया गया था। इस प्रकार का व्यय मुख्यतः राजस्व प्रकृति का था और स्थानीय निकायों के द्वारा उनकी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाना था। व्यय का 13 प्रतिशत से अधिक भाग उन कार्यों पर हुआ था, जो स्कीम दिशा-निर्देशों में अनुज्ञेय कार्यों के रूप में नहीं थे। अनुज्ञेय कार्यों हेतु निधियों का केवल 26.59 प्रतिशत संस्वीकृत किया गया था। अनुज्ञेय कार्यों की इस श्रेणी के अन्तर्गत भी, 561 कार्यों को केवल एक शीर्ष- 'पार्कों का विकास' के अन्तर्गत ₹ 35.79 करोड़ (अनुज्ञेय कार्यों के ₹ 122.87 करोड़ की कुल लागत का 41 प्रतिशत) की लागत पर संस्वीकृत किया गया था।

मरम्मत व रखरखाव के कार्यों की संस्वीकृति के मुद्दे को पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। जब कि श.वि.वि. ने इसी प्रकार के कार्यों को नियमित रूप से संस्वीकृत करना जारी रखा।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि सड़कों का प्रबंध, सीवर, नालियों के सुधार को नया कार्य माना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उपबंध है जब कि संदर्भित निर्माण कार्य परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु नहीं थे, बल्कि स्थानीय निकायों की विद्यमान परिसम्पत्तियों में सुधार के लिए थे।

#### 2-4-5-2 vuks dk k dh , drjQk l loh-fr

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि कार्यों की 28 श्रेणियों को समाविष्ट करते हुए अनुज्ञेय कार्यों की एक सूची पर एमएलए के द्वारा सिफारिश की जा सकती है। सूची में कार्यों को विशिष्ट श्रेणियों में शामिल करने का अभिप्राय स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना था कि कार्यों की जिम्मेवारी उन क्षेत्रों में ली गई है जिनमें अतिरिक्त अवसंरचनाओं के निर्माण के द्वारा मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2012-14 के दौरान, 70 एसी में से किसी के लिए भी सूची में शामिल कार्यों की 28 श्रेणियों में से, प्रथम 12 श्रेणियों (जैसे कि विद्यालय भवन का निर्माण, भूमिगत

पथों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सार्वजनिक पुस्तकालयों, विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर, सौर ट्रैफिक लाईट, अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार सड़कें, क्रीड़ा-परिसर, इत्यादि) में से एक भी कार्य की, सिफारिश नहीं की गई थी। शेष 16 श्रेणियों में से ₹ 122.87 करोड़ को शामिल करते हुए 1087 कार्यों की सिफारिश की गई थी तथा उसे संस्वीकृत किया गया था। आगे, ₹ 122.87 करोड़ के इस संस्वीकृत व्यय में से केवल छः श्रेणियों के कार्यों अर्थात् बरातघरों, चौपालों, नलकूपों, ऊर्ध्वस्थ विद्युत तारों का स्थानान्तरण, स्ट्रीट लाईटिंग, उद्यानों एवं बैठने की बेंचों के विकास पर ₹ 111.49 करोड़ की धनराशि का व्यय भारित हुआ। केवल इन छः श्रेणियों के कार्यों का अनुज्ञेय कार्यों पर कुल व्यय के 90.66 प्रतिशत का हिसाब दिया गया। अन्य 10 श्रेणियों (जैसे कि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों, बस स्टॉप, कूड़ा-कचरा संग्रहण केन्द्र, वर्षा जल संचयन तंत्र, सार्वजनिक पुस्तकालयों इत्यादि के लिए अस्पताल-गाड़ियों एवं गश्ती वाहनों का प्रावधान) को केवल 9.34 प्रतिशत का सीमान्त अंश उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलए स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अथवा सार्वजनिक माँग पर अनुज्ञेय कार्यों में से किसी की भी सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र थे तथा आगे कहा कि सूची सुविस्तृत थी जो कि एमएलए के द्वारा उपयोग में लायी गई थी। श.वि.वि. का उत्तर सराहनीय है, परन्तु सरकारी प्राथमिकताओं का एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कार्यों में यथोचित निरूपण भी किया जाना चाहिए था।

### 2.4-5-3 व्ययों के अन्तर्गत प्रमुख व्ययों के अन्तर्गत

श.वि.वि. ने स्कीम दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानकों का पूर्णतया पालन नहीं किया, क्योंकि अनुज्ञेय कार्यों की सूची में गैर-सम्मिलित कार्यों को भी संस्वीकृत किया गया था जैसा कि तालिका 2.4.2 में विवरणित है:

### तालिका 2.4.2 व्ययों के अन्तर्गत प्रमुख व्ययों के अन्तर्गत

₹ करोड़ में

क्र.सं.	व्ययों के अन्तर्गत प्रमुख व्ययों के अन्तर्गत	अनुज्ञेय व्यय (₹ करोड़)	कुल व्यय (₹ करोड़)
1.	द्वार, प्रवेश द्वार, स्वागत द्वार, डिजाइनर गेट,	258	14.43
2.	बस्ती की चारदीवारी	139	13.41
3.	पार्किंग के विकास के लिए आरएमसी उपलब्ध कराना	54	3.71
4.	विभिन्न बस्तियों के चारदीवारों हेतु कँटीलेदार कुण्डलित तारों को उपलब्ध कराना एवं उन्हें जड़ना, और कँटीला घेरा लगाना।।	25	1.50
5.	बेंचें (उद्यानों के अतिरिक्त)	17	2.19
6.	व्यायामशाला	03	3.56
7.	वातानुकूलित बस (दिल्ली छावनी परिषद)	01	0.26
8.	आन्तरिक सड़कों एवं कालोनियों के पथों पर मास्टिक परत	82	21.70
9.	तालाबों, झील का विकास एवं पार्क में भामाशाह की प्रतिमा	06	1.18
10.	हाफ हाई मास्ट लाईट	41	1.65
	<b>कुल</b>	<b>626</b>	<b>63.59</b>

विविध श्रेणियों के जो द्वार निर्मित किए गए थे उनकी उपयोगिता तो अल्प थी, परन्तु उनका प्रचार एमएलए की प्रसिद्धि अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए ज्यादा था। दिशा-निर्देश में निर्दिष्ट स्थानों के लिए सेमी हाई मास्ट लाईट (एसएचएमएल)<sup>36</sup> और बेंचें<sup>37</sup> संस्वीकृत किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि एचएचएमएल साधारणतः प्रयुक्त स्ट्रीट लाईट की अपेक्षा दस गुना ज्यादा मंहगी है और साधारणतः प्रयुक्त स्ट्रीट लाईट की अपेक्षा दस गुना बिजली की खपत करती है। श.वि.वि. ने न तो सुरक्षा और भविष्य में अनुरक्षण के लिए और न ही किसी सिविक एजेंसी को उन्हें सौंपने का प्रबन्ध किया।

पिछले प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद श.वि.वि. ऐसे कार्यों को संस्वीकृति देता रहा।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि प्रवेश द्वारों, चारदीवारी को बनाना, पार्किंग भू-भाग में आरएमसी बिछाना इत्यादि सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत लिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कार्यों को अनुज्ञेय कार्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

#### 2-4-5-4 कृ.वि.वि. के कार्यों की संस्वीकृति, एच.वि.वि. के कार्यों की संस्वीकृति

श.वि.वि. ने विद्यमान संरचनाओं का विध्वंस करने के पश्चात 11 भवनों के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 4.95 करोड़ को शामिल करते हुए सिं. एवं बा.नि.वि. को बरात घरों, चौपालों एवं सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और/अथवा मरम्मत के लिए 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 10.86 करोड़ के 41<sup>38</sup> कार्यों को संस्वीकृत किया था। श.वि.वि. को यह सुनिश्चित करना था कि भूमि/परिसंपत्ति कार्यान्वयन एजेंसी के होने चाहिए या भूमि/परिसंपत्ति स्वामी की पूर्व अनुमति कार्य सौंपने के पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। यद्यपि उपरोक्त मामलों में, न तो भूमि सिं. एवं बा.नि.वि. की थी, न ही भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या विध्वंस हेतु भूस्वामी एजेंसियों की सहमति प्राप्त की गई।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि संस्वीकृतियाँ परियोजना के अनुरूप थीं जिन्हें केवल सरकारी/स्थानीय निकायों की भूमि पर कार्यान्वित की जानी थीं। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा अन्य औपचारिकताएँ जैसे कि भू-स्वामी विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. के पास कार्य की संस्वीकृति देने से पूर्व भू-स्वामी विभाग की सहमति सुनिश्चित होनी चाहिए।

#### 2-4-5-5 कृ.वि.वि. के कार्यों की संस्वीकृति, एच.वि.वि. के कार्यों की संस्वीकृति

(i) कृ.वि.वि. के कार्यों की संस्वीकृति दिशा-निर्देशों में अनुबंध है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य दिल्ली के नगर निगमों, लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। माँग को सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी के समक्ष सर्वप्रथम रखा जाएगा और यदि 10 दिनों के अन्दर कोई जवाब नहीं मिलता है तो डिस्कॉम्स को शुरू किए गए

<sup>36</sup>सरकार द्वारा विकसित सड़क के किनारे, फ्लाईओवर के समीप और अण्डरपासेस, स्टेडियम और गोल्फ मैदान, ट्रक व बस टर्मिनल, पार्किंग स्थल और मार्केट कॉम्प्लेक्स,

<sup>37</sup>सरकार द्वारा विकसित सड़क के किनारे, फ्लाईओवर के समीप और अण्डरपासेस, स्टेडियम और गोल्फ मैदान, ट्रक व बस टर्मिनल, पार्किंग स्थल और मार्केट कॉम्प्लेक्स,

<sup>38</sup>सिं. एवं बा.नि.वि. के द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार



कार्य को लेने के लिए कहा जाएगा और उसका भुगतान सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी को सूचित करते हुए सीधे डिस्कॉम्स को किया जाएगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा, हालाँकि, दर्शाती है कि श.वि.वि. ने 2009-14 के दौरान सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के माध्यम से माँग को बिना प्रकाश में लाए और बिना औपचारिक समझौता किए ही केवल संस्वीकृत पत्रों के माध्यम से सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए 133<sup>39</sup> कार्यों को सीधे डिस्कॉम्स को सौंप दिया था। श.वि.वि. ने भी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी को बिना सूचित किए ही डिस्कॉम्स को सीधे ₹ 23.86 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि प्रत्येक आकलन पर विशेषज्ञ तकनीकी समिति के द्वारा विधिवत् सुविचार किया गया था जिसमें सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी से भी एक सदस्य शामिल किया गया था। आगे यह भी कहा डिस्कॉम्स भू-स्वामी एजेंसी से अनुमति/अनापत्ति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देश सुस्पष्ट रूप से स्ट्रीट लाईट कार्य के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करता है एवं श.वि.वि. को कार्यों की संस्वीकृति से पूर्व सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अनुबंध के गैर-कार्यान्वयन एवं कम्पनियों के अग्रिम भुगतान पर उत्तर मौन है।

(ii) , pVh@, yVh rklack LFkukrj .%लेखापरीक्षा में डिस्कॉम्स को विद्युत लाईनों के स्थानांतरण के 58<sup>40</sup> कार्यों की सुपुर्दगी में वर्तमान नियमों व प्रक्रियाओं के उल्लंघन पाए गए :

- निर्माण कार्यों को बिना किसी औपचारिक समझौते या कार्यादेश के संस्वीकृति आदेशों के माध्यम से सौंपा गया।
- सा.वि.नि. का उल्लंघन करते हुए ₹ 13.34 करोड़ का अग्रिम भुगतान, उनके द्वारा तैयार किए गए अनुमान के आधार पर किया गया था जिसका समायोजन नहीं किया गया।
- डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत अनुमान डीएसआर पर आधारित नहीं थे, जैसा कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निर्धारित किया गया है।
- कार्यों के क्रियान्वयन में डिस्कॉम्स ने सा.वि.नि. में निर्धारित खुली निविदा के प्रावधानों का पालन नहीं किया जैसा कि संस्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट है।
- श.वि.वि. ने संस्वीकृत कार्यों का समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया, न ही यह सत्यापित किया कि ये कार्य अनुमोदित विनिर्दिष्टाओं के अनुसार पूर्ण किए गए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि डिस्कॉम्स ने प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दरों की सूची पर बजट प्राक्कलन को तैयार किया था, जैसा कि डीईआरसी के द्वारा अनुबंध किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट प्राक्कलन डीएसआर के अनुसार होना चाहिए जैसा कि योजना दिशा-निर्देशों में अनुबंधित है। इसके अतिरिक्त, श.वि.वि. ने आधिकारिक रूप से डिस्कॉम्स के पक्ष में इस शर्त की छूट नहीं दी थी। पैराग्राफ में उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में बताया नहीं गया।

<sup>39</sup>डिस्कॉम्स के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार

<sup>40</sup>डिस्कॉम्स के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार

(iii) **11/12/2009-14** स्कीम दिशा-निर्देशों में सरकारी भूमि पर 20 वर्षों से अधिक स्थायित्व वाले पोर्टा केबिनों की व्यवस्था की अनुमति है। 2009-14 की अवधि के दौरान, श.वि.वि. ने एनडीएमसी को विभिन्न स्थानों पर ₹ 2.75 करोड़ की लागत वाले 112 पोर्टा केबिनों के निर्माण की संस्वीकृति दी थी। श.वि.वि. के द्वारा किसी दस्तावेज की जाँच यह प्रमाणित करने के लिए नहीं की गई थी कि प्रस्तावित पोर्टा केबिनों का स्थायित्व 20 वर्षों से अधिक है। आरडब्ल्यू को पोर्टा केबिनों के आवंटन हेतु कसौटी का भी निर्धारण नहीं किया गया था एवं इन केबिनों को न तो सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया था न ही उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक रूप से आवंटित किया गया था।

अपने उत्तर में, एनडीएमसी ने कहा (मार्च 2015) कि पोर्टा केबिन संरचना एमएस स्टील से निर्मित की गई थी एवं एंगिल्स 20 वर्षों के लिए डिजाइन किए गए थे तथा आरडब्ल्यू को उनके उपयोग के लिए सौंप दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इनके स्थायित्व से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र अथवा दस्तावेज श.वि.वि. को नहीं सौंपा गया था और पोर्टा केबिनें उचित रूप से उपयोगकर्ताओं को आवंटित नहीं की गई थीं।

(iv) **11/12/2012-14** श.वि.वि. ने सामान्य वित्तीय नियम 159(1) का उल्लंघन करते हुए सीधे एक निजी कम्पनी को 2012-14 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 165 नवीकरण ऊर्जा सहायता प्राप्त पम्पों को उपलब्ध कराने एवं अधिष्ठापित करने हेतु ₹ 9.90 करोड़ अग्रिम के रूप में जारी किया था। हालाँकि, इसने यह सत्यापित नहीं किया कि विक्रेता ने पम्पों को अधिष्ठापित कर दिया है।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि पम्पों को अधिष्ठापित किया गया था एवं समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था। उत्तर से अभिपुष्टि होती है कि श.वि.वि. के पास निर्माण कार्यों के समापन को सत्यापित करने के लिए स्वयं का साधन नहीं था।

#### 2-4-6 **fuf/k izaku**

वर्षवार बजट परिव्यय तथा 2009-14 की अवधि के दौरान स्कीम के अंतर्गत श.वि.वि. द्वारा जारी की गई वास्तविक धनराशि **rkfydk 2-4-3** में दी गई है:

**rkfydk 2-4-3 %o"lkj ct V ifjQ ; rFkk okRfod t kjh dh /kujk' k**

(₹ **djMfeq**)

<b>o"lkj</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>dy</b>
अनुमोदित परिव्यय	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	980.00
संशोधित परिव्यय	198.00	140.00	280.00	330.00	280.00	1228.00
वास्तविक जारी राशि*	186.74	111.77	260.82	300.75	279.90	1139.98

स्रोत: अनुदानों की माँग तथा जैसा श.वि.वि. द्वारा प्रदान किया गया। \*वास्तविक व्यय पर सूचना श.वि.वि. के पास उपलब्ध नहीं थी।

### 2-4-6-1 , t fl ; k}kjk yf kadh i Lrf r dh fuxjkuh grqdkkZizkkyh u gluk

क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियाँ प्रति कार्य के आधार पर इस शर्त के साथ जारी की गई कि एजेंसी को किए गए निर्माण कार्य के विवरण सहित निर्वाचन क्षेत्रवार लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यद्यपि यह पाया गया कि श.वि.वि. के पास इन लेखों तथा कार्यों का विवरण तथा इन प्रतिवेदनों का आगे प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई सांस्थानिक प्रणाली नहीं थी।

### 2-4-6-2 , e, y, yM ; kt uk fuf/k k dks xj&Q i xeuh; cukus ea 'kfo-fo- dh vl Qyrk

स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम की निधियाँ गैर-व्यपगमनीय समझी जाएँ तथा एक वर्ष जारी न की गई धनराशि अगले वर्ष प्रयोग की जा सकती है। यद्यपि, श.वि.वि. ने स्कीम की निधियों को गैर-व्यपगमनीय बनाने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की, परिणाम स्वरूप जारी न किया गया बजट आबंटन एक वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जाता है। अगले वर्ष में बजट आबंटन 70 वि.स.स. की कुल वार्षिक पात्रता तक सीमित हो जाता है तथा पिछले वर्ष जारी न की गई निधियों के लिए कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जाता। वर्ष 2013-14 के दौरान, वि.स.स. ने ₹ 315.17 करोड़ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जबकि प्रस्ताव वि.स.स. की संचयी पात्रता के पूर्णतया अन्तर्गत था परंतु श.वि.वि. मात्र ₹ 279.90 करोड़ जारी कर सका क्योंकि उस वर्ष के बजट में ₹ 280 करोड़ मात्र का ही आबंटन था। इस प्रकार, 404 संस्वीकृत कार्यों हेतु ₹ 35.27 करोड़ की निधि जारी नहीं की जा सकी। 2009-14 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श.वि.वि. को ₹ 43.30 करोड़ वापिस किए गए जिसे श.वि.वि. द्वारा घटाएँ-वसूलियाँ शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया जिसमें से व्यय की अनुमति नहीं है। इस स्थिति से बचा जा सकता था यदि श.वि.वि. ने इस संबंध में एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया होता और वार्षिक बजट आबंटन और वापिस की गई धनराशि एक समर्पित बैंक खाते में स्थानांतरित करना प्रारंभ किया होता और इस स्कीम के सभी वित्तीय मामलों का प्रबंध इसी बैंक खाते के माध्यम से किया होता।

इसके उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) की जब और जैसे अधिक निधियों की आवश्यकता हो, वित्त विभाग तुरंत आवश्यक निधियाँ आबंटित कर देता था। यह उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

### 2-4-6-3 dk kZ; u , t fl ; k dks fuf/k k dks gLrk rj. k dh vi ; k r izkkyh

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्कीम की निधियाँ वेतन व लेखा कार्यालय द्वारा आरटीजीएस से कार्यान्वयन एजेंसियों के मुख्य बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। यद्यपि निधियों के निर्गमन का कोई कार्रवाई या एजेंसीवार आँकड़ा/अभिलेख नहीं रखा गया तथा निधियों के इन हस्तांतरण की कोई औपचारिक सूचना कार्यान्वयन एजेंसियों को श.वि.वि. द्वारा नहीं दी गई। कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी निधियों के कार्यवार तथा तिथिवार आंकड़ा/अभिलेख नहीं रखा क्योंकि श.वि.वि. ने उन्हें ये सूचनाएँ संप्रेषित नहीं की। श.वि.वि. में संस्वीकृत कार्यों की स्थिति, निर्गत निधियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त निधियों

के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। दि.न.नि. ने यह भी माना कि वर्तमान में इस बात से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि श.वि.वि. द्वारा जारी सभी निधियों को समुचित ढंग से उनके बैंक खाते में डाला गया और श.वि.वि. द्वारा प्रत्येक संस्वीकृत कार्य हेतु निधियाँ जारी कर दी गई हैं।

समापन सम्मेलन में श.वि.वि., दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. ने संस्वीकृत कार्यों, जारी की गई धनराशि तथा आवधिक समाधान के आंकड़ों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु एक समुचित प्रणाली निर्मित करने का आश्वासन दिया।

### 2-4-6-4 ढ; ढ; u , t ढ; ढ; dsikl vQ f; r fuf/k dsmi ; ढ; grqdkZizkyh u gkuk

श.वि.वि. के पास कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त निधियों के बारे में कोई सूचना नहीं थी। यद्यपि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सूचना ने दर्शाया कि 2009-14 के दौरान श.वि.वि. द्वारा जारी की गई निधियों में से 31 मार्च 2014 तक उनके पास ₹ 304.33<sup>41</sup> करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे, जिसके अतिरिक्त दि.न.नि. द्वारा बैंक ब्याज के रूप में ₹ 30.80 करोड़ अर्जित किया गया, जिसका विवरण ढ; dyk 2-4-4 में है।

### ढ; dyk 2-4-4% fQ; ढ; u , t ढ; ढ; dsikl vQ f; r vf/k ढ; dk foj. k

(₹ ढ; ढ;)

Ø-1 -	, t ढ; ढ;²	foosk/ku fuf/k k		vfuoK Zfuf/k ढ;	
		viz ä /kjk' k	vÆ r C; kt	viz ä /kjk' k	vÆ r C; kt
1	उत्तरी दि.न.नि.	54.23	10.46	5.94	3.02
2	दक्षिणी दि.न.नि.	92.40	8.32	14.06	3.51
3	पूर्वी दि.न.नि.	52.64	4.31	10.48	1.24
4	दि.ज.बो.	7.15	-	45.59	-
5	न.दि.न.पा.	7.76	-	4.00	-
6	दि.छा.बो.	2.20	-	2.19	-
7	डिस्कॉम	5.69	-	-	-
	<b>dy</b>	<b>222.07</b>	<b>23.09</b>	<b>82.26</b>	<b>7.71</b>

अव्ययित निधियों को अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था यदि श.वि.वि. ने कार्यों की समाप्ति के तुरंत बाद अप्रयुक्त निधियाँ वापिस प्राप्त करने की एक प्रणाली बनाई होती।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2014 तक ₹147.20<sup>43</sup> करोड़ दि.न.नि. के गैर-प्रचालनीय बैंक खाते

<sup>41</sup>इसमें चालू कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि सम्मिलित हो सकती थी।

<sup>42</sup>सि.बा.नि.वि. ने एम एल ए एल ए डी एस के लिए पृथक बैंक खाता नहीं रखा।

<sup>43</sup>न.दि.न.पा.— ₹ 52.86 करोड़, द.दि.न.नि.— ₹ 59.97 करोड़, पू.दि.न.नि.— ₹ 34.37 करोड़

(तीसरी विधान सभा के) में अनुत्पादक पड़े रहे। इसी प्रकार, दि.ज.बो. के पास भी ₹ 4.78 करोड़ अप्रयुक्त पड़े रहे।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

#### 2-4-6-5 Ldhe fuf/k kadh cdx grqfu/wZj r izkkyh dk ikyu u fd; k t kuk

स्कीम दिशा-निर्देश कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्येक वि.स.स. हेतु पृथक बैंक खाता खोलने की अपेक्षा करते हैं। यद्यपि दि.ज.बो., न.दि.न.पा. तथा डिस्कॉमों ने स्कीम के लिए पृथक बैंक खाते नहीं खोले और अपने प्रमुख बैंक खातों में निधियाँ प्राप्त की। यद्यपि दि.न.नि. ने पृथक बैंक खाते खोले परंतु श.वि.वि. उनके प्रमुख बैंक खातों में ही निधियाँ जारी कर रहा था। सिं. एवं बा.नि.वि. सरकारी खाते में स्कीम निधियाँ प्राप्त की तथा दि.कै.बो. ने एमएलएलैड योजना व एमपीलैड योजना हेतु एक बैंक खाता रखा था। किसी भी एजेंसी ने कार्यवार खाता लेखों का रखरखाव नहीं किया था।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को प्रत्येक वि.स.स. के लिए पृथक बैंक खाता खोलने हेतु एक परिपत्र जारी किया गया है।

#### 2-4-6-6 Q ; djus dh nkki wZi z kkyh

दि.न.नि. में एमएलएलैड योजना के कार्यों हेतु व्यय करने की प्रणाली पर किए गए अध्ययन से पता चला कि कार्य संबंधित विभागों द्वारा श.वि.वि. द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों के आधार पर यह तय किए बिना सौंप दिए जाते थे कि श.वि.वि. से उस कार्य विशेष के लिए निधियाँ दि.न.नि. के वित्त खण्ड को प्राप्त हो गई हैं। इसके अतिरिक्त कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को भुगतान हेतु निधियाँ वित्त खण्ड द्वारा संबंधित विभाग को उस कार्य विशेष के लिए निधि की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि किए बगैर जारी कर दी गई। उदाहरण के लिए सितम्बर से अक्टूबर 2013 के दौरान श.वि.व. ने ₹ 35.27 करोड़ के 404 कार्यों के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किए परंतु निधियाँ जारी नहीं की और ये सभी संस्वीकृतियाँ निरस्त कर दी (जून 2014)। इस बीच दि.न.नि. ने इन कार्यों में से 261 सौंप दिए और श.वि.वि. द्वारा अन्य कार्यों के लिए जारी की गई निधियों में से ठेकेदारों को ₹ 13.77 करोड़ का भुगतान किया।

दि.ज.बो. में एमएलएलैड योजना निधियों को दि.ज.बो. के वित्त खण्ड द्वारा संबंधित विभागों को अग्रिम में आबंटन किया जा रहा था, परंतु इन आबंटनों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का कोई भी विवरण संबंधित विभाग द्वारा वित्त खण्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद दि.न.नि. ने प्रक्रिया के सुधार का आश्वासन दिया।

#### 2-4-6-7 vfuoK Zfuf/k kdk vufpr <x l sizak o mi ; kx

मंत्रिपरिषद ने जून 2010 में अनुमोदन किया कि प्रत्येक वि.स.स. की स्कीम निधियों (उस समय प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष ₹ 2.00 करोड़ था) को दो भागों ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक को अनिवार्य निधि व विवेकाधीन निधि में बाँटा जाएगा। अनिवार्य निधि को सीधे दि.न.नि., न.दि.न.पा., तथा दि.छा.बो. को जारी किया जाना अपेक्षित था और इन एजेंसियों को वि.स.स. द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों के लिए संस्वीकृति आदेश जारी करना और श.वि.वि. को मासिक व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तदनंतर सितम्बर 2012 में मंत्रिमण्डल ने इस तथ्य

के बावजूद, कि 2009-10 से 2011-12 की अवधि में जल तथा स्वच्छता कार्यों की औसत माँग प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष मात्र ₹ 8.59 लाख थी, जल व स्वच्छता कार्यों हेतु दि.न.नि. के बजाय दि.ज.बो. को प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष मात्र ₹ 1.00 करोड़ की अनिवार्य निधि जारी करने का निर्णय लिया। न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. के लिए यह घटक वही रहा। तदनुसार श.वि.वि. ने 2010-12 के दौरान दि.न.नि. को ₹ 136 करोड़, दि.ज.बो. को 2012-14 के दौरान ₹ 136 करोड़ और न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. में से प्रत्येक को ₹ 4 करोड़ जारी किए गए। दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. ने चालू परिसंपत्तियों की नैतिक मरम्मत व रखरखाव के लिए इन निधियों का उपयोग किया। न.दि.न.पा. ने निधियों का उपयोग नहीं किया और दि.छा.बो. ने इसका उपयोग अननुमन्य माल मदों को प्राप्त करने हेतु किया, जैसे कि बस, वातानुकूलित्र, ई-टायलेट, ट्रैक्टर, व्यायामशाला उपकरण, इत्यादि, जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति आदेशों के अनुसार एजेंसियों को स्कीम निधियों के अनिवार्य अंश के लिए प्रत्येक सदस्य हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलना अपेक्षित था और अनिवार्य निधियों को विवेकाधीन निधियों के खातों के साथ मिलाया नहीं जाना था। यद्यपि केवल दि.न.नि. ने इन आदेशों का अनुपालन किया। हालाँकि, दि.ज.बो. व न.दि.न.पा. ने इन निधियों को अपने सामान्य खाते में जमा किया, परन्तु दि.ज.बो. ने इन निधियों को विवेकाधीन निधियों के साथ मिला दिया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि कार्यान्वयन एजेंसियाँ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर प्रस्तुत करेंगी। तथापि अब तक दि.ज.बो. तथा दि.न.नि. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2015)।

#### 2-4-7 दि.न.नि. ; दि.ज.बो. ; न.दि.न.पा. के निर्माण कार्यों के निष्पादन में पायी गई अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

2009-14 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कुल 10821 निर्माण कार्यों में से लेखापरीक्षा ने सिं. एवं बा.नि.वि., दि.न.नि., दि.ज.बो. एवं न.दि.न.पा. के 59 मण्डलों में 933<sup>44</sup> निर्माण कार्यों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा में निर्माण कार्यों के निष्पादन में पायी गई अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) दि.न.नि. ; स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यय संस्वीकृत राशि से कदापि अधिक नहीं होना चाहिए। कार्यों के लिए श.वि.वि. के द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियाँ इस शर्त के साथ थीं कि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिना अनुमोदन के निधियों को एक कार्य से दूसरे कार्य में लगाया नहीं जाएगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के अनुसार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड ने शहरी विकास विभाग के बिना पूर्व अनुमोदन के 23 निर्माण कार्यों<sup>45</sup> में संस्वीकृत की गई राशि से ₹ 69.41 लाख के आधिक्य का व्यय किया था।

अपने उत्तर में, दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2015) कि आधिक्य की राशि का भुगतान अपने निजी संसाधनों से किया था। हालाँकि, उत्तर सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि दि.ज.बो. ने एमएलएलैड के लिए अलग खाता नहीं तैयार किया था।

<sup>44</sup>सिं. एवं बा.नि.वि.—232, दि.न.नि.—633, दि.ज.बो.—50 एवं नई दि.न.पा.—20

<sup>45</sup>दि.ज.बो.—10 निर्माण कार्यों के लिए ₹19.74 लाख एवं सिं. एवं बा.नि.वि.—13 कार्यों के लिए ₹ 69.40 लाख

(ii) **l 1oh-r fuelZk dk k& dks jI@ca djuk%** योजना दिशा-निर्देशों में श.वि.वि. के बिना अनुमोदन के संस्वीकृत कार्यों को रद्द/बंद करने के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, सिं. एवं बा.नि.वि. तथा दि.ज.बो. ने ₹ 33.17 करोड़ के 422 कार्यों को सौंपने के पश्चात् या तो प्रारम्भ नहीं किया अथवा बंद नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। इन कार्यों के लिए स्वीकृत निधियाँ एजेंसियों के पास पड़ी थीं।

अपने उत्तर में, सिं. एवं बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2015) कि कार्यों को अतिक्रमण, अदालती मामलों के कारण एवं एमएलए के अनुरोध पर बंद अथवा रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, सिं. एवं बा.नि.वि. ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्यों इन कार्यों को बन्द/रद्द करने से पूर्व श.वि.वि. की अनुमति प्राप्त नहीं हो पायी थी।

(iii) **fuelZk dk k& ds l eki u ea gqZ njl%** योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षित है कि श.वि.वि. के द्वारा निधियों के जारी होने के पश्चात् 60 दिनों की अवधि के अन्दर स्थापित प्रक्रिया एवं निर्णय कार्य आदेश के अनुसार सभी प्रारंभिक कदमों को उठाएँ। सिं.एवं बा.नि.वि., दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि 753 कार्यों को श.वि.वि. से संस्वीकृतियों की प्राप्ति के 62 से 804 दिनों के पश्चात् सौंपा गया। यह भी पाया गया कि सितम्बर 2014 तक 1049 निर्माण कार्यों को देरी से पूर्ण किया गया अथवा 60 महीनों की रेंज में विलंब से चल रहे थे। श.वि.वि. ने यद्यपि कार्यों को समाप्त करने में हुई देरी से बचने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की बावजूद कि पिछले प्रतिवेदन में इसे इंगित किया गया था।

अपने उत्तर में कार्यान्वयन एजेंसियों ने कहा (मार्च 2015) कि प्राशासनिक कारणों, भू-स्वामी एजेंसियों से अनुमति न मिलना, बाधाओं, विवाद एवं अदालती मामलों इत्यादि के कारण देरी हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि कार्यान्वयन एजेंसियाँ कार्य को सौंपने से पूर्व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियाँ करें।

(iv) **fufonkvl& dks vlef-r fd, fcuk dk k& dks l k& uk%** दि.न.नि. के आदेशों के अनुसार, ₹ 5.00 लाख तक की लागत के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्य को बिना निविदा आमंत्रित किए इकाई दर विधि (इ.द.वि.) पर सौंपा जा सकता है। हालाँकि, यह पाया गया कि ₹ 13.83 करोड़ के 322 निर्माण कार्यों को गलियों में रेडी मिक्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट खड़जा बिछाने तथा नालियों के विकास के लिए इकाई दर विधि के माध्यम से सौंपा गया था लेकिन इन निर्माण कार्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के मानने का कोई प्रमाण अथवा औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया था।

दि.न.नि. ने सूचित किया (मार्च 2015) कि इकाई दर विधि प्रणाली समीक्षा के अन्तर्गत थी एवं केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में इ.द.वि. के प्रयोग के लिए आवश्यक निर्देश दिये गए थे।

(v) **fuelZk dk k& dk vi/f/k-r fu'iknu%** अप्राधिकृत कालोनियों में जहाँ स्कीम निर्माण कार्य अनुज्ञप्त नहीं थे, सिं. एवं बा.नि.वि. के द्वारा ₹ 58.71 लाख के पाँच निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया था।

अपने उत्तर में, सिं. एवं बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2015) कि निर्माण कार्य अप्राधिकृत नियमित कॉलोनी में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कॉलोनियों को सरकार के द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

(vi) **राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के कार्य, स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं।** हालाँकि, नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकारी भवन परिसरों जैसे कि सीजीएचएस औषधालय, तीन मूर्ति एवं अशोक पुलिस लाइन्स, और पी एण्ड टी कालोनी में ₹ 3.24 करोड़ के निर्माण कार्यों को निष्पादित किया। इसके उत्तर में न.दि.न.पा. ने बताया (मार्च 2015) कि कार्यों को सरकारी भवन के सामान्य क्षेत्र में क्रियान्वित किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट कार्यों को केन्द्र सरकार के कार्यालय परिसरों में क्रियान्वित किया गया।

आगे यह देखा गया कि लक्ष्मीबाई नगर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी का कार्य क्षेत्र के वि.स.स. की सिफारिश पर जून 2013 में ₹ 45.54 लाख पर संस्वीकृत किया गया, परन्तु कार्य को चौथी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान नहीं सौंपा गया। स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मामले में कार्यों को क्षेत्र के नए वि.स.स. की सहमति से ही सौंपा जाना अपेक्षित था। यद्यपि, न.दि.न.पा. ने इन कार्यों को मार्च 2014 में नए वि.स.स. की सहमति माँगे बगैर सौंप दिया।

श.वि.वि.ने कहा कि वर्तमान एमएलए की स्वीकृति संभव नहीं थी क्योंकि 5वीं विधानसभा निलंबित थी तथा राष्ट्रपति शासन लागू था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विशिष्ट आदेश जारी किए गए थे जिसमें एमएलए को 5वीं विधान सभा के निलंबन की अवस्था में भी एमएलएलैड योजना का अपने विवेकाधिकार से प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी।

## 2-4-8 **आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों व विनियमों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का पर्याप्त आश्वासन प्रदान करता है।**

प्रतिवेदन में इंगित किए जा चुके मामलों के अलावा आंतरिक नियंत्रण में निम्न कमियाँ पाई गईं :

### 2-4-8-1 **दिल्ली विधानसभा (द्वितीय विधानसभा) की लोक लेखा समिति ने अपनी नौवीं प्रतिवेदन में सिफारिश की श.वि.वि. को एक प्रणाली का सृजन करना चाहिए जिससे अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित हो तथा उन्हें जब और जहाँ लागू हो लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाए।**

लो.ले.स. से निर्देशों के बावजूद श.वि.वि. ने स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों तथा जारी निधियों के आगत-निर्गत आंकड़ों को दर्ज करने के व्यवस्थित रखरखाव हेतु प्रणाली निर्मित नहीं की। श.वि.वि. वि.स.स. से प्रस्तावों की प्राप्ति की तिथियाँ दर्ज करने की रजिस्टर, आदेश संख्या तथा तिथि कार्य तथा निर्गत निधियों (एजेंसी तथा तिथि के क्रम से) का विवरण जैसे मूलभूत अभिलेख भी प्रदान नहीं कर पाया जो स्कीम के क्रियान्वयन के प्रति असंवेदनशील रवैया तथा विधानसभा की उपेक्षा को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त श.वि.वि. ने न तो स्कीम के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्ति हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया, न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसा करने को कहा। स्कीम निधियों से अधिप्राप्त मदों



हेतु स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2014) कि वि.स.स. वार सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी एजेंसियाँ परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव कर रही हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग की वेबसाइट पर केवल संस्वीकृति की प्रतियाँ ही अपलोड की गई हैं जबकि आंकड़ा/अभिलेख का श.वि.वि. द्वारा व्यवस्थित ढंग से रखरखाव होना चाहिए था। जहाँ तक परिसंपत्ति रजिस्टर की बात है, क्षेत्र दौरों में पाया गया कि कोई भी एजेंसी परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं कर रही थी।

### 2-4-8-2 यक्षि जह्लक गुरगि रक्यह दक वह्लो

यद्यपि संस्वीकृति आदेशों हेतु सा.वि.नि. के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे, उपयोग प्रमाण पत्र, तथा व्यय विवरण लेखापरीक्षा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। श.वि.वि. ने स्कीम निधियों व उ.प्र. की प्रस्तुति हेतु कोई एजेंसी या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की।

सरकार ने कहा (फरवरी-2015) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है और वार्षिक आधार पर अलग से स्कीम की लेखापरीक्षा कराए जाने के मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. लेखापरीक्षा निदेशालय के साथ लिया जा रहा है।

### 2-4-8-3 फुखजुह इ रक्यह

योजना के अन्तर्गत परियोजनाएँ शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं। हालाँकि, कोई संस्थावार प्रणाली परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए श.वि.वि. में स्थापित नहीं पायी गई जैसा कि नीचे वर्णित है:

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श.वि.वि. को अपेक्षित तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति की निगरानी तथा इसे सुनिश्चित करने तथा जैसा कि स्कीम दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित है, उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई गई।
- श.वि.वि. द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा कि संस्वीकृति पत्रों में विनिर्दिष्ट है।
- श.वि.वि. ने कार्यान्वयन एजेंसियों से क्रियान्वित कार्यों का विवरण तथा कार्यों की संतोषजनक ढंग से पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र कभी प्राप्त नहीं किया जैसा कि संस्वीकृतियों में विनिर्धारित है। ऐसे मामले पाए गए जिनमें कई संस्वीकृत कार्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अभिलेख दर्ज नहीं किया गया था। दि.न.नि. ने यह भी पुष्टि की कि कोई आश्वासन प्राप्त नहीं था कि प्रत्येक संस्वीकृत कार्य उनके द्वारा क्रियान्वयन के लिए लिया ही गया हो और किसी संस्वीकृत कार्य को चिह्नित किए बिना नहीं छोड़ा गया।

इस प्रकार, श.वि.वि. में योजना के लिये कोई निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था। स्कीम के क्रियान्वयन की अपर्याप्त निगरानी के संबंध में मामला भी पिछले प्रतिवेदन में उठाया गया। यद्यपि, श.वि.वि. ने निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों की समुचित निगरानी की जाती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उठाए गए मुद्दों में से किसी की भी चर्चा नहीं करता है।

## 2-4-9 I koZ fud I puk izkkyh

### 2-4-9-1 vi wZl koZ fud I puk izkkyh

केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेशों के अनुसार, श.वि.वि. एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत और निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि श.वि.वि. ने सूचना अपलोड करने के लिये अपनी वेबसाइट अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों की वेबसाइट पर किसी प्रारूप को निर्धारित नहीं किया। श.वि.वि. अपनी वेबसाइट पर केवल संस्वीकृत आदेशों की प्रति अपलोड कर रहा था। यद्यपि, दि.न.नि. और दि.ज.बो. ने अपनी वेबसाइटों पर कुछ विवरण अपलोड किए, सार्वजनिक हित के लिये महत्वपूर्ण जानकारी को अपलोड नहीं किया गया था जैसे कि संस्वीकृत आदेशों की संख्या, संविदागत राशि और कार्य के समापन की निर्धारित तिथि।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि वह अपनी वेबसाइट पर संस्वीकृत कार्यों की सूचना को नियमित रूप से अपलोड कर रहा था। कार्यान्वयन एजेंसी से भी कहा जा चुका है कि वे अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से सूचना का अद्यतन करें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल श.वि.वि. ने अपनी वेबसाइट पर संस्वीकृतियों की प्रति अपलोड की थी।

### 2-4-9-2 ddkh I puk vk kx ds vns'kd dh xj&vuq kyuk

शिकायतों का निपटान करते समय, मुख्य सूचना आयोग (मु.सू.आ.) ने रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था (फरवरी 2011), जिसमें एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत संबंधित विधानसभा सदस्यों द्वारा व्यय का ब्यौरेवार वर्णन हो और बोर्ड पर भी विभाग की वेबसाइट के पेज से सही लिंक/यू.आर.एल का उल्लेख हो, जहाँ पर सूचना देखी जा सके। बोर्ड पर पूर्व वर्ष के समापन के छः माह के अन्दर सूचना का प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाना था। श.वि.वि. ने इस कार्य को सिर्फ 2009-11 की अवधि के लिये ₹ 86.80 लाख की लागत पर जनवरी 2012 में पूरा किया। हालाँकि, इन बोर्डों पर 2011-14 की अवधि के लिये व्यय का विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया था और वेबसाइट के पेज के लिये कोई लिंक/यू.आर.एल उल्लिखित नहीं था। वास्तव में, श.वि.वि. की वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई पेज उपलब्ध नहीं था। 32 मामलों में, व्यय का विवरण निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर के स्थानों में प्रदर्शित किया गया था।

अपने उत्तर में, श.वि.वि. ने कहा (फरवरी 2015) कि मु.सू.आ. के आदेश का पालन किया जाएगा।

## 2-4-10 fu"d"K

श.वि.वि. ने अपनी भूमिका को किसी भी कार्यों के लिए केवल संस्वीकृति एवं निधियों के जारी करने तक सीमित रखा, जो कोई कार्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा सिफारिश किया जाता था। सिफारिश किये गये कार्यों की स्वीकार्यता के संबंध में श.वि.वि. में प्रस्तावों की संवीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य निर्माण कार्यों की संस्वीकृति पर कोई जाँच नहीं की गई थी। योजना की शुरुआत नई स्थायी परिसंपत्तियों और अवसंरचना के सृजन के लिये की गयी थी, लेकिन 60 प्रतिशत निधियाँ चालू परिसम्पत्तियों की मरम्मत व रखरखाव के लिए उपयोग की गई जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था। निधि प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास अव्ययित राशि व्यर्थ पड़ी हुई थी। यद्यपि योजना दिशा निर्देशों में योजना निधियों के व्ययगत न होने का उल्लेख है, योजना निधियों पर विचार करने एवं उसे गैर-व्ययगमनीय बनाने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, एक वित्तीय वर्ष की अप्रयुक्त निधियाँ आगामी वर्षों में योजना के लिए उपलब्ध नहीं थीं। निधियाँ जारी होने के पश्चात, श.वि.वि. और कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। यहाँ यह जानने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि क्या श.वि.वि. के द्वारा समस्त संस्वीकृत निर्माण कार्यों को निष्पादन के लिए ले लिया गया है तथा पूरा कर दिया गया है। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर निगरानी के लिए निगरानी तंत्र नहीं था।

## 2-4-11 fl Qkfj 'k

सरकार को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

- (i) एमपीलैड योजना के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर स्कीम दिशानिर्देशों की समीक्षा करना।
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के अंतर्गत कार्यों के चयन से सरकार की विकास प्राथमिकताओं का हल होता हो, साथ ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
- (iii) निधि प्रबंधन में सुधार, निधियों को गैर-व्ययगमनीय बनाने की प्रणाली का निर्माण तथा स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को बाद में रखरखाव प्रयोक्ता एजेंसियों को सौंपना, और
- (iv) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी मूलभूत अभिलेखों के रखरखाव, स्कीम निधियों की लेखापरीक्षा तथा उ.प्र. की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु एम.आई.एस. की स्थापना द्वारा श.वि.वि. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

## 'kgjh fodkl ea-ky;

### 2-5 l QlbZQ oLFkk rFkk LoPNrk l okvldh dk Zzkkyh

रा.रा.क्षे.दि.स. सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता सेवाओं की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत सफाई के स्तरों के सुधार हेतु पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने हेतु दिल्ली के नगर निगमों (दि.न.नि.) को निधि प्रदान करती है। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नोक्त है:

#### विशिष्टताएं

- दि.न.नि. में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त किए जाने वाले स्वच्छता सेवाओं के नियत लक्ष्यों के साथ कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाएँ भी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।  
(पैराग्राफ 2.5.2)
- 2013-14 के दौरान कचरे के प्रभावी एकत्रीकरण व पृथक्करण हेतु दि.न.नि. की उपलब्धि मात्र 17.44 तथा 25.30 प्रतिशत थी।  
(पैराग्राफ 2.5.3.2 एवं 2.5.3.3)
- 2013-14 के दौरान मात्र 41 प्रतिशत कचरे का तथा 47 प्रतिशत निर्माण व विध्वंस अवशिष्ट का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि बाकी कचरा भराव क्षेत्रों में डाल दिया गया।  
(पैराग्राफ 2.5.3.6 (i) एवं (ii))
- दि.वि.प्रा. द्वारा, क.म.क्षे. के लिए 600 एकड़ की भूमि की आवश्यकता के प्रति केवल 324.60 एकड़ भूमि ही आबंटित की गई थी जिसमें से 150 एकड़ भूमि ही क.म.क्षे. के लिए उपयुक्त थी।  
(पैराग्राफ 2.5.3.6 (iv))
- लगभग ₹22.96 करोड़ के 567 निर्जल मूत्रालयों के निर्माण के बावजूद दि.न.नि. साधारण जनता को गुणवत्तापूर्ण शौच सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहे।  
(पैराग्राफ 2.5.3.10)
- दि.न.नि. में इनके दिन प्रतिदिन स्वच्छता क्रियाकलापों जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालों की गाद साफ किया जाना, शौचालयों की सफाई, इत्यादि की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।  
(पैराग्राफ 2.5.7. (i))

### 2-5-1 iZrkouk

‘सफाई व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं का यंत्रीकरण’ (स्वास्थ्य सेवाएँ) रा.रा.क्षे.दि.स. का योजनागत शीर्ष है जिसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) तथा न.दि.न.प. को स्वच्छता स्तरों की पुनर्व्यवस्था के सुधार द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने, कचरे की सफाई, एकत्रण, परिवहन तथा निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को

न्यून करना, इत्यादि क्रियाकलापों हेतु निधि प्रदान करती है। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन करीब 7172 टन कचरा पैदा होता है। दिल्ली कैण्टोनमेन्ट बोर्ड, मछली बाजारों, सब्जी मण्डियों, बूचड़खानों, इत्यादि से कचरे को सीधे भराव क्षेत्र (क.भ.क्षे.) में पहुँचाया जाता है। दि.नि.न. क्षेत्रों से घरेलू कचरे को पहले 3204<sup>46</sup> ढलावों<sup>47</sup> और मुक्त क्षेत्रों में एकत्र करने के बाद उसे क.भ.क्षे. या प्रसंस्करण संयंत्रों को पहुँचाया जाता है। दिल्ली में मात्र चार कचरा प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनकी कुल दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 2929 टन है। कचरे के साथ-साथ दिल्ली में 2773 टन निर्माण व विध्वंस अवशेष (सी एण्ड डी वेस्ट) व 664 टन गाद दैनिक रूप से उत्पन्न होता है, बुरारी के एक प्रसंस्करण संयंत्र में 1290 टन प्रसंस्करण किया जाता है तथा बाकी क.भ.क्षे. में डाल दिया जाता है।

### 2-5-1-1 लक्षित क्षेत्र

शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.), जिसका अध्यक्ष सचिव होता है, दि.न.नि. का प्रशासकीय विभाग है। उत्तरी दि.न.नि. की स्वच्छता शाखा का अध्यक्ष प्रमुख निदेशक (स्वच्छता) होता है जिसकी सहायता मुख्य अभियंता (डीईएमएस) तथा निरीक्षक अभियंता (डीईएमएस तथा ऑटो), करते हैं दक्षिण व पूर्वी निगमों में, स्वच्छता शाखा का अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त होता है। सभी तीन क्षेत्रों में उपायुक्त अपने संबंधित क्षेत्रों के अध्यक्ष होते हैं और उनकी सहायता स्वच्छता अधीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व अन्य स्वच्छता स्टाफ करते हैं।

### 2-5-1-2 लक्षित क्षेत्र:

लेखापरीक्षा के मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- स्वच्छता सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वार्षिक योजनाएँ समयसीमा के साथ बनाई गई थी,
- स्वच्छता सेवाओं के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन व प्रबंधन संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी थे,
- संसाधन (वित्त, श्रम शक्ति एवं यंत्र) का दक्षतापूर्वक, प्रभावी रूप से व इष्टतम उपयोग किया गया था, तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्ष व प्रभावी थी।

### 2-5-1-3 लक्षित क्षेत्रों के लिए 2009-14 की अवधि को सम्मिलित करते हुए फरवरी से सितम्बर 2014 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा संपन्न की गई।

2009-14 की अवधि को सम्मिलित करते हुए फरवरी से सितम्बर 2014 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा संपन्न की गई। ठोस अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर तीन नगर निगम, चार क्षेत्रों<sup>48</sup> तथा उनके अंतर्गत विभागों के चयनित अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, आटो डिवीजनों व कचरा भराव क्षेत्रों (क.भ.क्षे.) के अभिलेखों को भी जाँचा गया। दि.न.नि. द्वारा प्रदान की जा रही स्वच्छता सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक धारणा का निर्धारण करने के लिए चयनित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत आ.क.स. के बीच एक सर्वेक्षण किया गया। आ.क.स. का चयन, बदलाव के बिना सरल यादृच्छिक नमूना के माध्यम से किया गया।

<sup>46</sup> न.दि.न.प. क्षेत्र के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि विवरण उपलब्ध नहीं थे

<sup>47</sup> कचरे हेतु अस्थायी भंडारण

<sup>48</sup> उत्तरी दि.न.नि. के रोहिणी क्षेत्र, दक्षिणी दि.न.नि. के मध्य क्षेत्र एवं पूर्वी दि.न.नि. के उत्तरी शाहदरा व शाहदरा दक्षिण क्षेत्र

न.दि.न.प. को आरंभ में पी.ए. में सम्मिलित किया गया परन्तु उन्होंने अध्यक्ष के स्तर पर सशक्त अनुपालन के बावजूद किसी भी लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया। इसलिए न.दि.न.प. को इस लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया जा सका।

निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, लक्ष्यों और कार्यविधि पर प्रवेश सम्मेलन, आयुक्त (उत्तरी दि.न.नि.), मुख्य अभियंता (दक्षिण दि.न.नि.) और अवर आयुक्त (पूर्वी दि.न.नि.) के साथ किए गए (29 मई तथा 25 और 26 जून 2014)। ड्राफ्ट प्रतिवेदन सरकार को जनवरी 2015 को भेजा गया और इस पर अवर सचिव, श.वि.वि. और दि.न.नि. के अधिकारियों के साथ समाप्ति सम्मेलन में चर्चा की गई। समाप्ति सम्मेलन (4 मार्च 2015) में सरकार के विचारों को व्यक्त किया गया तथा प्राप्त किया गया, तदन्तर उन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

#### 2-5-1-4 यक्षिण्णक एकुन. M

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न थे:

- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 व नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निर्वहन) नियमावली, 2000
- भा.स. के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बेंचमार्क की नियम पुस्तिका, तथा
- सामान्य वित्तीय नियमावली, समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश तथा निर्देश।

#### यक्षिण्णक फु"द"ळ

#### 2-5-2 फु; क्त उ

स्वच्छता सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यह बाध्यकारी है कि प्रत्येक घटक के अन्तर्गत दीर्घावधि लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु गतिविधियों के विवरण के साथ एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाए। यह परिप्रेक्ष्य योजना सम्पूर्ण लक्ष्यों को योजनाबद्ध ढंग से प्राप्त करने हेतु पुनः क्रियान्वयन योग्य योजनाओं व लक्ष्यों में विभाजित की जाती है।

यद्यपि ऐसी कोई परिप्रेक्ष्य योजना तीन भागों में विभाजन किए जाने से पूर्व दि.न.नि. द्वारा न ही 2012 में विभाजन होने के बाद तीनों में से किसी भी दि.न.नि. द्वारा बनाई गई। फिर भी दि.न.नि. एक नैतिक कार्य की भांति शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) को वार्षिक योजनाएँ प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रस्तावित निधि वास्तविक निर्धारण पर आधारित नहीं थी क्योंकि समेकित वार्षिक आवश्यकता निकालने हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु आवश्यक निधि क्षेत्रीय शाखाओं से एकत्रित नहीं की गई थी। पू.दि.न.नि. में श.वि.वि. को इसकी वार्षिक योजनाओं के रूप में मात्र गतिविधियों की सूची व उनके लिए आवश्यक निधियों को निधियों की प्रस्तावित आवश्यकता के लिए प्राप्त किए जाने वाले किन्हीं भौतिक लक्ष्यों की वचनबद्धता के बिना वार्षिक तौर पर भेजा गया था।

उत्तरी व पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) की उन्होंने वर्ष 2004 में सी.ओ.डब्ल्यू. आई. द्वारा एक कार्ययोजना तैयार कराई तथा उस पर कार्यवाही वर्ष 2012 में दि.न.नि. के तीन खण्डों में विभाजन होने तक चल रही थी। उत्तरी दि.न.नि. ने आगे यह बताया कि दिल्ली के पर्यावरण सुधार हेतु उत्तरी निगम कार्य योजना प्रक्रियाधीन थी जबकि पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि भौतिक लक्ष्यों के विवरण के साथ वार्षिक योजनाएँ तैयार कर ली गई थीं। यह

उत्तर इस तथ्य को दर्शाता है कि दि.न.नि. द्वारा दीर्घावधि योजनाएँ नहीं बनाई गई थीं। पूर्वी दि.न.नि. का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक योजनाओं में मात्र निधि आवश्यकताएँ थीं, जो नियोजन व निर्धारण की वास्तविक प्रक्रिया पर आधारित नहीं थी।

### 2-5-3 LoPNrk l okvkd fØ; kb; u

2009-14 की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ-साथ दि.न.नि. में योजना विभाग की वार्षिक योजनाओं में स्वच्छता सेवाओं के प्रमुख घटक<sup>49</sup> सम्मिलित थे। अधिकतर घटकों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया गया था जिससे स्वच्छता स्तर में सुधार होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मुख्यतः ठोस अपशिष्ट अर्थात् घरेलू व अन्य कचरा, नालों की गाद व निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट का एकत्रण, परिवहन तथा निपटान सम्मिलित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पाई गई कमियों पर आने वाले पैराग्राफो में चर्चा की गई है:

#### 2-5-3-1 LoPNrk l okvkd fØ; kb; u

स्वच्छता सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य स्वच्छता स्तरों के सुधार द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाना था। तथापि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार को किस प्रकार मापा जाए इसके लिए वहाँ कोई मानदण्ड/बेंचमार्क नहीं था।

इसके उत्तर में दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि स्वच्छता सेवाओं के क्रियान्वयन जैसे कचरा एकत्रण व परिवहन के कारण स्वच्छता स्तरों में सुधार हुआ। इस उत्तर में सुधार को मापने हेतु बेंचमार्क व प्रणाली न होने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

#### 2-5-3-2 viHhoh dMk , d=.k

नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व निर्वहन) नियमावली, 2000 (एम. एस. डब्ल्यू. नियमावली) की अनुसूची II के अनुसार दि.न.नि. को सामुदायिक कूड़ादान एकत्रण या घर-घर एकत्रीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को एकत्र करना है। वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के मात्र दो क्षेत्रों (रोहिणी व सिविल लाइन्स) में ही घर-घर से कूड़ा एकत्र किया जाता है। जबकि सभी तीन दि.न.नि. में तंग गलियों तथा सड़कों से कूड़ा एकत्र करने हेतु उलटाऊ गाड़ियाँ (छोटे वाहन) तैनात की गई, जो कूड़ा घर-घर जाकर एकत्र नहीं कर रही थी।

इस प्रकार, दिल्ली में प्रतिदिन पैदा होने वाले 7172 टन कचरे में से मात्र 1251 टन (17.44 प्रतिशत) ही रोहिणी तथा सिविल लाईन क्षेत्रों से प्रभावी ढंग से एकत्र किया जा रहा था।

जबाब में, उत्तरी और पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि दि.न.नि. अधिनियम में कचरे को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए केवल पात्र, कचरेदान आदि के प्रावधान की आवश्यकता है। पूर्वी दि.न.नि. ने आगे कहा कि इकपहिया टेला, साईकिल रिक्शा आदि को घरों/सड़कों से कचरा एकत्र करने के लिए नियुक्त किया गया था। दक्षिण दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि अनौपचारिक सैक्टरों से घर-घर कचरा एकत्र किया जाता था। उत्तर दर्शाता है कि एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के कार्यान्वयन को उचित प्राथमिकता के अनुसार नहीं अपनाया गया था।

<sup>49</sup> (i) 'कूड़ा-कचरा रहित समाज' की उन्नति सहित स्वच्छता स्तरों के सुधार से पर्यावरणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, (ii) कचरे की सफाई, एकत्रण, परिवहन तथा निपटान, (iii) नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निर्वहन) नियमावली 2000 (एमएसडब्ल्यू नियमावली) तथा प्लास्टिक बिल, (iv) ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को न्यून करना, (v) प्रबोध कार्यक्रम करने में सामुदायिक व सार्वजनिक भागीदारी तथा निजी उद्यमियों व गै.स.सं. की भागीदारी, तथा (vi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन।

### 2-5-3-3 दमडक i FkDj. k u fd; k t kuk

एमएसडब्ल्यू नियमावली की अनुसूची II की शर्तों के अनुसार कचरा भराव अजैविक कूड़े के अपघटन, अवस्थित अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट पर रोक लगाएगा जो न तो पुनः चक्रण और न ही जैविक प्रक्रिया हेतु उपयुक्त है। इस दिशा में पहला कदम यह है जैविक कूड़े के अपघटन, पुनः प्रयोग योग्य/पुनः चक्रण योग्य में कूड़े का पृथक्करण विभिन्न घटकों के पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, शोधन तथा वैज्ञानिक निपटान को समर्थ बनाना।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2013-14 के दौरान कूड़े का पृथक्करण उत्तरी दि.न.नि. में 57 प्रतिशत तथा दक्षिणी दि.न.नि. में 17 प्रतिशत था। पूर्वी दि.न.नि. व अन्य एजेंसियों जैसे न.दि.न.प., दिल्ली कैण्टोनमेंट बोर्ड, इत्यादि में कचरा पृथक्करण नहीं हुआ। 2013-14 में सृजित किए गए कुल 26.18 लाख टन के कुल कचरे में से मात्र 6.62 लाख टन (25.3 प्रतिशत) को ही जैविक व अन्य श्रेणियों में पृथक किया गया। अपृथक कचरे को डम्प करना प्रभावी ठोस कचरा प्रबंध के लिए हानिकारक है क्योंकि पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण योग्य कचरे को भी, क.भ.क्षे. में डाल दिया जाता है। भराव क्षेत्रों में जैविक कूड़े के अपघटन से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा ग्रीनहाऊस गैसों भी उत्पादित होती हैं।

अपने उत्तर में, उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि 90 प्रतिशत कचरा उनके द्वारा तैनात छूट ग्राहियों द्वारा पृथक किया जाता है तथा शेष को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पृथक किया जाता है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं जो यह दर्शाये कि 57 प्रतिशत से अधिक कचरे का पृथक्करण हुआ है। दक्षिण और पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि ज्यादातर पृथक्करण अनौपचारिक सैक्टरों द्वारा ही किया गया था। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र भी दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो पूर्वी दि.न.नि. से प्रतिदिन 1300 टन कचरा प्राप्त करेगा। तथ्य यह है कि पृथक्करण का वर्तमान स्तर आवश्यक स्तर से कहीं नीचे है।

### 2-5-3-4 eä Hk Mj. k l fo/kk ;

एमएसडब्ल्यू नियमों के अनुसार, अस्थायी भण्डारण सुविधाओं से आसपास अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा होने से बचने हेतु इन्हें इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि इनमें भण्डारित अपशिष्ट मुक्त वातावरण में खुला न रहे। दि.न.नि. द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की जाँच से देखा गया कचरा एकत्रण के पहले चरण हेतु प्रयोग में लाई जा रही 3204 भण्डारण सुविधाओं में से 499 (15 प्रतिशत) मुक्त क्षेत्र थे।

मुक्त क्षेत्रों में कचरे के एकत्रण व भण्डारण एमएसडब्ल्यू नियमों के अनुसार नहीं है और यह स्वास्थ्यकर पर्यावरण के लिए अहितकर था, विशेषतः तब जब वे घने बसे क्षेत्रों में अवस्थित थे।

अपने उत्तर में, उत्तरी और दक्षिण दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि लोग कचरे को खुले स्थान पर फेंक देते हैं, जहाँ पर ढलावों के निर्माण के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि इन स्थलों की नियमित सफाई और कीटाणु रहित होना भी सुनिश्चित किया जा रहा था तथा कचरे के खुले ढेर लगाने को रोकने हेतु डिब्बे प्रदान किए गए। उत्तर केवल लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।



### 2-5-3-5 vif'kV dk ifjogu

अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि पूर्वी दि.न.नि. ने अपशिष्ट एकत्रण स्थलों से प्रतिदिन कचरे को उठाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए 'ई.म्यूनिसिपलटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम' (अक्टूबर 2013) स्थापित किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, ढलावों/खुले स्थलों/कचरादानों के कचरा उठाने से पहले और बाद में फोटोग्राफ लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने है। ढलावों/कचरादानों/खुले स्थलों की संख्या के हिसाब से प्रतिदिन वेबसाइट पर 336 फोटोग्राफ शाहदरा दक्षिण क्षेत्र से (प्रत्येक स्थल की प्रतिदिन दो फोटोग्राफ) और 232 शाहदरा उत्तर क्षेत्र से अपलोड होनी चाहिए। जुलाई 2014 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि दक्षिण शाहदरा के 121 और उत्तर शाहदरा के 68 ढलावों/खुले स्थलों को छोड़कर, दक्षिण शाहदरा और उत्तर शाहदरा ने क्रमशः प्रतिदिन 94 और 95 फोटोग्राफ अपलोड की थी। इस प्रकार, प्रतिदिन कचरे का उठाया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि डाइवर को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और स्वच्छता अधीक्षकों को फोटोग्राफों की अपलोडिंग की निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे।

### 2-5-3-6 vif'kV dk fui Vku

अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु जैव व पुनः प्रयोग योग्य अपशिष्ट के प्रसंस्करण द्वारा कंपोस्ट, अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन इत्यादि को तैयार करना है। नवंबर 2014 को केवल पाँच अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र थे जैसा कि rkydk 2-5-1 में वर्णित है।

#### rkydk 2-5-1 %vif'kV iġ ġdj.k l a a- dk foofj.k

Ø- l a	l a a- dk uke	{lerk %hi ġMġ½	LFki uk dk o"K	bui ħ	mġi kn
1	उर्जा संयंत्र, ओखला को अपशिष्ट	1950	2010-11	कचरा	विद्युत
2	नरेला-बवाना में परिशोधित कचरा भराव क्षेत्र	ला.न.*	2011-12	कचरा	खाद तथा कचरे से उत्पन्न ईंधन
3	कम्पोस्ट संयंत्र ओखला	200	2007-08	कचरा	खाद
4	कम्पोस्ट संयंत्र भालसवा (बंद)	500	1999-2000	कचरा	खाद
5	सी एवं डी संयंत्र, बुराडी	1290	2009-10	सी एवं डी अपशिष्ट	ईंटे टाइल्स इत्यादि
<b>dy</b>		<b>5190</b>			

\*इस संयंत्र की क्षमता उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित है जो कुल कचरा रोहिणी तथा सिविल लाईंस क्षेत्रों से प्रसंस्कृत करती है।

लेखापरीक्षा में दिल्ली में अपशिष्ट के प्रसंस्करण में कई कमियाँ देखी गई हैं जिसे अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

(i) **ij l dj.k fd, cxj dpjs dks tek djuk%** एम एस डब्ल्यू नियमावली की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 6 (1), 6 (3) और 7 (1) के अनुसार नगर निगम प्राधिकारी को कचरा भराव क्षेत्रों पर बोझ को कम करने हेतु अपशिष्ट का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त तकनीक अपनानी चाहिए। नियम 4 की अनुसूची I में आगे दि.न.नि. को 31 दिसंबर 2003 तक अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं को स्थापित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा 2009-10 में चार प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 41 प्रतिशत हो गई, यह 100 प्रतिशत के वांछित स्तर से बहुत कम रही क्योंकि संयंत्रों की क्षमता दिल्ली में उत्पन्न सारे कचरे के प्रसंस्करण हेतु अपर्याप्त थी। यद्यपि, सितम्बर 2014 तक केवल चार कचरा प्रसंस्करण संयंत्र प्रचालन में थे। इनमें से, (500 ट.प्र.दि. क्षमता वाले) भलस्वा संयंत्र को पर्यावरण मानदण्डों का अनुपालन न करने के कारण दि.प.नि.स. द्वारा मार्च 2014 में बंद कर दिया गया।

दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में एक 1300 ट.प्र.दि. क्षमता के अपशिष्ट से उर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु मैसर्स ईस्ट डेल्ही प्रासिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया जिसे अगस्त 2010 में चालू होना था जबकि स्थल की सुपुर्दगी में देरी के कारण दिसंबर 2014 तक यह संयंत्र चालू न हो सका।

उत्तर में, उत्तरी और दक्षिण दि.न.नि. ने (मार्च 2015) दि.वि.प्र. से भूमि प्राप्त करने के लिए लगातार प्रत्यनों के बावजूद भी भूमि प्राप्त करने में असक्षमता व्यक्त की। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि गाजीपुर में अपशिष्ट शक्ति संयंत्र, (मार्च 2015) में परिचालन होने वाला था और इस तरह के और संयंत्र भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही स्थापित किये जायेंगे। उत्तर दि.न.नि. द्वारा यह स्वीकारना है कि विद्यमान संयंत्र दिल्ली में उत्पन्न संपूर्ण अपशिष्ट की प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त है। आगे, गाजीपुर का ऊर्जा संयंत्र मई 2015 तक प्रचालनीय नहीं था।

(ii) **l h , oaMh vif'kV dsfy, ij l dj.k l a a e adel%** मार्च 2015 तक बुराडी में नि.व.वि. अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु एकमात्र संयंत्र जो दिल्ली में उत्पन्न कुल नि.व.वि. अपशिष्ट का 47 प्रतिशत प्रसंस्कृत करता था। इस प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक नि.व.वि. अपशिष्ट को एस.एल.एफ में इकट्ठा किया जा रहा था जो कि पहले से ही अपनी स्वीकृत सीमाओं को पार कर चुके थे।

उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने जवाब (मार्च 2015) में बताया कि कुछ नि.व.वि. अपशिष्ट को कूड़ा कचरा ढँकने के लिए क.भ.क्षे. पर भेजा जा रहा था जैसा कि एम.एस.डब्ल्यू नियमों में प्रावधान है। आगे यह भी कहा कि नये नि.व.वि. अपशिष्ट संस्करण संयंत्रों की स्थापना (तीन उत्तरी व दो दक्षिणी दि.न.नि. में) प्रक्रियाधीन थी।

(iii) **Hwfkj .k LFkyk dkm) kj u gkuk%** इन सभी तीनों स्थलों (गाजीपुर, भलस्वा और ओखला) के भू भरण स्थल उपयोग योग्य नहीं रह गए उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी लेकिन नये क.भ.क्षे. के लिए भूमि का अभाव होने के कारण काम में लाये जा रहे थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना दस्तावेज के अनुसार, गाजीपुर क.भ.क्षे. का सुधार कार्य दि.न.नि. द्वारा किया जाना था लेकिन इस मामले में कार्यवाही अभी शुरू की

जानी है। वर्ष 2010-11 से दि.न.नि. ने अपनी वार्षिक योजनाओं में क.भ.क्षे. के सुधार का प्रस्ताव नियमित रूप से रखा था। फिर भी, किसी भी क.भ.क्षे. के सुधार का कार्य जुलाई 2014 तक शुरू नहीं हुआ था।

जबाब में उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि भलस्वा क.भ.क्षे. के सुधार के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए एक सलाहकार को मार्च 2014 में नियुक्त किया गया था और परियोजना के लिए निविदाएँ इनके तैयार होने के बाद ही आमंत्रित की जानी चाहिए थीं, पूर्वी और दक्षिणी दि.न.नि.ने बताया (मार्च 2015) कि गाज़ीपुर और ओखला स्थित क.भ.क्षे. का सुधार कार्य संशोधित सामग्री के भरण के लिए स्थल की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सके। क.भ.क्षे. को वापस प्रयोग की स्थिति में लाने में दि.न.नि. की अक्षमता एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष तौर पर तब जब वह नये क.भ.क्षे. हेतु, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(iv) **उच्चतम न्यायालय ने (फरवरी 2000) पाया कि दिल्ली को स्वच्छ रखना सरकार का कार्य है और यह देखना सभी सम्बंधितों का कर्तव्य है कि भू भरण स्थल जन स्वास्थ्य के हित में उपलब्ध कराए जाएँ तथा उसने चार अतिरिक्त कम्पोस्ट संयंत्र निर्माण हेतु 1996 के दिशानिर्देशों का पालन न होने पर भी चिन्ता व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा. भारत सरकार व अन्य एजेन्सियों को चार सप्ताह के अन्दर भू भरण स्थलों को चिह्नित करने व उन्हें स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु निर्देशित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.न.नि. की 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता के बदले, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल 324.60 एकड़ को आबंटित किया गया था जिसमें से नरेला-बवाना रोड पर 150 एकड़ भूमि को अभियंत्रित क.भ.क्षे. के लिए प्रयुक्त किया जा सका तथा शेष क.भ.क्षे. के लिए उपयुक्त नहीं थे। इन तीनों स्थलों में से दक्षिण दि.न.नि. द्वारा दो को सी एवं डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु संयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तावित किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क.भ.क्षे. के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए एक समिति का गठन किया (अप्रैल 2014) और पूर्वी दि.न.नि. के अंतर्गत समिति ने कुल 785.5 एकड़ के आठ स्थलों और दक्षिणी दि.न.नि. के 2138 एकड़ के 14 स्थलों का अनुमोदन किया था जिन्हें अभी दि. वि.प्रा. द्वारा सौंपा जाना था।**

इस प्रकार, अतिरिक्त भूमि की कमी के कारण दि.न.नि. नये अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिष्ठापित करने में असफल रही। चूंकि निर्माण और नये संयंत्रों को लागू करने में समय लगता है, ऐसा लगता है कि क.भ.क्षे. में कचरो का बिना प्रसंस्करण किए, आने वाले वर्षों में इसी प्रकार डाले जाना जारी रहेगा। दि.प्र.नि.क. द्वारा मार्च 2012 में तीनों क.भ.क्षे. के आसपास कराये गये परीक्षण दर्शाते हैं कि पीने के पानी में कैल्शियम की मात्रा व इसकी कठोरता, क्लोरीन तत्व व कुल विलयित विलेय निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक थे। अशुद्धता का स्तर अप्रैल 2009 की परीक्षण रिपोर्ट की तुलना में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

उत्तरी व दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के

आदेशों के अधीन सचिव (श.वि.वि) रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में गठित समिति ने 31 स्थानों को चिन्हित किया है लेकिन अभी कोई स्थान सौंपा नहीं गया है। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि दि.वि.प्रा. ने दो स्थान कचरा व नि.व.वि. अपशिष्ट हेतु संस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराए हैं।

### 2-5-3-7 द-क्षेत्रों में भू-भरण गैस नियंत्रण व एकत्रण तन्त्र

एम.एस.डब्लू नियमावली की अनुसूची III में क.भ.क्षे. में भू-भरण गैस नियंत्रण व एकत्रण तन्त्र की स्थापना व गैस का ताप अनुप्रसंगो या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग और अगर सम्भव न हो तो गैसों को हवा में जला देने का प्रावधान है। गैस सीधे वातावरण में नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इससे क.भ.क्षे. में तथा इसके आस-पास वातावरण में वायु की गुणवत्ता बनी रहेगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी सूचनानुसार भू-भरण भलस्वा में कोई गैस नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जबकि भू-भरण ओखला, 50 मीटर की वृद्धि उँचाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। गाजीपुर क.भ.क्षे. तन्त्र में, भू भरण गैस निकालने/भीतर बंद करने हेतु एक प्रणाली है परन्तु वह सक्रिय नहीं थी।

क.भ.क्षे. क्षेत्रों को उचित गैस नियंत्रण प्रणालियों का तथा वायु में गुणवत्ता का अभाव न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक था बल्कि आस पास के क्षेत्र में रह रही आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है, उचित गैस नियंत्रण तन्त्र के साथ अभियंत्रित क.भ.क्षे. स्थापित करा दिए जाएँगे। पूर्वी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि भू भरण गैस का संग्रह व नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि कचरा अभी भी गाजीपुर क.भ.क्षे. पर फेंका जा रहा था।

### 2-5-3-8 निष्कालक के भूजल के साथ मिश्रण से स्थानीय समुदायों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, विशेषकर जब निष्कालक में खारिज बैटरी, इलेक्ट्रोनिक्स या घरेलू सफाई वाले पदार्थ आदि के अपघटन से बनने वाले हानिकारक रसायन हों।

एम.एस.डब्लू नियमों की अनुसूची-II यह निर्धारित करती है कि अपशिष्ट निपटान क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर एक गैर पारगम्य परत प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कि निष्कालक<sup>50</sup> गढ़के के भीतर ही रहे। निष्कालक के भूजल के साथ मिश्रण से स्थानीय समुदायों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, विशेषकर जब निष्कालक में खारिज बैटरी, इलेक्ट्रोनिक्स या घरेलू सफाई वाले पदार्थ आदि के अपघटन से बनने वाले हानिकारक रसायन हों।

इन सभी तीनों क.भ.क्षे. सभी प्रकार के अपशिष्ट जैसे घरेलू समान, सी एंड डी, सब्जी मंडियों के अपशिष्ट, कसाई घरों आदि के लिए मुक्त निक्षेप स्थल है। नियमों के प्रभाव में आने के पहले से ही ये स्थल अस्तित्व में थे, इसलिए क.भ.क्षे. के स्थान पर निष्कालक के एकत्रण संसाधन की कोई प्रणाली नहीं थी।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने उत्तर में (मार्च 2015) बताया कि एकत्रित निष्कालक कचरे पर फ़ैल जाती थी। तथापि क.भ.क्षे. में अपारगम्य परत न होने की दशा में निष्कालक के एकत्रीकरण पर उनका कोई जबाव नहीं था। पूर्वी दि.न.नि. (मार्च 2015) ने बताया कि सतह

<sup>50</sup>निष्कालक एक तरल पदार्थ है जो कि सामान्यतः घरेलू अपशिष्ट के प्राकृतिक अपघटन के परिणामस्वरूप एक कचरे के ढेर या व्यवस्थित कूड़ा संग्रहण स्थल के भीतर या इससे होकर बाहर निकलकर बहता है।

पर निक्षालक के शोधन हेतु एक शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

### 2-5-3-9 Bk vif'kV dsizaku eavi; kr bZxouf

स्वच्छता सेवाओं के अन्तर्गत, दि.न.नि. को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से कार्यान्वित करना था।

दि.न.नि. के अभिलेखों की जाँच और वेबसाइट ने दर्शाया कि किसी भी दि.न.नि. में कोई भी प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं थी जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित सभी डाटा को विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के लिए एकत्र किया जा सके। इसी प्रकार, जी.आई.एस. क.भ.क्षे. में एकत्रित, पहुँचाये गये और निपटाए गए अपशिष्ट से संबंधित भौगोलिक सूचना को एकत्रित करता है। हालांकि, कचरे के संग्रह के लिए तैनात किये गये आटो टिपर ही जी.पी.एस.<sup>51</sup> उपकरण से लैस थे। पूर्वी दि.न.नि. में यद्यपि विभागीय ट्रकों में जी पी एस उपकरण प्रतिष्ठापित किया गया था, लेकिन डाटा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि सभी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाह्य सेवा प्रदाता हेतु टेण्डर प्रक्रिया जारी थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एम.आई.एस भी शामिल था। पूर्वी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) में बताया कि समस्या प्रबंधन, वाहन प्रबंधन, बायोमैट्रिक उपस्थिति आदि जैसे बहुत से सूचना तन्त्र मौजूद थे। तथापि लेखा परीक्षा के दौरान वाहन प्रबंधन तन्त्र या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तन्त्र के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

### 2-5-3-10 fut ų ewky; lkd k izalu

जनवरी 2011 में दि.न.नि. ने दो निजी ग्राहियों को 567 मूत्रालयों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा। एजेंसियों को निःशुल्क मूत्रालयों की दैनिक सफाई तथा अनुरक्षण करने के अलावा मूत्रालयों की दीवारों पर विज्ञापन के अधिकारों के बदले दि.न.नि. को रियायत शुल्क (एक नियत राशि प्रति माह प्रति मूत्रालय) का भुगतान करना था। दि.न.नि. ने मई 2011 में एजेंसियों की सेवाओं को असंतोषजनक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् ठेके को निरस्त कर दिया। तथापि एजेंसियों ने समझौतों के निरस्तीकरण के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। दि.न.नि. ने न्यायालय को संचालक समूह के सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव रखा (जून 2011) जिसमें 530 में से 379 मूत्रालयों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसके पश्चात् न्यायालय ने स्थगन को जारी रखने की अनुमति देते हुए मामला मध्यस्थ निर्णय हेतु भेज दिया (मई 2013)। अनुसरण में दि.न.नि. ने दिसंबर 2003 में एक मध्यस्थ की नियुक्ति की।

लेखापरीक्षा ने ठेके के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ पाईं:

(i) एजेंसियों के साथ किए गए समझौते के अनुसार दि.न.नि. को एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की निगरानी हेतु समझौते के 15 दिनों के भीतर दि.न.नि. और ग्राहियों के सदस्यों को सम्मिलित कर एक संचालक समूह का गठन करना था। तथापि संचालक समूह का

<sup>51</sup> भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली

गठन जून 2011 में ही अर्थात् समझौते के निरस्तीकरण के पश्चात् किया गया।

(ii) समझौतों के अनुसार स्वच्छता अधीक्षकों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए परियोजना प्रभारी होना था तथा उन्हें संचालक समूह को निर्जल मूत्रालयों के अनुरक्षण तथा सफाई की रिपोर्ट देनी आवश्यक थी। तथापि लेखापरीक्षा में इस तथ्य के लिए अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं मिल सका कि ऐसी रिपोर्टें किसी भी समय संचालक समूह को प्रस्तुत की गई थीं।

(iii) दि.न.नि. अपने ग्राहियों से लाइसेंस शुल्क लेने में असफल रहा। केवल एकमात्र दक्षिणी दि.न.नि. के मामले में ही इस संदर्भ में ₹ 2.72 करोड़ का लाइसेंस शुल्क (जनवरी 2011 से सितम्बर 2014) बकाया था। उत्तरी व पूर्वी दि.न.नि. के मामले में बकाया लाइसेंस शुल्क उपलब्ध नहीं था।

(iv) जैसाकि संचालक समूह को सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्रमाणित है कि अधिकतर मूत्रालयों का अनुरक्षण ग्राहियों द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा था परन्तु दि.न.नि. ने इन मूत्रालयों के रख-रखाव हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार लगभग ₹ 22.96 करोड़<sup>52</sup> की लागत से निर्मित ये मूत्रालय जनवरी 2011 से अप्रयुक्त रहे।

उत्तर में उत्तरी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि मूत्रालयों का अब अधिग्रहण कर लिया गया है, उन्हें परम्परागत स्वरूप में बदल दिया गया है तथा विभागीय स्तर से उनका रखरखाव किया जा रहा है। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मूत्रालयों को जनवरी 2011 से मार्च 2015 के दौरान प्रयोग में नहीं लाया गया। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि बकाये की गणना की जा रही थी। मूत्रालयों के रखरखाव पर कोई जबाब नहीं था।

#### 2-5-4 foYkr izaku

2009-14 की अवधि के लिए दि.न.नि. को निधियों की आवश्यकता, आबंटित निधियाँ, दि.न.नि. के संबंध में प्राप्त और व्यय निधियाँ (दि.न.नि. के तीन भाग होने से पूर्व की अवधि को सम्मिलित करते हुये) rkydk 2-5-2 में दी गई है।

rkydk 2-5-2%ct V vloV u vK Q ;

(₹ करोड़ में)

c"Z	ifj; ktr dk vlo'; drk	fuf/k kckk vloV u	vloVr i fr'krk	iAr fuf/k k	okrfod Q ;
2009-10	378.15	170.00	44.96	170.02	170.02
2010-11	459.90	182.55	39.69	172.80	172.28
2011-12	480.00	255.80	53.29	256.32	246.32
2012-13	510.00	279.00	54.71	287.01	289.37
2013-14	591.60	344.99	58.31	345.00	331.34
dy	2419.65	1232.34	50.91	1231.15	1209.33

स्रोत : जैसा कि दि.न.नि. द्वारा मुहैया कराया गया था

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि आबंटित निधियाँ दि.न.नि. द्वारा परियोजित आवश्यकता से बहुत कम थीं। 31 मार्च 2014 को उत्तरी तथा दक्षिणी दि.न.नि. में क्रमशः ₹ 43.26 करोड़ तथा ₹ 52.95 करोड़ की बकाया देयताएँ थीं। उत्तरी तथा दक्षिणी दि.न.नि.

<sup>52</sup> ₹ 22.96 करोड़ = 567 निर्जल मूत्रालय x ₹ 4.05 लाख प्रति इकाई (औसत लागत)

के पास उसी तिथि तक क्रमशः ₹ 27.11 करोड़ तथा ₹ 50.71 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताएँ भी थीं। इसके अतिरिक्त उत्तरी दि.न.नि. के पास सितम्बर 2014 तक विलंबित भुगतानों पर देय ब्याज के रूप में ₹ 4.75 करोड़ की देयता भी थी।

इसके उत्तर में, उत्तरी व दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि आबंटित निधियाँ केवल आकस्मिक कार्यों को करने हेतु ही पर्याप्त थीं तथा योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सम्भव नहीं था। तथापि, ये उत्तर दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया के मामले का हल नहीं करते। विलंबित भुगतानों पर ब्याज के संबंध में उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि उन्होंने इस कारण से कोई भुगतान नहीं किया है। तथापि तथ्य यह है कि देयता बकाया है।

## 2-5-5 mi dj. k dk i zaku

### 2-5-5-1 d-Hk{ls eax\$ dk kEd e' hularFlk mi dj. k dh deh

मशीनों और उपकरण जैसे बुलडोजर, हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, बैकहोभारक इत्यादि को क.भ.क्षे. पर कचरा को समतल और ड्रेसिंग के काम पर लगाया जाता है। लेखा परीक्षा ने सभी तीन क.भ.क्षे. में उपकरणों की कमी पायी जैसा कि rkydk 2-5-3 में दिया गया है।

### rkydk 2-5-3% d-Hk{ls eami dj. k dh mi yC/krk

Øa l a	mi dj. k	HyLok		vkl'kyk d-Hk{ls		xkt hi ğ d-Hk{ls	
		vlo'; d	dk kEd	vlo'; d	dk kEd	vlo'; d	dk kEd
1	बुलडोजर	6	3	5	1	6	2*
2	एक्सकेवेटर	2	1	2	0	3	0
3	लोडरस	1	0	1	1	1	0

\*तीन शिपटों में कार्यरत किराए के बुलडोजर

जैसाकि देखा जा सकता है, भलस्वा क.भ.क्षे. में छः बुलडोजर की आवश्यकता के प्रति केवल तीन उपलब्ध थे जबकि ओखला क.भ.क्षे. में आवश्यक पाँच के प्रति केवल एक ही उपलब्ध था। गाजीपुर क.भ.क्षे. में 6 की आवश्यकता के प्रति किराए के दो बुलडोजर कार्य कर रहे थे। वहाँ सभी तीन क.भ.क्षे. में एक्सकेवेटरों तथा लोडरस की भी कमी थी।

इसके अतिरिक्त, क.भ.क्षे. भलस्वा में लगाई गई मशीनों और उपकरणों की स्थिति दर्शाती है कि जून 2013 को 5 से 26 महीने की अवधि तक मशीनें अकार्यशील थीं। दो बुलडोजर अपनी खरीद से दो वर्ष की अल्प अवधि में ही टूट गये। यद्यपि ये मशीन वार्षिक अनुरक्षण ठेके के अन्तर्गत थी, उत्तरी दि.न.नि. ने मशीनों की मरम्मत कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी प्रकार, कचरा और अन्य अपशिष्ट को विभिन्न क.भ.क्षे. में निक्षेपण के प्रबन्धन के लिये दि.न.नि. ने नौ बुलडोजर तथा पाँच एक्सकेवेटर मैसर्स बी.ई.एम.एल. से कुल ₹ 9.38 करोड़ की कीमत में खरीदे। ये सभी यंत्र 6 वर्ष की अवधि के लिये व्यापक रखरखाव संविदा (व्या. र.सं.) के अंतर्गत थे। जिसके बाद मैसर्स बी.ई.एम.एल. ने उन्हें कार्यशील करके दि.न.नि. को सौंपना था। दि.न.नि. को तीन भागों में बाँटने के बाद पाँच बुलडोजर, तीन एक्सकेवेटर, पूर्वी दि.न.नि. के अधिकार में क.भ.क्षे. गाजीपुर में तैनाती के लिये आए। एक बुलडोजर जिसकी नमूना जाँच की गई थी, अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 तक औसत 12 दिन प्रति माह तक

गैर कार्यात्मक रहा और इसी प्रकार एक एक्सकेवेटर जुलाई 2009 से मार्च 2014 तक 12 दिन प्रति माह गैर कार्यात्मक रहा। यह दर्शाता है कि ये मशीनें विस्तृत अनुरक्षण ठेके के लगभग एक तिहाई समय में गैर कार्यात्मक रही। इसके अतिरिक्त, जब व्या.र.सं. का समय मई 2014 में समाप्त हो गया था, सभी उपकरण मैसर्स बी.ई.एम.एल. द्वारा गैर कार्यात्मक स्थिति में छोड़ दिये गये।

जबाव में उत्तरी दि.न.नि ने (मार्च 2015) बताया कि फर्म को बहुत से कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं था। फर्म अतिरिक्त पुर्जों की भी आपूर्ति करने को तैयार नहीं थी। इसमें आगे बताया गया कि फर्म को ब्लैकलिस्ट करने तथा उपकरणों की मरम्मत हेतु खुली निविदाओं का आमंत्रण किया जाना प्रक्रियाधीन था। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि फर्म पर समझौते के अनुसार जुर्माना लगाया गया है और फर्म के जोखिम तथा लागत पर उपकरण की मरम्मत का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था। तथापि तथ्य यह है कि वा.अनु.टे./वि.अनु.टे. के अंतर्गत होने के बावजूद उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

**2-5-5-2 fdjk s ds Vdk ds fy; s Hxrk djus l s iwZr; dh xbZ njh dk xj-l R ki u**

गाजीपुर के क.भ.क्षे. को कचरा पहुँचाने के लिए पूर्वी दि.न.नि. प्रथम 100 किलोमीटर के लिये ₹ 3268.50 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर प्रति ट्रक प्रति दिन के लिए ₹ 23.82 की दर पर 73 किराया ट्रकों (38 उत्तर शाहदरा में तथा 35 दक्षिण शाहदरा क्षेत्र में) की सेवाओं का उपयोग करती थी। वर्ष 2012-14 के दौरान इसके कारण कुल खर्च ₹ 22.66 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किराये के ट्रकों द्वारा तय की गयी दूरी को मापने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूरी, प्रत्येक ट्रक द्वारा क.भ.क्षे. तक तय की गयी यात्राओं की संख्या के आधार पर मापी जाती थी। उनके द्वारा तय की गई यात्राओं की संख्या के समर्थन में दावों के साथ क.भ.क्षे. द्वारा जारी टोल पर्चियाँ नहीं लगाई गई थीं अपितु केवल टोल पर्चियों की क्रमांक संख्या दी गई। इन क्रमांकों के आधार पर से.प्र. यात्राओं की संख्या सत्यापित करता है। यह पाया गया कि स्वच्छता खण्ड में इसके अपने ट्रकों को डीजल वितरण करने हेतु टोल पर्ची माँगी जाती है, जबकि किराए के ट्रकों के संबंध में बिलों के समय ऐसा नहीं किया गया।

ट्रक संचालकों द्वारा प्रस्तुत दावों की सत्यता निश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा में वेब आधारित टोस अपशिष्ट परिवहन प्रबन्ध प्रणाली (प्रणाली) को अपनाया गया जिसमें प्रत्येक ट्रक द्वारा क.भ.क्षे. तक की गई यात्राओं के विवरण उपलब्ध माने जाने थे। 2012-14 के दौरान लेखापरीक्षा में विभिन्न महीनों में पाँच ट्रकों द्वारा की गई यात्राओं की नमूना जाँच की गई तथा दावों और प्रणाली में उपलब्ध सूचना के बीच असंगतियाँ पाई गईं जो निम्नोक्त हैं:

कुछ ट्रकों ने 6-7 घण्टों में 200 कि.मी. से अधिक दूरी तय की जिस दौरान उन्हें भण्डार स्थलों से भी कूड़ा उठाना पड़ा था। उदाहरणस्वरूप एक ट्रक ने चार यात्राएँ (लगभग 160 कि.मी.) 4 घण्टे 50 मिनट में पूरी की, जिसमें क.भ.क्षे. में बिताए 28 मिनट शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य ट्रक ने आठ यात्राएँ (करीब 320 कि.मी.) 10 घंटे 45 मिनट में की, जिसमें क.भ.क्षे. में बिताए 55 मिनट शामिल हैं। दिल्ली की यातायात स्थिति, स्थल पर ट्रकों की अधिकता तथा प्रवेश व निर्गम दोनों पर लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी



इतनी छोटी अवधि में तय करना संशयपूर्ण है, विशेषकर तब जब कि पूर्वी दि.न.नि. के अपने ट्रकों ने मात्र 39 से 65 कि.मी. प्रतिदिन ही तय किए।

इसके अतिरिक्त तीन नमूना जाँच किए ट्रकों के संबंध में वेब आधारित सिस्टम में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। एक ट्रक ने माह मार्च 2014 के दौरान 145 यात्राएँ कीं, जिसमें 4163.5 कि.मी. दूरी तय की गई तथा अप्रैल 2014 में 162 यात्राएँ की गई जिसमें 4630.50 कि.मी. (28 दिन) की दूरी तय की गई। इसी प्रकार दो ट्रकों ने अप्रैल 2013 में 132 तथा 152 यात्राएँ कीं जिनमें क्रमशः 3960 व 4560 कि.मी. दूरियाँ तय कीं। सिस्टम में सूचना के अभाव में पू.दि.न.नि. के पास दावों के सत्यापन हेतु कोई उपाय नहीं था।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि इन ट्रकों द्वारा तय दूरियों की निगरानी अपर्याप्त थी।

जबाब में, पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि जिससे किराये के ट्रकों द्वारा तय की गयी दूरी कार्य पंजिका में दर्ज और स्वच्छता अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने हेतु एक प्रणाली है। किराये के ट्रकों के लिए बिलों के साथ टोल पर्चियाँ संलग्न होना और कार्य पंजिका प्रविष्टि द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। पुनः यह सूचित किया गया कि किराये के ट्रकों में जी.पी.एस स्थापित किया गया। उत्तर तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता क्योंकि बिलों की नमूना जाँच में कार्य पंजिका और टोल पर्ची नहीं पायी गयी।

## 2-5-6 ekuo lã k/ku izaku

### 2-5-6-1 LVKQ dh deh

लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त सूचना और रिकार्ड की जाँच दर्शाती है कि सभी तीन निगमों में विभिन्न संवर्गों में स्वच्छता स्टाफ की कमी थी। ~~4/4~~ उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. में दो तिहाई स्वीकृत स्वच्छता अधीक्षक पद खाली थे। पूर्वी दि.न.नि. के पास 31 मार्च 2014 को स्व.अ. के छः पदों में से दो पद रिक्त थे। अन्य संवर्गों में कमी, उत्तरी दि.न.नि. में 10 से 64 प्रतिशत, दक्षिण दि.न.नि. में 4 से 42 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. में 11 से 75 प्रतिशत की रेंज में थी।

### 2-5-6-2 LVKQ dh vko' ; drk dk xj-fu/kj. k

मार्च 2012 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा एकीकृत दि.न.नि. के दक्षिणी क्षेत्र में स्वच्छता स्टाफ की आवश्यकता के निर्धारण हेतु अध्ययन किया गया। अध्ययन में यह अनुशंसा की गई कि दि.न.नि. द्वारा स्वयं अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अध्ययन किए जाने चाहिए। यद्यपि इस अध्ययन के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक, दि.न.नि. ने इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि यद्यपि प्रतिवेदन पर कई फोरमों में विचार-विमर्श किया गया, परंतु इसकी प्रयोज्यता ज्ञात नहीं की जा सकी। पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि निगमों द्वारा स्वीकृत होने पर प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जायेगा। तथापि तथ्य यह है कि दि.न.नि. ने स्वच्छता सेवाओं के लिए स्टॉफ की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया।

### 2-5-7 वक्रांकित; U=k

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। रिपोर्ट में पहले से इंगित किए मामलों के अलावा आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थी:

(i) **निष्पादित रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली चयनित दक्षिणी और पूर्वी दि.न.नि. क्षेत्र में नहीं हैं।** पदानुक्रम के किसी भी स्तर पर कोई भी निर्धारित रिपोर्ट कार्यप्रणाली नहीं है यह पूर्वी दि.न.नि. द्वारा सूचित किया गया कि यद्यपि ढलाव, सीटीसी<sup>53</sup> इत्यादि पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरीक्षित किये जाते हैं, ऐसे किसी निरीक्षण अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ ढलावों/सी.टी.सी./कूड़ेदानों इत्यादि की स्थिति को बताने के लिए कोई निर्धारित प्रणाली नहीं थी जिससे स्वच्छता सेवाओं की नियमित मरम्मत तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

जवाब में उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि, ठोस कचरे को उठाने और ले जाने के लिए ठेके सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि (मार्च 2015) अधिकारियों का एक दल स्वच्छता और ढलावों और कूड़ेदानों से नियमित कचरा हटाने की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। यद्यपि अधिकारियों की नियुक्ति स्वच्छ भारत मिशन का भाग था और निगरानी तंत्र में सन्निहित नहीं माना जा सकता था।

(ii) **भौतिक-सह-उपलब्धि रिपोर्ट अथवा मासिक व्यय विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जैसाकि श.वि. वि. से अनुदानों के लिए संस्वीकृत आदेशों में निर्दिष्ट था।** केवल व्यय विवरणियाँ श.वि.वि. को भेजी गयीं थीं जिसमें स्वच्छता सेवाओं के तहत किया हुआ कुल व्यय प्रत्येक गतिविधि के तहत प्रगतिशील व्यय को स्पष्ट किए बिना शामिल था। श.वि.वि. ने भी दि.न.नि. को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया और अपना कार्य केवल अनुदान के निर्गमन तक सीमित रखा।

जवाब में, उत्तरी और दक्षिणी दि.न. नि. ने कहा कि (मार्च 2015) भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा। दि.न.नि. ने कहा कि श.वि.वि. को उचित जानकारी के साथ नियमित रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षा के दौरान या उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(iii) **चयनित क्षेत्रों में शिकायत रजिस्ट्रों की जाँच** ने दर्शाया कि सभी प्रकार की शिकायतें एक ही रजिस्टर में दर्ज की जाती थीं। विभिन्न श्रेणियों जैसे सफाई, जल निकासी, अनधिकृत निर्माणों इत्यादि की शिकायतों को अलग-अलग दर्ज नहीं किया जाता था। चयनित क्षेत्रों के नियंत्रण कक्ष में शिकायतों की नमूना जाँच में पता चला कि 37 से 71 प्रतिशत मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही को रिकार्ड नहीं किया गया। इस प्रकार उचित अभिलेखों के अभाव में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि सभी शिकायतों पर कार्यवाही शीघ्रता के साथ हुई।

<sup>53</sup> सामुदायिक शौचालय परिसर

जवाब में, उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि प्राप्त शिकायतों को निवारण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र स्टाफ को अग्रेषित कर दिया गया था, जबकि पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रचलन में है। रिकार्डों के रखरखाव में कमी पर कोई उत्तर नहीं दिए गए थे।

## 2-5-8 LoPNrk l okvksdsh/kku ij turk dh/kj.kk

दि.न.नि. द्वारा प्रदान की जा रही स्वच्छता सेवा की गुणवत्ता पर जन धारणा सुनिश्चित करने के लिये लेखा परीक्षा में 946 में से यादृच्छिक रूप से चयनित 316 निवासी कल्याण संघों से, एक प्रश्नावली के माध्यम से सड़क की सफाई और नालियों से गाद निकालना, ढलावों की स्वच्छता, मूत्रालय, सामुदायिक शौचालय परिसर आदि पर राय जानने हेतु उनके विचार मांगे। रोहिणी क्षेत्र में 87 में से 80, दक्षिण क्षेत्र में 61 में से 36 तथा दक्षिण और उत्तर शाहदरा क्षेत्र के 168 में से 113 प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। सर्वेक्षण के परिणाम संक्षेप में **vuqXud 2-4** में दिये गये हैं, जिसका विश्लेषण नीचे है:

- रोहिणी के नि.क.सं. के 43 प्रतिशत के अनुसार सड़क प्रतिदिन साफ नहीं होती थी। आंकड़ा मध्य क्षेत्र में 44 प्रतिशत तथा दि.न.नि. में 35 प्रतिशत था। 45 प्रतिशत नि.क.सं. रोहिणी, 58 प्रतिशत मध्य क्षेत्र और 56 प्रतिशत पूर्वी दि.न.नि. का मत था कि सफाई के तुरन्त बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं उठाया गया।
- रोहिणी में 80 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र में 82 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. में 67 प्रतिशत नि.क.सं. का कहना है कि नालियाँ प्रतिदिन साफ नहीं की जाती थीं। 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोहिणी में, 92 प्रतिशत ने मध्य क्षेत्र में और 66 प्रतिशत ने पूर्वी दि.न.नि. में, कहा कि नालियों से निकाला गया अपशिष्ट तुरन्त नहीं हटाया गया।
- रोहिणी से 39 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 55 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. से 32 प्रतिशत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कचरा घरों से एकत्र ही नहीं किया गया।
- रोहिणी से 45 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 33 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. से 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कचरे को इन्हीं स्थानों पर खुले स्थल में ढेर लगा दिया गया।
- रोहिणी से 80 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र से 81 प्रतिशत पूर्वी दि.न.नि. से 68 प्रतिशत नि.क.सं. ने कहा कि कचरा उनके क्षेत्र के ढलावों/खुले स्थानों से प्रतिदिन नहीं उठाया गया। जबकि रोहिणी से 72 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 41 प्रतिशत और पूर्व डी.एम.सी. से 73 प्रतिशत ने कहा कि यह लाने ले जाने के दौरान ढका नहीं गया। सभी चयनित क्षेत्रों से 70 प्रतिशत से अधिक आर.डब्ल्यू.ए ने भी कहा कि कचरा उठाने के बाद ढलावों को साफ और रोगाणु मुक्त नहीं किया गया।
- रोहिणी से 84 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 95 प्रतिशत और पूर्व डीएमसी से 64 प्रतिशत ने कहा कि इन क्षेत्रों के सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लैक्स प्रतिदिन साफ और रोगाणुमुक्त नहीं किये गये।

सर्वेक्षण का परिणाम दिल्ली नगर निगम की तरफ से जनता को मुहैया करायी गयी स्वच्छता सुविधाओं के प्रति उनके शिथिल संतोषजनक स्तर का सूचक है। फिर भी, यह

पूर्ववर्ती पैराग्राफों और उप-पैराग्राफों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मजबूत बनाती है कि वर्तमान में दिल्ली में स्वच्छता सेवायें स्वीकार्य मानकों से काफी नीचे हैं और तीनों नगर निगमों द्वारा एक प्रतिबद्ध दृष्टिकोण के साथ ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

इस मामले पर पू. दि. नि. ने कहा (मार्च 2015) कि साफ-सफाई के लिये निगम पर आरोप लगाना आम बात है। जबकि इसके लिये कारण निगमों द्वारा प्रदान की गयी जगह के अतिरिक्त अन्य जगह पर निरंतर गन्दगी और कूड़ा फेंकना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिकतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनता की धारणा के अनुरूप नहीं हैं।

### 2-5-9 fu'd"K

दि.न.नि. के पास दिल्ली में स्वच्छता सेवाओं के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाओं ने वास्तविक निधि आवश्यकता को व्यक्त नहीं किया। केवल एक चौथाई कचरे को ही जैव-अवशिष्ट और गैर जैव-अपशिष्ट में पृथक किया गया जबकि 2013-14 में उत्पन्न आधे से अधिक कचरे तथा सी व डी अपशिष्ट की संसाधित किए बिना क.भ.क्षे. में निक्षेपित कर दिया गया। तीन क.भ.क्षे. में से एक में भी गैस और निक्षालक एकत्र करने और संसाधित करने की उपयुक्त प्रणाली नहीं थी। भूमि की अनुपलब्धता ही नये क.भ.क्षे. तथा संसाधित संयंत्रों के विकसित न होने का मुख्य कारण है। खराब ठेका प्रबंधन के कारण दि. न.नि. निर्जल मूत्रालयों के अनुरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सका। निधियाँ क्रियाकलापवार उद्दिष्ट न होने के कारण बजट नियंत्रण ढीला था। सभी क.भ.क्षे. में उपकरण जैसे बुलडोजर, लोडर इत्यादि की बहुत अधिक कमी थी और उनमें से अधिकतर गैर-कार्यात्मक थे यद्यपि वे अनुरक्षण ठेके के अंतर्गत आते थे। सड़कों की सफाई, गद्दों से गाद खत्म करना, ढलावों, आदि से प्रतिदिन कूड़ा करकट उठाना, इत्यादि के लिए कोई निश्चित निगरानी प्रणाली नहीं थी। दक्षिण और पूर्व डी एम सी में विभिन्न स्तर पर किया गया दैनिक निरीक्षण का दस्तावेज नहीं था। आर डब्ल्यू ए के सर्वेक्षण भी यह दर्शाते हैं कि दि.न.नि. द्वारा मुहैया करायी गई स्वच्छता सेवाओं से जनता संतुष्ट नहीं थी।

### 2-5-10- fl Qkj 'ka

सरकार को निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए:

- (i) स्वच्छता सेवाओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना बनायी जाये और योजना के कार्यान्वयन योग्य छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें वार्षिक रूप से प्राप्त किया जाये,
- (ii) अधिसूचित स्वच्छता मानकों का अनुरक्षण दि.न.नि. द्वारा किया जाए,
- (iii) कचरे के एकत्रण व पृथक्करण में कार्यक्षमता में सुधार किया जाए,
- (iv) वर्तमान क.भ.क्षे. के सुधार हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए तथा क.भ.क्षे. में गैस नियंत्रण, निक्षेपण एकत्रण व संसाधित सिस्टमों को अधिष्ठापित किया जाए, और
- (v) विस्तृत एमआईएस तथा जीआईएस की स्थापना करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को लागू किया जाये

v/; k, -III

vuq kyuk ys[ kki j hkk

v/; k; &III  
vuqkyuk ys[ kki j h[kk

-f'k foi . ku funs'kky;

3-1 iz ks'kkyk mi dj. k dk x\$&mUk; u

₹ 89-18 yk[k ds 0; ds ckt w] jkT; Js krdj. k iz ks'kkyk  
1/4y rFk l fCt; k/2dk yf{kr mUk; u i klr ughafd; k t k l dka

राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला (फल तथा सब्जियाँ), जिसे इसके आगे प्रयोगशाला कहा गया है, की स्थापना की गई थी (जुलाई 2006) तथा कृषि विपणन निदेशालय (निदेशालय) ने जुलाई-अगस्त 2006 में, कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'फल तथा सब्जियाँ श्रेणीकरण नियम 2004' के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फलों तथा सब्जियों के श्रेणीकरण के लिए, उपकरण (जीसीएमएस<sup>1</sup>, एचपीएलसी<sup>2</sup>, यू.वी.-वी.आई.एस<sup>3</sup>, स्पैक्ट्रोफोटोमीटर) खरीदे तथा संस्थापित किए, जो 28 प्रकार के कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण कर सकते थे।

जनवरी 2010 में, निदेशालय ने एच.पी.एल.सी. की विद्यमान पद्धति को एलसीएमएसएमएस<sup>4</sup> में उन्नयन करने का प्रस्ताव, 153 से अधिक कीटनाशकों का विश्लेषण करने तथा फलों, सब्जियों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (वि.नि.नि.), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय तथा अन्य दिशा निर्देशों (यू.एस. एफ.डी.ए<sup>5</sup> तथा ई.यू.<sup>6</sup> दिशानिर्देशों), की आवश्यकताओं को पूरा करने को दृष्टिगत करते हुए रखा। यह दावा किया गया कि उन्नयन के पश्चात्, प्रयोगशाला को (उस समय केवल दक्षिण-पूर्व एशियन देशों के लिए पंजीकृत) सभी देशों को निर्यात की जाने वाली मर्दों के विश्लेषण तथा सत्यापन के लिए ए.पी.इ.डी.ए<sup>7</sup> द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। ए.पी.इ.डी.ए., से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् जांच के लिए आने वाले नमूनों में वृद्धि होगी, निर्यातकों की माँग पूरी होगी तथा प्रयोगशाला देश में विशिष्ट संस्थान होगी। इस औचित्य के आधार पर, निदेशालय ने ₹ 89.18 लाख की लागत का एक 'एलसीएमएसएमएस तिहरा चौहरा' उपकरण क्रय किया जो कि जून 2010 में संस्थापित किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नये उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के लिए इसे दिन-रात लगातार चलाये जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि, निदेशालय उपकरण को चलाने के लिए लगातार पॉवर बैक-अप का इन्तजाम नहीं कर सका। फलस्वरूप प्रयोगशाला, मार्च 2014 तक उन्नतिशील प्रणाली का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सकी तथा प्रयोगशाला केवल 28 कीटनाशक अवशेषों की पहचान कर रही थी, जो कि

<sup>1</sup>गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पैक्ट्रोमेट्री

<sup>2</sup>हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी

<sup>3</sup>अल्ट्रा वॉयलट विजिबल स्पैक्ट्रोस्कोपी

<sup>4</sup>लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पैक्ट्रोमेट्री

<sup>5</sup>यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन

<sup>6</sup>यूरोपियन यूनियन

<sup>7</sup>एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी

वह नये उपकरण के क्रय से पूर्व ही कर रही थी। निदेशालय ने लो.नि.वि. द्वारा एक कमरे के निर्माण तथा डीजी सैट के संस्थापन के प्रस्ताव को केवल अगस्त 2012 में अनुमोदित किया। यह भी सितम्बर 2014 तक चालू नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निदेशालय इसके इष्टम संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी के कारण ₹ 89.18 लाख के व्यय के बावजूद, विद्यमान पद्धति, एच.पी.एल.सी. को एल.सी.एम. एस.एम.एस. में उन्नयन नहीं कर सका जिससे विभिन्न प्राधिकरणों जैसे आई.एस.ओ<sup>8</sup> ए ए.पी.ई.डी.ए तथा एन.ए.बी.एल<sup>9</sup> से प्रमाणिकता प्राप्त की जा सके, जिसके कारण वहन केवल निर्यातकों की मांगों को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य में असफल रहा अपितु प्रयोगशाला के लक्षित उच्च स्तर तथा विशिष्टता को पाने में भी असमर्थ रहा।

निदेशालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (सितम्बर 2014) कि उपकरण संचालन में थे यद्यपि अपनी इष्टम क्षमता पर नहीं थे। क्योंकि निरंतर विद्युत आपूर्ति निश्चित नहीं थी, पॉवर ब्रेकडाउन के कारण किसी गंभीर क्षति से बचाने के लिए उपकरण को निरंतर नहीं चलाया जा सका। निदेशालय का उत्तर केवल इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका जैसा कि लक्षित था।

मामला, अगस्त 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### f' kkk foHkx

### 3-2 fnYyh ea l j d kj h L d y l a d k , dh-r vol j p u k l q k j 1/2 i k r j 1/2

i f j ; k t u k d k s f' k k k f o H k x 1/2 k f o - 1/2 } k j k f n Y y h j k t ; v k s k s x d , o a v o l j p u k f o d k l f u x e 1/2 f n - j k v k s v - f o - f u - 1/2 d k s f c u k f d l h v k s p k j d v u c a k d s l k s f n ; k x ; k r f k k d k ; Z d s f o L r r f o o j . k d s v H k o e a f' k k k f o H k x l q u f' P k r u g h a d j l d k f d f n - j k v k s v - f o - f u - u s i f j ; k t u k d s v a r x z f n , x , l H h d k ; Z i w z d j f n ; A i H h o d k j h f u x j k u h Q o L F k k u g h a F k A 183 f o | k y ; k a e s l s t g k f n - j k v k s v - f o - f u - } k j k d k ; Z i w z d j u s d k n l o k f d ; k x ; k f' k f o - u s d o y 78 d k s i w z i k k 50 i x f r i j l r f k k 55 d k s f o | k y ; d s i k p k ; Z } k j k l R k f i r f d ; k t k u k F k A f' k f o - u s f n - j k v k s v - f o - f u - d k s ₹ 343-13 d j k M f u x z f d ; k ; | f i d s c u v u s i f j ; k t u k d s f y , d o y ₹ 272-94 d j k M L o h - r f d ; k F k A

शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को 'रूपान्तर' परियोजना के अन्तर्गत तीन जिलों (पूर्वी, उत्तर-पूर्वी एवं उत्तर-पश्चिमी-क) के 198 सरकारी स्कूलों में अवसंरचना के रख-रखाव एवं सुधार का कार्य सौंपा (नवम्बर 2006)। परियोजना के लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किए गए ₹ 272.94 करोड़ के बजट प्राक्कलन का अनुमोदन फरवरी 2008 में व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) द्वारा एवं मार्च 2008 में मंत्रिमण्डल द्वारा किया गया था।

<sup>8</sup> इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडरडाइजेशन  
<sup>9</sup> नेशनल एक्रेडीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कॅलिब्रेशन लेबोरेट्रीज

दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा रूपान्तर के अंतर्गत बोली प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन में अनियमितताओं पर एक प्रतिवेदन नि.म.ले.प. के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं. 1 में शामिल किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की गई कि शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने की अपनी भूमिका का कितने प्रभावकारी तरीके से निर्वहन किया था। शि.वि. के मुख्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा मार्च से जुलाई 2014 के दौरान की गई तथा स्वीकृत अनुमानों के आधार पर 39 विद्यालयों<sup>10</sup> का चयन किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है:

### 3-2-1- **वर्ष 2014 में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में शामिल किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की गई कि शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने की अपनी भूमिका का कितने प्रभावकारी तरीके से निर्वहन किया था। शि.वि. के मुख्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा मार्च से जुलाई 2014 के दौरान की गई तथा स्वीकृत अनुमानों के आधार पर 39 विद्यालयों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है:**

दि.रा.औ.अ.वि.नि. को 'पेशगी कार्य' के आधार पर परियोजना सौंपी गई थी, हालाँकि, पेशगी कार्य के विभिन्न पहलुओं को निबंधन एवं शर्तों में रखते हुए, निदेशालय एवं दि.रा.औ.अ.वि.नि. के बीच कोई समझौता नहीं किया गया था। किसी औपचारिक समझौते के अभाव में, शि.नि. सार्वजनिक हित का रक्षोपाय करने की स्थिति में नहीं था जैसाकि आगे के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है। शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ था क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. दिल्ली सरकार का एक अंग है और निर्माण/नवीकरण की दरें के.लो.नि.वि. सूची दरों के अनुसार थीं। इनका दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. एक सरकारी उपक्रम है न कि एक सरकारी विभाग।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने मेसर्स आई एल एण्ड एफ एस एजूकेशन एण्ड टेक्नॉलॉजी सर्विसेज के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 198 विद्यालयों में प्रत्येक के लिए अनुमान तैयार किए। परंतु ये मात्र वित्तीय प्रस्तावनाएँ थीं, जिनमें कार्यों के विस्तृत विषय क्षेत्र, जैसे किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की संख्या व मात्रा सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार 'रूपांतर' परियोजना के लिए कार्य का विषयक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था।

शि.नि. ने बताया (जून 2014) कि कार्य का विषय क्षेत्र दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

### 3-2-2 **परियोजना प्रबंध समिति (परि.प्र.स.), सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में अक्टूबर 2008 में मासिक आधार पर, परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। परि.प्र.स. की एकमात्र आयोजित बैठक (नवम्बर 2008) का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया था। केवल परि.प्र.स. की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, दि.रा.औ.अ.वि.नि. को 101 स्कूलों के नवीनीकरण हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने से पूर्व उन्हें निदेशालय को दिखाने के लिए निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इन निविदाओं से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।**

परियोजना प्रबंध समिति (परि.प्र.स.), सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में अक्टूबर 2008 में मासिक आधार पर, परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। परि.प्र.स. की एकमात्र आयोजित बैठक (नवम्बर 2008) का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया था। केवल परि.प्र.स. की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, दि.रा.औ.अ.वि.नि. को 101 स्कूलों के नवीनीकरण हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने से पूर्व उन्हें निदेशालय को दिखाने के लिए निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इन निविदाओं से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

<sup>10</sup> ₹ 2.00 करोड़ और अधिक के अनुमान वाले 50 प्रतिशत विद्यालय (15 विद्यालय), ₹ 1.00 करोड़ और अधिक के किन्तु ₹ 2.00 करोड़ से कम अनुमान वाले 20 प्रतिशत विद्यालय (15 विद्यालय) और ₹ 1.00 करोड़ से कम के अनुमान वाले 10 प्रतिशत विद्यालय (09 विद्यालय)



इसके जवाब में, शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि यद्यपि समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती थी, परन्तु उनके कार्यवृत्त तैयार नहीं किए गए थे तथा निविदाओं के प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यह बताया गया कि संबद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उत्तर परियोजना की निगरानी पर परि.प्र.स. में गंभीरता की कमी होने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को प्रमाणित करता है।

### 3-2-3 dk kZeanjh vFlök mudk xj-1 eki u

किसी औपचारिक समझौते के न होने के कारण, परियोजना के पूर्ण होने के लिए कोई निर्धारित समयसीमा नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने जनवरी से मार्च 2012 के बीच 183 विद्यालयों के सम्बन्ध में समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। शि.नि. ने सभी प्रधानाचार्यों को दि.स.औ.अ.नि.नि. द्वारा पूर्ण होने का दावे किए गए कार्यों का सत्यापन करने को कहा। उपरोक्त 183 विद्यालयों में से मात्र 128 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों द्वारा सत्यापन किया गया, जिनमें से मात्र 78 विद्यालयों में कार्य पूर्ण किया गया था और अन्य 50 में प्रगति पर था, जो यह दर्शाता है कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समापन रिपोर्टों में गलत तथ्य दर्शाए। अतः जून 2014 तक 105 विद्यालयों<sup>11</sup> में कार्य प्रगति पर था या प्रधानाचार्यों द्वारा सत्यापन शेष था।

शि.नि. (जून 2014) ने बताया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद दि.रा.औ.अ.वि.नि. कार्य पूर्ण नहीं कर पाया और विलम्ब हेतु कारण बताने में असमर्थ था। फिर भी यह तथ्य ही है कि शि.नि. एक औपचारिक समझौता न होने के कारण कार्य पूर्ण कराने में असफल रहा।

### 3-2-4 fn-jkvlsv-fo-fu- dks ₹ 70 djkm-dk vfu; fer Hxrkü fd; k t luk

मंत्रिमंडल ने ₹ 272.94 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ इस परियोजना को अनुमोदित किया था, जिसमें से 50 प्रतिशत का भुगतान संस्वीकृति के समय एवं शेष 50 प्रतिशत का वि.अ. से समापन प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर किया जाना था। हालाँकि, अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता था कि मंत्रिमंडल अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए वि.अ. से समापन प्रमाण-पत्रों को बिना प्राप्त किए ही दि.रा.औ.अ.वि.नि. को फरवरी 2011 तक ₹ 194 करोड़ का भुगतान जारी किया गया था। आगे यह पाया गया कि, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने जून 2011 में ₹ 371.64 करोड़ के संशोधित अनुमान को प्रस्तुत किया था एवं ₹ 177.64 करोड़ के शेष भुगतान को जारी करने हेतु निवेदन किया था। शि.नि. की अक्टूबर 2011 में कुल भुगतान को ₹ 258.14 करोड़ (13 स्कूलों के लिए ₹ 14.80 करोड़ के धनराशि की कटौती करने के पश्चात्, जहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था) सीमित करते हुए ₹ 64.14 करोड़ जारी किये थे। जब दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने शेष ₹ 98.70 करोड़ को जारी करने के लिए पुनः निवेदन किया तो शि.नि. ने मार्च 2012 में मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन पर ₹ 85 करोड़ जारी किया, यद्यपि न तो मंत्रिमण्डल के द्वारा संस्वीकृति में संशोधन किया गया था और न ही सभी स्कूल अध्यक्षों से समापन रिपोर्टों को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के दि.रा.औ.अ.वि.नि. को जारी किया गया ₹ 70.19 करोड़ (₹ 343.13 करोड़ - ₹ 272.94 करोड़) अनियमित था।

<sup>11</sup>50 विद्यालयों में कार्य अपूर्ण और 55 विद्यालयों में सत्यापन शेष था।

अपने जवाब में, शि.नि. ने कहा (जून 2014) कि संशोधित अनुमान के लिए अनुमोदन उस समय प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि दि.रा.औ.वि.नि. के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी। इनका जवाब युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि भुगतान जारी होने से दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति और न ही सभी वि.अ. से समापन रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।

### 3-2-5 वि.रा.औ.वि.नि. को 198 सरकारी स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन हेतु किराये पर लिया गया था। यद्यपि अभिलेखों की संवीक्षा से, निम्नांकित कमियों का पता चला:

(i) जुलाई/अगस्त 2011 में योजना विभाग द्वारा परियोजना हेतु किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, 14 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने सूचित किया कि कार्य संतोषजनक था, 33 प्रतिशत ने आंशिक संतुष्टि व्यक्त की और 53 प्रतिशत अपने स्कूलों में निष्पादित किए गए कार्य से संतुष्ट नहीं थे।

(ii) 39 चयनित स्कूलों में से, 36 विद्यालयों के अभिलेखों को लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया। अभिलेखों की जाँच और लेखापरीक्षा दल एवं विद्यालय के वि.अ. द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षणों से बहुत-सी कमियों का पता चला 3-1½ प्रमुख कमियाँ शौचालयों, क्रीड़ा-स्थलों, वर्षा जल की नालियों, पथों के विकास कार्यों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं बागवानी कार्य के क्षेत्रों में पायी गई थीं। इस परियोजना के तहत स्कूलों में पानी के शुद्धिकरण हेतु रीवर्स ओस्मोसिस सिस्टम (आर.ओ.) लगाए जाने थे, लेकिन दि.रा.औ.वि.नि. ने किसी भी चयनित स्कूल में आर.ओ. तंत्र नहीं लगाया था।

इस प्रकार औपचारिक समझौता न होने और कार्य का विस्तृत विषय क्षेत्र न होने के कारण शि.नि. यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि दि.रा.औ.वि.नि. द्वारा, ₹ 343.13 करोड़ जारी करने के बावजूद, परियोजना में परिकल्पित सभी कार्यों को पूर्ण किया गया। इसमें से ₹ 70.19 करोड़ मंत्रिमण्डल की मंजूरी के बगैर जारी किए गए। प्रभावी निगरानी नहीं थी क्योंकि पीएमसी नियमित रूप से बैठक नहीं करती थी।

मामले को जनवरी 2015 में सरकार के पास भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### लोक निधि; वित्त विभाग; केंद्र लेखा

#### 3-3 ₹ 1-26 द्वा.रा.औ.वि.नि. को ;

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 का नियम 21 कहता है कि लोक निधि से व्यय या व्यय को अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिये।

अगस्त 2005 में, लो.नि.वि. ने निदेशक, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक आदि के लिये अस्पताल परिसर में चार बंगलों के (टाईप VI) निर्माण हेतु ₹ 68.16 लाख के प्रारंभिक

अनुमान को प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति (प्र.अ.औ.व्य.सं.) हेतु चिकित्सा अधीक्षक (चि.अ.), जीटीबी अस्पताल को प्रस्तुत किया। हिस्ट्री रिपोर्ट में (अनुमान के अंश के रूप) यह उल्लेखित किया गया कि, भवनों की आवश्यकता चि.अ., जीटीबी द्वारा उनके कक्ष में की गयी बैठकों में उठायी गयी। यद्यपि, अभिलेखों में न तो अस्पताल से औपचारिक प्रस्ताव/ माँग और न ही बैठकों के कार्यवृत्त, जिसमें चि.अ., जीटीबी ने भवनों की आवश्यकता बतायी थी, उपलब्ध थीं। फिर भी, चि. अ., जीटीबी ने (मार्च 2006) ₹ 68.16 लाख के प्र.अ.औ.व्य. सं. को स्वीकृति दी जो बाद में वित्त विभाग की सहमति से संशोधित होकर दिसंबर 2008 में ₹ 1.34 करोड़ हो गयी। बंगलों का निर्माण सितम्बर 2008 में ₹ 1.26 करोड़ की कुल लागत पर पूरा हुआ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लो.नि.वि. ने अप्रैल 2009 में चि.अ., जीटीबी से नये निर्मित बंगलों को अधिकार में लेने का अनुरोध किया। यद्यपि, अस्पताल ने चि.अ., जीटीबी द्वारा नामित टीम के निरीक्षण करने के बाद फरवरी 2010 में बंगलों को अधिकार में लिया।

पुनः यह देखा गया कि प्रधानाचार्य, यूसीएमएस<sup>12</sup> तथा चि.अ., जीटीबी ने व्यक्तिगत कारणों से इन बंगलों में रहने में असमर्थता दिखाई। बंगले अन्य अधिकारियों को भी आबंटित नहीं किये जा सके क्योंकि इन बंगलों की कोई माँग नहीं थी। इसके फलस्वरूप (फरवरी 2010) यह निर्णय किया गया कि दो बंगलों का उपयोग 'संकाय क्लब/तनाव-मुक्ति कक्ष' की तरह और शेष दो का उपयोग 'गेस्ट हाउस' की तरह किया जाये। बंगलों के उपयोग में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए स्वा.औ.प.क.वि. को अगस्त 2011 में भेजा गया। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस कर दिया (अक्टूबर 2011), लेकिन फाईल तब से गायब रही (सितम्बर 2014)। इससे आगे, अस्पताल ने इन भवनों का रख-रखाव और निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि वर्तमान में इनकी स्थिति खराब है।

पाँच वर्षों से अधिक बंगलों को काम में न लाया जाना, केवल यह प्रकट करता है कि बंगले बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के निर्मित किये गये तथा इन बंगलों के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल था।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

; -r , oafi Yk foKku l 1.Fku

3-4 l 1.Fku dsfct ud ekMy l sfopyu

l 1.Fku viusfct ud ekMy l sfopyr gksx; kD; kD ; g viusl alk  
l nL; k dks , d , deqr l 1.Fku viusl dsct k; fu; fer orueku  
o Hkls dk Hkrku dj jgk FkA ef=emY dk vuoknu iHr fd; sfcuk  
LVkQ dks ns njk l svf/kd ij jkt Lo fgLl k ekMy ds fo: ) edku  
fdjk; k Hkls o okd vfHof) rFk l alk, l nL; k dks xS-Q ogk; ZHkls  
fn; k x; kA

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (संस्थान) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में अक्टूबर 2002 में पंजीकृत हुआ, जिसका उद्देश्य वहन करने योग्य

<sup>12</sup>चिकित्सा विज्ञान के महाविद्यालय

लागत पर विश्व स्तरीय रोगी की देखरेख, यकृत एवं पित रोगों पर अनुसंधान, स्नातकोत्तर/ पोस्ट डॉक्टरेट स्तर पर शिक्षण व प्रशिक्षण, इत्यादि प्रदान करना था। इस संस्थान का प्रबन्धन व प्रशासन कार्यकारी परिषद (का.प.) के द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. है। का.प. के सदस्यों में प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (स्वा. एवं. प. क.) व चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हैं। इस संस्थान का वित्त पोषण प्रमुखतः अपने संसाधनों तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान से होता है।

अस्पताल सेवाएँ परामर्श निगम (अ.से.प.नि.) ने संस्थान के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे मंत्रिमंडल द्वारा मई 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस बिजनेस मॉडल के अनुसार, संस्थान के सभी चिकित्सकों व स्टाफ को चार वर्षों के लिए संविदा के आधार पर रखा जाएगा, जिसकी अवधि कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाई जाएगी व वेतन ढाँचा सलाहकारों व प्रोफेसरो को छोड़कर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के वेतन के समान होगा। सलाहकारों व प्रोफेसरो हेतु, यह पद वेतनमान पर न होकर अगले स्तर के पद हेतु एकमुश्त पैकेज पर होगा। मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए पैकेज को संशोधित किया जाएगा। यह बिजनेस मॉडल सभी सलाहकारों, प्रोफेसरो, सह प्रोफेसरो एवं सहायक प्रोफेसरो को पारिश्रमिक पैकेजों में राजस्व हिस्सा भी प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष परवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि संस्थान ने अपने नियुक्ति पत्रों के अनुसार समेकित मासिक वेतन पर प्रोफेसरो, अतिरिक्त प्रोफेसरो, सह प्रोफेसरो एवं सहायक प्रोफेसरो को नियुक्त किया। हालाँकि, उन्हें पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 में निर्धारित वेतनमानों पर आधारित दूसरे भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मँहगाई भत्ता, गैर-व्यवहार्य भत्ता (गै.व्य.भ.) इत्यादि के साथ वेतन का भुगतान किया जा रहा था। 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक अभिवृद्धि उनके मूल वेतन (ग्रेड वेतन व गै.व्य.भ. सहित) पर अनुमत थी। संकाय सदस्यों<sup>13</sup> में से चार मामलों (प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, सह प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर में प्रत्येक के संवर्ग में) की लेखापरीक्षा जाँच ने यह दर्शाया कि इन मामलों में अदा की गई मासिक निवल धनराशि बिजनेस मॉडल के अनुसार दी जाने वाली धनराशि से अधिक थी। नियुक्ति पत्रों के अनुसार जो धनराशि अदा किए जाने की सहमति है, उसका भी पालन नहीं किया गया। वास्तविक वेतन में ये अवयव शामिल हैं जैसे कि मूल वेतन, मँहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, गै.व्य.भ., यात्रा भत्ता, अ.भ.नि., टेलीफोन भत्ता, इंटरनेट भत्ता, बाल शिक्षण भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं शैक्षणिक भत्ता बिजनेस मॉडल में विचलन के रूप में दी गई है जैसाकि **वृत्त 3-2** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्य राजस्व हिस्से के हकदार थे। संस्थान की वित्त समिति ने बिजनेस मॉडल के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी लागू किए जाने तक संकाय सदस्यों को गैर-व्यवहार्य भत्ता की अनुमति दी (नवम्बर 2008)। इसे अप्रैल 2009 में शासी परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। हालाँकि संस्थान ने राजस्व हिस्से को सितम्बर 2014 तक क्रियान्वित नहीं

<sup>13</sup> 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान संकाय सदस्यों की कुल संख्या औसतन 40 ओर 50 के बीच थी।

किया था और राजस्व हिस्से के स्थान पर गै.व्य.भ. का भुगतान जारी रखा। संस्थान ने 2009 से 2014 के दौरान अपने संकाय सदस्यों को और इससे भत्तों में वृद्धि के लिए गै.व्य.भ. ₹ 5.39 करोड़ का भुगतान किया।

(ii) एम्स में मकान किराया भत्ता (म.कि.भ.) मूल वेतन व ग्रेड वेतन के जोड़ के 30 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है जैसा कि पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 के अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को देय है। हालाँकि संस्थान अपने सभी कर्मचारियों (संकाय, असंकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ) को मूल वेतन व ग्रेड वेतन के जोड़ के 30 प्रतिशत की दर के बदले 50 प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2009 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 10.12 करोड़ का अधिक व्यय किया। इसी प्रकार, एम्स अपने स्टाफ को मूल वेतन व ग्रेड वेतन तथा गै.व्य.भ. (जहाँ लागू है) के जोड़ के तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि करता है। हालाँकि, संस्थान अपने स्टाफ, को मूल वेतन, ग्रेड वेतन व गैर व्यवहार्य भत्ता (जहाँ लागू हो) के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति देता है।

इस प्रकार, संस्थान ने संकाय सदस्यों को नियमित वेतनमान और गै.व्य.भ. सहित भत्ते का भुगतान किया, और वार्षिक अभिवृद्धि की भी स्वीकृति मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित बिजनेस मॉडल के उल्लंघन में दी। आगे, म.कि.भ. और वार्षिक अभिवृद्धि का भुगतान भी कर्मचारियों को उच्च दरों पर किया। संस्थान के ये निर्णय न्यायसंगत नहीं थे, क्योंकि इनकी मंजूरी मंत्रिमण्डल द्वारा नहीं की गई थी।

अपने जवाब में, संस्थान ने कहा (सितम्बर 2014) कि संस्थान की कार्यकारी परिषद को संकाय सदस्यों, अन्य अधिकारियों व स्टाफ की नियुक्ति करने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। इसमें यह भी बताया गया कि सभी पदों के लिए वेतन पैकेज की सिफारिश एक कार्यकारी समूह द्वारा जिसमें वित्त विभाग के सदस्य भी सम्मिलित हैं, की गई जिसे प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा पृष्ठांकित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि राजस्व अंश के बजाय गै.व्य.भ. के भुगतान के परिणामस्वरूप संकाय सदस्यों एवं सलाहकारों को निम्न वेतन पैकेज दिया गया व राजकोष की बचत हुई।

जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्यकारी परिषद को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित बिजनेस मॉडल के ढाँचे के भीतर अपने अधिकारों को लागू करना अपेक्षित है। आगे, प्रधान सचिव (वित्त) का अनुमोदन केवल संकाय सदस्यों के लिए एम्स के अगले स्तर हेतु एक मुश्त पैकेज पर और शेष कर्मचारियों के लिए एम्स के प्रचलित वेतनमान के अनुसार भुगतान पर दिया गया था। इसका यह तर्क कि राजस्व हिस्से के स्थान पर गै.व्य.भ. के भुगतान से वेतन पैकेज कम होता है, तथ्य से सिद्ध नहीं होता क्योंकि राजस्व हिस्से का फार्मूला अभी संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

यह पैराग्राफ सरकार को नवम्बर 2014 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

**xg foHkx**

**3-5 fct yh fcykij ₹ 70-06 yk[k dk ifjgk ZQ ;**

**oKkfud tlp iz kx'kyk }kjk vius l fonk Hkj dk vkdyu ml dh oKrfod vk'; drk ds vuq i djus ea foQy gkus ds ifj. keLo: i ₹ 70-06 yk[k dk ifjgk ZQ ; gqk**

दिल्ली में उत्तरी दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) गैर घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए संविदा भार पर माँग प्रभार की उगाही वास्तविक उपभोग के बावजूद ₹150 प्रति कि.वो.ए. प्रतिमाह की दर से करती है।

वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला (वै.जाँ.प्र.), रोहिणी के पास अपनी बिल्डिंग के लिए उत्तरी दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) से संस्वीकृत भार 1413 कि.वा. एवं संविदा भार 1663 कि.वो.ए. का गैर घरेलू बिजली कनेक्शन (क.स. 441026025300) दिनांक 7 अगस्त 2003 को किया गया है। वै.जाँ.प्र. सितंबर 2008 से जुलाई 2012 की अवधि के वै.जाँ.प्र. के बिजली बिलों की जांच से प्रदर्शित हुआ है कि वास्तविक उपभोग 674 कि.वो.ए. एवं 192 कि.वो.ए.प्रतिमाह के बीच में रहा, साथ ही अगस्त 2010 में अधिकतम उपभोग 674 कि.वो.ए.था। हालांकि, एनडीपीएल ने संविदा भार (1663कि.वो.ए.) पर 150 प्रति कि.वो.ए. प्रतिमाह की दर से माँग प्रभार लगाया। इस प्रकार, वै.जाँ.प्र. अपनी आवश्यकता से अधिक माँग प्रभार का भुगतान कर रहा था। वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला द्वारा अपने संविदा भार का आकलन उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 70.06 लाख<sup>14</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर (अगस्त 2012) वै.जाँ.प्र. ने सूचित किया (मई 2013) कि उसने अपनी संविदा माँग को घटवाकर 16 फरवरी 2013 से 1663 कि.वो.ए. के बजाय 625 कि.वो.ए. प्रतिमाह करा लिया है। जिससे यह पुनः सिद्ध हो जाता है कि वै.जाँ.प्र. ने सितम्बर 2008 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए प्रतिमाह 1038 कि.वो.ए. (1663 कि.वो.ए.–625 कि.वो.ए.) पर अतिरिक्त माँग प्रभार का भुगतान किया।

मामला सितंबर 2014 में सरकार के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

**Je-foHkx**

**fnYyh Hou , oavU fuekZk Jfed dY; k k ckMZ**

**3-6 ₹ 37-10 yk[k ds C; kt dh gkfu**

**vLoh-r@okil fd, x, pdl dh mi dj jk'k dks ol y djus grq' k?k dkjZkZ ijk djus ea ckMZ , oa mi k æ Je dh fuf'Ø; rk ds dkj. k ₹ 37-10 yk[k ds C; kt dh gkfu gqA ckMZ us yk[k jh'k ea bfxr ₹ 4-80 dkMZ-eal s ₹ 3-95 dkMZ-dh ol yh dh**

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत दिल्ली

<sup>14</sup>1038 कि.वो.ए. x ₹ 150 x 45 महीने

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) निर्माण एजेंसियों से एक प्रतिशत उपकर संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है। उपकर भुगतानकर्ता देय उपकर को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित उपायुक्त-श्रम (डीएलसी) के कार्यालय में चेकों के रूप में जमा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु बोर्ड 10 अप्रकार्यात्मक बैंक खातों का प्रचालन कर रहा है, जिसमें से एक मुख्यालय में है और नौ को डीएलसी कार्यालयों को आबंटित किया गया है जो कि बोर्ड के मुख्य/प्रधान खातों से संबद्ध हैं। डीएलसी कार्यालयों में प्राप्त किए गए चेकों को उनके द्वारा उनसे संबंधित उपकर खातों में जमा किया जाता है। यदि, किसी कारणवश कोई चेक अस्वीकृत कर दिया जाता है तो अस्वीकृति रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा के द्वारा बोर्ड को भेज दी जाती है। बोर्ड, उसके बाद, डीएलसी कार्यालयों से उपकर राशि को वसूल करने के लिए निवेदन करता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा एवं बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि जनवरी 2010 से फरवरी 2014 के दौरान, ₹4.80 करोड़ के 94 चेकों को बैंक के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। चेकों को सामान्यतः आदेशक के खाते में अपर्याप्त निधियों के होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था अथवा चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने से पहले समय बाधित हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, कुछ चेकों को वापस कर दिया गया था क्योंकि उन्हें बोर्ड के बजाय डीएलसी के पक्ष में निकाला गया था। बोर्ड ने इन अस्वीकृत किए गए /वापस किए गए चेकों के अनुरूप राशि को वसूल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2014) कि ₹ 4.80 करोड़ में से ₹ 4.00 करोड़ की वसूली हो चुकी है। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 35 चेकों से प्राप्त ₹ 3.95 करोड़ की राशि को ही सत्यापित किया जा सका। यद्यपि, बोर्ड ने ₹ 3.95 करोड़ की वसूली तब की जब लेखापरीक्षा के द्वारा फरवरी 2014 में इसे इंगित किया गया, लेकिन तब तक इस राशि को वसूल किए जाने की कार्रवाई में विलम्ब किए जाने के कारण ₹ 37.10 लाख<sup>15</sup> के ब्याज की हानि पहले ही हो चुकी थी।

मामले को सितंबर 2014 में सरकार के पास भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### यकल फुलक फोहक

3-7 फुफुक वलर fd, fcuk vfu; fer : i l s ₹ 1-77 djkm-dk dk Zl lk t kuka

यकल फुलक फोहक jkjk{ksn-l - us ₹ 1-77 djkm-dk dk Zl {ke i f/kdjh ds i wZvuoknu , oa [lyh fufonk vle. k dsfcuk fu/wjr fu; ekdk mYyaku djrs gg l kka dk Zea 551 fnuk dh njh l si yk gya

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली, 2012 का अनुच्छेद 14.1(1) अनुबंध करता है कि ₹ 50,000 से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के लिए सामान्यतः निविदा आमंत्रित करनी चाहिए। जिन मामलों में कार्य शीघ्र प्रदान करना हो, अत्यावश्यक मामलों में सूचना की निर्धारित अवधि को घटाया जा सकता है, अथवा अधिक महत्व वाले कार्यों में या जहाँ

<sup>15</sup> अस्वीकृत किए गए/समय बाधित हुए चेकों की तारीख से नए चेकों (₹ 3.95 करोड़ की राशि) की तारीख तक प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर पर परिकलित और शेष चेकों पर, ब्याज की गणना चेक की तारीख से 4 सितम्बर 2014 तक की गई थी

उनको शीघ्र करना आवश्यक हो, कार्य को **ifjf'KV-I** में दिए अधिकारों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद बिना निविदा आमंत्रित किए प्रदान किया जा सकता है। **ifjf'KV-I** के अनुसार मुख्य अभियन्ता अपने प्राधिकार के तहत ₹ 25 लाख तक ए.डी.जी. के पूर्व अनुमोदन के साथ ₹ 100 लाख तक एवं डी.जी. के पूर्व अनुमोदन के साथ ₹180 लाख तक के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए प्रदान कर सकता है।

लोक निर्माण विभाग के मंडल एम-112 के अभिलेखों की जांच से प्रदर्शित हुआ कि मुख्य अभियन्ता (एम-1) ने मार्च 2012 में "यू मोड़ प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर लाल बत्ती (दिल्ली रोहतक रोड पर पीरागढ़ी से मुंडका तक सुचारु यातायात के लिए) के निष्कासन" के कार्य के लिए ₹ 95.86 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (प्र.अ. एवं व्य.सं.) प्रदान की। कार्यपालक अभियन्ता (एम-112) ने (जून 2012) कार्य ₹ 70.48 लाख के निविदा मूल्य पर सौंप दिया जो ₹ 94.28 लाख की अनुमानित लागत से 25.25 प्रतिशत कम था। कार्य के आरम्भ करने एवं पूरा करने की अनुबद्ध तिथियों क्रमशः 2 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 के साथ प्रदान किया। कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि 3 जनवरी 2014 थी।

लेखापरीक्षा जांच में आगे प्रकट हुआ कि मुख्य अभियन्ता (एम-1) ने "पीरागढ़ी से मुंडका के लिए सुचारु यातायात हेतु रा.राजमार्ग-10 (दिल्ली रोहतक रोड) पर यू मोड़ प्रदान करने के लिए आर.सी.सी. नाले के स्थानांतरण" के कार्य के लिए अलग से ₹ 1.77 करोड़ का प्र.अ. एवं व्य.सं. प्रदान किया। अनुमान दस्तावेज में इस कार्य के पूरा होने का निर्धारित समय 2 महीने दर्शाया गया था। यह अतिरिक्त कार्य मौजूदा ठेकेदार को कार्य पूरा होने में देरी से बचने की दलील देकर खुली निविदा आमंत्रण के बिना सौंपा गया। ₹ 2.59 करोड़ की राशि (अतिरिक्त मदों के लिए ₹ 1.48 करोड़ सहित) अतिरिक्त कार्य के लिए जारी की जा चुकी थी। कार्य पूरा होने में विलंब से बचने के लिए विभाग द्वारा दी गई दलील भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि मूल कार्य वास्तव में 551<sup>16</sup> दिनों की देरी से पूरा हुआ।

इसलिए विभाग ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं खुली निविदा आमंत्रण के बिना ₹ 1.77 करोड़ का कार्य सौंपा, जिससे विभाग न केवल प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाने में असफल रहा अपितु ठेकेदार को अवांछित लाभ भी दिया गया।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### 3-8 dk; Zinku djus dh vfu; fer Loh-fr

yk d fuekZk foHkx dseq ; vfHk; ūrk ¼ et M-3½rFlk v/ħk k vfHk; ark ¼ e-35½us i k k ft r foHk; 'kã; k dk mYyaku djrs gq , d dk Zds rhu foHkft r Hkxk ds fy, vfu; fer : i l s ₹ 13-54 djM+ dh cky; k Loh-r dH

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली के **ifjf'KV-I** के मद सं. 20 में यह अनुबद्ध है कि ₹ 16 करोड़ से अधिक के कार्य के विभाजित अंशों अथवा विशिष्ट उप-शीर्ष की निविदाएँ केन्द्रीय कार्य बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जाएँगी। इस प्रावधान की टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण/विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विभाजित कार्यों की निविदाएँ उस प्राधिकारी

<sup>16</sup> 1 जुलाई 2012 से 2 जनवरी 2014 तक



द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए जिसने मूल कार्य को संस्वीकृति विभाजित घटकों के प्रस्तुत मूल्य की अपेक्षा किए बिना प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग के दो डिविजनों<sup>17</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि "802 सं. के डी ए फ्लैट्स-टाइप बी, सी तथा डी, तिमारपुर दिल्ली के अतिरिक्त साधारण मरम्मत के उन्नयन" कार्य के लिए लो.नि.वि. के सहायक आवास आयुक्त ने ₹ 18.72 करोड़<sup>18</sup> के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की जानकारी दी (जनवरी 2012)। विभाग ने कार्य को दो भागों में बाँटा-पैकेज I-एस.एच-392 फ्लैट्स जिनमें 360 फ्लैट्स टाइप 'बी'के तथा 32 फ्लैट्स टाइप 'डी'के हैं तथा पैकेज II- एस.एच-410 फ्लैट्स जिनमें 320 फ्लैट्स टाइप 'बी' के तथा 90 फ्लैट्स टाइप 'सी' के हैं।

लेखापरीक्षा जाँच में आगे यह पाया गया कि मुख्य अभियंता (एम जैड-3) ने पैकेज-II के सिविल भाग की ₹ 9.09 करोड़ की बोली की स्वीकृति के लिए दिल्ली कार्य सलाहकार बोर्ड (डी डब्ल्यू ए बोर्ड) से अनुमोदन माँगा जबकि पैकेज-I के सिविल भाग की बोली मुख्य अभियंता (एम जैड-3) द्वारा ₹ 9.03 करोड़ के प्रस्तुत मूल्य पर (मार्च 2013) स्वीकृत की गई। दोनों पैकेजों के विद्युत भाग के लिए अधीक्षण अभियन्ता (एम-35) द्वारा नवम्बर 2012 में ₹ 2.25 करोड़ के विक्रय मूल्य पर तथा दिसम्बर 2012 में ₹ 2.26 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बोलियाँ स्वीकृत की गईं।

इस प्रकार डी.डब्ल्यू.ए.से स्वीकृति के बिना एक कार्य के तीन विभाजित भागों के लिए ₹ 13.54 करोड़ की बोली की स्वीकृति ने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन किया तथा अनियमित रही।

यह बताए जाने पर अधिशासी अभियंता (एम-323) ने कहा (जून 2014) कि 14 मार्च 2013 में हुई दिल्ली कार्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में मुख्य अभियंता (एम जैड-3) ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा खर्च की संस्वीकृति एकल थी, इसे दो पैकेजों में बाँटा गया था तथा पैकेज I के सिविल भाग की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की योग्यता के भीतर थी। इसके आगे यह कहा गया कि पैकेज I की बोली मुख्य अभियंता द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ स्वीकृत की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता ने विभाजित कार्यों की स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की शक्तियों पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया तथा अनियमित रूप से पैकेज I की बोली को स्वीकृति दी जो डी.डब्ल्यू.ए के क्षेत्राधिकार के भीतर थी। ₹ 18.72 करोड़ के कार्य की एकल मंजूरी तथा विभाजित कार्यों की बोलियों की स्वीकृति केवल डी.डब्ल्यू.ए बोर्ड की योग्यता में थी।

मामला सरकार को अगस्त 2014 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### 3-9 | **Melk ds l q<hdj.k ij ifjgk ZQ ; -₹ 73-31 yk[k**

fcVwsh l rg ij fuEu foLdkl Vh okys fcVwu feJ.k ds LFku ij mPprj  
fofunZku okys olt h10 xM ds gkLV LVW ju fcVwu ds bLrøky , oa, d  
VSl dkW ds LFku ij Mcy dkW yxkus ds ifj.kkLo: i ₹ 73-31 yk[k dk  
ifjgk ZQ ; gylA

<sup>17</sup> नगर भवन अनुरक्षण मण्डल (सीबीएमडीएम-323) एवं विद्युत अनुरक्षण मण्डल (ईएमडीएम-351)।

<sup>18</sup> ₹15.04 करोड़ सिविल एवं ₹ 3.68 करोड़ विद्युत कार्य हेतु।

लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग के दो नगर सड़क अनुरक्षण मण्डलों (एम-212 तथा एम-112) में 11 सड़कों के सुधार एवं सुदृढीकरण के कार्य की नमूना जाँच की। इन कार्यों के संविदा अनुबंधों में सम्मिलित सामान्य विनिर्देशों के अनुसार सड़क पर बिटूमन की दूसरी परत निर्माण करने से पहले उस पर कम गाढ़े बिटूमन पदार्थ की एक परत का कार्य होना चाहिए और इस परत में उपयोग किया जाने वाला बन्धक उचित श्रेणी का होना चाहिए। कार्य सड़क व पुल के कार्यों (IV पुनर्लेखन) 2001 के मोर्थ<sup>19</sup> विनिर्देशों के खण्ड 503 एवं उसके उपखंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

पुनः, अनुच्छेद 503.2.1- 'बन्धक' के अनुसार टैक परत के लिए उपयोगी बन्धक आई एस 8887 के प्रकार एवं श्रेणी वाला जैसाकि अनुबंध में निर्देशित या अभियंता द्वारा स्पष्ट किया हो ऐसा बिटूमन इमल्शन होना चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा जाँच में कार्य में निर्धारित विनिर्देशनों एवं प्रणालियों का उल्लंघन पाया गया जो निम्न प्रकार वर्णित है:

1/2 मण्डल (एम-212) के पाँच कार्यों में तकनीकी संस्तुति प्राप्त करने के लिए विस्तृत आकलन तैयार करते समय मण्डल ने टैक परत कार्य के लिए बिटूमन इमल्शन के स्थान पर वीजी 10 श्रेणी के हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन को सम्मिलित किया एवं उसे मात्रा अनुसूची में भी शामिल किया। परिणामस्वरूप जैसा कि **rfydk 3-9-1** में दिया गया है, सभी पाँचों कार्यों में वीजी-10 श्रेणी के लगातार हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन का उपयोग किया गया।

**rfydk 3-9-1 %oh t h&10 xM dsyxkrkj gkW LVW ju fcVwu dk mi ; lx**

1/2 क० ए०

Øe la	dk Zdk ule	fu'ikfnr ek=k %oxZelt½	Mh, l vkJ (*) ds vuq kj fcVwu fe.J.k dh nj	Mh, l vkJ (* ) ds vuq kj fcVwu %lt h 10½dj nj	vfrfjDr Q ;
1	2	3	4	5	6 {(5-4)x3}
	l qkj , oal q<kdj.k				
1.	कोंदली पुल से मदर डेयरी तक खिचड़ीपुर रोड इत्यादि (69/12-13)	98721.75	7.70	23.39	1548944
2.	चिल्ला चौक से नोयडा टी-पोएंट तक मेन त्रिलोकपुरी रोड इत्यादि (70/12-13)	28826.39	7.70	23.39	452286
3.	एनएच 24 से खिचड़ीपुर ब्लाक सं 1 तक की सड़क इत्यादि (71/12-13)	103182.85	7.77	23.60	1633385
4.	एनएच 24 से कोंदली पुल तक गाजीपुर नाला के साथ वाली सड़क इत्यादि (72/12-13)	21600.77	7.77	23.60	341940
5.	हाई लैंड अपार्टमेंट से सूचना अपार्टमेंट तक वसुन्धरा एनक्लेव वाली सड़क इत्यादि (81/12-13)	52939.41	7.94	24.10	855501
<b>clq</b>					<b>4832056</b>

(\*) Bxlnkj }kj k fuofnr Mh, l vkJ (-) 12 % (+) 8-05% (+/-) dh nj l sifr'kr nj dh x.kuk

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बिटूमन इमल्शन की तुलना में वीजी-10 श्रेणी का हॉट स्ट्रेट रन बिटूमन महंगा है। फिर भी, तकनीकी संस्तुति प्राप्त करने के लिए विस्तृत आकलन

<sup>19</sup> सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय

तैयार करते समय महंगी मद के उपयोग का तर्क दर्ज नहीं किया गया था। मोर्थ विनिर्देशों से विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 48.32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

1/2 मंडल एम-112 में छः कार्यों के निष्पादन में अनुबंध में निर्धारित एक कोट के स्थान पर सड़क की सतहों पर एक से अधिक बार टैक कोट लगाया गया था। संबंधित विवरण rkydk 3-9-2 में निम्न प्रकार दिया गया है:

rkydk 3-9-2 %vfrfjä Vsl ijr dk mi ; l

₹ k ₹ e

Øe- l a	l Ml dk uke	fu"i kñr l d ; k %xZ eh½	fu"i kñr Vsl dW vfrfjä l d ; k %xZeh½	nj	ifjgk ZQ ;
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	टंकी वाला मार्ग, टैगोर गार्डन एवं देवकी नंदन मार्ग(65/सीआरएमडी/एम-112/13-14)	48207.57	33146.65	8.25	273460
2.	पंजाबी बाग से जखीरा तक रोहतक रोड (73/ सीआरएमडी/एम -112/12-13)	192525.43	114232.91	6.81	777926
3.	रिंग रोड से मोती नगर तक शिवदास पुरी मार्ग(76/ सीआरएमडी/एम -112/12-13)	161932.77	101593.61	6.65	675598
4.	सं. 235 एक्सटेंशन तिलक नगर मेन रोड तथा सुभाष नगर नाला से पटेल नगर मार्ग तक(88/ सीआरएमडी/एम -112/13-14)	55070.96	32331.46	7.39	238929
5.	हंसराज माडल स्कूल से पंजाबी बाग तक, उत्तरी पश्चिम एवेन्यू रोड से पंजाबी बाग तक, पश्चिम पुरी चौक से नई झुगी क्वार्टर(102/ सीआरएमडी/एम -112/13-14)	59057.64	32877.69	8.98	295242
6.	एन जी रोड से एन जी नाला तक, मिलन सिनेमा से गृह सं 19/289 तक, गृह सं एच-1 से आई-42 तक, एच.आई.एल. से मिलन सिनेमा बस टर्मिनल तक, श्रीमति गिन्नी देवी रोड(118/ सीआरएमडी/एम .112/13-14)	67426.79	30477.67	7.79	237421
<b>dy</b>					<b>2498576</b>

इसलिए महंगी श्रेणी (वीजी-10) एवं अतिरिक्त टैक परत के उपयोग के परिणाम स्वरूप ₹ 73.31 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (जुलाई 2014) कि तकनीकी संस्तुति के लिए आकलन दिल्ली अनुसूची दर-2012 के आधार पर तैयार किये गये थे और तदनुसार कार्य निष्पादित हुआ। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सामान्य विनिर्देशों में निर्धारित कम गाढ़े तरल बिटूमन इमल्शन को अपनाने के बजाय विभाग ने बिना किसी उचित तर्क के महंगी मदों को अपनाया, विशेषकर जबकि अन्य मण्डल (एम-112) के छः नमूना जाँच में पाए गये उसी प्रकार के कार्यों में बिटूमन इमल्शन का उपयोग किया। विभाग का यह दावा कि जो आकलन दिल्ली अनुसूची दर के आधार पर किये गये थे, लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुरूप नहीं

हैं। दोहरी टैक परत चढ़ाने के बारे में विभाग का जवाब मौन था।

मामला जनवरी 2015 में सरकार को भेज दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### जैत लो फोहक

#### 3-10 हफे व्/कग.क द्यद्वजलध दक, लकय

हफे व्/कग.क द्यद्वज fu/कजर ले; ds हर्ज व्/कग.क ifØ; क्वा द्क  
 ijk djusearfk हफे द्क दत्त क यस l sigyseqkots dक हर्कु djuse  
 vl Qy jg\$ ft l ds ifj. के लो: i ₹ 12-68 djkm- dक ifjgk; ZC; kt हर्कु  
 djuk iMA rdkfydrk [M dks, d fu; fer < k l s ykxwfd; k x; k  
 FkA हफे व्/कग.क dh ifØ; k ds fu; fer fu; k. k djus ds fy, fu/कजर  
 l fefr; k dक xBu ughafd; k x; kA

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा 1 जनवरी 2014 से प्रभावी उचित मुआवजा के अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत भूमि के अधिग्रहण को नियंत्रित किया जाता है।

‘भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की कार्य प्रणाली’ का अधिग्रहित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर 2011-14 तक की अवधि का लेखापरीक्षण चयनित 11 में से 4 जिलों में आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में चयनित जिलों के सभी 48 मामलों<sup>20</sup> की और भूमि एवं भवन विभाग में प्रासंगिक अभिलेख की जाँच हुई।

#### 3-10-1 ₹ 12-68 djkm-dsC; kt dक ifjgk; ZHर्कु@ns rk

लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों ने 18 मामलों में ₹ 12.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 ए के अनुसार कलेक्टर को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर एक अधिनिर्णय लेना चाहिए। हालांकि ₹ 26.01 करोड़ के मुआवजे से जुड़े पाँच मामलों में 12 वर्षों तक की अवधि के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई विलंबित रही। इस देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान/देयता करना पड़ा।

(ii) धारा 34 के तहत, यदि भूमि पर कब्जा करने पर या उससे पहले मुआवजा नहीं दिया गया तो भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के लिए अधिनिर्णित राशि पर 9 फीसदी की दर से ब्याज देय रहेगा और उसके बाद 15 फीसदी से देय रहेगा। हालांकि, 13 मामलों में, कब्जा लेने पर या उससे पहले ₹ 158.10 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान तथा ₹ 6.01 करोड़ की देनदारी हुई।

अपने उत्तर में (जून 2014), भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तरी पश्चिम) ने कर्मचारियों की कमी

<sup>20</sup> (i) जिलेवार विवरण-दक्षिण-19, दक्षिण पूर्व-9, उत्तर पश्चिम-7 और उत्तर-13 (कुल 48 मामले) (ii) विभाग/ एजेंसी वार विवरण - डी.एम आर सी-18, डीडीए-14, दिल्ली जल बोर्ड-6, पी डब्ल्यू डी-5, एम सी डी-3 और डेसू-2 (कुल 48 मामले)

व कानूनी स्पष्टीकरण के अभाव को जिम्मेदार ठहराया। जबकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर) ने (अगस्त 2014) कहा कि उनकी ओर से विलम्ब नहीं किया गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तरी पश्चिम) ने दिसम्बर/ जनवरी 2013 में ही अभिलेखों का स्थानांतरण किया था। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उत्तरी पश्चिम जिले ने वर्ष 2011-14 के दौरान कुछ ही (कुल 7) अधिनिर्णयों की घोषणा की थी तथा विलम्ब समग्र रूप से विभाग की ओर से हुआ था।

### 3-10-2 Hfe dk vfrfj ä vf/kxg. k

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने (फरवरी 2012) भूमि एवं भवन विभाग से ओखला गांव में 129.24 वर्गमीटर की भूमि के लिए अनुरोध किया। इसके पश्चात 24 सितंबर 2013 को डीएमआरसी ने एलएसी (दक्षिणी पूर्व) को सूचना दी कि केवल 77.71 वर्गमीटर की भूमि पर्याप्त होगी। हालांकि, एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने दिसम्बर 2013 के अधिनिर्णय में 129.46 वर्गमीटर की भूमि का अधिग्रहण कर लिया लेकिन डीएमआरसी को केवल 77.71 वर्गमीटर की भूमि का कब्जा दिया गया। शेष भूमि और जमींदारों को मुआवजा जारी करने की स्थिति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने कहा (दिसम्बर 2014) कि मामला प्रगति पर है।

### 3-10-3 vuqj d vf/kfu. k dh vukf/k-r ?kšk k

(i) भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2012 को जारी किए गए ओ एम सं.-15519-33 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2012 से कोई भी अनुपूरक अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जाना था। हालांकि लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि एलएसी (दक्षिण) ने जून 2011 में अधिग्रहित भूमि मौजूदा संरचनाओं के संबंध में ₹ 3.06 करोड़ के एक अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा की। जुलाई 2009 के पहले के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2012 में अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा की गई। प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 3.06 करोड़ के मुआवजे का अनाधिकृत भुगतान करना पड़ा।

(ii) भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जारी किए गए स्थाई निर्देशों के पैरा 2 (v) में यह कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों को सुपर संरचनाओं के मूल्यांकन के अनुमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करने चाहिए तथा केवल उन्हीं अधिकृत निर्मित संरचनाओं के मूल्यांकन के अनुमान मान्य है जो दिल्ली नगर निगम या दि.वि.प्रा. से अनुमोदित हों। हालांकि लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि पाँच मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई जानकारी शामिल नहीं थी कि इन संरचनाओं को दिल्ली नगर निगम या दि.वि.प्रा. द्वारा अधिकृत किया गया है या नहीं।

### 3-10-4 vf/kfu; e dsrkdkfydrk [kM dks vuqpr : i l sykxwdjuk

स्थायी निर्देशों के पैरा 1(एम) के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, जब भूमि की आवश्यकता तात्काल और समयबद्ध परियोजनाओं के लिए हो। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि 48 चयनित मामलों में से 35 मामलों में तात्कालिकता खंड लागू किया गया था। हालांकि घोषणा के जारी करने के बाद, एलएसी (दक्षिणी पूर्व) ने आठ ऐसे मामलों में से चार मामले

निश्चित करने में तीन से सात महीनों का समय लिया। शेष मामलों में, अधिनिर्णयों की घोषणा 17 महीनों के बाद से लेकर 12 वर्षों तक की गई थी, जबकि किसानों के पास अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के प्रकाशन के खिलाफ अपील करने के लिए केवल 15 दिन थे। यह दर्शाता है कि तात्कालिकता खंड का नियमित रूप से प्रयोग किया गया था जबकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की ओर से कोई अत्यावश्यकता नहीं देखी गई।

### 3-10-5 cdk k eqkot k

(i) 42 मामलों में, भूमि एवं भवन विभाग द्वारा 11 से लेकर 49 महीनों तक के बीच की देरी के साथ संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों को ₹ 52.16 करोड़ का मुआवजा जारी किया जाना बाकी था। विलम्ब के कारणों को प्रस्तुत करते हुए, भूमि एवं भवन विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 30 से 45 दिनों की अवधि आवश्यक है। हालांकि उत्तर बताए गए विलम्ब का औचित्य सिद्ध नहीं करता है।

(ii) स्थाई निर्देशों के पैरा 4 के अनुसार, अधिग्रहित एजेंसी से मुआवजे की राशि प्राप्त होने पर तथा भूमि का कब्जा लेने पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को 60 दिनों के भीतर ज़मींदार को भुगतान कर देना चाहिए। हालांकि, छः मामलों में, तीन भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों (दक्षिण, उत्तर, दक्षिणी पूर्व) ने भूमि एवं भवन विभाग से राशि की प्राप्ति के बावजूद ज़मींदारों को ₹ 18.70 करोड़ का मुआवजा जारी नहीं किया था।

### 3-10-6 mi ; kxrk iek ki = dh x\$-iZrfr

स्थायी निर्देशों के पैरा 5 (iii) के अनुसार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर राशि के वितरण के 15 दिनों के भीतर भूमि एवं भवन विभाग को मुआवजे के भुगतान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि 2011-14 के दौरान दिसंबर 2014 तक जारी किए गए ₹ 704.53 करोड़<sup>21</sup> के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। विभाग ने (सितम्बर 2014 में) कहा कि मामला एलएसी के साथ उठाया गया था।

### 3-10-7 vU Cnq

(i) vlarfj d ys kki jh k% लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2011-12 तक लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केवल उत्तरी पश्चिम जिले के आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया था। अन्य जिलों के संबंध में, लेखापरीक्षा जाँच करने के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी।

(ii) fu/kZj r l fefr; kcdk x\$-l xBu% स्थाई निर्देशों के पैरा 8 व 9 के अनुसार दो समितियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित किया जाना था जिसमें एक समिति का नेतृत्व प्रमुख सचिव द्वारा (भूमि एवं भवन विभाग) तथा दूसरी समिति का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव द्वारा (भूमि एवं भवन विभाग) किया जाना था। हालांकि भूमि एवं भवन विभाग ने सूचित किया (मई 2014) कि ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया लेकिन दि.वि.प्रा. के अधिकारियों तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों की बैठकें जटिलताओं/ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की गई थी। उत्तर लेखापरीक्षा

<sup>21</sup>2011-12- ₹ 496.95 करोड़, 2012-13- ₹149.79 करोड़ एवं 2013-14- ₹ 57.79 करोड़

अभ्यक्तियों को पुष्ट करता है तथा स्थाई अनुदेश की गैर अनुपालना को इंगित करता है।

(iii) एलएआरआर अधिनियम की धारा 101 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जब कोई अधिग्रहित भूमि पाँच वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहती है तो वह भूमि मूल मालिक अथवा सरकार की भूमि बैंक को लौटा दी जाएगी। लेखापरीक्षा के एक प्रश्न का, भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों ने (उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम) यह उत्तर दिया (जुलाई/ अगस्त 2014) कि भूमि का कब्जा सौंपने के बाद भूमि अधिग्रहण शाखा के पास निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं थी। जवाब में यह निहित है कि विभाग में माँग करने वाले विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी।

अधिनिर्णयों की घोषणा में देरी के परिणामस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान/ देयता करना पड़ा। भूमि एवं भवन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों तथा उसके बाद जमींदारों को मुआवजा जारी करने में देरी की जा रही थी। विभाग में निगरानी की कमी थी क्योंकि स्थाई निर्देशों के तहत आवश्यक समितियों का गठन नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, भूमि एवं भवन विभाग की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

मामला अक्तूबर 2014 में सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

**3-11 ₹ 75-94**

**₹ 75-94**

**₹ 75-94**

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.) ने अप्रैल 2007 में अपने परिसर में- 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क' को विकसित करने के लिए एक परियोजना को संप्रत्ययीकरण किया। सू.प्रौ. सं. ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एसोसिएशन तथा सर्विस कंपनी (रा.सॉ.ऐ.स.क.) को साझेदार के रूप में नियुक्त किया, जिससे दिसम्बर 2007 में ₹ 30 लाख की लागत पर डी.पी.आर. /व्यवहार्यता रिपोर्ट को बनाया तथा प्रस्तुत किया।

इस परियोजना के व्यय का आकलन ₹ 425 करोड़ था जिसमें परियोजना भूमि, उपयोग अधिकारों तक सीमित ने.सु.प्रौ.सं. के अंशदान के साथ मुख्यतः निजी डेवलपर द्वारा वित्तपोषित की जानी थी। पार्क में किरायेदारों से लीज किराये के रूप में राजस्व परियोजित था जोकि प्रतिवर्ष ₹ 200 करोड़ आकलित था।

परियोजना को मंत्रिमंडल के "सैद्धान्तिक अनुमोदन" प्रदान किये जाने (जुलाई 2008) के पश्चात ने.सु.प्रौ सं. ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली आमंत्रित करते हुए जनसंचार माध्यमों में विज्ञापनों के द्वारा वास्तुकार और तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए 'प्रस्तावों का निवेदन' (प्र.नि.) के साथ-साथ परियोजना के विकास के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति' (रु.अ.) को जारी (सितम्बर/अक्तूबर 2008) किया, जिस पर ₹ 45.13 लाख का व्यय किया गया था।

प्र.नि. के प्रत्युत्तर में केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ। मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मामले पर चर्चा कि गई (फरवरी 2009) एवं देखा गया कि गंभीर आर्थिक मंदी के कारण खराब प्रदर्शन रहा जो सभी सा.नि.भा. परियोजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। ने.सु.प्रौ.सं. को निर्देश दिया गया:

(i) गंभीर मंदी के चालू आर्थिक यथार्थताओं को विचार में लेते हुए परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए परियोजना सलाहकार को कहा गया,

(ii) योजना आयोग की सलाह पाने के लिए कि क्या आर्थिक मंदी के प्रबल शर्तों के अंतर्गत परियोजना को आस्थगित किया जाना चाहिए।

हालाँकि, ने.सु.प्रौ.सं. ने उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। बजाय, नियंत्रण परिषद ने कुछ समय के लिए (वि.प्रौ.) परियोजना के कार्यान्वयन को आस्थगित करने एवं आर्थिक मंदी के स्थिर होने के बाद परियोजना का पुनः आकलन का फैसला किया (09 अप्रैल 2009)। तब से, यद्यपि पाँच वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, परियोजना की स्थिति अपरिवर्तित रही।

यदि, इस स्थिति में परियोजना पुनः प्रारंभ की जाती है, तो वि.प.रि. व विज्ञापन पर खर्च किए जा चुके कुल ₹ 75.94 लाख<sup>22</sup> के व्यय की तकनीक के इतने तेजी से बदलते परिदृश्य में कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। इस प्रकार ने.सु.प्रौ.सं. द्वारा इस परियोजना पर किया गया ₹ 75.94 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

निदेशालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि दिल्ली में साथ ही साथ देश में सू.प्रौ. एवं सू.प्रौ. परिचालित सेवाओं को प्रोन्नत करने के लिए परियोजना की कल्पना की गई थी एवं भविष्य में इस प्रकार की पहल से ने.सु.प्रौ.सं. एवं सरकार के लिए वि.प.रि. से प्राप्त ज्ञान व अनुभव बहुत ही उपयोगी होगा।

तथ्य यह है कि निदेशालय/ने.सु.प्रौ.सं. ने परियोजना का पुनः आकलन नहीं किया जैसा कि मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया था (फरवरी 2009) एवं प्रतिवेदन की उपयोगिता पुनः संदेहपूर्ण रह जाती है।

मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### ifjogu foHkx

3-12 Q ogk Zk v/; ; u ij ₹ 9-85 djM+dk fu"Qy Q ;

₹ 9-85 djM+dk Q ; fu"Qy jgk D; kd ifjogu foHkx ¼ fo-½us ih vkj Vh i) fr ds fy, fnYyh bWlxVM eYVheKMy Vlt V fl LVe fyfeVM ½MEVl ½ds }kj k cuk s x, Q ogk Zk ifronuk ij] vks fdl h dk Zlgh dks vkj Ek ughafd; kA

परिवहन विभाग में अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि एक संयुक्त उद्यम कम्पनी, डिम्ट्स, ने दिल्ली में वसंत कुंज तथा वसंत विहार/मुनिरका क्षेत्र में तथा उसके आसपास व्यक्तिगत त्वरित पारगमन प्रणाली (पी आर टी)<sup>23</sup> पर व्यवहार्यता अध्ययन करने

<sup>22</sup>वि.प.रि.—₹ 30.00 लाख, विज्ञापन—₹ 45.13 लाख एवं विविध व्यय ₹ 0.81 लाख

<sup>23</sup> पी आर टी प्रणाली एक सार्वजनिक पारगमन प्रणाली है जो कार जैसी निजता के साथ, एक टैक्सी के समान स्तर पर लचीलापन देने के



का प्रस्ताव किया (27 अप्रैल 2009)। परिवहन विभाग ने मई 2009 में प्रस्ताव का अनुमोदन किया और तत्पश्चात उसने चार किशतों (जून 2009 से अप्रैल 2010) में ₹1.63 करोड़<sup>24</sup> डिम्ट्स को जारी किए, जिसने अक्टूबर 2009 में अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। प.वि. ने रिपोर्ट पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

डिम्ट्स ने फिर से, पी.आर.टी. प्रणाली पर पांच स्थानों (द्वारका सब सिटी, नार्थ कैम्पस, आई.टी.पी.ओ, करोल बाग तथा सैन्ट्रल दिल्ली से पूर्वी दिल्ली संपर्क) में व्यवहार्यता अध्ययन तथा दिल्ली में पी.आर.टी. के लिए एक चयनित स्थान का एक विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को शुरू करने का प्रस्ताव किया (2 मई 2011)। प.वि. ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया (6 मई 2011) तथा डिम्ट्स के पक्ष में ₹ 7.45 करोड़ की स्वीकृति जारी की स्वीकृति के आदेशानुसार, प.वि. के अन्तर्गत एक सरकारी उपक्रम दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी टी आई डी सी) द्वारा डिम्ट्स को अध्ययन के लिए अपने आवर्ती निधि से निधियों को जारी किया जाना था। जून 2011 में डिम्ट्स तथा प.वि. के बीच एक समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया था। डिम्ट्स को ₹ 7.45 करोड़ की राशि जारी की गई थी (10 मई, 2011) तथा मार्च 2013 में डी पी आर सहित व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, प.वि. ने प्रतिवेदन या डी.पी.आर. पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

सेवा कर के ₹ 77 लाख शामिल करते हुए, ₹ 9.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि प.वि.ने व्यवहार्यता प्रतिवेदनों पर नवम्बर 2014 तक आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

इसके साथ, डिम्ट्स को दूसरी व्यवहार्यता अध्ययन की पूरी लागत (₹ 7.45 करोड़) को नियम 159 का उल्लंघन करके अग्रिम रूप में जारी किया गया था जिसमें अनुबद्ध है कि निजी फर्मों को संविदा मूल्य की कुल लागत का 30 प्रतिशत तक अग्रिम जारी किया जा सकता है। प.वि. ने डिम्ट्स को निधियों को जारी करने से पूर्व वित्त विभाग/ई.एफ.सी की सहमति प्राप्त नहीं की थी।

मामला, अक्तूबर 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

### 3-13 ₹ 1.47 djkm+ dh fuf/k k dk vojku

ifjogu foHkx ¼-fo-½ dh iorZi 'kkkk ea bZpkyku dh ifj; k uk dh vi; kr ; k uk ds ifj. keLo#i mi dj. k t k fd rhu o"kl s Hh vfeld l e; l sfuf'Ø; iMjg ds Ø; ij 1-47 djkm+ dh fuf/k k dk vojku gykA

दिल्ली में लगातार बढ़ती वाहन की संख्या को ध्यान में रखते हुए प.वि. ने, डिम्ट्स के साथ परामर्श से, प्रवर्तन वाहनों को ऑनलाईन चालान, मुख्यालय सर्वर के साथ संयोजकता, चालानों की प्रिंटिंग, इलैक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स, कैमरा इत्यादि जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुसज्जित करने का निर्णय लिया (जून 2010)। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि 40

लिए परिकल्पित है। प्रणाली में विशिष्टतः विद्युत ऊर्जा वाहन (पोड्स) जिसमें केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली के साथ 4-6 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है, जो या तो भूमि स्तर अथवा उच्चत पथप्रदर्शक मार्ग पर चल कर यात्रियों को उनके गतंय स्थान पर बिना रुके तथा कम प्रतीक्षा समय के साथ पहुँचाने के लिए शामिल है।

24 परियोजना ₹ 1.48 करोड़ की लागत पर लागू सेवा कर सहित अनुमोदित किया गया था। 10.3 प्रतिशत की दर से सेवा कर सहित ₹ 1.63 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

मोबाइल वाहनों के लिए, ई-प्रवर्तन (चूक करने वाले वाहनों/वाहकों की ई-चालान) के लिए 40 उपकरणों के सैटों को खरीदा जाए। प्रस्तावित प्रणाली 3 जी डाटा से परिचालित तथा केन्द्रीय डाटा बेस से संयोजन के योग्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली थी। प्रणाली द्वारा, उल्लंघन करने वाले वाहनों के संबंध में सभी पुराने दोषों तथा जुर्मानों के पूर्ववृत्त को इसकी पंजीकरण संख्या भरकर तुरन्त, पुनरु प्राप्त किया जा सकता था। यह विभाग के अन्य तंत्रों के साथ होने में भी समर्थ थी। उदाहरण के लिए यदि एक मोटर चालक ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान करने में या न्यायालय में उपस्थित होने में असफल होता है तो वह अपने चालान किए हुए वाहन से संबंधित अन्य कार्रवाई संचालित करने में, समर्थ नहीं होगा, जैसे की किशतों में क्रय की प्रविष्टियों को जमा तथा रद्द करने, वाहन का विक्रय तथा स्थानांतरण, बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण इत्यादि।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि परियोजना के कार्यान्वयन में प.वि.ने डिम्ट्स को सम्बद्ध किया यद्यपि दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। डिम्ट्स के परामर्श पर जो कि प्रवर्तन विंग एवं प्रणाली विश्लेषक द्वारा समर्थित था, प.वि. ने जुलाई से अक्टूबर 2010 के दौरान ₹1.47 करोड़ की लागत पर 40 टफ बुक्स, 40 प्रिंटर, 80 स्मार्ट कार्ड रीडर, 40 यूपीएस, 40 डाटा कॉर्ड तथा दो प्लास्मा स्क्रीन (63") क्रय किए गए। उसी समय डिम्ट्स के द्वारा प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। यद्यपि सॉफ्टवेयर के विकास तथा प्रणाली के अनुरक्षण के लिए अनुबंध को उनके अधिक मूल्य उद्घृत करने के कारण डिम्ट्स के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। फलस्वरूप, प.वि. के अनुरोध पर अक्टूबर 2013 में एन.आइ.सी ने सॉफ्टवेयर को विकसित किया। जुलाई 2014 में दो वाहनों पर प्रणाली का प्रयोग करने हेतु प्रक्षेपित किया गया। सितम्बर 2014 तक प्रणाली परीक्षण की अवस्था में ही थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त योजना यथा औपचारिक समझौते का न होना तथा सॉफ्टवेयर के विकास एवं प्रणाली के रख-रखाव के लिए अनुबन्ध को समयानुसार अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका तथा क्रय किए गए उपकरण तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

यह मामला, दिसम्बर 2014 में सरकार को प्रेषित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

'kj h fodkl foHkx

3-14 cgqrjh; dkj i kEdx l g-olk. kT; d ifjl jk dh vo/kj. k vk kt u  
fuekZk vk l pkyu dh ys k k j h k

u-fn-u-i- us ij k' kZrk dh fu; fä ea l fgrkx i to/kuk dk i kyu ugh  
fd; k i q% i k r dk Zzkyh ea ifjorZ dh vu efr l s fj; k rxzgh dks  
vu efr y k k fn; k x; k fj; k rxzgh us 96-36 yk k fj; k r ' k d de t ek  
fd; k l kof/kd fofu; e k ds x j- vu i kyu l s dLryck x k h ekZ cgqrjh;  
dkj i k dx-l g-olk. kT; d ifjl j dks LFkx dj fn; k x; k ft l l s 9-13  
dj k dk voj k k g y k v k / k j k r y i k dx dks c n djus ds dkj. k 11-71  
dj k dk ? k v k g y k u-fn-u-i- us LFkx ifj; k t uk ds fy, v k b Z ds  
' k d ds: i ea 1-22 dj k dk vi 0 ; fd; k

नई दिल्ली नगर परिषद (न.दि.न.प.) ने बहुस्तरीय कार पार्किंग सह-वाणिज्यिक परिसरों (ब.स्त.का.पा.) के निर्माण के लिये तीन स्थानों (i) बाबा खड्ग सिंह मार्ग (बा.ख.सि.मा.) (ii) सरोजिनी नगर (स.न.) और (iii) कस्तूरबा गांधी मार्ग (क.गां.मा.) की पहचान की। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)<sup>25</sup> प्रणाली के तहत गठन प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर ब.स्त.का.पा. विकसित किये जाने थे। न.दि.न.प. को भूमि प्रदान करनी थी एवं ब.स्त.का.पा. संचालक से एक वार्षिक रियायत शुल्क चार्ज करना था और ठेकेदार (रियायतग्राही) को परियोजना के पूरे निर्माण संचालन और रखरखाव के खर्च की वित्तीय व्यवस्था करनी थी। परियोजनाओं के संविदा हेतु तकनीकी वाणिज्यिक अध्ययन रिपोर्ट और दस्तावेजों की बोली (रियायत अनुबंध के साथ) तैयार करने हेतु न.दि.न.प. ने जनवरी 2005 में मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसियल कारपोरेशन (आईडीएफसी) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। स.न. तथा बा.ख.सि.मा. ब.स्त.का.पा. के लिए निर्धारित परियोजना समाप्ति तिथि (नि.प.स.ति.) मई 2010 थी लेकिन इन्हें क्रमशः मई और सितम्बर 2012 में पूर्ण किया गया। क.गां.मा. के लिए नि.प.स.ति. जून 2010 थी लेकिन परियोजना मई 2010 में रोक दी गई।

मई से नवम्बर 2014 की अवधि में सभी तीन परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य सामने आए:

### 3-14-1 ifj; kt uk ijke' kkrk dh vfu; fer fu; ä

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 176 अनुबंध करता है कि विशेष परिस्थितियों में जहाँ एकल स्रोत चयन किया जाना है, ₹ 25 लाख से अधिक लागत वाले कार्य हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पूर्ण औचित्य के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.दि.न.प. ने (जून 2004) आईडीएफसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जिसके तहत, आईडीएफसी को वाहन पार्किंग स्थलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में शहरी आधारभूत अवसंरचना के विकास, उन्नति एवं रख-रखाव हेतु न.दि.न.प. की मदद करनी थी। यद्यपि इस समझौता ज्ञापन में लिये गये कार्य का कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, जबकि न.दि.न.प. ने तीन ब.स्त.का.पा. परियोजनाओं के लिये परामर्शदाता के रूप में आईडीएफसी को नियुक्त किया, जिसके लिए आई.डी.एफ.सी. को ₹ 27 लाख (प्रत्येक गतिविधि हेतु ₹ 9.00 लाख) का भुगतान होना था। आई.डी.एफ.सी. की नामांकन आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति अनियमित थी, इसमें पारदर्शिता का अभाव था तथा इससे न.दि.न.प. प्रतिस्पर्धी बोलियों के लाभ से वंचित हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि आईडीएफसी को सभी संहितागत औपचारिकताओं का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद नियुक्त किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकल स्रोत चयन हेतु कोई स्पष्टीकरण दर्ज किया गया नहीं पाया गया।

<sup>25</sup> पीपीपी परियोजना में एक रियायत अनुबंध, लागत प्रभावी डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी प्रदान कर प्रबंध कौशल के माध्यम से आधारभूत अवसंरचना के सृजन हेतु सरकार एवं एक निजी कम्पनी के बीच हस्ताक्षरित होता है। पीपीपी में एक साफ व पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए परियोजना के चयन में सख्त शासन एवं दीर्घ अवधि के ठेके दिये जाने हेतु प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है एवं रियायत अवधि के अन्त में परिसंपत्ति के ढाँचा, निर्माण, वित्त, संचालन, स्वामित्व एवं हस्थानांतरण हेतु निजी क्षेत्र को उत्तरदायी बनाता है।

### 3-14-2 cgtrjh dk ikrx dk fuelZk

#### 3-14-2-1 p; fur rduhd dk l fonk l k us ds ckn l akku

सरोजिनी नगर और बाबा खड़ग सिंह मार्ग में ब.स्त.का.पा. के परियोजना कार्य सितम्बर 2007 में मै. डीएलएफ को सौंपे गए और समझौते पर हस्ताक्षर नवम्बर 2007 में किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के लिए बोली लगाते समय डीएलएफ ने ब.स्त.क.पा. के प्रचालन हेतु मै. सिमपार्क इंफ्रास्ट्रक्चर (कोलकाता) द्वारा मै. प्लेनटिफ नीदरलैण्ड) की 'ईकोसैफ पैलेट टेक्नोलोजी' प्रस्तावित की। यद्यपि, बाद में डीएलएफ ने मैसर्स सिमपार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेदखल किया और मैसर्स प्रिसिशन ओटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स इण्डिया लिमिटेड (पीएआरआई) को तकनीक के प्रतिष्ठापन करने के लिये शामिल किया। यह सीए की शर्तों का उल्लंघन था क्योंकि डीएलएफ ने 'ईकोसैफ पैलेट टेक्नोलोजी' ही उद्धृत करके तकनीकी बोली जीती थी। न.दि.न.प. ने डी.एल.एफ. द्वारा प्रयुक्त नयी तकनीक पर यह अभिलेख और सूचना उपलब्ध नहीं करवायी कि क्या यह तकनीक पिछली तकनीक के समान थी एवं सक्षम प्राधिकारी और त.मू.स. द्वारा अनुमोदित थी। इसके अतिरिक्त यह कि क्या पीएआरआई को परियोजना के लिये पर्याप्त तकनीकी अनुभव था, यह भी अभिलेखों में दर्ज नहीं था।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि ईकोसेफ पैलेट तकनीक मैसर्स सिमपार्क का एक ब्राण्ड नाम था एवं मै. पीएआरआई द्वारा भी ठीक उसी प्रकार की तकनीक प्रदान की गई। यह परिवर्तन त.मू.स. एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया था। विभाग का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण एवं तकनीकी सहायता पर सीए विशेष रूप से उल्लेख करता था कि स्थापना, जाँच व प्रवर्तन मै. सिमपार्क द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीए में तकनीकी के संशोधन की अनुमति नहीं थी। न.दि.न.प. ने मै. पीएआरआई द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी/त.मू.स. के अनुमोदन का कोई प्रामाणिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया।

#### 3-14-2-2 iq%iklr dk Zkkyh eacnyko- fj; k rxlgh dks vuqpr ykHk

'प्रस्ताव के लिये अनुरोध' दस्तावेज के अनुसार (तकनीकी प्रस्तावों की मद 2.2.2) वाहन का पुनःप्राप्ति समय<sup>26</sup> तीन मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

लेखापरीक्षा जांच दर्शाती है कि मैसर्स डिम्टस, जिन्हे स्वतंत्र अभियंता (स्व.अ.) (समीक्षा, निगरानी और डिजाइन, निर्माण, संचालन, एवं रखरखाव आवश्यकता इत्यादि के संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु) नियुक्त किया गया, ने स.न. ब.स्त. का.पा. में पार्किंग प्रणाली तथा पुनः प्राप्ति समय के कार्य पर डीएलएफ द्वारा की गई जांच को देखा (नवम्बर 2011) और पाया कि पुनः प्राप्ति की प्रणाली सीए के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठापित नहीं की गयी। जाँच के दौरान पुनः प्राप्ति का समय 3 से 14 मिनट

<sup>26</sup>सी.ए. के अनुसार, पुनः प्राप्ति समय का वर्णन शार्किंग संरचना में किसी वाहन का अधिकतम पुनः प्राप्ति समय— प्रवेश/निकास क्षेत्र से सबसे दूरस्थ बिन्दु पर पार्क किए गए वाहन को प्रवेश/निकास बिन्दु तक, जहाँ से वाहन भवन में चलायी जा सकती है, लाने में लिए गए समय एवं पूर्णतया स्वचालित पार्किंग सुविधाओं में 3 मिनट से अधिक न लिए गए समय के रूप में किया जाता है।

के बीच था। पुनः प्राप्ति के समय को घटाकर 3 मिनट करने के लिए डीएलएफ ने एक दो चरणों वाली संशोधित तकनीकी का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2012), जिसमें टोकन किऑस्क पर समीपता कार्ड स्वाइप करना और उक्त समयावधि के अंतर को समायोजित करने हेतु प्रचालक द्वारा पुनः प्राप्ति आदेश के लिए प्रतीक्षा करना भी शामिल था। मैसर्स डीएलएफ ने दावा किया कि अप्रैल 2012 में 120 कारों पर किये गये परीक्षणों के अनुसार, संशोधित कार्यप्रणाली के साथ पुनः प्राप्ति समय तीन मिनट के भीतर था। हालाँकि, डीआईएमटीएस ने टिप्पणी की कि टोकन की-ऑस्क पर कार्ड स्वाइप करने व ऑपरेटर द्वारा आदेश प्राप्त करने के बीच का समय प्रणाली में दर्ज नहीं था और अतिरिक्त था, जो पार्किंग भार के अनुसार अलग-अलग हो सकता था और अधिकतम बोझ की स्थिति में अधिक से अधिक पहुँच सकता था। डीआईएमटीएस के विचारों के बावजूद न.दि.न.प. ने संशोधित कार्यप्रणाली की पुष्टि की (अप्रैल 2012) और डीआईएमटीएस को कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया जो डीआईएमटीएस ने इन टिप्पणियों के साथ मई 2012 में जारी किया था कि पुनः प्राप्ति समय सीए के प्रावधानों के अनुरूप अब भी नहीं था। ऐसी ही संशोधित कार्यप्रणाली को अपनाने पर बाबा खड्ग सिंह मार्ग पर भी ब.स्त.का.पा. के लिए समाप्ति प्रमाणपत्र सितम्बर 2012 में जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'टोकन किऑस्क' का प्रावधान, जहाँ ग्राहक टोकन सं. प्राप्त करता है और फिर भुगतान और अपनी कार की पुनः प्राप्ति के लिए ऑपरेटर को टोकन देने हेतु अपनी बारी का इंतजार करता है, सीए का भाग नहीं था। इस प्रकार संशोधित कार्यप्रणाली के साथ भी पुनः प्राप्ति समय तीन मिनट की स्वीकार्य सीमा के भीतर नहीं था। लेकिन न.दि.न.प. ने डीएलएफ को अनुचित लाभ देते हुए दोनों स्थलों के लिए संशोधित कार्यप्रणाली को स्वीकार किया।

न.दि.न.प. ने बताया (जनवरी 2015) कि पुनः प्राप्ति समय निर्धारित सीमा के भीतर था एवं लिखित तथा वास्तविक पुनः प्राप्ति समय में भ्रम को दूर करने के लिए टोकन किऑस्क लगाया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनः प्राप्ति का समय कार्ड स्वाइप करने के समय से कार की सुपुर्दगी तक माना जाएगा। सच यह है कि टोकन किऑस्क न.दि.न.प. द्वारा रियायतग्राही को प्रदत्त बचाव का एक तरीका था, जिससे उक्त निर्धारित पुनः प्राप्ति समय प्राप्त हो सके और जिसमें पुनः प्राप्ति समय की गणना के लिए टोकन/प्रतीक्षा समयान्तराल पर विचार नहीं किया गया।

### 3-14-2-3 **fj; k rxzgh ds vks , .M , e dk Zdsfu"i knu dk xj-vuq{k k**

सीए के अनुच्छेद 4 की अनुसूची 5 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि आई.ई. को परियोजना के प्रचालन व अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) की समीक्षा करनी चाहिए, जब तक कि ब.स्त.का.पा. को न.दि.न.प. के पास वापस नहीं सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त इसमें आई.ई. का उत्तरदायित्व - (i) परियोजना के प्रत्यक्ष, तकनीकी व वित्तीय पहलुओं पर रिपोर्ट करना तथा (ii) रियायतग्राही के निष्पादन का अनुवीक्षण तथा ओ एण्ड एम आदेशों की महत्वपूर्ण व लगातार अवहेलना की सूचना देना निर्धारित किया है।

स.न.और बा.ख.सि.मा. परियोजनाओं हेतु एक समय पर दो से अधिक वर्षों के विस्तार की

मनाही के साथ तीन वर्षों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 4.89 लाख मासिक के पारिश्रमिक पर (जून 2008) डीआईएमटीएस को आईई के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि न.दि.न.प. ने आई.ई. को 15 अक्टूबर 2012 तक नियुक्त रखा जिस दौरान दोनों परियोजना को पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र जारी किए गए (स.न. मई 2012 तथा बा.ख.सि.मा.-सितम्बर 2012)। हालाँकि 15 अक्टूबर 2012 के बाद न.दि.न.प. ने न तो डीआईएमटीएस के सेवाओं का विस्तार किया, न ही ओ एण्ड एम के क्रियाकलापों हेतु किसी फर्म को आई.ई. के रूप में नियुक्त किया।

इस प्रकार, आई.ई. या किसी दूसरे सलाहकार की अनुपस्थिति में न तो परियोजनाओं के ओ एण्ड एम क्रियाकलापों की समीक्षा की जा रही थी न ही रियायतग्राही के निष्पादन की निगरानी की जा रही थी।

### 3-14-2-4 **विलम्बित शुल्क के भुगतान के लिए न.दि.न.प. द्वारा रियायतग्राही को प्रदान की गई छूट**

सी.ए. के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, आई.ई. को दिए जाने वाले सभी शुल्क रियायतग्राही तथा न.दि.न.प. के द्वारा बराबर-बराबर बाँटे जाने चाहिए थे। रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक माह के पहले दिवस को न.दि.न.प. को हिस्सा अदा करना चाहिए था। भुगतान में 90 दिनों से अधिक के लिए विलम्ब होता है तो अनुच्छेद 10 के अनुसार न.दि.न.प. द्वारा रियायतग्राही के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रियायतग्राही ने न.दि.न.प. को हिस्से के भुगतान में एक से 17 माह तक का विलम्ब किया। यद्यपि रियायतग्राही शुल्क के अपने हिस्से के भुगतान में नियमित नहीं था, न.दि.न.प. ने इसके लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे रियायतग्राही को अनुचित लाभ हुआ।

न.दि.न.प. ने अपने जवाब में (जनवरी 2015) रियायतग्राही द्वारा विलम्ब से आई.ई. के शुल्क की अदायगी स्वीकार की है। हालाँकि रियायतग्राही के खिलाफ की गई कार्यवाही के बारे में जवाब में कुछ कहा नहीं गया।

### 3-14-2-5 **रियायतग्राही द्वारा न.दि.न.प. को प्रदान की गई छूट**

सी.ए.के अनुच्छेद 7 के अनुसार, रियायतग्राही को स.न. और बा.ख.सि.मा. पर ब.स्त.ता.का. पा. हेतु पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष क्रमशः 15.00 लाख व ₹ 22.00 लाख रियायत शुल्क का भुगतान करना था। रियायत शुल्क परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (नि.प.स.ति.)<sup>27</sup> की प्रत्येक वार्षिकी पर अग्रिम रूप में दी जानी थी तथा प्रथम रियायत शुल्क नि.प.स.ति.के सात दिन के भीतर देय था। चूंकि नवम्बर 2007 में दोनों कार्यस्थलों के लिए करार क्रियान्वित किया गया था, रियायतग्राही जून 2010 से रियायत शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था। न.दि.न.प.के द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण दर्शाता है कि रियायतग्राही ने स.न. हेतु ₹ 48.90 लाख तथा बा.ख.सि.मा. हेतु ₹ 47.46 लाख कम रियायत शुल्क जमा किया। इस प्रकार, न.दि.न.प. द्वारा कुल राशि ₹ 96.36 लाख कम प्राप्त हुई।

<sup>27</sup>नि.प.स.ति. का मतलब प्रभावी तिथि से 24 महीनों की तिथि होती है, एवं प्रभावी तिथि का मतलब वह तिथि जिस पर सी.ए. की अनुसूची 3 के अनुरूप अनुमोदन पूरा कर लिया गया है या नियत तिथि से छः महीने, जो भी पहले हो।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) विलम्ब का कारण विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा देरी से अनुमोदन एवं परियोजना प्रबंधन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ नि. प.स.ति. का विस्तार माना है। जवाब मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि सीए में ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अलग से छः महीने प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त न.दि.न.प. ने एस.पी.सी.डी. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विस्तारण का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

### 3-14-2-6 ifj; kt ukvksd siwZgkuseafoyEc dsfy, l h, ean.M mi cU/k dk u gkuk

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के भाग 33.1 (3) के अनुसार कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की क्षतिपूर्ति ठेकेदारों से निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक वसूली योग्य है।

संविदा अनुबंध के अनुसार, बा.ख.सि.मा.व स.न. में ब.स्त.का.पा. परियोजनाओं का निर्माण डीएलएफ द्वारा 30 महीनों के भीतर (अर्थात् जून 2010 तक) पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि सीए में रियायतग्राही द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की तिथियाँ व प्राप्त किए जाने वाले मील-पत्थरों के निर्धारण उपबन्ध को शामिल किया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर मील के पत्थरों की प्राप्ति न होना व परियोजनाओं के अपूर्ण होने के लिए कोई दण्ड उपबन्ध नहीं था। स.न. व बा.ख.सि.मा. परियोजनाओं हेतु पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मई 2012 तथा सितम्बर 2012 में जारी किया गया जिसमें क्रमशः 23 व 27 महीनों का विलम्ब दर्शाया गया। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों को न.दि. न.प. द्वारा नहीं दिया गया।

इस प्रकार सी.ए. में परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुए विलम्ब हेतु दण्ड उपबन्ध के शामिल न होने से आम जनता भी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रही और रियायतग्राही को अनुचित लाभ हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि सा.नि.भा. अवधारणा नई होने के कारण इसके संविदा करार में जुर्माना उपबन्ध शामिल करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार, संविदा सौंपते समय समाप्ति समय सीमा, विलम्ब से पूर्ण होने हेतु दण्ड, आदि से सम्बन्धित उपबन्ध को बोली दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए।

### 3-14-3 dLrjck xkxk ekZij c-Lr-dkik dk fuekZk

#### 3-14-3-1 , -, l -vkbZ l s vuki fYk iZk k i= dh iwZvko'; drk dks ijk ugha djuk

कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ब.स्त.का.पा. का निर्माण कार्य मैसर्स डी एस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (सितम्बर 2007) को सौंपा गया तथा संविदा अनुबंध दिसम्बर 2007 में कार्यान्वित किया गया। यद्यपि न.दि.न.प. ने परियोजना के लिए भूमिग्रहण नहीं किया जो जनवरी 2009 में उसे

आवंटित की गई थी। सीए के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, रियायतग्राही को स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों से परियोजना हेतु सभी उपयुक्त अनुमतियाँ प्राप्त करनी थीं। चूंकि परियोजना स्थल 'उग्रसेन की बावली', जो एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, से 203.85 मी. के अन्दर स्थित है, परियोजना हेतु ए.एस.आई. की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। मै. डी एस कंस्ट्रक्शन द्वारा दी गई इस सूचना (जुलाई 2008) के अनुसार कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, न.दि.न.प. ने उन्हें कार्यस्थल पर उत्खन्न की अनुमति प्रदान कर दी। आगे जाँच में पता चला कि मै. डी एस कंस्ट्रक्शन ने न.दि.न.प. को इस मामले में दिग्भ्रमित किया ए.एस.आई. से अनुमति के लिए आवेदन वास्तव में मार्च 2010 में ही किया। इस दौरान, एएसआई ने न.दि.न.प. के अवैध निर्माण के विरुद्ध एक एफआईआर (मई 2010) दायर की और इन टिप्पणियों के साथ आवेदन पत्र को वापस कर दिया (जुलाई 2010) कि ए.एम.ए. एस.आर. अधिनियम 2010 लागू होने के कारण, रियायतग्राही को भारतीय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (भा.रा.स्मा.प्रा.) से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। फलस्वरूप, ब.स्त.का. पा. कार्य 1 मई 2010 से रूका रहा।

इस प्रकार, न.दि.न.प. ने सितम्बर 2007 में ब.स्त.का.पा. का कार्य जल्दबाजी में प्रदान किया जबकि परियोजना हेतु भूमि जनवरी 2009 में आवंटित की गयी अर्थात् कार्य देने के 15 महीने बाद। इसके बावजूद, न.दि.न.प. कार्य शुरू होने से पहले ए.एस.आई. (भा.रा.स्मा.प्रा.) से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्वयं या रियायतग्राही के द्वारा) की व्यवस्था नहीं कर सका। न.दि.न.प. तथा स्व. अ. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा, कि खुदाई कार्य हेतु अनुमति देने से पहले रियायतग्राही ने ए.एस.आई. (या भा.रा.स्मा.प्रा.) से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। परिणामस्वरूप परियोजना को रोकना पड़ा।



एएसआई अनुमति के अभाव में केजी मार्ग पर स्थित ब.स्त.का.पा. का निर्माण कार्य

न.दि.न.प. ने बताया (जनवरी 2015) कि रियायतग्राही अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास गया, किन्तु मामले का समाधान न हो सका क्योंकि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार भारतीय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (भा.रा.स्मा.प्रा.) को हस्तांतरित कर दिये गये थे, जो कि 30 मार्च 2010 को गठित हुआ। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रियायतग्राही 2007, अर्थात् भा.रा.स्मा.प्रा. की स्थापना के पूर्व ही अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकता था।



### 3-14-3-2 **oSkud fofu; eak dk vuiky u djus ds dkj .k fuf/k ds vojku l s ₹ 11-71 dkM+dk uql ku**

(1/2 शहरी विकास मंत्रालय ने (जनवरी 2009) कस्तूरबा गांधी मार्ग पर न.दि.न.प. को बहुस्तरीय कार पार्किंग बनाने के लिए भूखण्ड (6143 वर्ग मी. क्षेत्र) ₹ 9.13 करोड़<sup>28</sup> की लागत पर आवंटित किया। आवंटन की शर्तों के अनुसार, भूमि हेतु भुगतान, आवंटन की तिथि से देय हो गया। न.दि.न.प. को भूमि के अधिग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भवन का निर्माण करना था व अग्रिम में भूमि के किराये का भुगतान करना था, चाहे किराये की माँग की जाए या नहीं शर्तों का पालन न करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा जाँच, हालाँकि, दर्शाती है कि न.दि.न.प. ने जनवरी 2010 के बाद भूमि के किराये का भुगतान नहीं किया जो जनवरी 2015 तक कुल ₹ 1.11 करोड़ हो गया।

1/2 आवंटन से पहले न.दि.न.प. इस भूखण्ड को 'धरातल पार्किंग सुविधा' के रूप में पहले से ही उपयोग कर रही थी और न.दि.न.प. ₹ 14.11 लाख मासिक लाइसेंस शुल्क प्राप्त कर रही थी। दिसम्बर 2007 में भूखण्ड बहुस्तरीय कार पार्किंग के निर्माण हेतु रियायतग्राही को दिया गया। हालाँकि जनवरी 2015 तक ब.स्त.का.पा. का निर्माण पूरा न हो सका। इस प्रकार अप्रैल 2009 से ₹ 9.13 करोड़ अवरुद्ध रहे एवं न.दि.न.प. को 'धरातल पार्किंग' बन्द करने के कारण ₹ 11.71 करोड़<sup>29</sup> का नुकसान हुआ और जमीन के किराये के रूप में ₹ 1.11 करोड़ की देयता संचित हो गई।

न.दि.न.प. ने अपने जवाब में (जनवरी 2015) कहा कि रियायतग्राही एवं न.दि.न.प. ने उच्चतम स्तर से कोशिश की किन्तु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायतग्राही एवं न.दि.न.प. ने आवश्यक अनुमति प्राप्त करने से पहले खुदाई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से प्राथमिकी भी दर्ज हो गई थी।

### 3-14-3-3 **Lo-v- dls Hxrk ds dkj .k ₹ 1-22 dkM+dk Q FKQ ;**

मैसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड इण्डिया (एमएसपीएल) को कस्तूरबा गांधीमार्ग पर ब.स्त.का.पा. हेतु स्व.अ. के रूप में नियुक्त किया गया तथा ठेका करार (आई.ई. ठेका) तीन वर्षों के लिए ₹ 7.09 लाख मासिक पारिश्रमिक पर मई 2008 में हस्ताक्षरित हुआ। लेखापरीक्षा जाँच यह दर्शाती है कि कार्य हेतु स्व.अ. को परियोजना हेतु भूमि आवंटित होने (जनवरी 2009) से पूर्व नियुक्त किया गया जो कि उचित नहीं था।

न.दि.न.प. ने सितम्बर 2010 में आई.ई. का ठेका निलंबित कर दिया और मैसर्स एमएसपीएल को ₹ 2.12 करोड़ (रियायतग्राही के हिस्से के रूप में ₹ 1.06 करोड़ को शामिल करके)

<sup>28</sup> वाणिज्यिक दर पर 25 प्रतिशत भू क्षेत्र (₹ 57960 प्रति वर्ग मी.+2.5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया), एवं 75 प्रतिशत भूमि अलाभकारी भूमि दर पर (₹ 11,000 प्रति एकड़ + 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया)

<sup>29</sup> दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2014 तक ₹14.11 लाख मासिक की दर से परिकलित किया गया

का भुगतान किया। यद्यपि रियायतग्राही ने मई से अगस्त 2010 की अवधि से संबंधित ₹ 0.16 करोड़ की धनराशि वापिस नहीं की। चूंकि परियोजना मई 2010 में रोक दी गई, ₹ 1.22 करोड़ (न.दि.न.प. का हिस्सा + ₹ 0.16 करोड़) का व्यय जो स्व.अ. के भुगतान पर किया गया, व्यर्थ हुआ।

न.दि.न.प. ने (जनवरी 2015) बताया कि स्व.अ. ने अपने विहित उत्तरदायित्व उचित ढंग से निभाये एवं उसे की गई अदायगी फिजूल नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्व.अ. भूमि आवंटन से पहले नियुक्त किया गया था एवं कार्य मई 2010 में बन्द कर दिया गया था। तब तक मात्र खुदाई का कार्य पूरा हुआ था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न.दि.न.प. ने परामर्शदाता की नियुक्ति में संहितागत औपचारिकताओं का पालन नहीं किया। चयनित तकनीकी तथा पुनः प्राप्ति प्रणाली में बदलाव की अनुमति देकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया। प्रचालन व अनुरक्षण की निगरानी हेतु कोई आई.ई. नियुक्त नहीं किया गया। रियायतग्राही ने नि.प.स.ति. का ध्यान न रखकर ₹ 96.36 लाख रियायत शुल्क कम जमा किया। सांविधिक विनिर्देशों का पालन न करने के कारण क.गा.मा. के ब.स्त.का.पा. का कार्य स्थगित हुआ जिससे ₹ 9.13 करोड़ अवरुद्ध हुए और बंद की गई धरातल पार्किंग के कारण ₹ 11.71 करोड़ का घाटा हुआ। न.दि.न.प. ने स्थगित परियोजनाओं के लिए आई.ई. के शुल्क पर ₹ 1.22 करोड़ का अपव्यय किया।

मामला सरकार को दिसंबर 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था, (अप्रैल 2015)।

**3-15 ₹ 73-85 yk[k dk fu"Qy 0 ;**

fn-t -cls }kjk fu-vkl w dh Loh-fr vls l ks s x; s dk Z ds fy, ck/keq  
dk LFky dh mi yC/krk dks l fuf' Pkr dj kuseanjn/Ekrk ds vHko ep l hot  
jlbQt x esu dh i fj; kt uk dks chp esNkMak i Mk ₹ 73-85 yk[k dk fu"Qy  
0 ; gylA

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली 2012 की धारा 15.1 (2) के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) की स्वीकृति से पूर्व निम्नलिखित वांछनीय है (i) बाधामुक्त कार्य-स्थल की उपलब्धता, निधि, स्थानीय निकायों से निर्माण योजना की स्वीकृति, (ii) ठेकेदारों को जारी माल उपलब्ध होने की पुष्टि (iii) नींव के लिये संरचना ड्राइंग और (iv) सभी सेवाओं के लिए अभिन्यास योजना।

कार्यकारी अभियन्ता (नि.) ड्रेनेज-III, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में अवधि 2005–2014 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जाँच ने दर्शाया कि सितम्बर 2007 में ₹ 1.02 करोड़ की निविदा राशि के विरुद्ध 'आजादपुर एसपीएस से कोरोनेशन पिलर एसटीपी तक 350 मि.

मी. व्यास की डी.आई./सी.आई. की मेन राइजिंग को उपलब्ध कराने, बिछाने और जोड़ने का कार्य ₹ 1.25 करोड़ की लागत पर सौंपा गया। एकत्रित सीवेज को आजादपुर एसपीएस (कमांड एरिया - दि.न.नि. कॉलोनी आजादपुर, नानीवाला बाग और आजादपुर व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स) से कोरोनेशन पिलर एसटीपी तक ले जाने के लिए 350 मि.मी. व्यास के 2910 मीटर लम्बे डी.आई. पाईप को उपलब्ध कराने तथा बिछाने का कार्य कार्यक्षेत्र में शामिल था। कार्य के प्रारम्भ और समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 26 नवम्बर 2007 और 25 मई 2008 थी। ठेकेदार ने वास्तव में 01 फरवरी 2008 को कार्य शुरू किया था। कार्य के शुरू होने में विलम्ब के कारण अभिलेखों में नहीं था। यद्यपि, 2277.20 मीटर लम्बाई की पाईप लाइन को उपलब्ध संरेखण में डालने के बाद, रामेश्वर नगर के निवासी कल्याण संघ के द्वारा विरोध उत्पन्न करने, मानसून सत्र के दौरान दि.न.नि. के क्षेत्र कर्मचारी द्वारा खुदाई कार्य को रोकने एवं जहाँगीरपुरी नाले पर लो.नि.वि. के कार्य और उस क्षेत्र में पुलों के निर्माण के साथ दिल्ली मेट्रो के कार्य के कारण कार्य को बन्द कर दिया गया (अगस्त 2008)।

जब ठेकेदार ने अनुबंध को खत्म करने व ₹ 6.25 लाख की जमानत राशि के साथ शेष राशि के भुगतान का अनुरोध किया, (4 अगस्त 2008) दि.ज.बो. ने ठेकेदार को अगस्त 2008 तक बाधामुक्त कार्यस्थल सौंपने के लिए आश्वस्त किया लेकिन अपने आश्वासन को पूरा करने में विफल रहे। अंत में जब दि.ज.बो. ने अक्टूबर 2008 में कार्य करने की अनुमति दी तो ठेकेदार ने शेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए ₹ 1.25 करोड़ की प्रारंभिक लागत के विरुद्ध ₹ 2.45 करोड़ (निविदा लागत के ऊपर 140 प्रतिशत) की माँग की। उच्च दरें दि.ज.बो. द्वारा नहीं मानी गयी और अनुबंध को बन्द करने का निश्चय (अप्रैल 2009) किया गया। ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के लिये ₹ 73.85 लाख का भुगतान किया गया और ₹ 6.25 लाख की जमानत राशि भी वापिस की गयी। शेष कार्य जनवरी 2015 तक नहीं सौंपे गये, हालांकि पाँच से अधिक वर्ष व्यतीत हो गये थे, क्योंकि कार्य अप्रैल 2009 में बंद किया गया था।

इस प्रकार, दि.ज.बो. की ओर से नि.आ.सू. की स्वीकृति से पूर्व और सौंपे गये कार्यों से पहले बाधामुक्त कार्य स्थलों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में दूरदर्शिता की कमी के कारण, परियोजना को बीच में छोड़ना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 73.85 लाख का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि आजादपुर एस.पी.एस. से कोरोनेशन पिलर एस.टी.पी. तक सीवेज का परिवहन, जैसाकि विचारित था, नहीं किया जा सका।


अपने प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि अवरोधों का पूर्वानुमान संभव नहीं था, क्योंकि सम्बन्धित एजेंसियों ने संभावित घटनाओं से उन्हें कभी अवगत नहीं कराया। दिल्ली में, राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की अवधि के दौरान युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जाने के कारण कार्य में देरी हुई और अंततः रोक दिया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि के.लो.नि.वि. नियमावली 2012 स्पष्ट रूप से

अनुबंध करती है कि कार्य हेतु नि.आ.सू. का अनुमोदन पहले से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमण्डल खेल अक्टूबर 2010 में आयोजित किए गए, परन्तु शेष कार्य, यहाँ तक की खेलों के चार वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सौंपा नहीं गया।


मामला अगस्त 2014 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

ubZfnYyh  
fnukd%01 t w 2015

  
MSyh p0cri%2  
izku egkys[ kdkj %ys[ ki jh(kk) fnYyh

i frgLrk(kj)r

ubZfnYyh  
fnukd%01 t w 2015

  
%k' k dkr 'le%2  
Hkj r dsfu; a-d-egkys[ ki jh(kd

vuqXud

**वृत्त 2.1**  
**नवंबर से मई तक की कुल राशि का वार्षिक विवरण**  
**2.2.4.2 नवंबर से मई तक**

(मात्रा लीटर में)

वर्ष	वृत्त 1		वृत्त 2		वृत्त 3		कुल		वर्ष	प्रति व्यक्ति	कुल
	नवंबर से मई तक	मई से नवंबर तक	नवंबर से मई तक	मई से नवंबर तक	नवंबर से मई तक	मई से नवंबर तक	नवंबर से मई तक	मई से नवंबर तक			
मार्च-10	7106	4708.60	11702	11152.63	12368	5853.25	6890	5765.30	10586.22	16.20	171497
मार्च-11	7403	4923.25	10518	10191.18	13328	5365.45	6134	5283.00	11620.12	18.80	218458
मार्च-12	6648	4370.90	10702	10333.65	8916	4765.75	5877	5132.00	7540.70	23.49	177131
मार्च-13	7141	4488.15	10507	10090.13	9351	4532.45	6390	5910.00	8368.27	23.00	192470
मार्च-14	6539	5418.45	9012	8628.70	10805	5383.20	8291	7000.65	8216.00	22.40	184038
<b>कुल</b>	<b>34837</b>	<b>23909.35</b>	<b>52441</b>	<b>50396.29</b>	<b>54768</b>	<b>25900.10</b>	<b>33582</b>	<b>29090.95</b>	<b>46331.31</b>		<b>943594</b>

vuy&u&2-2  
 , e-ihy 0, e, y, - y dsn' kfun' kdsi ko/ku lckr y ulRed foj .k  
 ¼ y kxkQ 2-4-2 dsl aHkE½

Ø-1 a	, e-ihy dsi ko/ku	, e, y, y ealLfr
iZrto lch iZrfr		
1	संसद सदस्यों के लिए जिला प्राधिकारी के समक्ष जाँच व तकनीकी / वित्तीय प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा करने के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु एक समुचित निर्धारित प्रारूप है जिसमें निर्माण कार्य का नाम व प्रकृति स्थान व अनुमानित लागत का उल्लेख हो।	प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारूप व प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में नहीं वर्णित है।
i f j ; kt ukv lcht kp o l l oh-fr		
2	जिला प्राधिकारी को अग्रिम रूप में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित परिसम्पत्तियों	कार्य की संस्वीकृति के पूर्व क्रियान्वयक एजेंसी / प्रयोक्ता एजेंसी से ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त करने का बंधन नहीं है।
3	प्रस्ताव अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर संस्वीकृत किए जाएँ।	योजना दिशानिर्देशों में प्रस्तावों की संस्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
4	संस्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर कार्य समाप्त न करने की स्थिति में लागू होने वाले दण्डात्मक उपबन्ध के साथ क्रियान्वयक एजेंसी को कार्य समाप्त करने हेतु एक समय सीमा का अनुबंध किया जाता है।	योजना दिशानिर्देशों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृति पत्र में संस्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी हेतु समयसीमा निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश नहीं है।
5	निर्माण कार्य को मंजूरी देने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यों के लिए सभी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त हो चुके हैं।	
6	संसद सदस्य से अनुशंसा प्राप्त होने पर और कार्य हेतु संस्वीकृति जारी होने पर जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्वीकृत कार्यों का विवरण क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा पर्याप्त रूप से परिकल्पित इनपुट डाटा प्रारूप, मास्टर डाटा प्रविष्टि प्रारूप, मासिक डाटा प्रविष्टि प्रारूप तथा डाटा प्रविष्टि प्रारूप	योजना दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनपुट / आउटपुट डाटा के अनुरक्षण की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता।

Ø-1 a	, e-i hysM dsi to/ku	, e, y, ysh esLMr
7	जिला प्राधिकारी जाँच कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी अनुमान, अनुमोदन, निविदा की स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगा।	प्रस्तावों की जाँच हेतु कोई विशेष प्रक्रिया परिभाषित नहीं है।
8	प्रत्येक संसदीकृत कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक पहचान संख्या जारी की जाएगी।	विधानसभा सदस्य क्रियान्वयक एजेंसी का चयन करता है।
9	प्रत्येक संसदीकृत कार्य के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा आई.डी. संख्या जारी की जानी थी।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
<b>t kj hfuf/k kr FkkfoYMr i xUku</b>		
10	संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किए गए कार्य में सार्वजनिक व सामुदायिक योगदान की अनुमति है।	योजना दिशानिर्देशों में इस विषय पर कुछ कहा नहीं गया है।
11	इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों पर अर्जित बैंक ब्याज आगे उपयोग किए जाने हेतु जिला प्राधिकारी हेतु भुगतान किया जाएगा।	योजना दिशानिर्देशों में श.वि.वि द्वारा जारी की गई निधियों पर क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में कोई नीति नहीं है।
12	एम पी लैड्स के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किए गए आकस्मिकता व्यय हेतु एक पृथक खाता रखा जाएगा तथा संबद्ध संसद सदस्य को लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच के विवरण उपलब्ध कराए जाने के अलावा इसकी सूचना दी जाती रहेगी।	योजना दिशानिर्देशों में श.वि.वि. तथा क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा आकस्मिकता व्यय का खाता रखने हेतु कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं है।
13	क्रियान्वयक एजेंसियों द्वारा मंत्रालय से प्राप्त निधियाँ केवल राष्ट्रीय बैंक के बचत खाते में ही रखा जाएगी।	योजना दिशानिर्देशों में योजनागत निधियों को जमा करने हेतु पृथक खाता / खाते के प्रकार संबंधी कोई विशिष्ट विनिर्दिष्ट अनुबंध नहीं है। योजनागत निधि बचत खाते में रखने की कोई पाबंदी नहीं है।
<b>y q katu i Ø; k</b>		
14	जिला प्राधिकारी भी एम पी लैड्स की निधियों के संसद सदस्यों के क्रम में रखेगा। रोकड़ बही व अन्य लेखा बहियाँ राज्य / संघ प्रदेश की प्रक्रियानुसार रखी जाएगी।	श.वि.वि. द्वारा विधानसभा सदस्यों के क्रमवार लेखों का रखा जाना अनिवार्य नहीं किया गया है।
15	जिला प्राधिकारी भी सभी एम.पी. लैड्स कार्यों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में क्रियान्वित किए गए कार्यों की विभिन्न शीर्षवार सूचियाँ रखेगा।	योजना के दिशानिर्देशों में निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्रवार शीर्ष व कोड का प्रावधान नहीं है तथा सृजित परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखने के लिए कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।



Ø-1 a	, e-ihy dsi b/ku	, e, y, y eslfkr
16	अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत तक क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम तथा शेष उस अग्रिम का 60 प्रतिशत खर्च होने के बाद	योजना दिशानिर्देशों में क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम रूप में पूर्ण संस्वीकृत राशि जारी करने की अनुमति दी गई है।
17	जिला प्राधिकारी निधियों के लेखे संसद सदस्यों के क्रम में रखेंगे और वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा लेखे, रिपोर्ट व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।	लेखों के रखरखाव व योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
vkrfj d fu; a. kiz.kyh		
18	जिला प्राधिकारी इन कार्यों के समय से व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।	श.वि.वि. को योजनागत कार्यों के समय से व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है।
19	जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को समुचित ढंग से निर्धारित प्रारूप पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।	उपयोग प्रमाणपत्र की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारूप योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित नहीं है।
20	जिला प्राधिकारी प्रतिवर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखों, रिपोर्टों तथा प्रमाणपत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।	योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया/विधि योजना के दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं है।
21	राज्य सरकार द्वारा राज्य / संघ प्रदेश के महालेखाकार की अनुशंसा पर नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एक समुचित रूप से निर्धारित प्रक्रिया है।	योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया/विधि योजना के दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं है।
22	जिला प्राधिकारी और क्रियान्वयक एजेंसी विलम्ब किए बिना परिसम्पत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेंगे। प्रयोक्ता एजेंसी इन्हें इनके सामान्य प्रचालन व अनुरक्षण हेतु अपने खातों में दर्ज करेंगी।	श.वि.वि. या क्रियान्वयक एजेंसी को परिसंपत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। परिसंपत्तियाँ प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन परिसंपत्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं है।
23	निगरानी प्रणाली का प्रावधान है।	योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Ø-l a	, e-i hyM dsi ho/ku	, e, y, yM eafMfr
I koZ fud I puki zkylh		
24	<p>जैसे ही योजनान्तर्गत कोई कार्य समाप्त हो, इसे सामान्य जन के उपयोग हेतु रखा जाए। अधिक जन जागरुकता हेतु एम पी लैंडस के अंतर्गत क्रियान्वित सभी जागरुकता हेतु एम पी लैंडस के अंतर्गत क्रियान्वित सभी जागरुकता हेतु एम पी लैंडस कार्य लेखयुक्त एक धातु की प्लेट जिस पर इसमें शामिल लागत, कार्य के आरंभ, समाप्ति व उद्घाटन की तिथि तथा संसद सदस्य का नाम दर्शाया गया हो, स्थाई रूप से लगाई जाए।</p>	<p>योजना दिशानिर्देशों में परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा इन परिसंपत्तियों के लिए निधियों के स्रोत के प्रति जन सामान्य को सूचित करने हेतु कोई विशेष निर्देश नहीं है।</p>
25	<p>सभी समाप्त और चल रहे कार्यों को जिला प्राधिकारी जन साधारण की सूचना हेतु प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन पट्ट पर लगाया जाए और वेबसाइट पर डाला जाए।</p>	<p>सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन हेतु लगाना आवश्यक नहीं किया गया है।</p>

वृत्त 2.3  
 निम्नलिखित लेखों के लिए विवरण देना  
 अनुसूची 2-5-6-1 के अनुसार

Ø-1 -	लेख		संशोधन		संशोधन		विवरण		विवरण				
	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या			
1.	स्वच्छता अधीक्षक	15	6	4	5	4	4	8	10	2	66.66	66	33
2.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	14	8	8	5	8	2	6	9	6	64.28	42	75
3.	स्वच्छता निरीक्षक	118	68	117	108	59	1	5	1	9	--	4	13
4.	सहायक स्वच्छता निरीक्षक	312	181	280	249	130	32	74	32	51	10.25	23	28
5.	स्वच्छता गाइड	262	174	157	236	101	105	43	73	73	40.08	15	42
6.	सफाई कर्मचारी	17141	13526	8561	9436	7589	3292	4090	972	972	19.20	30	11

वृत्त-2-4  
 वृत्त-1 - धर्मिक; कक्षा 1-2  
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Ø-1 -	i zu D; k	i frfØ; k								
		j kfg. kh {k=			d k h r {k=			i w l f n - u - fu-		
		gk	ugla	m-u-	gk	ugla (%)	m-u-	gk	ugla (%)	m-u-
1	सड़कों / गलियों में प्रतिदिन झाड़ू लगता है?	45	35 (43)		20	16 (44)		72	40 (35)	1
2	झाड़ू लगाने के तुरंत बाद कूड़ा उठाया जाता है?	37	43 (53)		15	21 (58)		49	63 (56)	1
3	नाले / नालियाँ प्रतिदिन साफ किए जाते हैं?	16	64 (80)		6	28 (82)	2	36	76 (67)	1
4	नालों से गाद / कचरा सड़कों से तुरंत हटाया जाता है?	16	61 (79)	3	2	34 (94)		38	74 (66)	1
5	कूड़ा घर-घर जाकर उठाया जाता है?	47	31 (39)		15	19 (55)	2	76	36 (32)	1
6	कूड़े-कचरे के लिए मुक्त भण्डारण क्षेत्र हैं?	28	23 (45)	29	24	12 (66)		38	58 (60)	17
7	ढलावों / मुक्त क्षेत्रों से कूड़े-कचरे को रोज उठाया जाता है?	9	38 (80)	33	6	27 (81)	3	29	64 (68)	20
8	कूड़े-कचरे को भराव क्षेत्रों में पहुँचाते समय ढँका जाता है?	11	29 (72)	49	20	14 (41)	2	25	68 (73)	20
9	कूड़ा कचरा उठाने के बाद ढलाव / मुक्त क्षेत्रों को साफ किया / धोया / असंक्रमित किया जाता है?	10	34 (77)	36	7	29 (80)		27	68 (71)	18
10	सी टी सी / मूत्रालय रोज साफ / असंक्रमित किए जाते हैं?	7	39 (84)	34	1	23 (95)		11	20 (64)	82

वृत्त 3-1

36 प; फुर फो | क्य; क ds l a d fujh k k ds fu" d" k dk l k j k k  
 3-2-5 (ii) ds l n H Z e

Ø-l a	वृत्त 3-1 वृत्त 3-2-5 (ii) वृत्त 3-2-5 (ii)	df; k@nk	fo   ky; k dhl d; k
1.	प्रसाधन	i) रुके हुए/चोक ii) टोटियों में पानी नहीं iii) टूटा फर्श/पानी का जमाव iv) सीवर लाईन से जुड़ा नहीं	13 6 6 7
2.	पेय जल	i) आर ओ सिस्टम उपलब्ध नहीं ii) शिरोपरि पानी की टंकी उपलब्ध नहीं iii) टूटी/ठीक ढंग से नहीं लगाई गई पानी की टोटियाँ	12 6 2
3.	आर.डब्ल्यू.एच.एस.	i) उपलब्ध नहीं ii) कार्यशील नहीं	13 4
4.	चारदीवारी की मरम्मत/ नवीनीकरण	i) नहीं किया गया ii) अपूर्ण/असंतोषजनक कार्य	7 2
5.	खेल के मैदान का उन्नयन	i) उन्नयन नहीं किया गया	12
6.	पुस्तकालय का उन्नयन	i) सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं	12
7.	विद्युत प्रणालियाँ	सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं	8
8.	विकास कार्य	स्ट्रॉम वाटर नाले, आंतरिक पथ, बागवानी प्रचालन हेतु स्थल श्रेणीकरण नहीं किया गया	17
9	भवन	i) कक्षाओं की छतों से पानी का रिसाव ii) दिवारों में दरार iii) टूटे दरवाजे / बगैर खिड़कियाँ	7 1 3
10	शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में निर्माण	शि.स.सा. सम्बन्धी कार्य नहीं किए गए	36
11	अग्नि सुरक्षा	i) कक्षाओं में दूसरा दरवाजा उपलब्ध नहीं ii) अतिरिक्त सीढियाँ उपलब्ध नहीं iii) डिजाईनदार गेट उपलब्ध नहीं iv) पम्प उपलब्ध नहीं v) पाईप/होज रील उपलब्ध नहीं vi) भूमिगत पानी की टंकियाँ उपलब्ध नहीं vii) अग्निशामक संयंत्र/पानी की बाल्टियाँ उपलब्ध नहीं	3 4 5 6 11 6 2

**वृद्धि 3.2**  
**लाभ, नुकसान और अन्य व्यय का विवरण**  
**3.4(i) के अंतर्गत**

वर्ष	माह	प्रारंभिक मूल्य (अनुमानित व्यय, देय, अन्य आय, मूल्य में परिवर्तन आदि)	अंशदान का मूल्य (अनुमानित व्यय, देय, अन्य आय, मूल्य में परिवर्तन आदि)	अंशदान का मूल्य (अनुमानित व्यय, देय, अन्य आय, मूल्य में परिवर्तन आदि)	
				अंशदान का मूल्य (अनुमानित व्यय, देय, अन्य आय, मूल्य में परिवर्तन आदि)	अंशदान का मूल्य (अनुमानित व्यय, देय, अन्य आय, मूल्य में परिवर्तन आदि)
प्रोफेसर	फरवरी 2012	₹ 1,47,483	₹ 1,35,930	बै.वे. - ₹ 47,100 (न्यूनतम) प.वे. - ₹ 12,000	₹ 1,88,368
अतिरिक्त प्रोफेसर	मई 2011	₹ 1,56,983	₹ 1,21,900 (5 अग्रिम अभिवृद्धियों के साथ)	बै.वे. - ₹ 59,125 प.वे. ₹ 10,000	₹ 2,08,318
सह प्रोफेसर	जनवरी 2013	₹ 1,36,578	₹ 1,12,930* (वेतन सुरक्षा के साथ)	बै.वे. - ₹ 48,580 प.वे. ₹ 8,900	₹ 1,90,122
सहायक प्रोफेसर	मई 2012	₹ 1,21,470	₹ 1,06,030*	बै.वे. - ₹ 37,400 (न्यूनतम) प.वे. ₹ 8,700	₹ 1,67,222
		<p>*(क) एकमुश्त धनराशि में बै.वे., प.वे. मं.भ., म.कि.भ. (30%), शैक्षणिक भत्ता (₹10,000) तथा परिवहन भत्ता व नियोक्ता का भ.नि. अंशदान</p> <p>(ख) वार्षिक अभिवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से अनुमत</p> <p>(ग) एकमुश्त धनराशि के परिकलन में राजस्व अंश शामिल नहीं</p>	<p>**धनराशि में बै.वे., प.वे., एन पी ए (बै.वे.+प.वे. का 25%), म.भ. (नियत 22%) म.कि.भ. (50%) तथा नियोक्ता की भ.नि. अंशदान इसके अतिरिक्त परिवहन भत्ता तथा बा.शि.भ. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत हैं।</p>	<p>***(क) इस धनराशि में निम्नोक्त शामिल हैं: बै.वे., प.वे., एन पी ए (बै.वे.+प.वे. का 25%), मं. भ., म.कि.भ. (बै.वे.+प.वे.+एन पी ए का 50%) बा.शि.भ. (₹ 2,000 अधिकतम), परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता (₹5.00 नियत), अनुसंधान भत्ता (₹ 2,000 नियत) चिकित्सा भत्ता सीपीएफ, टेलीफोन भत्ता, इंटरनेट भत्ता</p> <p>(ख) वार्षिक अभिवृद्धि 7.5 प्रतिशत की दर से</p>	